

जमुनादास अख्तर



पाकिस्तान की टूटती राजनीति पर एक रोचक पुस्तक

यह पुस्तक

६ दिसम्बर '७१ को एशिया महाद्वीप में एक नए राज्य 'गण-प्रजा-तन्त्रीय बंगला देश' का वास्तविक जन्म हुआ, जब भारत सरकार द्वारा इसको मान्यता प्रदान की गई। इस नए देश की आबादी साठे सात करोड़ है, और चीन, भारत, रूस, अमरीका, इण्डोनेशिया और ब्राजील के बाद यह विश्व का सबसे बड़ा देश होगा। अब यह प्रमाणित हो चुका है कि यह नया देश पाकिस्तानी-तानाशाहों की स्वार्थपूर्ण नीतियों के कारण बना। गत २४ वर्षों में पाकिस्तान के राजनीतिज्ञों ने एक-दूसरे के विरुद्ध—एक अपने पड़ोसी देश भारत के विरुद्ध—जो पड़्यन्त्र रचे, वे अपने में सनसनीपूर्ण भी हैं और शिक्षाप्रद भी। इस कड़ो का अन्तिम पड़्यन्त्र, जुलफिकार अली भुट्टो द्वारा भूतपूर्व राष्ट्रपति याहिया-खान को निकालना रहा है। किन्तु पड़्यन्त्रों का यह चक्र तो चल ही रहा है।

और इस पुस्तक में १९४७ से अब तक की पाकिस्तानी राजनीति का रोचक विवरण है, जिसे हम नए 'बंगला देश' के नेताओं को समर्पित करते हैं।

लेखक की कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनायें :

- पोलिटिकल कास्पीरेसीज इन पाकिस्तान (अंग्रेजी)
- पाक एसयॉनैज इन इंडिया (अंग्रेजी)
- कश्मीर की बेटी (हिन्दी)
- पंजाब की बेटी (हिन्दी)
- दि सागा ऑफ बंगला-देश (अंग्रेजी)



हिन्दी बुक सेन्टर, नई दिल्ली-१

द्वारा प्रसारित

सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

प्रकाशक :

प जाबी पुस्तक भण्डार

दरीबा काना, दिल्ली-६

द्वितीय (पुस्तकालय) संस्करण . जनवरी १९७२

मूल्य : छः रुपये (Rs. 6 00)

एक-मात्र वितरक

हिन्दी बुक सेन्टर

आसफ अली रोड, नई दिल्ली-१

मुद्रक - हिन्दी प्रिंटिंग प्रेस, नारायणा इण्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-२८

इस पुस्तक के सम्बन्ध में :

दो वर्ष पहले जब “पाकिस्तान मे राजनीतिक पड्यत्र” के नाम से अग्रेजी मे मेरी पुस्तक प्रकाशित हुई तो देश-विदेश मे इसका स्वागत हुआ और प्रमुख समाचार पत्रो ने लिखा कि पाकिस्तान की समस्याओ, पाकिस्तान मे घरेलू षड्यन्त्रो और भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के शासको के खतरनाक हथकडो पर इस से अच्छी पुस्तक इस से पहले प्रकाशित नही हुई। इस पुस्तक की कीमत ४५ रुपये थी। इसके अति-रिक्त यह पुस्तक अग्रेजी मे थी इसलिए साधारण जनता, विशेषतया हिन्दी प्रेमियो के लिये इसका अध्ययन करना कठिन था। इसलिये फैसला किया गया कि हिन्दी प्रेमियो के लिये पाकिस्तान की समस्याओ और इसके भविष्य पर एक ऐसी पुस्तक लिखी जाये जिससे साधारण जनता विशेषतया हिन्दी प्रेमी लाभ उठा सके। मै स्टार पब्लिकेशन्स के सचालिक श्री अमरनाथ का आभारी हू कि उन्होने मेरी इस पुस्तक को प्रकाशित करना स्वीकार किया।

दुर्भाग्य ही तो है कि हमारे देश मे यूरोप और अमरीका पर तो बहुत पुस्तके लिखी और प्रकाशित की जाती है परन्तु पाकिस्तान जैसे देश पर जो कि हमारा निकटतम पडोसी है और जिसकी गतिविधियों का हमारे देश पर गहरा प्रभाव पडता है बहुत कम पुस्तके प्रकाशित होती है। गत २४ वर्षों मे पाकिस्तान के शासको ने चार बार हमारे देश पर आक्रमण किया। पाकिस्तान के तानाशाहो को जब भी अपने देश मे विरोधी जनता की ओर से अपनी गद्दिया डोलती हुई दिखाई दी, उन्होने जनता को हमारे देश मे धकेलना और हमारे विरुद्ध युद्ध के नारे लगाना शुरू कर दिया। हमारे देश पर चार बार हमले करने के साथ ही पाकि-

स्तान के तानाशाही ने हमारे प्रमुख नेताओं की हत्या करने के लिए कितने ही षड्यंत्र रचाये। कुछ ही वर्षों में हजारों सशस्त्र घुसपैठिये, जासूस और एजेंट हमारे देश में भेजे गये। अपनी समस्याओं का समाधान करने की बजाय पाकिस्तानी शासक हमारे इलाकों पर सशस्त्र अधिकार करने के लिये षड्यंत्र करते रहे। पाकिस्तान के शासकों ने गत २४ वर्षों में दूसरे देशों से जब भी कोई सैनिक अथवा असैनिक गठजोड़ किया, उनका लक्ष्य यही रहा कि भारत को कमजोर और परेशान किया जाये और यदि हो सके तो इसके टुकड़े-टुकड़े कर दिये जायें। अपनी जनता की आर्थिक स्थिति के सुधार पर ध्यान देने और जनता को उसके अधिकार देने की बजाय उन्होंने भारत से छेड़-छाड़ करना अपनी आदत बना ली है। इस बार पाकिस्तान ने जो हमला किया उसका फैसला उन्होंने अचानक ही नहीं किया बल्कि इसके लिये १९६५ के युद्ध में हार जाने के बाद ही जोर-शोर से तैयारियां शुरू कर दी गईं और पहले की भांति अब भी पाकिस्तानी शासकों ने हमला करने के लिये यह झूठा आरोप लगाया कि भारत ने पहल की है।

इस युद्ध के परिणाम के सम्बन्ध में मुझे कोई सदेह नहीं। 'गण-प्रजातन्त्रीय बंगला देश' को गत ६ दिसम्बर को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की जा चुकी है—और अब यह क्षेत्र तो पाकिस्तान में कभी दोबारा सम्मिलित नहीं होगा। याहिया खा ने अपनी शर्मन-सत्ता बनाये रखने के लिये एक बहुत बड़ा जुआ खेला है। इसके परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। बंगला देश की स्वतंत्रता का एक अर्थ यह भी है कि जहाँ पश्चिमी पाकिस्तानियों के लिये घर की यह मण्डी उनके हाथों से निकल चुकी है—और इससे पश्चिमी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को तबाही का सामना करना पड़ेगा वहाँ युद्ध स्वयं उसके लिये तबाही ला रहा है। इसके साथ ही बंगला देश में पश्चिमी पाकिस्तान के हजारों सैनिकों का सफाया पश्चिमी पाकिस्तान में तानाशाही के विरुद्ध क्रोध की आग भड़कायेगा। १९६५ के आक्रमण की असफलता ने अयूब-शाही का अन्त किया था। इस बार याहिया-शाही का अन्त होगा ही परन्तु इसके साथ ही युद्ध के दौरान

ही पश्चिमी पाकिस्तान में विद्रोह हो सकता है। पश्चिमी पाकिस्तान के टुकड़े-टुकड़े भी हो सकते हैं। पाकिस्तान नाम के देश का विनाश होकर उसकी जगह पाँच नये देशों की स्थापना भी हो सकती है।

इस पुस्तक में मैंने पाकिस्तान के सम्पूर्ण इतिहास और वर्तमान स्थिति के सभी पहलुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। मैं स्वयं पश्चिमी पाकिस्तान से आया हूँ जहाँ मैंने १५ वर्ष तक पत्रकार की की हैसियत से काम किया है। पाकिस्तान के वर्तमान शासकों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। पाकिस्तान बनने के बाद भी मैंने वहाँ जाने का अवसर मिला है। अपने अनुभवों की बुनियाद पर मैंने यह पुस्तक लिखी है। मुझे आशा है कि जनता इसे पसन्द करेगी।

दिल्ली ८-१२-७१

—जमुनादास अख्तर

दूसरे संस्करण के सम्बन्ध में

इस पुस्तक का पहला संस्करण १२ दिसम्बर को प्रकाशित हुआ था। चार दिन बाद बंगला देश में पाकिस्तानी सेना ने हथियार डाल दिये। भारत सरकार ने तुरन्त ही घोषणा कर दी कि १७ दिसम्बर को आठ बजे रात पश्चिमी मोर्चे पर लड़ाई बन्दी कर दी जायेगी। याहिया सरकार का दम टूट चुका था। इसके परिणाम स्वरूप उसने भी लड़ाई-बन्दी की घोषणा कर दी और २० दिसम्बर को याहिया खा की ताना-शाही का अन्त हो गया। श्री भुट्टो को पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनने का अवसर मिल चुका है। उन्होंने याहियाशाही से सम्बन्धित कई जनरलों को हटा दिया है। परन्तु देखना यह है कि वह बचे खुचे नेता पाकिस्तान की नाव को किनारे लगा सकते हैं अथवा वह ऐसी गलतियाँ करेंगे जिनके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान का अन्त हो जायेगा। इस पुस्तक के अन्तिम दो अध्यायों में इसी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया गया है। और यह इस पुस्तक में पहले संस्करण के बाद का महत्वपूर्ण संशोधन है।

दिल्ली ५ जनवरी १९७२

—जमुनादास अख्तर

क्रम

घृणा की नींव पर	६
काश्मीर और कल्लात पर आक्रमण	१६
जिन्नाह की रहस्यमयी मृत्यु और लियाकत अली की हत्या	२६
नाजिमुद्दीन सरकार का अन्त	
जनता के विरुद्ध नौकरशाही की जीत	४६
इस्कन्दर मिर्जा की तानाशाही, जनता पर प्रहार	५१
डाक्टर खा साहिब की हत्या	६१
इस्कन्दर मिर्जा के अन्तिम हथकड़े	६६
अयूब खा की सैनिक तानाशाही	७३
भारतीय नेताओं की हत्या के लिये पाकिस्तानी षड्यंत्र	९१
हजरत मुहम्मद के बाल की चोरी	
(पाकिस्तानी षड्यंत्र और शेख अब्दुल्ला)	९४
रणकच्छ और काश्मीर पर हमला	१००
पाकिस्तान में विद्रोह अयूबशाही का अन्त	१०७
फातिमा जिन्नाह और सोहरावर्दी के हत्यारे कौन ?	१४०
याहिया खा की तानाशाही बंगला देश में विद्रोह	१४७
भारत पर आक्रमण याहियाशाही का अन्त	१७६
क्या पाकिस्तान जिन्दा रहेगा ?	१८६

घृणा की नींव पर

१४ अगस्त १९४७ को जब पाकिस्तान की स्थापना हुई और बाहगा के उस पार निर्दोष पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों और वृद्धों के लहू की नदिया बह रही थी, पाकिस्तान के नेता यह समझ कर खुशी से फूले नहीं समाने थे कि उन्होंने अपने स्वप्नों के देश की स्थापना कर ली है। करोड़ों दूसरे लोग यह समझ रहे थे कि उनके लिये इस्लाम की बुनियाद पर ऐसे देश की स्थापना की गई है जिसमें रहने वाले प्रत्येक मुसलमान को समान अधिकार प्राप्त होंगे और वह अपनी इच्छा अनुसार अपने भविष्य का निर्माण कर सकेंगे।

मुस्लिम लीग के आन्दोलन में उन्हें यही बताया गया था कि मुसलमान और हिन्दू अलग-अलग कौमे हैं। हिन्दू उनके शत्रु हैं और हिन्दू ही मुसलमानों की आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों के लिए जिम्मेदार हैं। हिन्दुओं के लिये घृणा और शत्रुता की भावना पैदा करने के लिए प्रचार किया जाता था कि अखण्ड भारत की स्वतन्त्रता का परिणाम यह होगा कि हिन्दू मुसलमानों को गुलाम बना लेंगे और इस्लाम और इस्लामी सभ्यता को नष्ट कर दिया जायेगा। जो मुस्लिम नेता इससे विरोध प्रकट करते थे उन पर इस्लाम और मुसलमानों से गद्दारी का आरोप लगाया जाता था।

धर्म के नाम पर घृणा की नींव अंग्रेज शासकों ने अपनी सत्ता कायम रखने के लिये ही तो रखी थी। अंग्रेज भारत में व्यापारियों के रूप में आये। उन्होंने विभिन्न भारतीय नरेशों को आपस में लड़ाना शुरू किया।

उनकी कमजोरियों से लाभ उठा कर धीरे-धीरे उन्होंने समस्त भारत पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज अफगानिस्तान पर भी अधिकार करना चाहता था। १८४२ में जब अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो उस समय के गवर्नर जनरल लार्ड एलनबुरो ने इस हमले को हिन्दुओं के हित के लिये ठीक जाहिर करते हुए एक घोषणा में कहा था कि

“हमारी विजयी सेना ने वीरता का प्रमाण देने हुए भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमणों का बदला ले लिया है। हम सोमनाथ के पवित्र मन्दिर के किवाड़ भारत में वापस ले आये हैं। महमूद गजनवी की नापाक कबर गजनी के खण्डहरों को देख कर रो रही है। आठ सौ वर्ष पहले की बेइज्जती का पूरा-पूरा बदला ले लिया गया है। सोमनाथ मन्दिर के किवाड़ जो आपकी पराजय के चिन्ह थे, आज आपकी शानदार विजय के प्रतीक हैं। यह जीत सिन्धु नदी के उस पार के देशों में आपकी बहादुरी का प्रमाण है।”

मजे की बात यह है कि यह एक बहुत बड़ा धोखा था। यह किवाड़ वास्तव में सोमनाथ मन्दिर के नहीं थे। बल्कि किसी साधारण व्यक्ति के मकान के किवाड़ थे। हिन्दुओं की निगाहों में घूल भोकने के लिये और अंग्रेजों को मुसलमानों के मुकाबले में हिन्दुओं का हितैषी जाहिर करने के लिये यह कहानी गढ़ी गई थी। इसी प्रकार बंगाल में मुसलमानों का शासन खतम करते समय कम्पनी सरकार के अधिकारियों ने दावा किया कि यह सब कुछ हिन्दुओं को स्वतंत्र कराने के लिये किया गया है। जब गवर्नर जनरल ने दिल्ली में मुगल शासन खतम करने का फैसला किया तो पंजाब में हिन्दुओं और सिक्खों को बताया गया कि ब्रिटिश सरकार ने समस्त भारत को जालिम मुसलमानों के शासन से स्वतंत्र करा लिया है। पंजाब में सिक्ख राज का अन्त करने के लिये मुसलमानों को बताया गया कि अंग्रेज ने पंजाब के मुसलमानों को सिक्खों से मुक्त कराया है। मजे की बात यह है कि १८५७ के स्वतंत्रता-संग्राम में पंजाब के सिक्ख और हिन्दू सैनिकों को दिल्ली पर हमला करने के लिये यह कह कर ईस्तेमाल किया गया कि अंग्रेज नहीं चाहता कि पंजाब पर एक बार फिर

मंगलो का शासन स्थापित हो जाये। वास्तव में अंग्रेज शासक इस बात से परेशान थे कि इस देश को स्वतंत्र कराने के लिये हिन्दू-मुसलमान एक हो गये हैं। बंगाल आर्मी ने जिस में हिन्दू, मुसलमान और सिख शामिल थे विद्रोह में भाग लिया था। ब्रिटिश सरकार के “पील कमीशन” ने इस स्थिति की जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट में लिखा कि “बंगाल आर्मी की कमजोरी का कारण यह था कि उसके सिपाहियों में धर्म और जाति के नाम पर कोई मतभेद नहीं था। इससे इनमें एकता की भावना आ गई थी। सर जान लार्स ने इस रिपोर्ट का अनुमोदन करते हुए कहा कि सेना का इस प्रकार में पुनर्संगठन किया जाये कि प्रत्येक प्रान्त की सेना के मुसलमान, हिन्दू और सिख सिपाही दूसरे प्रान्त के सिपाहियों से घृणा करे। उनमें प्रान्तीयता की भावना पैदा हो जाये।

सर चार्ल्स वुड ने १८६२ में गवर्नर जनरल लार्ड एलगन को लिखा कि “यदि समस्त भारत हमारे विरुद्ध खड़ा हो जाये तो हम कब तक अपने शासन को बचा सकेंगे। अपनी सिख सेनाओं को पंजाब में ही रखो और उन्हें बाहर के हिन्दुओं के खिलाफ इस्तेमाल करो। अपने हिन्दू सिपाहियों को पंजाब से बाहर रखो और आवश्यकता होने पर उन्हें सिखों के विरुद्ध इस्तेमाल करो, अपने शासन की रक्षा के लिये हमें विभिन्न जातियों में परस्पर विरोध की भावना पैदा करनी चाहिये।”

इसी योजना के अनुसार सेना का पुनर्संगठन किया गया। १८५७ के युद्ध में विहाबी मौलवियों ने अंग्रेज के विरुद्ध फतवे दिये थे। सरकार ने कुछ मौलवियों को खरीदा और उनसे अपने हक में और हिन्दुओं के खिलाफ फतवे प्राप्त किये। जौनपुर के मौलवी करामत अली इनमें से एक थे। कुछ शैय्या मौलवी भी खरीदे गये। इनमें एक पटना के मौलवी अमीर अली थे। इनसे भी ऐसे ही फतवे प्राप्त किये गये।

सर सैयद अहमद खान जिन्होंने बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय की स्थापना की, अंग्रेज सरकार के अधीन एक सब जज थे। १८५७ के युद्ध में उन्होंने बिजनौर में कुछ अंग्रेज अधिकारियों की रक्षा की थी। जब यह समाचार दिल्ली पहुँचा तो विद्रोहियों ने

उनका मकान लूट लिया। इसके बदले में अंग्रेज सरकार ने उन्हें जज बना दिया और उनके और उनके बेटे के लिये आजीवन पेंशन की घोषणा कर दी। सर सैय्यद ने उर्दू में एक पुस्तक लिखी जिसमें कहा गया कि “मुसलमानों ने विद्रोह नहीं किया था, वह तो अंग्रेजों के वफादार है।” उन्होंने लिखा कि यदि मुसलमानों और हिन्दुओं की अलग-अलग सेनाएँ संगठित की जाती तो उनमें एकता की भावना पैदा न होती और विद्रोह न होता। यह पुस्तक भारत और ब्रिटेन में गोरे अधिकारियों में बाटी गई। सरकार ने प्रसन्न हो कर उन्हें “सर” बना दिया। वह इंग्लैण्ड गये और लौटने पर उन्होंने कई पुस्तकें लिखी जिनमें मुसलमानों से कहा गया कि वह अंग्रेज के वफादार बन कर अंग्रेजी सीखें और नौकरियाँ प्राप्त करें। १८०२ में उन्होंने अजीगढ़ में मुस्लिम कालेज की स्थापना के लिये एक कमेटी स्थापित की और १८७७ में गवर्नर जनरल लार्ड लिटन ने इस कालेज की आधार-शिला रखी। सर सैयद ने इस अवसर पर कहा कि मुस्लिम जनता अंग्रेजों के शासन की विरोधी नहीं। उनके साथी नवाब अब्दुल लतीफ ने लिखा कि “मुसलमान समझते हैं कि उनकी सुरक्षा अंग्रेजों के शासन की मजबूती पर निर्भर है।”

मुसलमानों को काबू करने की इस योजना के साथ ही जब १८८५ में एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी मि० ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की तो इसके लिये भी गवर्नर जनरल लार्ड डफरिन ने सकेत किया था। अंग्रेज चाहता था कि कांग्रेस हिन्दुओं की संस्था बने। इसी समय अंग्रेज अधिकारी मुसलमानों को कांग्रेस के विरुद्ध फसाद कराने के लिये भड़का रहे थे। परन्तु कांग्रेस ने अंग्रेज के इशारे पर चलने से इन्कार कर दिया। इस से बिगड़ कर गवर्नर जनरल ने कांग्रेस को “विद्रोही” करार दिया और सैय्यद अहमद और उनके साथियों को भड़काया कि वह कांग्रेस के विरुद्ध आन्दोलन करें। सैय्यद अहमद ने १० दिसम्बर १८८८ को एक ब्रिटिश अधिकारी मि० ग्राहम को लिखा कि “मैंने तथाकथित नेशनल कांग्रेस के विरुद्ध एक भारी काम का

बोझा उठाया है।” उन्होंने मागे की कि नौकरियों में भरती के लिये मुकाबले के इन्तहान नहीं होने चाहिये। चुनाव भी नहीं होने चाहिये। बल्कि साम्प्रदायिकता के सिद्धान्त पर भरती होनी चाहिये। अलीगढ़ कालेज के अग्रेज प्रिंसिपल मि० ट्यूडर बैंक ने कालेज के मुस्लिम विद्यार्थियों में कांग्रेस और हिन्दुओं के विरुद्ध प्रचार शुरू किया। एक लेख में उसने लिखा कि मुसलमानों और अग्रेजों को मिलकर कांग्रेस का मुकाबला करना चाहिये। परन्तु यह आन्दोलन विफल हो गया। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भारी सख्या में मुसलमान सम्मिलित हुए। इससे परेशान होकर सरकार ने बंगाल का विभाजन कर दिया। मुसलमानों को कहा गया कि पूर्वी बंगाल में मुसलमान बहुसंख्यक होने के कारण हिन्दुओं के मुकाबले में फायदे में रहेंगे। ढाका के नवाब सलीम उल्ला इम योजना के विरुद्ध थे परन्तु उन्हें आसान शर्तों पर एक लाख पाउण्ड का ऋण दे कर अपने साथ मिला लिया गया। इन्हीं नवाब साहिब ने अग्रेज के सकेत पर “मुस्लिम लीग” की स्थापना की। बंगालियों ने अपने प्रान्त के विभाजन के विरुद्ध भारी आन्दोलन किया। विदेशी माल को जगह-जगह आग लगाई गई। इस से भयभीत हो कर सरकार ने अपना फैमला वापिस ले लिया परन्तु नवाब साहिब के हाथ मजबूत करने के लिये असम का कुछ भाग बंगाल में मिला कर बंगाल को मुस्लिम बहुसंख्यक प्रान्त बना दिया गया।

१९०६ में अलीगढ़ कालेज के नये मुख्याध्यापक मि० आर्कवॉल्ड ने गवर्नर जनरल के सैक्रेट्री कर्नल जैम्ज से भेंट की। दोनों ने मिल कर “मुसलमानों की मागों का प्रार्थना पत्र” लिखा। सर आगा खा को लन्दन से बुलाया गया। उनके नेतृत्व में एक “मुसलिम डेलीगेशन” ने गवर्नर जनरल से भेंट करके यह “मागें” प्रस्तुत की। गवर्नर जनरल की धर्म पत्नी लेडी मिण्टो ने इस वार्तालाप का उल्लेख अपनी डायरी में करते हुए लिखा कि .

“आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। एजीटेटर मुसलमानों में असन्तोष पैदा कर रहे थे। मुसलमान कांग्रेस की ओर झुक रहे

थे। परन्तु एक अधिकारी ने मुझे आज लिखा कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है। भारत के इतिहास पर वर्षों तक इसका प्रभाव रहेगा। हमने ६ करोड़ ८० लाख मुसलमानों को विद्रोही विरोधियों से मिल जाने से रोक लिया है।”

वास्तव में भारतवासियों के लिये यह एक दुःखदायक दिन था क्योंकि अंग्रेज ने अपना शासन मजबूत करने के लिये हिन्दुओं और मुसलमानों में फूट डालने और भारत का विभाजन करने के लिये आधार-शिला रख दी थी। अंग्रेज ने नौकरियों में साम्प्रदायिकता का विष दाखिल कर दिया था। सर आगा खा मुस्लिम लीग के प्रधान बन गये। उन्होंने लीग की ढाका शाखा के प्रधान को लिखा कि “लीग इस बात पर विश्वास करती है कि भारत के लिये अंग्रेज का शासन आवश्यक है और मुसलमानों का कर्तव्य है कि जनता के हृदय में त्रिटेन के लिये आदर और प्यार की भावना पैदा की जाये।”

१९०७ में लीग ने स्वराज्य और स्वदेशी आन्दोलन की निन्दा की। विभिन्न प्रान्तों में लीग की शाखाएँ बड़े-बड़े वफादार जमींदारों की अध्यक्षता में स्थापित की गईं। दक्षिण में लीग के प्रधान पुराने टोडी निजाम हैदराबाद थे।

देशभक्त मुस्लिम नेताओं ने इस खतरे को भाप लिया। मौलाना आजाद, डाक्टर किचलू और दूसरे देशभक्त मुस्लिम लीग में शामिल हो गये। १९२३ में उन्होंने लीग का विधान बदल कर विभिन्न सम्प्रदायों में मित्रता की भावना पर जोर देते हुए वैधानिक सुधार की मांग की। मि० जिन्नाह कांग्रेस के प्रधान दादा भाई नारोजी के प्राइवेट सैक्रेटरी थे। उन्होंने भारत में प्रिंस आफ वेल्स के आगमन पर सरकार के विरुद्ध भाषण दिया था। इम्पीरियल कौंसिल के सदस्य की हैसियत से भी वह ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते थे। पहले महायुद्ध के दिनों उन्होंने कांग्रेस के प्रतिनिधि की हैसियत से लन्दन में जाकर “इण्डियन कौंसिल बिल” का विरोध किया था। दिसम्बर १९१६ में कांग्रेस के अधिवेशन में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि मैं नहीं

चाहता कि तग नज़र लोग कांग्रेस को कमजोर करे। मुस्लिम लीग में सम्मिलित होकर उन्होंने सरकार के हिमायतियों से झगड़े किये। इन लोगों ने बम्बई में मि० जिन्नाह के जलसे में गड़बड़ की। परन्तु जब महात्मा गांधी कांग्रेस में आये तो जिन्नाह साहिब ने महसूस किया कि उनकी लीडरी को खतरा है। गांधी जी के सुझाव पर “होम रूल लीग” ने पूर्ण स्वराज्य की माग की। मि० जिन्नाह ने इस का विरोध करते हुए कहा कि होम रूल लीग की कार्यकारिणी समिति अपना विधान बदल नहीं सकती। इस पर सभा के अध्यक्ष ने उन्हें कहा कि यदि आप इस परिवर्तन को पसन्द नहीं करते तो अलग हो जायें। मि० जिन्नाह उठ कर चले गये और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। गांधी जी ने जिन्नाह को एक पत्र लिख कर त्यागपत्र वापस ले लेने के लिये अनुरोध किया। मि० जिन्नाह ने इन्कार करते हुए एक अत्यन्त कड़ा पत्र लिखा जिसमें उन्होंने गांधी जी के प्रोग्राम पर आपत्ति की और कहा कि आप जो आन्दोलन करना चाहते हैं इससे देश भर में अराजकता फैल जायेगी और इसके परिणाम खतरनाक होंगे।

दिसम्बर १९२० में कांग्रेस के खुले अधिवेशन ने स्वतंत्रता की माग करने और देश भर में आन्दोलन करने का फैसला किया। केवल मि० जिन्नाह ने इसका विरोध किया। उन्होंने गांधी जी की माग को गलत करार दिया। इस पर मौलाना मुहम्मद अली और मि० जिन्नाह में तू-तू मैं-मैं हो गई। मि० जिन्नाह मायूस हो कर चले गये। मुस्लिम लीग में भी उनकी पोजीशन शिथिल हो गई। हताश हो कर वह लन्दन चले गये। वहाँ अपनी पत्नी से उनका झगड़ा हो गया। उनकी पत्नी रुठ कर पेरिस चली गई। वहाँ उसने आत्महत्या के लिये विष खा लिया। एक मित्र मि० जिन्नाह को पेरिस ले गये। उनकी पत्नी की जान बच गई। दोनों में दीवान चमन लाल ने समझौता कराया परन्तु पति के हठील स्वभाव के कारण फिर झगड़ा हो गया। पत्नी रुठ कर बम्बई चली गई जहाँ उसने १९२८ में ताजमहल होटल में आत्महत्या कर ली। कुछ वर्ष जब जिन्नाह की इकलौती बेटी ने एक पारसी युवक से पिता

के विरोध पर भी विवाह कर लिया तो मि० जिन्नाह उससे भी बिगड़ गये। इस प्रकार मि० जिन्नाह अकेले रह गये। दीवान चम्मन लाल ही फिर उन्हें भारत में लाये। मि० जिन्नाह अब भी देश भक्त थे। जब सर इक्वाल ने पाकिस्तान की माग की तो जिन्नाह ने इसका विरोध किया परन्तु जहा गांधी जी के होते हुए कांग्रेस में उनकी दाल नहीं गलती थी वहा मि० जिन्नाह जनता के आदमी न होने के कारण कोई आन्दोलन शुरू करने और जेल यात्रा करने का साहस नहीं कर सकते थे। इस लिये वह फिर मायूस होकर लन्दन चले गये। जुलाई १९३२ में मि० लियाकत अली और उनकी बेगम ने मि० जिन्नाह से भेट की और उन्हें फिर भारत आने के लिये तैयार कर लिया। लियाकत अली का प्रभाव होने पर भी मि० जिन्नाह ने पहले गोल-मेज सम्मेलन के अवसर पर “पाकिस्तान” की माग का विरोध किया था।

मि० जिन्नाह को धीरे-धीरे मि० लियाकत अली ने रास कर लिया। उन पर मि० खलीकुज्जमान का प्रभाव भी था। यह साहिब यद्यपि कांग्रेस में थे और श्री जवाहरलाल नेहरू के बहुत निकट थे परन्तु बहुत कम लोग जानते हैं कि वह वास्तव में अंग्रेज सरकार के गुप्तचर थे। खलीकुज्जमान ने अपनी पुस्तक Path way to Pakistan के पृष्ठ २५७ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश के गवर्नर सर फ्रांसेस मुडी ने उन्हें गवर्नर जनरल से मिल कर पाकिस्तान की माग समझाने के लिये कहा था। उन्होंने यह भी लिखा है कि बहुत से अंग्रेज अधिकारी इस माग के समर्थक थे।

मि० खलीकुज्जमान को अंग्रेज मि० जिन्नाह का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इसलिये यह साहिब भारतीय लोक सभा में भारत से वफादारी की सौगंध उठाने के बाद एक दिन अचानक बहाने से कराची चले गये और पाकिस्तानी बन गये।

मि० जिन्नाह कई वर्ष तक अंग्रेज के विश्वास पात्र नहीं बने थे। उन में परिवर्तन लाने वाले मि० लियाकत अली और खलीकुज्जमान थे। यह परिवर्तन दूसरे महायुद्ध में ही शुरू हो गया था। मि० जिन्नाह

को ब्रिटेन की एक जहाजरानी कम्पनी ने ६ हजार रुपया मासिक "लीगल इलौस" देना शुरू कर दिया था। यह एक महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन है कि ब्रिटिश सरकार गुप्तचर विभाग से भी मि० जिन्नाह का सम्पर्क हो गया था।

१९४७ में पाकिस्तान की स्थापना होने से पहले अंग्रेजों ने क्या-क्या चालें चलीं। किस प्रकार देश के विभिन्न भागों में हिन्दुओं और मुसलमानों में फसाद कराये। किस प्रकार अंग्रेज सरकार साठे-दसौ रियासतों को भारत से अलग रखने की चालें चल रही थी। यह सब कुछ कल के इतिहास की घटनाएँ ही तो हैं। तात्पर्य यह कि देश का विभाजन घृणा की बुनियादों पर हुआ और अंग्रेजों और पाकिस्तान के शासकों के लिये आवश्यक था कि हिन्दू-मुस्लिम घृणा को भारत और पाकिस्तान के अमिट झगड़ों में बदल दिया जाये। ब्रिटिश सरकार जानती थी कि स्वतंत्र भारत शीघ्र ही प्रगति के पथ को अपना कर अपने पाव पर खड़ा हो जायेगा और इस से निसन्देह पाकिस्तान की जनता और एशिया के दूसरे देशों के लोग भी प्रभावित होंगे। इसलिये भारत को कमजोर रखने के लिये उसकी पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर पाकिस्तान के दो भाग बनाये गये। यह तैयार किया गया कि पाकिस्तान पर ऐसे नेताओं का शासन होगा जो भारत को अपना शत्रु समझ कर उससे लड़ते-झगड़ते रहे। पाकिस्तान की स्थापना होते ही उसकी सरकार में तमाम महत्वपूर्ण पद भारत विरोधी अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दिये गये। तमाम पाकिस्तानी प्रदेशों के राज्यपाल अंग्रेज अधिकारी ही नियुक्त किये गये। मि० जिन्नाह के अपने स्टाफ पर इन्हीं अधिकारियों का कंट्रोल रहा। अंग्रेज जानता था कि पाकिस्तान की जनता भारत की प्रगति से प्रभावित होगी इसलिये उसने अपने हितों की रक्षा के लिये जहाँ लयाकत अली, खलीकुज्जमान और सिकन्दर मिरजा जैसे व्यक्तियों को मि० जिन्नाह के निकट रखा वहाँ अंग्रेज अफसरों ने समस्त पाकिस्तान में अल्प-संख्यक सम्प्रदायों के

लोगो पर हमले करा के उन्हें भारत में धकेलना शुरू कर दिया ताकि एक तो भारत परेशान हो और दूसरे भारत में जवाबी तौर पर फसाद हो और भारत से मुसलमान भाग-भागकर पाकिस्तान में आये तो उन्हें आसानी से भारत के विरुद्ध भड़का कर जनता के अधिकारों की मांग करने वालों के मुंह बन्द कर दिये जायें।

अंग्रेज जहाँ पाकिस्तान को भारत को परेशान और कमजोर बनाने के लिये इस्तेमाल करना चाहता था वहाँ पाकिस्तान को अपने माल की मन्डी बनाना और उसकी जनशक्ति को एशिया के दूसरे देशों में अपने हितों के लिये युद्ध में इस्तेमाल करना चाहता था।

पाकिस्तान के शासकों को जनता ने नहीं चुना था। इसलिये अपनी शासन सत्ता बनाये रखने के लिये उन्होंने अंग्रेजों के बताये हुए मार्ग पर चलने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान की गत २४ वर्षों की कहानी इसलिये षड्यन्त्रों की कहानी है। इसमें कई पाकिस्तानी नेताओं की हत्या हुई। जनता के अधिकारों को कुचलने के लिये “इस्लाम और पाकिस्तान खतरे में” के नारे लगाकर देश भक्त नेताओं को जेलों में बन्द किया गया। भारत पर तीन बार आक्रमण किया गया। अपनी सत्ता बनाये रखने के लिये शासकों ने कभी एक देश से और कभी दूसरे देश से गठजोड़ किया। परन्तु भूठ और मक्कारी की दीवार हमेशा कायम नहीं रहती। अब स्थिति ऐसी पैदा हो चुकी है कि पाकिस्तान के शासकों की तानाशाही के कारण पाकिस्तान का अपना ही अस्तित्व खतरे में पड़ चुका है।

काश्मीर और कल्लात पर आक्रमण

पाकिस्तान की स्थापना तो हो गई परन्तु ऐसा होते ही पाकिस्तान के शासको के सामने गम्भीर समस्याये आ गई। लाखों हिन्दू, सिख पाकिस्तान से भगा दिये गये तो उनकी जगह लाखों मुसलमान बेघर भी आने लग गये। इनको आबाद करने और रोजगार देने की समस्या का कोई हल नहीं था। साम्प्रदायिक दगो मे गुण्डो और बदमाशो को आगे आने का अवसर मिल गया। इन लोगो ने खुले कैम्पो मे पडे हुए शरणार्थियो को लूटना और उनकी बेटियो और पत्नियो का अपहरण करना शुरू कर दिया। श्री शिहान साकिब ने जो कुछ वर्षों बाद अयूब खान के सैक्रेट्री नियुक्त हुए १९४७ मे ही कराची मे एक पुस्तक प्रकाशित करके गुण्डो की इन हरकतो का रहस्योद्घाटन किया था।

स्थानीय लोगो ने हिन्दू-सिख निवासियो की बहुत-सी जायदादो पर अधिकार कर लिया था। निकासियो की जमीनो पर भी बडे-बडे स्थानीय मुस्लिम जमीदारो ने अधिकार कर लिया था। इसलिये भारत से आये हुए लाखो मुसलमानो को सिर छिपाने के लिए जगह नहीं मिली। इससे उनमे असन्तोष बढने लगा।

सीमा प्रान्त मे पठानो ने अपनी स्वतन्त्रता के लिये आन्दोलन शुरू कर रखा था। जब डाक्टर खा साहिब के काग्रेसी मन्त्रिमण्डल को भंग करके अब्दुल कयूम खा को मुख्य मन्त्री बनाया गया और उसने विधान

सभा में बहुमत बनाने के लिये कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया तो पठानों और कबाइलियों में क्रोध और घृणा की ज्वाला भड़क उठी। यही स्थिति बिलोचिस्तान में भी उत्पन्न हो रही थी। पाकिस्तान के शासक इससे परेशान होने लगे। इस परेशानी का हल यह निकाला गया कि काश्मीर पर आक्रमण करने का फैसला किया गया। अंग्रेज भी इसके लिए दबाव डाल रहा था। ब्रिटिश सरकार काश्मीर में अपने सैनिक अड्डे बना कर रूस को भारत से अलग रखना चाहती थी। उसकी इच्छा यह भी थी कि पाकिस्तान से गठजोड़ कर के रूस और चीन की सीमाओं पर अपनी सेनाएं रखी जायें। और अपनी पोजीशन मजबूत बना कर अंतर्राष्ट्रीय मैदान में अमरीका से सौदेबाजी की जाये। पाकिस्तानी शासक काश्मीर पर आक्रमण करके अपनी जनता के मुहं बंद करना चाहते थे। पठानों को लूट-मार का लालच देकर वह यह भी समझते थे कि, जितने पठान मारे जायेंगे उतनी ही पठानों की आबादी कम हो जायेगी।

इस सम्बन्ध में यह स्मरण रहे कि ब्रिटिश सरकार वर्षों से काश्मीर पर अधिकार करने के लिये साज-बाज कर रही थी। १८८७ में ब्रिटिश सरकार ने जाली दस्तावेजात तैयार करके महाराजा काश्मीर श्री प्रताप सिंह पर यह आरोप लगाया था कि वह रूसी सम्राट की सहायता से भारत में बांग्लादेश को छुड़ाने की कोशिशें कर रहा है। इन जाली दस्तावेजात की वजह से १९३३ में ब्रिटिश सरकार ने काश्मीर के विभाजन की एक गुप्त योजना बनाई। सर आगा खां ने जिन्होंने अंग्रेजों के इशारे पर भारत में मुसलमानों के लिए विधान सभाओं और नौकरियों से अलग भाग की मांग की थी, अंग्रेज के इशारे पर काश्मीर का नवाब बनने के लिये हाथ-पाव मारने शुरू कर दिये थे। इन दिनों मि० जिन्नाह अभी अंग्रेज के विश्वास पात्र नहीं बने थे। अंग्रेज उस समय भी पाकिस्तान की स्थापना के लिये मैदान तैयार कर रहा था। इसके लिये सर आगा-

खा को वही पोजीशन देने के लिये साज-ब्राज की जा रही थी जो बाद में मि० जिन्नाह को दी गई। अंग्रेजों ने यह योजना बनाई कि काश्मीर घाटी और गिलगित को महाराजा से छीन कर सर आगा खा को उसका नरेश बना दिया जाये। महाराजा को कहा गया कि जम्मू और लद्दाख के साथ ही उन्हें पंजाब में कांगडा और पठानकोट के जिले दे दिये जायेंगे। यह योजना १९३३ में गोल मेज सम्मेलन की एक समिति में प्रस्तुत की गई परन्तु महाराजा ने इसे ठुकरा दिया। इस पर अंग्रेजों के इशारे पर लाहौर में सर मोहम्मद इकबाल ने “काश्मीर कमेटी” के नाम से एक संस्था स्थापित की। इस संस्था ने काश्मीर में शेख अब्दुल्ला आदि को अपने साथ मिलाकर महाराजा के विरुद्ध आन्दोलन शुरू किया। काश्मीर में जगह-जगह साम्प्रदायिक फसाद कराये गये और यद्यपि यह आन्दोलन सफल नहीं हुआ परन्तु महाराजा पर दबाव डालकर अंग्रेज सरकार ने एक आयोग नियुक्त किया जिसकी सिफारशों के अनुसार विधान सभा की स्थापना हुई और शेख साहिब के साथियों को मन्त्रिमण्डल में लिया गया। बाद में जब मि० जिन्नाह ने दखल देना शुरू किया और शेख की बजाय विरोधियों को आगे लाने का प्रयत्न किया तो शेख अब्दुल्ला ने मुस्लिम कान्फ्रेस भग करके नेशनल कान्फ्रेस की स्थापना कर ली। १९४६ में शेख साहिब ने “काश्मीर खाली करो” का नारा दिया। ऐसा मालूम होता है कि वह उस समय भी “स्वतंत्र काश्मीर” की स्थापना के स्वप्न देख रहे थे। मि० जिन्नाह की मुस्लिम लीग उनका विरोध कर रही थी। १९४७ में देश के विभाजन के समय शेख अब्दुल्ला जेल में थे। महाराजा पर गवर्नर जनरल लार्ड माउंटबैटन अनेक तरीकों से पाकिस्तान में सम्मिलित होने के लिये दबाव डाल रहे थे। जबकि महाराजा का प्रधान मंत्री काश्मीर को “स्वतंत्र देश” बनाकर ब्रिटिश कॉमन वेल्थ का सदस्य बनाना चाहता था। शेख के प्रतिनिधियों ने मि० जिन्नाह से लाहौर में भेंट की। मि० जिन्नाह ने शेख की यह शर्त रद्द कर दी कि पहले काश्मीर में लोक-

तत्र के सिद्धान्तों के अनुसार सरकार बनाने का अवसर देकर यह फैसला करने दिया जाये कि काश्मीर का भविष्य क्या होना चाहिये। महाराजा परेशान था। चूँकि काश्मीर का डाक और तार संचार लाहौर के अधीन था और श्रीनगर में रावलपिण्डी के मार्ग से सभी आवश्यक वस्तुएँ जाती थी इसलिये महाराजा ने इस व्यवस्था को बनाये रखने के लिये पाकिस्तान से समझौता कर लिया। भारत सरकार से इसी तरह के सम्बन्ध बनाये रखने के लिये उसने सधि की पेशकश की।

पाकिस्तान काश्मीर पर आक्रमण करने की तैयारियाँ कर रहा था। उसने काश्मीर को जाने वाला तमाम सामान रोक लिया और काश्मीर की सीमाओं पर गडबड शुरू कर दी। मि० जिन्नाह ने अपने निजी सैक्रेटरी रतुरशीद अहमद को श्रीनगर में गडबड कराने के लिये गुप्त रूप से भेज दिया। इधर स्यालकोट, रावलपिण्डी, मररी हिल्ज और एबटाबाद से लुटे-पिटे हिन्दू सिख भाग-भाग कर काश्मीर में प्रवेश कर रहे थे। काश्मीर की सेना के कमाण्डर एक अग्रेज अफसर मि० स्काट थे। गिलगित में सेना का कमाण्डर और सैनिक का गवर्नर एक अग्रेज अफसर कर्नल ब्राउन था। ये दोनों गुप्त रूप से पाकिस्तान से मिले हुए थे। पंजाब और सीमा प्रान्त के अग्रेज राज्यपाल पठानों और पंजाबियों को काश्मीर पर आक्रमण के लिये भर्ती कर रहे थे। सीमा प्रान्त का एक भूतपूर्व अग्रेजी गवर्नर सैर के बहाने कुछ सप्ताह पहले काश्मीर गया था। कुछ में रियासत के मुसलमान सिपाहियों को गुप्त रूप से खरीद लिया गया। पहले तो मुस्लिम लीग की तथा कथित नेशनल गार्ड के कमाण्डर खुरशीद अनवर को आक्रमण करने वालों का कमाण्डर नियुक्त किया गया। इसके बाद पाकिस्तानी सेना के मेजर जनरल अकबर खा को अपना नाम जनरल तारक रख कर आक्रमणकारी सेना का अध्यक्ष बनाया गया।

अमरीका भी यह सब कुछ देख रहा था, उसने भी बहती गंगा में

हाथ धोने का निश्चय किया। अमरीका की सेना के एक अफसर सार-जैन्ट रस्सल ने जो एक ठेकेदार के वेष में कई वर्षों से पिशावर और काबुल के चक्कर काट कर अमरीका के लिये गुप्तचर भर्ती कर रहा था, वेष बदलकर अपना नाम ब्रिगेडियर सलीम खा रख लिया और पठानों जैसे वस्त्र पहन कर आक्रमणकारियों में सम्मिलित हो गया। उसने काश्मीर में कोटली और भिम्बर के स्थानों पर हमला किया। गिलगित में सैनिक गवर्नर कर्नल ब्राउन ने महाराजा के नियुक्त किये हुए राज्यपाल ब्रिगेडियर घसारासिंह को गिरफ्तार कर प्रान्त का शासन प्रबन्ध पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले कर दिया। यहाँ से पाकिस्तानी सेना ने लद्दाख के प्रान्त पर हमला कर दिया।

पाकिस्तानी आक्रमणकारी बढ़ते हुए लूट-भार करने लगे। इस समय महाराजा ने भारत सरकार से सहायता के लिये प्रार्थना की। भारत सरकार के सुझाव पर महाराजा ने शेख को रिहा कर दिया। शेख को प्रदेश का प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया। काश्मीर ने भारत में अपने आप को सम्मिलित कर लिया। भारतीय सेना ने काश्मीर में प्रवेश कर के आक्रमणकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया।

लार्ड माउंट बैटन इस समय भी भारत के गवर्नर जनरल थे। उनके दबाव पर घोषणा की गई कि युद्ध के अन्त में भारत में काश्मीर के विलय की घोषणा की तत्सदीक कराने के लिये जनता को अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जायेगा।

आक्रमणकारियों की पग-पग पर हार हो रही थी। पाकिस्तान सरकार अब भी कह रही थी कि उसकी सेना ने आक्रमण नहीं किया। बल्कि पठान काश्मीर के मुसलमानों की सहायता के लिये लड़ रहे हैं। आक्रमणकारियों को भागते देख कर फिर अंग्रेज अधिकारियों और पाकिस्तानी शासकों ने आपस में साजबाज की। इस के अनुसार भारत सरकार को बताया गया कि मि० जिन्नाह ने अपने अंग्रेज सेनाध्यक्ष को

काश्मीर पर बाकायदा हमला करने का आदेश दिया है परन्तु सेनाध्यक्ष ने इन्कार कर दिया है इसलिये श्री नेहरू मि० जिन्नाह से समझौता की बातचीत करे। श्री नेहरू ने इसका उत्तर गवर्नर जनरल को यह दिया कि पाकिस्तानी-पंजाब के जिन अड्डों से पाकिस्तानी सेना हमले कर रही है भारतीय सेना उन पर जवाबी हमला करेगी। परन्तु नेहरू पर इतना दबाव डाला गया कि काश्मीर का भगडा सयुक्त राष्ट्रीय सस्था मे रखा गया।

बाद की घटनाओं से यह बात सिद्ध हो जाती है कि अग्नेज की इस चाल का अभिप्राय यह था कि काश्मीर के जिस भाग पर पाकिस्तानी सेना ने अधिकार कर लिया है वह पाकिस्तान के अधिकार मे ही रहे और यह भगडा इतना लम्बा किया जाये कि पाकिस्तान को एक और आक्रमण करने की तैयारिया करने का अवसर मिल जाये। परन्तु पाकिस्तानी सेना का काश्मीर पर अधिकार करने मे विफल हो जाना पाकिस्तानी शासको के लिये बड़ी परेशानी का कारण बना। जिन लोगो के सम्बन्धी इस आक्रमण मे मारे गये थे उन्होने क्रोध मे आकर शासको के विरुद्ध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी सेना मे भी असन्तोष फैलने लगा।

पठानो ने अपने अधिकारो की माग की तो उनके नेताओ को गिरफ्तार कर लिया गया। पिशावर मे चारसदा के स्थान पर पुलिस ने हजारो पठान मदों, स्त्रियो और बच्चो पर जो नमाज पढने के लिये एकत्रित हुए थे मशीन गनो और बन्दूको से हमला कर दिया। कम-से-कम तीन हजार पठानो को गोलियो से भून दिया गया।

बिलोचिस्तान मे कल्लात की रियासत के शासक ने पाकिस्तान मे सम्मिलित होने से इन्कार कर दिया। मि० जिन्नाह के आदेश से मेजर जनरल अकबर खा ने कल्लात पर हमला कर रियासत को जबरदस्ती पाकिस्तान मे सम्मिलित कर लिया।

बहावलपुर के शासक ने भी पाकिस्तान से अलग रहने की इच्छा प्रकट की थी परन्तु बहावलपुर पर हमला करने की धमकी दी गई। नवाब बहावलपुर को भयभीत होकर झुकना पडा।

प्रश्न उठता है कि क्या ऐसी धाधलियों से पाकिस्तान की घरेलू समस्याओं का समाधान हो गया? मि० जिन्नाह तो इस बात से परेशान हो रहे थे कि यद्यपि वह श्रीनगर में एक विजयी शासक की हैसियत से प्रवेश करने के लिये स्वप्नों के महल बना रहे थे परन्तु उन्हें विफल होना पडा। वह अब नये हमले के लिये तैयारियां कर रहे थे परन्तु पाकिस्तान की जनता माग कर रही थी कि उनकी रोटी और कपड़े की समस्या का समाधान किया जाये। लोग यह भी माग कर रहे थे कि उन्हें पाकिस्तान की स्थापना के लिये कुर्बानियां करने का आदेश देते हुए उनसे जो वायदे किये गये थे अब उन्हें पूरा किया जाये।

लाहौर, गुजरो-वाला और कराची में भूखे-नगे मुसलमान शरणार्थी रोटी, कपडा और मकान के लिये प्रदर्शन कर रहे थे। लाहौर में जब मि० जिन्नाह एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिये गये तो इन लोगों ने “जिन्नाह मुर्दाबाद” के नारे लगाये। कराची में प्रधान मंत्री लियाकत अली का घेराव किया गया। पुलिस ने दोनों स्थानों पर जनता पर गोली चलाई। कितने ही व्यक्ति मारे गये।

जिन्नाह की रहस्यमयी मृत्यु और लियाकत अली की हत्या

पाकिस्तान की स्थापना होते ही पाकिस्तानी नेताओं ने एक-दूसरे के विरुद्ध साजबाज शुरू कर दी थी। मि० जिन्नाह को तपेदिक और कैसर की बीमारी ने घेर लिया था। उनकी सेहत तेजी से बिगड़ रही थी। उत्तर प्रदेश से चौधुरी खलीकुज्जमान अग्रेज के इशारे पर कराची पहुँच गये। मि० जिन्नाह उनसे प्रसन्न नहीं थे। वह चाहते थे कि चौधुरी साहिब भारत में साजबाज के लिये ठहरे रहे। परन्तु चौधुरी साहिब तो पाकिस्तान के जन्मदाता मि० जिन्नाह की मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए स्वयं पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनने के स्वप्न देख रहे थे। शायद अग्रेज सलाहकारों के कहने पर मि० जिन्नाह को झुकना पड़ा और चौधुरी साहिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रधान नियुक्त कर दिये गये। चौधुरी साहिब ने सीमा प्रान्त में मुख्यमंत्री मि० अब्दुलकयूम से गठजोड़ कर लिया। पंजाब में उन्होंने मुख्यमंत्री नवाब ममदोट से सौदेबाजी कर ली। पूर्वी बंगाल में वह एक गुट से सौदेबाजी कर रहे थे। कराची में उन्होंने दिल्ली और उत्तर प्रदेश से आये हुए मुसलमानों में अपना एक मजबूत गुट बना लिया।

प्रधान मंत्री चौधुरी साहिब की इन गतिविधियों से परेशान थे। उन्होंने अपने गुट को मजबूत करना शुरू कर दिया। सीमा प्रान्त में उन्होंने कयूम के विरुद्ध खा यूसुफ खटक, खा गुलाम मुहम्मद, मुल्ला मानकी

आदि का गुट्ट सगठित किया। पंजाब में उन्होंने नवाब दौलताना को अपने साथ मिलाया और पूर्वी बंगाल में मि० सोहरावर्दी खा के मुकाबले में मुख्यमंत्री सर नाजिमुद्दीन से गठजोड़ किया।

मि० जिन्नाह इन घटनाओं से परेशान थे। उनकी बीमारी बढ़ती गई। मि० लियाकत अली खा अपने हाथ मजबूत करने में लगे हुए थे। मि० जिन्नाह की बीमारी की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। मि० जिन्नाह की बहन मिस फातमा लियाकत अली के विरुद्ध थी। उन्हें लियाकत अली पर इतना भी विश्वास नहीं था कि अपने भाई की चिकित्सा के लिये सरकारी डाक्टर की सेवाये प्राप्त करे। उन्होंने जब मि० जिन्नाह के लिये एक प्रसिद्ध डाक्टर बुलाया और लियाकत अली को मालूम हुआ कि मि० जिन्नाह की हालत खतरनाक है तो वह भागे-भागें ज्यारत के पहाड़ी स्थान में मि० जिन्नाह की कोठी में पहुँचे परन्तु डाक्टर ने मि० जिन्नाह की इच्छा अनुसार बीमारी का व्योरा लियाकत अली को देने से इन्कार कर दिया। जब कुछ देर बाद लियाकत अली जिन्नाह से मिले तो जिन्नाह ने लियाकत अली को बुरी तरह से फटकारा। मि० जिन्नाह पहले ही बीमार थे। इस गर्म-गुप्तारी से वह मूर्छित हो गये। लियाकत अली उन्हें इसी अवस्था में छोड़ कर कराची चले गये।

लियाकत अली को अब इस बात की आशंका थी कि मि० जिन्नाह अपनी बहन को अपने बाद गवर्नर जनरल और खलीकुज्जम्मान को प्रधान मंत्री बनाना चाहते हैं। इसलिये वह अपनी गद्दी सुरक्षित करने के लिये सेना के कुछ उच्च अधिकारियों से साजबाज करने लग गये। दूसरी ओर कुछ और सैनिक अधिकारी उनका तख्ता उलट देने के लिये तैयारियाँ करने लगे। १४ अगस्त १९४८ को मि० जिन्नाह ने अपने डाक्टर मि० वक्श को कहा

“मे जीवित रहना चाहता था। परन्तु अब यह बात कोई महत्त्व

नहीं रखती कि मैं जीवित रहूँ अथवा मर जाऊँ।”

डाक्टर बक्श ने मि० जिन्नाह की आखों में आँसू देखे। उसका कहना है कि मि० जिन्नाह को कोई आघात पहुँचा था जिससे वह मायूस हो गये थे।

इस आघात का कारण लियाकत अली की साज़्जाज थी। मि० जिन्नाह ने कहा “मैं समय आने पर जनता को अपनी बीमारी की सूचना दूँगा।”

वह समय आ गया। मि० लियाकत अली मि० जिन्नाह से सर्वथा लापरवाह हो गये थे। २१ सितम्बर १९४८ को मि० जिन्नाह ने कराची जाने की इच्छा प्रकट की। इसकी सूचना कराची पहुँचा दी गई थी परन्तु जब मि० जिन्नाह का विमान उसी दिन सवा चार बजे शाम मौरीपुर (कराची) के हवाई अड्डे पर पहुँचा तो उनका स्वागत करने के लिये न तो लियाकत अली, न ही कोई दूसरा मंत्री अथवा अधिकारी हवाई अड्डे पर पहुँचा। मि० जिन्नाह को स्ट्रेचर समेत सेना की एक एम्बुलैस गाड़ी में रखा गया। यह गाड़ी राजभवन को जाने वाले मार्ग पर ही खराब हो गई। एक घण्टे तक चालक मरम्मत करने की कोशिश करना रहा परन्तु उसे सफलता प्राप्त न हुई। कराची शहर से एक और गाड़ी लाने के लिये चालक गया।

मि० जिन्नाह की नर्स सिस्टर डनहम ने इस घटना का वर्णन करते हुए बताया कि

“हमारी खराब गाड़ी शरणार्थियों की एक बस्ती के निकट खड़ी थी। उसके निकट कूड़े-करकट का ढेर था जिस पर सैकड़ों मक्खियाँ भिनभिना रही थी। यह मक्खियाँ मि० जिन्नाह को परेशान कर रही थी। मैंने गत्ते का एक टुकड़ा उठाया और मक्खियों को हटाने के लिये उससे पखा करने लगी। कुछ पल के लिये केवल मैं ही उनके पास थी। मि० जिन्नाह ने कृतज्ञता प्रकट करने के लिये अपना

कमजोर हाथ मेरे हाथ पर रख कर मेरी ओर जिस दृष्टि से देखा, मैं उसे कभी भूल नहीं सकती। मि० जिन्नाह बोल नहीं सकते थे। परन्तु उनकी आखों में आसू थे। इस समय उनकी आत्मा उनकी आखों में थी। कुछ दूर शरणार्थी बच्चे खेल रहे थे। कई लोग निकट से होकर गुजर जाते। उन्हें क्या मालूम था कि पाकिस्तान का जन्मदाता सड़क के किनारे एक टूटी गाड़ी में जीवन की अन्तिम स्वास ले रहा था।”

६ बज कर १० मिनट पर दूसरी गाड़ी आई। मि० जिन्नाह को स्ट्रेचर पर डाल कर राजभवन में उनके कमरे में लाया गया। डाक्टरों ने उन्हें बचाने के लिये टीका लगाया परन्तु मि० जिन्नाह के मुह से भाग बहने लगे।

उसी रात लगभग दस बजे मि० जिन्नाह के प्राण-पखेरू उड़ गये। मि० लियाकत अली और उनके मन्त्रिमण्डल के अन्य सदस्य उस समय वहाँ उपस्थित नहीं थे। प्रश्न उठता है कि वे कहाँ थे। भारत सरकार के उस समय के राजदूत श्री श्रीप्रकाश का कहना है कि उस शाम लियाकत अली फ्रांस के दूतावास में शराब की एक पार्टी में उपस्थित थे। यह एक विचित्र बात है कि पाकिस्तान का जन्मदाता दम तोड़ रहा था और उसका प्रधान मंत्री शराब के जाम उड़ा रहा था।

कई दिन बाद मि० लियाकत अली ने भारत के राजदूत को बताया शराब की पार्टी के समय मुझे मालूम नहीं था कि मि० जिन्नाह कराची में आये हुए हैं और उनकी अवस्था इतनी गम्भीर है।

लियाकत अली के इस उत्तर से किसी को भी तसल्ली नहीं होगी। २१ सितम्बर को दिल्ली में मि० जिन्नाह की कराची में अन्तिम यात्रा की सूचना पहुँच चुकी थी। यही नहीं बल्कि यह सूचना भी मिल गई थी कि लाहौर और दूसरे बड़े शहरों में पुलिस गश्त कर रही है।

वास्तव में मि० लियाकत अली को सब कुछ मालूम था परन्तु वह

मि० जिन्नाह से अन्तिम भेट करने का साहस नहीं रखते थे। उन्हें इस बात की आशंका थी कि मि० जिन्नाह अपने उत्तराधिकारी का फैसला सुना देगे। इसलिए मि० लियाकत अली दूर रह कर अपनी गद्दी को सुरक्षित करने के लिए साजब्राज करने में लगे रहे।

भारतीय राजदूत को रात के बारह बजे पाकिस्तान के एक उच्च अधिकारी ने टेलीफोन पर मि० जिन्नाह की मृत्यु की सूचना दी। इस अधिकारी ने मत्क के लिए बड़े अनुचित और असभ्य शब्दों का प्रयोग किया। इसी अधिकारी ने शाम की पार्टी में भारतीय राजदूत को बताया था कि मि० जिन्नाह स्वस्थ है। उसने अब राजदूत को बताया कि

“पार्टी में शराब पीने के बाद हम डिनर के लिए गए। आधी रात को मुझे मृत्यु की सूचना मिली। मि० जिन्नाह के उत्तराधिकारी के नाम का फैसला होने के बाद मैं अभी-अभी रोजभवन को आया हूँ। हमारे नए गवर्नर जनरल सर नाजिमुद्दीन इस समय दिल्ली में हैं। मैं चाहता हूँ कि उन्हें यहाँ तक लाने के लिए तुरन्त एक विशेष विमान के लिए परमिट दिया जाए।”

इसका अर्थ यह था कि मि० लियाकत अली का षड्यन्त्र सफल हो गया था। मिस फातमा जिन्नाह को गवर्नर जनरल और चौधुरी खलीकुज्जमान को प्रधान मंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान के जन्मदाता की योजना विफल बना दी गयी थी। मि० जिन्नाह की मृत्यु का समाचार रेडियो पाकिस्तान से प्रसार करने से पहले ही लियाकत अली ने मि० जिन्नाह के विशेष अधिकारियों को बदल दिया था।

मिस फातमा जिन्नाह नाराज हो गई थी। लियाकत अली ने उनकी गतिविधियों की निगरानी का आदेश दे दिया। उनकी डाक सैसर होने लगी। उनका टेलीफोन टैप किया जाने लगा। फातमा ने बदला लेने के लिए बगल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मि० शहीद सोहरावर्दी से गठ-जोड़ कर लिया। इसके परिणामस्वरूप पहले तो जिन्नाह मुस्लिम लीग

बनी और इसके बाद इसे आवासी लीग का नाम दिया गया ।

१२ सितम्बर १९५१ को कराची के समाचार पत्र "इवनिंग न्यूज" ने लिखा कि

"मिस फातमा जिन्नाह ने अपने भाई की पहली वर्सी पर रेडियो पाकिस्तान से प्रसारित करने के लिए जो सन्देश रिकार्ड कराया था उसमें उन्होंने लियाकत अली की सरकार की कड़ी आलोचना की थी परन्तु रेडियो से जो सन्देश प्रसारित किया गया उसमें से ये शब्द काट दिए गए ।"

पाकिस्तान के लगभग सभी समाचार पत्रों ने इस हरकत के लिए लियाकत अली को दोषी ठहराया । विरोधी दलों के नेताओं ने उनकी निन्दा की ।

बहुत कम लोग जानते हैं कि मि० जिन्नाह पाकिस्तान के भविष्य के विधान पर भी लियाकत अली की विचारधारा से सहमत नहीं थे । उन्होंने पार्लियामेंट के पहले अधिवेशन में सभी सम्प्रदाय के लोगों को समान अधिकार देने का वचन दिया था । भारत से लीग के जो नेता उनसे मिलने के लिए कराची पहुँचे थे उन्हें मि० जिन्नाह ने कहा था कि मैं कुछ देर पाकिस्तान में रह कर भारत लौट जाऊँगा ।

मि० जिन्नाह की रहस्यमयी मृत्यु से पहले कराची में उनके निवास स्थान पर दो बार उनकी हत्या करने की कोशिश की गई । एक बार कुछ नवयुवक जो पंजाबी मालूम होते थे दीवार फाद कर आ घुसे परन्तु जहाँ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया वहाँ सरकारी तौर पर यह समाचार दबा लिया गया । इन युवकों को शायद जेल में गोली मार दी गई । मुकदमा नहीं चलाया गया ।

मि० जिन्नाह की रक्षा के लिए राजभवन की दीवारें ऊँची कर दी गयीं । पहरा कड़ा कर दिया गया । सारी रात राजभवन के बाहर बिजली रौशन रहती । मि० जिन्नाह एक तरह से अपने राजभवन में

कैदी से बन गये थे। समस्त देश में खून-खराबा से उनके दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ा था और प्रायः रातों को उठ कर वह पागलों की तरह बड़बड़ाने लग जाते। उन्होंने पाकिस्तान की जो मांग की थी वह तो पूरी हो गई थी परन्तु इतना खून-खराबा होगा, इसकी शायद उन्हें आशाका नहीं हुई थी।

लियाकत अली ने अपने हाथ मजबूत करने के लिये पंजाब में नवाब ममदौद को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया। इसके बाद उन्होंने शरणार्थियों से चौधुरी खलीकुज्जमान के विरुद्ध आन्दोलन कराया और उन्हें मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र देने के लिये विवश करके यह पद स्वयं सम्भाल लिया।

लियाकत अली ने सीमा प्रान्त के मुख्य मंत्री मि० अब्दुल कयूम पर भी त्यागपत्र के लिये दबाव डाला परन्तु उन्होंने इन्कार कर दिया। मि० लियाकत अली स्वयं पिशावर पहुँचे। मुख्यमंत्री ने एक सार्वजनिक सभा में प्रधान मंत्री को धमकी दी। प्रधान मंत्री मायूस होकर लौट आये। मुस्लिम लीग के चुनाव में सीमा प्रान्त से लियाकत अली का कोई भी व्यक्ति सफल न हुआ। कयूम खा लियाकत अली के विरोध पर भी प्रान्तीय लीग के प्रधान बना लिये गये।

लियाकत अली ने सिंध के मुख्य मंत्री श्री अयूब खुर्रो को डिसमिस कर दिया। अयूब के विरुद्ध आरोपों की जाच के लिये एक आयोग भी नियुक्त किया परन्तु लियाकत अली अपने इस विरोधी का राजनैतिक जीवन खत्म न कर सके।

लियाकत अली तीन वर्ष तक दौड़धूप करने पर भी पाकिस्तान के लिये विधान तैयार न करा सके। नेशनल असैम्बली की एक समिति ने विधान का जो खाका तैयार किया था उसे पंजाब और बंगाल दोनों ने रद्द कर दिया। पंजाबी नेता पूर्वी बंगाल को उसकी आबादी के अनुसार पार्लियामेंट में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार देने के लिये

तैयार नहीं थे। लियाकत अली ने मि० जिन्नाह के रास्ते पर चलते हुए बंगालियों को साफ-साफ कह दिया था कि बंगाली भाषा को किसी भी हालत में सरकारी भाषा का दर्जा नहीं दिया जायेगा। जब एक बंगाली सदस्य ने केन्द्रीय विधान सभा में सरकारी भाषा का प्रश्न उठाया तो लियाकत अली ने उसे धमकाते हुए कहा —“पाकिस्तान मुसलमानों का देश है। इसलिये केवल उर्दू ही पाकिस्तान की भाषा हो सकती है।” पूर्वी बंगाल में इसके विरुद्ध विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। उन पर गोलिया चलाई गईं। पूर्वी बंगाल में पुलिस के कर्मचारी बेतन बढ़ाने की माग कर रहे थे। उनके आन्दोलन ने विद्रोह का रूप धारण कर लिया। उस समय जनरल अयूब खान पूर्वी बंगाल में पाकिस्तानी सेना के कमाण्डर थे। उनके आदेश से सेना ने पुलिस पर हमला किया। कितने ही बंगाली सिपाही मारे गये। इन घटनाओं से बंगाली जनता उत्तेजित हो गई।

लियाकत अली हर जगह फेल हो रहे थे। लाहौर और कराची के बाजारों में उनके विरुद्ध जलूस निकल रहे थे। जनता की कोई भी समस्या हल नहीं हो रही थी। उनके विरोधी मजबूत हो रहे थे। श्री हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने मिस जिन्नाह, नवाब ममदोट, मिया इफतखार उद्दीन, मौलाना भाषानी और जी एम सैय्यद से मिल कर जो अवामी मुस्लिम लीग स्थापित की थी, उसका जगह-जगह स्वागत किया जा रहा था। जब लियाकत अली ने श्री सोहरावर्दी के लिये “गद्दार” शब्द का प्रयोग किया और फतवा दिया कि मुस्लिम लीग के मुकाबले में कोई सस्था स्थापित करना इस्लाम से गद्दारी करना है तो विरोधियों ने पूछा कि खुले मुँह फिरने वाली और काफ़रों से हाथ मिलाने वाली बेगम लियाकत अली क्यों कर अपने आप को मुसलमान कह सकती है ?

लियाकत अली के विरोधी चौधरी खलीकुज्जमान लन्दन गये। उन्होंने अपने पुराने अंग्रेज मित्रों से परामर्श कर के सभी इस्लामी देशों का ब्लाक कायम करने की योजना की घोषणा की। उन्होंने कराची

मे एक अन्तर्राष्ट्रीय इस्लामी सम्मेलन की आयोजना की। वास्तव मे यह अग्रेज की चाल थी। लियाकत अली इससे भी परेशान हो रहे थे। उन्होने इसके मुकाबले मे अमरीका से गठजोड करने का फैसला किया।

इन्ही दिनों पठानिस्तान आन्दोलन तीव्र हो रहा था। लियाकत अली अमरीका से साजबज कर रहे थे। अफगानिस्तान और रूस को इस से चिन्ता हुई। दोनों ने पठानों की आकांक्षाओं का समर्थन किया। अफगानिस्तान की सरकार ने माग की कि अग्रेजों ने उसके जो इलाके छीन लिये थे वे अफगानिस्तान को लौटा दिये जायें और खैबर से सिंधु नदी तक के पठानों के इलाके की जनता को अपने भविष्य का फैसला करने के लिये आत्म-निर्णय का अधिकार दिया जायें। अफगानिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सभा में भी यह प्रश्न उठाया। पाकिस्तान सरकार ने इसके उत्तर में अफगानिस्तान की सीमाओं पर सेनाएं एकत्रित कर दी। कई स्थानों पर दोनों देशों की सेनाओं में झड़पें भी हुईं और पाकिस्तानी विमानों ने कबायली इलाके पर बमबर्षा की। इस से तनाव बढ़ता गया। पाकिस्तान सरकार ने किराये के कुछ व्यक्तियों को लेकर पिशावर में “आजाद अफगान सरकार” का ढोंग खड़ा कर दिया। इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वह अफगानिस्तान को आजाद करायेंगे।

जनता में असंतोष की बढ़ती हुई लहर से परेशान होकर लियाकत अली ने बावेला मचाना शुरू कर दिया कि भारत पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहता है। स्थान-स्थान पर भड़कीले भाषण देते हुए उन्होंने समस्त काश्मीर पर अधिकार करने के लिये लोगों को नई लड़ाई करने के लिये तैयार रहने के आदेश देना शुरू कर दिये।

लियाकत अली अमरीका गये। जहाँ उन्होंने अपने भाषणों में कहा कि पाकिस्तान समस्त एशिया में “स्वतंत्रता की रक्षा के लिए” अमरीका का साथी बनने के लिये तैयार है। उन्होंने कहा कि अमरीका पाकिस्तान

की मित्रता पर विश्वास कर सकता है। उन्होंने भारत के विरुद्ध भी भाषण और वक्तव्य दिये। अमरीका से लौटने से पहले लियाकत अली अमरीका को अपने देश में सैनिक अड्डे देने के लिये गुप्त रूप से वचन दे आये थे। इसके बदले लियाकत अली अमरीका से सैनिक सामग्री प्राप्त करना चाहते थे।

अमरीका और ब्रिटेन दोनों पश्चिमी एशिया में अपने तेल भण्डारों को सुरक्षित रखने और इन देशों में स्वतंत्रता की भावनाओं को कुचल देने के लिये इस्लाम के नाम पर एक ब्लाक की स्थापना करने के लिये दौड़-धूप कर रहे थे। रूस और चीन की बढ़ती हुई ताकत से भी उन्हें परेशानी थी। इस्लाम की रक्षा के नाम पर वे इन दोनों देशों के मुकाबले में एक सैनिक गठजोड़ करने के लिये इस्लामी देशों पर डोरे डाल रहे थे। भारत ने पश्चिम की ताकतों को सैनिक अड्डे देने से इन्कार कर दिया था। भारत की आर्थिक प्रगति से भी ये ताकते परेशान थीं। लियाकत अली अपनी गद्दी बचाने के लिये भारत से भगड़ा करना आवश्यक समझते थे और वह यह भी समझ रहे थे कि अमरीका की सहायता से वह समस्त काश्मीर पर अधिकार कर लेंगे। इसलिये वह अमरीका से सैनिक गठजोड़ करने के लिये तैयार हो गये।

सेना में अपने हाथ मजबूत करने के लिये उन्होंने अयूब खा को सेनापति के पद पर नियुक्त कर दिया और कई दूसरे जूनियर अधिकारियों को भी इसी तरह तरक्की दे दी। इससे कई दूसरे सैनिक अधिकारी उनसे बिगड़ गये। सेना के युवक अफसर इसलिये भी नाराज थे कि लियाकत अली अपने हित के लिये देश की स्वतंत्रता को विदेशियों के पास गिरवी रख रहे थे। यह अफसर प्रगतिशील विचारधाराओं पर विश्वास रखते थे। उन्होंने पाकिस्तान की स्थापना के लिये गुप्त रूप से मि० जिन्नाह की सहायता की थी। इसलिये जब उन्होंने देखा कि लियाकत अली देश को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं तो उनमें असंतोष फैलने लगा। इस बात के

प्रमाण मिलते हैं कि मि० लियाकत अली के कुछ विरोधी नेताओं से सम्पर्क स्थापित कर लिया गया था। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि एक और सीमा प्रान्त के मुख्य मंत्री अब्दुलकयूम ने लियाकत का तख्ता उलटने के लिये सेना और पुलिस के कुछ उच्च अधिकारियों से साज-बाज शुरू कर दी थी और दूसरी ओर साम्यवादी दल के नेताओं से पंजाब के कुछ सैनिक अधिकारियों ने परामर्श शुरू कर दिया था। साम्यवादी नेताओं से इन अफसरों ने अपनी योजना के सम्बन्ध में बातचीत की थी। साम्यवादी नेताओं का कहना है कि उन्होंने इन अफसरों को परामर्श दिया था कि वह यह कदम न उठाये परन्तु बाद की घटनाओं से मालूम होता है कि ये अफसर लियाकत अली का तख्ता उलट देने के लिये तैयारियाँ करते रहे।

लियाकत अली ने अमरीका से लौटते ही इस्लामी देशों के तथाकथित प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सम्मेलन में शामिल होने वाले अधिकतर नेता अग्नेजों के विरोधी परन्तु अमरीका के मित्र थे। उदाहरणतया ईरान के मुल्ला काशानी और फलस्तीन के मुफती आजम। मुल्ला काशानी ईरान में तेल की अग्नेजी कम्पनी के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे थे। उनके एजेण्टों ने दो मंत्रियों की हत्या कर दी थी। मुल्ला काशानी अमरीका से मिले हुए थे। इसका प्रमाण यह है यद्यपि इस आन्दोलन को देशभक्तों ने शुरू किया था परन्तु शाह ईरान के तेल के सलाहकार अमरीका की तेल कम्पनी के एक डायरेक्टर थे। अमरीका अग्नेजों की 'मनापली' खतम कर स्वयं ईरान के तेल पर कंट्रोल करना चाहता था।

इस सम्मेलन के दो और भी लक्ष्य थे। पहला यह कि चौधरी खलीकुजमान अग्नेज के पिटठू की हैसियत से "इस्लामी ब्लाक" स्थापित करने के लिए जो कुछ कर रहे थे उसे विफल करके लियाकत अली का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को अमरीका के कंट्रोल में लाया जाये।

और “जेहाद” के नारे लगा कर भारत को भयभीत और कमजोर किया जाये ।

इस सम्मेलन में इस्लामी देशों के तथाकथित नेताओं ने पाकिस्तान को भारत से युद्ध के लिये सहायता देने की घोषणा की । भारत को धमकिया दी गई कि पाकिस्तान इस्लामी देशों की सैनिक सहायता से काश्मीर पर अधिकार करके ही दम लेगा । सम्मेलन में “लियाकत अली जिन्दाबाद” के नारे लगाये गये । कराची, रावलपिण्डी और लाहौर में कई ऐसी सस्थाएँ स्थापित की गईं जिन्होंने काश्मीर के लिये भारत पर हमला करने के लिये “मुजाहिदों” की भरती की घोषणा की । सीमा प्रान्त में जगह-जगह जलसे करके दावे किये गये कि लाखों पठान काश्मीर पर हमला करने के लिये तैयार हैं । लाहौर में एक पत्रकार ने गप्प हाकी कि वह ५० हजार “मुजाहिद” भरती करके भारत पर आक्रमण करेगा । कराची में एक पत्रकार ने घोषणा की कि समस्त भारत को “स्वतंत्र” कराने के लिये उसने एक सैनिक सस्था स्थापित की है । यह सभी हरकतें लियाकत अली को हीरो बनाने के लिये की जा रही थी ।

इस गर्मा-गर्मी में अचानक कराची से सरकारी तौर पर घोषणा की गई कि मि० लियाकत अली की सरकार का तख्ता उलटने और एक “सैनिक तानाशाही” कायम करने के लिये मेजर जनरल अकबर खा के नेतृत्व में एक सैनिक गुट्ट ने षडयंत्र किया है और एक साथ छापे मार कर इस गुट्ट के सभी अफसरों और उनके समर्थक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है । जो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये उनके नाम यह हैं :

- (१) मेजर जनरल अकबर खा
- (२) पाकिस्तान वायु सेना के उपाध्यक्ष एयर कमांडर एम० के० जजुआ
- (३) ब्रिगेडियर सादिक हस्सन कमाण्डर बन्नू ब्रिगेड

- (४) लेफ्टीनैन्ट कर्नल जियाउद्दीन आफ “आजाद काश्मीर”
हैडक्वार्टर्ज। कर्नल जिया उद्दीन वास्तव मे पाकिस्तानी
सेना के सीनियर अफसर थे परन्तु काश्मीर पर आक्रमण
के लिये उन्हे आक्रमणकारियो की सहायता के लिये भेजा
गया था।
- (५) लेफ्टीनैन्ट कर्नल सिद्दीकी राजा आफ आर्मी हैडक्वार्टर्ज
- (६) मेजर इसहाक मुहम्मद आफ कल्लात फोरसिज
- (७) मेजर जनरल नजीर अहमद
- (८) मेजर खान मुहम्मद आफ खैबर राइफलज
- (९) मेजर मुहम्मद यूसफ आफ जनरल हैडक्वार्टर्ज
- (१०) कैप्टन जफरुल्ला पोशी आफ १६ पंजाब रेजीमेन्ट
- (११) कैप्टन खिजर हयात ऑफ पंजाब रेजीमेन्ट
- (१२) मेजर मिस खा, आफीसर कमांडिंग महिला नैशनल गार्ड
- (१३) श्री फ़ैज अहमद फ़ैज सम्पादक “पाकिस्तान टाइम्ज”
लाहौर
- (१४) कर्नल गुलज्जार अहमद

मेजर जनरल अकबर खा पंजाब मुस्लिम लीग की प्रमुख नेता बेगम
शाह नवाज के दामाद थे। उनकी पत्नी कई वर्ष पहले पंजाब में कांग्रेस
मे काम करती रही थी। मेजर जनरल अकबर खा ने काश्मीर पर हमला
करने वालो की कमान की थी और वह मि० जिन्नाह के बहुत निकट
और उनके विश्वास-पात्र थे। फ़ैज अहमद फ़ैज देश के विभाजन से पहले
आकाशवाणी मे काम किया करते थे। कर्नल गुलज्जार अहमद मि०
जिन्नाह के बहुत निकट थे। देश के विभाजन से पहले उन्होने मि०
जिन्नाह के सामने श्री नेहरू और दूसरे कांग्रेसी नेताओ की हत्या की योजना
रखी थी और विश्वास प्रकट किया था कि ऐसा करके केन्द्रीय सरकार
पर अधिकार किया जा सकता है।

गिरफ्तारियों की घोषणा करते हुए मि० लियाकत अली ने आरोप लगाया कि ये अभियुक्त उनकी सरकार का तख्ता उलट कर सैनिक तानाशाही स्थापित करना चाहते थे। लन्दन के समाचार पत्र “टाइम्स” ने लिखा कि इस षड्यंत्र के नेताओं ने सरकार का तख्ता उलट कर केन्द्र और प्रान्तों में सैनिक सरकार स्थापित करने का फैसला किया था। उन्होंने यह भी योजना बनाई थी कि प्रधान सेनापति (जनरल अयूब खा) और सरकार के मंत्रियों और राज्यपालों को गिरफ्तार कर लिया जाये और जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिये कराची में प्रदर्शन कराये जाये। उन्होंने यह भी फैसला किया था कि एक ऐसी विदेशी ताकत से सैनिक गठजोड़ किया जाये जो एंग्लो-अमरीकन ब्लाक के विरुद्ध हो।

मतलब यह कि यह लोग रूस से गठजोड़ करना चाहते थे। इसका कारण यह था कि पाकिस्तान के शासक कभी ब्रिटेन और कभी अमरीका के पास पाकिस्तान की स्वतन्त्रता को इस्लाम के नाम पर बेच कर जनता को धोखा देना चाहते थे। इसलिये सैनिक अधिकारियों ने उनका तख्ता उलट देने का फैसला किया।

असली योजना यह थी कि गवर्नर जनरल सर नाजिमुद्दीन को उनकी स्पेशल ट्रेन से पकड़ लिया जाये। उनसे लियाकत अली और उनकी सरकार को डिसमिस कराया जाये और मेजर जनरल अकबर खा इसके बाद गवर्नर जनरल को गिरफ्तार करके अपनी सरकार की स्थापना की घोषणा कर दे।

साम्यवादियों का कहना है कि उनसे इस योजना के सम्बन्ध में अवश्य ही बात-चीत हुई थी परन्तु पार्टी ने इसे पसन्द नहीं किया, इस पर इसे कैसल कर दिया गया। परन्तु एक सैनिक अधिकारी की गैपबाजी से भेद खुल गया और जनरल अयूब खा ने अपनी पोजीशन बनाने के लिए अपने विरोधियों को गिरफ्तार करा दिया। कहना मुश्किल है कि

इन सब बातों में कहा तक सच्चाई है परन्तु यह ठीक है कि लियाकत अली को इस से अपने विरोधियों को गिरफ्तार करने का अवसर मिल गया। उन्होंने एक सैनिक अदालत को इन व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने का आदेश दिया। इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात यह है कि इस केस में श्री हुस्सैन शहीद सोहरावर्दी ने मेजर जनरल अकबर खा और उनके साथियों की वकालत की। अदालत ने किसी को फासी की सजा का आदेश नहीं दिया बल्कि उन्हें लम्बी कैद की सजा दी गई।

इस केस से फायदा उठाने वाले दो व्यक्ति थे। रक्षा-विभाग के एक सैक्रेट्री मेजर जनरल इस्कन्दर मिर्जा, जिन्होंने सेना में अपना गुट बनाना शुरू किया और दूसरे स्वयं लियाकत अली जिन्होंने “पाकिस्तान खतरे में” के नारे लगा कर पाकिस्तान को अमरीका के सैनिक ब्लाक में सम्मिलित करने के लिए अपनी गतिविधियां तेज कर दी। जनता को भ्रम बनाने के लिए उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान पर भारत, अफगानिस्तान और रूस के आक्रमण का खतरा है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना को भारत की सीमाओं पर एकत्रित होने का आदेश दे दिया। लियाकत अली यह भी समझ रहे थे कि वह अमरीका को काश्मीर के मामले में भारत पर दबाव डालने के लिए तैयार कर लेंगे।

भारत सरकार ने तुरन्त कार्यवाही की। भारत की सेनायें पश्चिम में पंजाब और काश्मीर की सीमा पर पहुंच गईं। बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री नेहरू ने फ़ैसला कर लिया था कि यदि जरा भी गड़बड़ हो तो भारतीय सेना पाकिस्तान में प्रवेश कर जाये जिस से पाकिस्तान की आए दिन की धमकियां देने का सिलसिला हमेशा के लिए खतम हो जाए।

कई वर्ष बाद जनरल अयूब खा ने पाकिस्तान सरकार पर अधिकार करने के बाद अपनी पुस्तक “Friends Not Master” में लिखा कि जब लियाकत अली भारत से युद्ध करने की बातें कर रहे थे तो पाकिस्तान

के पास गिनती के कुछ टैंक और पुराने विमान थे। भारत की सेना मजबूत थी। जनरल अयूब ने लियाकत अली को बताया कि युद्ध सेना करती है और पाकिस्तान के पास युद्ध करने की शक्ति नहीं है।

लियाकत अली ने युद्ध तो न किया परन्तु अपनी जनता को मूर्ख बनाने के लिए उन्होंने कराची में एक भारी प्रदर्शन का आयोजन किया। इस में उन्होंने भारत को मुक्का दिखाया। जलूस में शामिल होने वालों ने भारत के विरुद्ध नारे लगाए।

मि० लियाकत अली ने बाहवाही तो प्राप्त कर ली परन्तु उन्हें क्या पता था कि उनकी मृत्यु की घड़िया निकट आ रही हैं और हत्यारे की गोलियाँ उन्हें हमेशा के लिए खतम करने के लिये बेचैन हो रही हैं। उन्होंने समस्त देश में अपने विरोधियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया परन्तु उन व्यक्तियों को भाप न सके जो उनका खून करने के लिए खामोशी से तैयारियाँ कर रहे थे।

१६ अक्टूबर १९५१ को लियाकत अली एक विशेष विमान पर रावलपिण्डी पहुँचे जहाँ कम्पनी बाग में एक भव्य सभा का आयोजन किया गया था। प्रधान मंत्री की हैसियत से वह इस सभा में “इस्लामी ब्लाक” की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहते थे। उन्हें इस सभा में स्वागत पत्र पेश किया गया। आकाश जिन्दाबाद की ध्वनियों से गूँज उठा। लियाकत अली उठे। उन्होंने मुस्करा कर जनता की ओर देखा। कुरान शरीफ की आयत लाउडस्पीकर पर पढ़ी और भाषण शुरू करने लगे। परन्तु अभी उन्होंने “ब्रादराने मिल्लत” के शब्द ही कहे थे कि किसी ने सामने से लगातार दो फायर किये। लियाकत अली वहीं गिर पड़े। लोग भागने लगे। एक और गोली चली और लोगों ने मंच के सामने एक नवयुवक का शव लहू में लथपथ देखा। लियाकत अली को हस्पताल पहुँचाया गया परन्तु उनके प्राण-पखेरू उड़ चुके थे।

लियाकत अली का हत्यारा कौन था? क्या इस हत्या के पीछे कोई

पड़्यत्र काम कर रहा था ?

हुयारा अफगानिस्तान से भागा हुआ एक युवक सैय्यद अकबर बबरक था। उसके परिवार ने अंग्रेजों के राज्य में विद्रोह किया था। उसका बाप इस विद्रोह में मारा गया था। अकबर और उसके एक भाई को जो अफगानिस्तान से भाग आये थे अंग्रेज सरकार ने एबटाबाद में रखा था। उसे सरकार गुजारे के लिये पैशन देती थी। देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान सरकार उसे पैशन दे रही थी। उसे सरकार से आज्ञा लिये बिना बाहर जाने की मनाही थी। इतना होने पर भी वह रावल-पिण्डी आया। सदर बाजार में खाकसार होटल में अपने आपको गुप्तचर विभाग का अधिकारी जाहिर करके ठहरा। उसके साथ उसका एक बेटा भी था। होटल के रजिस्ट्रो की पडताल पुलिस करती रही। फिर भी अकबर को किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। प्रधान मंत्री के जलसों में गुप्तचर विभाग के कर्मचारी सैकड़ों की सख्या में होते हैं परन्तु अकबर को किसी ने मंच के सामने बैठने से नहीं रोका और किसी ने उसकी तलाशी भी नहीं ली। जब उसने गोली मार कर प्रधान मंत्री को ठंडा कर दिया तो उसे गिरफ्तार करने की बजाय एक पुलिस अफसर ने गोली मारकर ठण्डा कर दिया। मतलब यही हो सकता था कि यदि अकबर गिरफ्तार हो जाये तो कोई भेद न खोल दे।

अकबर का बेटा भाग कर लाहौर चला गया। अकबर की तलाशी पर उसके जेब से २ हजार के नोट और कबायली इलाके का एक नकशा मिला।

जाच हुई परन्तु क्या परिणाम निकला ? यह किसी को मालूम नहीं। कई वर्ष बाद जनता ने बाबेला मचाया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उसे असलीयत का पता लग गया है परन्तु वह जिस विमान पर रावलपिण्डी जा रहा था वह नष्ट हो गया। पुलिस अधिकारी मारा गया। कह दिया गया कि जाच के कागजात भी जल गये हैं। जनता इस

से सन्तुष्ट नहीं हुई। इस बार स्काटलैंड यार्ड के एक उच्च अधिकारी को जाच के लिये बुलाया गया। उसकी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई। इसके बिना ही अयूब खा ने कह दिया कि मुझे विश्वास हो गया है कि यह एक हत्यारे की व्यक्तिगत हरकत थी। कोई षड्यंत्र नहीं था।

जनता को ऐसी किसी भी रिपोर्ट पर विश्वास नहीं। बेगम लियाकत अली ने कई बार कहा कि एक विदेशी ताकत का उनके पति की हत्या के षड्यंत्र में हाथ था। कई प्रमुख नेता भी इस में सम्मिलित थे।

लियाकत अली के बेटे ने भी यही आरोप लगाया। अयूब खा का शासन समाप्त होने पर फिर माग की गई कि इस षड्यंत्र के बारे में निरपेक्ष रूप से जाच कराई जाये, परन्तु इस माग को दबा दिया गया।

इस सम्बन्ध में कुछ पहलू महत्वपूर्ण हैं वह यह कि

- (१) सैय्यद अकबर वर्षों अग्रेजों का जासूस और एजेंट रहा। उसे पाकिस्तान सरकार एलाउस देती थी।
- (२) अकबर सीमा प्रांत के मुख्यमंत्री अब्दुल कयूम खा का मित्र था। वह प्रायः मुख्य मंत्री की कोठी पर देखा जाता था। लियाकत अली कयूम को हटाना चाहते थे।
- (३) सरकारी तौर पर प्रतिबन्ध होने पर भी अकबर क्योकर रावलपिण्डी पहुँचा ? उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ?
- (४) रावलपिण्डी में लियाकत अली की सरकार के मंत्री श्री गुलाम मुहम्मद, चौधुरी मुहम्मद अली और मिया मुस्ताक अहमद गुर्माँनी भी कराची से आये थे। वे प्रधान मंत्री के जलसे में क्यों नहीं गये। जलसे के समय वे क्या कर रहे थे ?
- (५) अकबर को पकड़ने की बजाय गोली क्यों मार दी गई ? गोली मारने वाले अफसर को प्रमोशन क्यों दी गई जबकि जनता उसकी गिरफ्तारी की माग कर रही थी।

(६) जनता को यह क्यों नहीं बताया गया कि अकबर अग्रेजों का जासूस रहा है ?

१९६८ में बरमिंघम के पाकिस्तानी साप्ताहिक “एशिया” में रावल-पिण्डी षड्यंत्र केस के अभियुक्त एयर कमांडर ब्रिगेडियर जजुआ ने लिखा था कि लियाकत अली की हत्या में सेना और पुलिस के कुछ अधिकारियों का हाथ था। मैंने अपनी पुस्तक *Political conspiracies in Pakistan* में सभी प्रमाण प्रस्तुत कर के लिखा कि -

“लियाकत अली से अग्रेज नाराज हो गये थे क्योंकि वह पाकिस्तान को अमेरिका के पास बेचने का फैसला कर चुके थे। कयूम खा और पजाबी नेता भी उनके विरोधी बन गये थे। इसलिये इन सब ने एक षड्यंत्र रचा कर लियाकत अली को खतम करा दिया। नेताओं में कयूम खा, गुलाम मुहम्मद, मुश्ताक अहमद गुर्मांनी और चौधुरी मुहम्मद अली शामिल थे। जाच करने वाली किसी भी अदालत अथवा अधिकारी ने इन व्यक्तियों के बयान नहीं लिये हालांकि जनता इन्हें दोषी ठहरा रही थी।”

१९६८ में ही “एशिया” के सम्पादक महोदय दिल्ली में आये। उनसे नई दिल्ली के एक होटल में भेंट हुई। उन्होंने मुझ से पूछा कि क्या आप का भी ख्याल है कि गुलाम मुहम्मद आदि का इस हत्या में हाथ है। मैंने इन सब व्यक्तियों के नाम लिये। उन्होंने कहा कि उन्हें भी ऐसी ही आशंका है। जब मैंने उन्हें अपनी पुस्तक भेजी तो उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि पाकिस्तान के इन नेताओं पर झूठा आरोप लगाया गया है। इस पर एयर कमांडर जजुआ ने उन्हें लिखा कि पाकिस्तान सरकार इन आरोपों को क्यों नहीं झुठलाती। इसके लिये वह किसी निरपेक्ष अदालत से जाच क्यों नहीं कराती ?

मुझे विश्वास है कि आज के पाकिस्तानी नेताओं को भी निरपेक्ष तरीके से जाच कराने का साहस नहीं हो सकता। लियाकत अली की

हत्या के लिये यह षड्यंत्र किया गया था। लियाकत अली की हत्या से कयूम खा की गद्दी सुरक्षित हो गई। गुलाम मुहम्मद वित्तमंत्री से गवर्नर जनरल बन गये। पंजाबी अफसरों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। पाकिस्तान पर अमरीकी कंट्रोल की योजना कुछ देर के लिये ठप्प हो गई।

पंजाब के दो समाचार पत्रों “दैनिक निवाये वक्त” और साप्ताहिक “स्टार” ने जो कि लियाकत अली के विरोधी नवाब ममदौद के समर्थक थे कुछ सप्ताह बाद लिखा

“सैय्यद अकबर की दो गोलियों ने लियाकत अली को गद्दीद बना दिया। यदि वह जीवित रहते तो पाकिस्तानी जनता फतवा देती कि वह परले दर्जे के गद्दार थे।”

लियाकत अली की हत्या हो जाने से पाकिस्तान की समस्याओं का समाधान तो नहीं हुआ। देश में एकता की भावना भी पैदा नहीं हुई बल्कि एक भूतपूर्व आई० सी० एस० गुलाम मुहम्मद के गवर्नर जनरल बन जाने से नौकर शाही को पाकिस्तानियों के भविष्य से खेलने का अवसर मिल गया और देश में षड्यंत्रों का एक नया दौर शुरू हो गया।

नाज़िमुद्दीन सरकार का अन्त जनता के विरुद्ध नौकरशाही की जीत

नये प्रधान मंत्री सर नाज़िमुद्दीन अग्रेज के पुराने पिटू थे । उनका सम्बन्ध बंगाल के उस परिवार से था, जिसने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के दौर में अग्रेजों से मिलकर सुराजुद्दौला का शासन खत्म करने में भाग लिया था । अखण्ड भारत में अग्रेजों से वफादारी के लिए उन्हें “सर” की उपाधि मिली थी । नये गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद वर्षों अखण्ड भारत में अग्रेज सरकार के अफसर की हैसियत से काम करते रहे । पाकिस्तान के निर्माण में उसका कोई हाथ नहीं था ।

नाज़िमुद्दीन यह समझ रहे थे कि राजनीति से कोई सीधा सम्बन्ध न होने के कारण गवर्नर जनरल का अपना कोई गुट नहीं । इसलिए वह उनके इशारे पर चलेंगे । परन्तु वह इस बात को भूल गये कि गुलाम मुहम्मद का सम्बन्ध नौकरशाही से था और नौकरशाही राजनीतिक प्रभुत्व खत्म कर के शासन सत्ता पर स्वयं अधिकार जमाना चाहती है । नौकरशाही पर अधिकतर पंजाबी अफसर छाए हुये थे । सेना पर भी अधिकतर उन्हीं का प्रभुत्व था । इसलिये व किसी भी ऐसे विधान को पसंद नहीं कर सकते थे जिसमें आबादी के हिसाब से दूसरे प्रान्ती विशेषकर पूर्वी बंगाल के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिल जाये । जब प्रधान मंत्री ने बंगाली होने के नाते बंगालियों को सरकारी नौकरियों में उचित भाग देने की कोशिश की और ऐसा विधान

तैयार करना शुरू कर दिया जिस से केन्द्रीय सरकार में पंजाबियों की जगह बंगालियों को अधिक सख्या में आने का अवसर मिलने की आशका पैदा हुई तो पंजाबी नेताओं और अफसरों ने नाजिमुद्दीन के विरुद्ध साज-बाज शुरू कर दी। इस अभिप्राय के लिए गवर्नर जनरल और पंजाब के मुख्य मंत्री मिया मुमताज दौलताना ने गठजोड़ कर लिया। आधी दर्जन पार्टियों ने कट्टरपंथी मौलवियों को एकत्रित किया। एक “बार कौंसल की स्थापना की गई। इसने माग की कि अहमदी मुसलमानों को दूसरे मुसलमानों से अलग कर के “अल्प सख्यक सम्प्रदाय” घोषित किया जाये और विदेश मंत्री सर जफरुल्ला समेत समस्त अहमदियों को सरकार से अलग कर दिया जाए। स्थान-स्थान इस माग के समर्थन के लिए सार्वजनिक सभाएं आयोजित की गयीं। मौलवियों ने फतवे दिए कि अहमदी इस्लाम के शत्रु हैं। उन्होंने हमेशा मुसलमानों को धोखा दिया है। जमायते इस्लामी के अध्यक्ष मौलाना अबुलदला मौदूदी ने फतवा दिया कि इस्लाम में मूर्तियों (पतितों) के लिए पत्थर मार-मार कर मृत्यु के घाट उतार देने की सजा का आदेश दिया गया है। इसलिये उन से पाकिस्तान की इस्लामी स्टेट में यही बर्ताव होना चाहिए।

जलसों में सर जफरुल्ला को अग्रज का एजेन्ट होने का दोषी ठहराया जाता और धमकियां दी जाती कि यदि उन्हें अलग न किया गया तो हिंसात्मक आन्दोलन शुरू कर दिया जायेगा।

“संघर्ष समिति” (बार कौंसल) के प्रमुख नेता शेख हिस्सामुद्दीन दिल्ली में आये। वह अखंड भारत के दिनों मेरे भी मित्र थे। देश भक्त मुसलमानों की सस्था मजलिल एहरार के प्रधान थे और उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में काफी हिस्सा लिया था। परन्तु अन्तिम दिनों में उन्होंने और उनकी सस्था ने पाकिस्तान की माग का विरोध करना छोड़ दिया था। शेख साहिब श्री नेहरू से भी मिले। श्री नेहरू ने उनकी सहायता करने से इन्कार कर दिया। शेख साहिब इसके बाद मुझसे भी

मिले। उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया कि प्रधान मंत्री पाकिस्तान के शासको के विरुद्ध उनकी सहायता करने से साफ इन्कार कर रहे हैं। शेख साहिब ने मुझसे कहा कि

“भारत हमारी सहायता नहीं करता। इस पर हमें भायूसी हुई है। परन्तु अब हम आप से यही सहायता चाहते हैं कि शासको से हमारे सघर्ष की हालत में भारत हमारे शासको की सहायता न करे। हमने अपने आप को इतना सगठित कर लिया है कि कम से कम छ मास तक अपने शासको का मुकाबला कर सकते हैं।”

उन्होंने बताया कि मिया मुमताज़ दौलताना सघर्ष समिति के साथ हैं और सेना के कई उच्च अधिकारी भी उन से सहयोग करेंगे। उन्हें विश्वास था कि वह सरकार का तख्ता उलट देने में सफल हो जायेंगे।

मेरी अपनी धारणा यह थी कि यह सघर्ष पाकिस्तान की जनता के लिये हानिकारक सिद्ध होगा। यदि सघर्ष करने वालों को विजय प्राप्त हो गई तो पाकिस्तान में कट्टरपथियों की एक ऐसी सरकार स्थापित हो जायेगी जो भारत के हितों के लिये और भी खतरनाक होगी। शेख साहिब का विचार इसके विपरीत था। उनका कहना था कि कोई भी नई सरकार प्रगतिशील होगी।

यह मार्च १९५३ के दिन थे। शेख साहिब मेरे कार्यालय में बैठे हुए थे। एकाएक टेलीप्रिन्टर पर कराची की सूचना आई कि “सघर्ष समिति” के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कराची और लाहौर में फायरिंग हो रही है। हिंसात्मक जनसमूह दुकानों और मकानों को लूट रहे हैं। शेख साहिब ने यह समाचार पढ़ते ही कहा - “अख्तर भाई! सलाम! मैं लाहौर जा रहा हूँ।” मैंने उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए कहा कि मौत के मुह में जानबूझ कर जाना अकलमन्दी नहीं। परन्तु शेख साहिब नहीं माने और चले गये। तीसरे दिन सूचना मिली कि सीमा पार करते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।

सरकार ने अपने विरोधियों का मुकाबला करने के लिये लाहौर, कस्सूर, स्यालकोट और पंजाब के कई दूसरे शहरे को सेना के हवाले कर दिया। मिया मुमताज दौलताना को मुख्यमंत्री के पद से अलग कर दिया गया। सेना और जनता में जम कर लड़ाई हुई। सरकार के विरोधियों ने सैकड़ों अहमदियों की हत्या की और उनकी जायदादों को लूट कर आग लगा दी। लाहौर में काश्मीरी गेट की विशाल मस्जिद पर आन्दोलन चलाने वालों ने अधिकार कर के “स्वतन्त्र पाकिस्तान सरकार” की स्थापना की घोषणा कर दी। मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए। मस्जिद के एक गुम्बद पर एक रेडियो ट्रांसमीटर लगाया गया। यहाँ से “स्वतन्त्रता सन्नाम” के बुलेटिन प्रसारित किये जाते।

जनरल अयूब खा के आदेश से सेना ने जनरल आहजम खा की कमान में विद्रोहियों पर बार किया। अकेले लाहौर में दो दिनों में ८ सौ से अधिक व्यक्ति मारे गये। विद्रोहियों की ओर से जो गुप्त सरकुलर जारी किये जाते उन में पाकिस्तानी सेना के लिये “यजीद की सेना” □ के शब्दों का प्रयोग किया जाता और जनता से अपील की जाती कि वह “इस्लाम की रक्षा के लिये” इसका मुकाबला करे। इस आन्दोलन ने पश्चिमी पंजाब में सरकार की व्यवस्था बहुत हद तक भग कर दी थी। यहाँ तक कि विद्रोहियों के पोस्टर, गुप्त बुलेटिन आदि लाहौर और स्यालकोट से मुम्बे/डाक से मिल रहे थे। पाकिस्तान के डाक विभाग के अधिकारी सैसर का प्रतिबन्ध होने पर भी इन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते थे।

□ यजीद ने इस्लाम के जन्मदाता हजरत मुहम्मद के दोहते अमाम हुसैन की हत्या की थी इसलिये मुसलमान यजीद का नाम घृणा से लेते हैं। किसी के लिये “यजीद” के शब्द का प्रयोग करना उसे गाली देना समझा जाता है।

विद्रोहियों को उनकी सहानुभूति भी प्राप्त थी ।

सेना ने मस्जिद को घेर कर उसके किवाड तोड़ डाले और अन्दर घुस कर बंदूको और मशीन-गनो से विद्रोहियों पर हमला कर दिया । मस्जिद के फर्श पर लहू की नदिया बह निकली । कहा जाता है कि इस जगह ५०० से अधिक व्यक्ति मारे गये । मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी बुर्का पहन कर भागे परन्तु रायेविड में गिरफ्तार कर लिये गये । जेल में उन्हें और दूसरे मौलवियों को बुरी तरह पीटा गया । कई एक को नंगा कर-कर उन पर थूका गया ।

यह आन्दोलन तो सख्ती से कुचल दिया गया परन्तु प्रधानमंत्री की शामत आ गई । १७ अप्रैल को वह सरकारी दौरे पर जा रहे थे । ज्यू ही कराची के रेलवे स्टेशन पर पहुँचे और गाडी के डिब्बे में सवार होने लगे, गवर्नर जनरल का एक अधिकारी एक लिफाफा लेकर आया । प्रधान मंत्री ने इसे पढ़ा । उनके चेहरे पर हवाई उड़ने लगी । पंजाबी गवर्नर जनरल ने बंगाली प्रधान मंत्री को हटा दिया था ।

प्रधान मंत्री लौट आये । उन्होंने ब्रिटेन की महारानी से टैलीफोन पर शिकायत करने की कोशिश की परन्तु राजभवन का टैलीफोन कनेक्शन कट चुका था ।

जनता के विरुद्ध नौकर-शाही की और बंगालियों के विरुद्ध पंजाबियों की यह पहली जीत थी । इसने पाकिस्तान में रहे-सहे प्रजातंत्र के विनाश की बुनियाद रख दी । नेताओं के मुकाबले में नौकर-शाही ने अपने आप को मजबूत बना कर जनता के अधिकारों का खाता करने के लिये मैदान तैयार कर लिया ।

इस्कन्दर मिर्ज़ा की तानाशाही जनता पर प्रहार

जिस दिन गवर्नर जनरल गुलाम मुहम्मद ने जनता के चुने हुए प्रधान मंत्री सर नाज़िमुद्दीन को हटा कर मुहम्मद अली बोगरा को प्रधान मंत्री बना दिया, पाकिस्तान में प्रजातंत्र का विनाश हो गया और नौकरशाही के रूप में परले दर्जे की घिनावनी तानाशाही की नींव रख दी गई।

मुहम्मद अली बोगरा ससद सदस्य नहीं थे। वह अमरीका में पाकिस्तान के राजदूत थे। ससद सदस्यों में उनका कोई भी गुट नहीं था। उन्हें प्रधान मंत्री बना देने का अर्थ यह था कि वह पंजाबी गवर्नर जनरल के हाथों में खेले। गवर्नर जनरल पंजाबी नेताओं से भी अधिक पंजाबी नौकरशाही पर अपनी सत्ता को निर्भर रखते थे। उनकी छत्रछाया में नौकरशाही मंत्रियों को अपनी उगलियों पर नचाने के लिये काम करने लगी।

नौकरशाही से भयभीत होकर मुस्लिम लीग दल ने सर नाज़िमुद्दीन से सहानुभूति नहीं की और नामज़द किये हुए प्रधान मंत्री को अपना नेता बनाना स्वीकार कर लिया। यही नहीं बल्कि नाज़िमुद्दीन को पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रधान पद से भी त्यागपत्र देने के लिये मजबूर कर दिया। मुहम्मद अली बोगरा मुस्लिम लीग के प्रधान बन गये। इस प्रकार से गवर्नर जनरल के हाथों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नकेल

भी आ गई ।

नाजिमुद्दीन का भुकाव ब्रिटेन की ओर था तो गुलाम मुहम्मद का भुकाव अमरीका की ओर था । अक्तूबर १९५३ में उन्होंने प्रधान मंत्री बोगरा और सेनापति जनरल अयूब खा को अमरीका भेजा । इसी वर्ष दिसम्बर में अमरीका के उप राष्ट्रपति श्री निक्सन पाकिस्तान आये । इसके परिणाम स्वरूप अमरीका और पाकिस्तान में सैनिक संधिया होने लगी । मई १९५४ में दोनों देशों में परस्पर सैनिक सहायता की संधि हुई । सितम्बर में पाकिस्तान दक्षिण पूर्वी एशिया संधि सगठन में सम्मिलित हुआ । और फरवरी १९५५ में बगदाद पैक्ट में जौ बाद में केन्द्रीय संधि सगठन (सैन्टो) कहलाया, पाकिस्तान ने सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया । इन संधियों के परिणाम-स्वरूप पाकिस्तान पूर्ण रूप से अमरीका के प्रभाव में आ गया । पाकिस्तान सरकार ने अमरीका को सैनिक अड्डे का निर्माण करने की अनुमति दे दी । गिलगित और सीमा प्रान्त में अमरीका ने रूस और चीन पर जासूसी उडानों के लिये अपने अड्डे बनाये । अमरीका ने पाकिस्तान की सेना का पुनर्गठन करने की जिम्मेदारी ली । अमरीका के विशेषज्ञ इस मतलब के लिये पाकिस्तान में आने लगे और पाकिस्तान सरकार ने यह शर्त स्वीकार कर ली कि पाकिस्तान में साम्यवादी तत्वों को कुचल दिया जायेगा और अमरीका के शत्रुओं और विरोधियों के मुकाबले में अपनी जन-शक्ति और दूसरे साधनों का अमरीका को इस्तेमाल करने की खुली छुट्टी देगा ।

इसमें सन्देह नहीं कि पाकिस्तान शासकों ने अपनी तानाशाही की सुरक्षा के लिये और भारत से काश्मीर छीनने के लिये अमरीका से यह गठजोड़ किया था कि अमरीका काश्मीर के लिये उसकी सहायता करेगा । अमरीका ने इसके लिये भी पाकिस्तान को गुप्तरूप से वचन दिया । अमरीका ने भारत को अन्दर से कमजोर करने के लिये

पाकिस्तान के गुप्तचर विभाग के पुनर्संगठन की जिम्मेदारी सम्भाल ली ।०

बोगरा को प्रधान मंत्री बना दिये जाने के विरुद्ध पूर्वी बंगाल में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी थी । विरोधी दलों ने चुनाव में शासक दल का मुकाबला किया । मुकाबले में मुस्लिम लीग की बुरी तरह हार हुई । पूर्वी बंगाल के लीगी मुख्य मंत्री श्री नुरुलउद्दीन भी हार गये । श्री फजलुलहक मुख्य मंत्री बन गये । इससे गुलाम मुहम्मद और बोगरा के पाव तले से जमीन फिसल गई । श्री हक लीग के पुराने और ओजस्वी नेता थे । उन्होंने ही लीग के लाहौर अधिवेशन में देश के विभाजन की माग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । इस कारण से उन्हें शेर बंगाल कहा जाता था परन्तु जब मि० जिन्नाह ने बंगाल सरकार के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप किया था तो उन्होंने विद्रोह का झंडा उठा लिया था । इसी कारण उन्हें मुस्लिम लीग से निकाल दिया गया था परन्तु बंगालियों में उनका बहुत प्रभाव था । श्री हक ने बंगालियों से अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई और जनता उनके झंडे तले एकत्रित होने लगी ।

श्री हक की सरकार को खतम करने के लिये नौकरशाही ने षड्यंत्र रचाया । पूर्वी बंगाल में किराये के मौलवी भेजे गये जिन्होंने “इस्लाम खतरे में” का बावला मचाया । जगह-जगह पर कहा गया कि भारत पाकिस्तान पर अधिकार करने के लिये सैनिक तैयारियां कर रहा है । इसलिये मुस्लिम लीग का विरोध करने वाले वास्तव में हिन्दुओं और भारत के एजेंट हैं । पूर्वी बंगाल में पश्चिमी पाकिस्तान के जिन बड़े-बड़े मिल मालिकों ने अपनी मिलें लगा ली थीं और व्यापार पर अधिकार कर लिया था, उन्हें बंगाली देशभक्तों की बढ़ती हुई ताकत से परेशानी

० इसका विस्तारपूर्वक उल्लेख इसी पुस्तक में आगे चलकर किया गया है ।

हो रही थी। पूर्वी बंगाल में मजदूर न्याय की मांग कर रहे थे। इन मिल मालिकों ने इन्हें भी भारत के एजेंट और पाकिस्तान और इस्लाम के शत्रु करार देना शुरू कर दिया। इन पूजीपतियों ने अपने किराये के मीलवियों द्वारा बिहार और पंजाब से आये हुए मुसलमानों को भड़का कर फसाद करा दिया। इससे ढाका में बंगाली और गैर बंगाली मुसलमानों में दंगे होने लगे। सैकड़ों हिन्दू भी फसाद की लपेट में आकर मारे गये। गवर्नर जनरल ने श्री हूक को आदेश दिया कि वह बंगालियों के विरुद्ध कार्यवाई करे। उनकी यूनियनों को कानून से भग कर दे और उनके नेताओं को गिरफ्तार कर ले। श्री हूक इसके लिये तैयार नहीं थे। उन्हें कराची में तलब किया गया। कलकत्ते के हवाई अड्डे पर आवेश में आकर उन्होंने नेताजी सुभाष बोस का जिक्र आने पर कहा कि पश्चिमी बंगाल के दो भाग हो चुके हैं परन्तु दोनों भागों के बंगाली मन से एक हैं। उनके इस बयान को पाकिस्तान से गद्दारी करार देकर गवर्नर जनरल ने उनका मन्त्रिमण्डल भग कर दिया और पूर्वी बंगाल में गवर्नर राज की घोषणा कर रक्षा विभाग के सैक्रेटरी मेजर जनरल इस्कन्दर मिर्जा को प्रान्त का गवर्नर नियुक्त कर दिया। मिर्जा ने चार्ज लेते ही धडाधड गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया।

प्रधान मंत्री मुहम्मद अली बोगरा ने पंजाबियों की बढ़ती हुई ताकत से परेशान होकर सिंध और सीमा प्रान्त के मुख्यमंत्रियों से गठ-जोड़ कर लिया था। उनमें यह तै हुआ था कि केन्द्र में पठान, सिंधी और बंगाली एक-दूसरे का साथ देंगे। इसका मुकाबला करने के लिये गवर्नर जनरल ने पश्चिमी पाकिस्तान के अलग-अलग प्रान्तों को खतम करने और सब का एक प्रान्त बना देने की योजना तैयार की। सीमा प्रान्त और सिंध के नेता इसका विरोध कर रहे थे। गवर्नर जनरल ने उन्हें धमकी दी कि यदि उन्होंने उनकी योजना का समर्थन न किया तो उनको मन्त्रिमण्डल भग करके उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों में कार्य-

वाही की जायेगी। प्रधान मंत्री ने इसके उत्तर में सदन से वह कानून मसूदा करा लिया जिससे गवर्नर जनरल को मुख्यमंत्रियों और दूसरे मंत्रियों के विरुद्ध इस प्रकार का कदम उठाने का अधिकार मिला हुआ था। गवर्नर जनरल उस दिन एबटाबाद में थे। उनकी अनुपस्थिति में प्रधान मंत्री ने गवर्नर जनरल से प्रान्तीय मन्त्रिमण्डल और केन्द्रीय मंत्रियों को डिसमिस करने का अधिकार छीन लेने का बिल अकस्मान सदन में पेश करके एक घण्टे के अन्दर-अन्दर स्वीकृत करा लिया।

अपनी तानाशाही को इस प्रकार मिटते देख कर श्री गुलाम मुहम्मद क्रोध में आ गये। परन्तु उनके कराची लौटने से पहले ही प्रधान मंत्री मुहम्मद अली बोगरा ऋण की सधि के लिये बातचीत करने के बहाने अमरीका चले गये।

गवर्नर जनरल को अधरग का हमला हुआ था। वह काफी देर से इलाज करा रहे थे। वह चल फिर नहीं सकते थे। ठीक तरह बोल भी नहीं सकते थे परन्तु नौकरशाही को उनकी आवश्यकता थी। इसलिये वह अपनी गद्दी पर डटे हुए थे। कराची लौटते ही उन्होंने प्रधान मंत्री को तार द्वारा आदेश दिया कि वह तुरन्त लौट आये। प्रधान मंत्री ने जब यह आदेश पढ़ा तो उनके हाथ कापने लगे। उन्हें इस बात का भय था कि कराची पहुँचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जायेगा। परन्तु जनरल अयूब खान उन्हें साहस दिलाकर अपने साथ ले आये। कराची पहुँचते ही प्रधान मंत्री गवर्नर जनरल से मिलने की बजाय अपनी कोठी पर चले गये। गवर्नर जनरल की कोठी पर जनरल अयूब खा और मेजर जनरल इस्कन्दर मिर्जा गये। गवर्नर जनरल क्रोध से काप रहे थे और न समझ में आने वाली आवाज में प्रधान मंत्री को गन्दी गालियाँ दे रहे थे। उन्होंने अयूब खा को लिख कर बताया कि मैं मन्त्रिमण्डल भग करके सैनिक शासन स्थापित करना चाहता हूँ। अयूब खा को इस समय अपने आप पर भरोसा नहीं था। उन्हें इस बात की आशंका थी कि सैनिक

शासन स्थापित होते ही देश भर में विद्रोह की आग भड़क उठेगी। उन्होंने प्रधान मंत्री से गवर्नर जनरल का समझौता करा दिया। प्रधान मंत्री भुक्त गये और फैसला हुआ कि केन्द्रीय विधान सभा (संसद) को भग कर दिया जाये। ऐसा ही हुआ। सभा के बंगाली प्रधान मौलवी तमीजुद्दीन ने इसके विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील की। फैसला गवर्नर जनरल के विरुद्ध हुआ परन्तु मुख्य न्यायालय ने गवर्नर जनरल के इस अधिकार को ठीक विधानानुसार करार दिया कि वह सभा को भग कर सकते हैं। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि सभा ने विधान तैयार करने की जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इसलिये गवर्नर जनरल ने यह कदम उठाया है।

यद्यपि गवर्नर जनरल ने प्रधान मंत्री को उसके पद से नहीं हटाया परन्तु उसके भुक्त जाने से उसकी पोजीशन जनता की निगाहों में गिर गई। यही नहीं बल्कि मन्त्रिमण्डल में नौकरशाही की ताकत बढ़ाने के लिये मेजर जनरल इस्कन्दर मिर्जा और सेनापति जनरल अयूब खा को भी नियुक्त कर दिया गया। सीमा प्रान्त के मुख्य मंत्री अब्दुल कयूम को त्याग पत्र देने के लिये मजबूर कर के उसी प्रान्त के इसपैक्टर जनरल सरदार अब्दुल रशीद को मुख्य मंत्री नियुक्त कर दिया गया। कयूम को केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में नियुक्त कर दिया गया। सिंध के मुख्य मंत्री पीरजादा अब्दुल सत्तार ने पश्चिमी पाकिस्तान के अलग-अलग प्रान्तों को खतम करने की योजना के विरुद्ध प्रान्तीय विधान सभा से एक प्रस्ताव स्वीकृत करा लिया था। गवर्नर जनरल ने पीरजादा का मंत्री मंडल भग कर दिया और मुहम्मद अयूब खुर्रो को मुख्य मंत्री नियुक्त कर दिया। नये मुख्य मंत्री ने विधान सभा के सदस्यों को डरा-धमका कर अपना पहला प्रस्ताव रद्द कर दिया और पश्चिम के सभी प्रान्तों को भग कर के "एक यूनिट" की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार करा लिया। पूर्वी बंगाल में गवर्नर का शासन था और पंजाब सरकार गवर्नर जनरल की

घर की बान्दी थी। इस तरह गवर्नर जनरल ने अपने सभी विरोधियों को कुचल दिया था। अपने षड्यंत्र को कार्यरूप देने के लिये उन्होंने एक अध्यादेश द्वारा १९३५ के कानून में संशोधन कर पश्चिम में “एक यूनिट” की स्थापना का अधिकार प्राप्त कर लिया और घोषणा की कि वह अब स्वयं समस्त देश के लिये विधान तैयार करेंगे। इसका अर्थ यह था कि यद्यपि नाम का मंत्रिमण्डल मौजूद था परन्तु सरकार चलाने और संसद के सभी अधिकार गवर्नर जनरल ने स्वयं सम्भाल कर अपनी तानाशाही की स्थापना कर ली थी। निःसन्देह इस षड्यंत्र में मेजर जनरल इस्कन्दर मिर्जा और सेनापति जनरल अयूब खा भी सम्मिलित थे। यह तिगडम परस्पर गठजोड़ कर के उसी भाँति सैनिक तानाशाही स्थापित करने और जनता को हमेशा के लिए प्रजातंत्र के अधिकारों से वंचित करने की साजबाज कर रहा था जिस तरह कुछ वर्ष बाद मेजर जनरल इस्कन्दर मिर्जा और जनरल अयूब खा ने की थी और जिस प्रकार जनरल याहिया खाने की।

इस्कन्दर मिर्जा ने एक वर्ष पहले ढाका में पूर्वी बंगाल का गवर्नर नियुक्त होने पर कहा था कि “पश्चिम से लाया हुआ प्रजातंत्र पाकिस्तान के लोगों के स्वभाव के अनुकूल नहीं है क्योंकि अनपढ़ लोग और राजनैतिक नेता इससे गड़बड़ कर देते हैं।”

गवर्नर जनरल अब एक अध्यादेश द्वारा देश पर एक ऐसा विधान ठोस देना चाहते थे जिसका अभिप्राय जनता को अपनी इच्छा से अपने भविष्य का निर्णय करने के अधिकार से वंचित कर देना था। २७ मार्च १९५५ को जब उन्होंने यह अधिकार स्वयं सम्भाल लेने का अध्यादेश जारी किया तो प्रधान मंत्री मेजर जनरल इस्कन्दर मिर्जा, जनरल अयूब खा अथवा कयूम ने इसका विरोध नहीं किया। यह बात स्पष्ट थी कि ये सभी पाकिस्तानी जनता के विरुद्ध गवर्नर जनरल से मिले हुए थे।

विरोधियों ने मुख्य न्यायालय में इस अध्यादेश को चैलेंज किया। अदालत ने फैसला दिया कि गवर्नर जनरल विधान सभा के किसी बिल की स्वीकृति तो रोक सकता है परन्तु वह स्वयं विधान सभा नहीं। विधान सभा के भंग किये जाने पर गवर्नर जनरल वह अधिकार स्वयं नहीं ले सकता जो इससे पहले प्राप्त नहीं थे।

केस की कार्यवाही के दौरान सरकारी वकील ने भाप लिया था कि गवर्नर जनरल की दाल चलने वाली नहीं। इसलिये उसने न्यायाधीशों को विश्वास दिलाया कि गवर्नर जनरल विधान सभा के चुनाव करायेगे। अदालत ने अपने फैसले में यह बात भी लिख दी। अदालत ने गवर्नर जनरल को यह चेतावनी भी दी कि उन्हें विधान सभा के सदस्यों को स्वयं नियुक्त करने का अधिकार नहीं।

अदालत के इस फैसले से नौकरशाही को बड़ी परेशानी हुई। जनता पर तानाशाही ठोस देने के लिये उनका षड्यंत्र विफल हो गया था परन्तु उन्होंने अपनी साजबाज खतम नहीं की। जनता को उसके अधिकारों से वंचित करने के लिये वे दूसरे तरीके ढूँढने लगे।

गवर्नर जनरल ने विधान तैयार करने के लिये जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं दिया। प्रान्तीय विधान सभाओं के सदस्यों को देश का विधान तैयार करने वाली केन्द्रीय सभा के सदस्य चुनने के लिये कहा गया। बिलोचिस्तान और कबाइली क्षेत्रों में सरकारी अलाऊस लेने वाले सरदारों को स्वयं “जनता के प्रतिनिधि” आपस में से ही चुन लेने का अधिकार दे दिया गया। मुहम्मद अली बोगरा को “त्यागपत्र” देने के लिये मजबूर करके पुन अमरीका में राजदूत बना कर भेज दिया गया। उनकी जगह आई० सी० एस० के भूतपूर्व अफसर चौधुरी मुहम्मद अली को प्रधान मंत्री बना दिया गया। वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रधान भी बन गये। सितम्बर १९५५ को विधान ने गवर्नर जनरल गुलाम मुहम्मद को अधिकार दे दिया कि वह पश्चिमी

पाकिस्तान में सभी अलग-अलग प्रान्तों को भग करके “एक यूनिट” की स्थापना कर दे ।

इस्कन्दर मिर्जा अपनी तानाशाही स्थापित करने के लिये साज-बाज कर रहे थे । उन्होंने गवर्नर जनरल को विवश किया कि वह “बीमारी की छुट्टी” पर चले जाये । इस प्रकार इस्कन्दर मिर्जा ने गवर्नर जनरल का पद स्वयं सम्भाल लिया । इसके बाद उन्होंने अब्दुल कयूम को मन्त्रिमंडल से अलग कर दिया क्योंकि उन्हें मालूम हुआ था कि कयूम खा सेना के कुछ अधिकारियों से मिल कर सरकार का तख्ता उलट देने के लिये तैयारियां कर रहे थे ।

इस्कन्दर मिर्जा ने विधान सभा से यह अधिकार प्राप्त कर लिया कि वह प्रधान मन्त्री के पद पर नियुक्ति के लिये स्वयं फैसला कर सकते हैं और प्रधान मन्त्री का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने शासन प्रबन्ध और तैयार किये जाने वाले विधेयकों के सम्बन्ध में गवर्नर जनरल को सूचित करते रहे । बाद में इस्कन्दर मिर्जा ने इस अधिकार का भरपूर प्रयोग किया ।

इस्कन्दर मिर्जा ने मुस्लिम लीग के नेताओं से साजबाज कर के उनके समर्थन से अपने आप को पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पद के लिये सफल बना लिया । इसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को ही खतम करने और इसी प्रकार सभी दलों और उनके नेताओं को बदनाम करने के लिये एक खतरनाक योजना बनाई ।

इस्कन्दर मिर्जा अपने दौर में सबसे चालाक और खतरनाक शासक थे । उनका सम्बन्ध बंगाल के मीर जाफर के परिवार से था जिसने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को बंगाल पर अधिकार करने के लिये सहायता दी थी । इस्कन्दर मिर्जा बंगाली होने पर भी अपने आप को बंगाली कहना अपनी बेइज्जती समझते थे । इस्कन्दर मिर्जा सीमा प्रान्त में भारत की ब्रिटिश सरकार के बदनाम पोलिटिकल डिपार्टमेंट के एक सीनियर

अधिकारी की हैसियत से काम करते थे और वह डाक्टर खा साहिब के कांग्रेस मन्त्रिमण्डल के दिनों पिशावर के जिलाधीश भी थे । वह इतने चालाक थे कि अंग्रेज के विशेष अधिकारी होते हुए भी उन्होंने डाक्टर साहिब को यह विश्वास दिला रखा था कि वह उनके मित्र और हितैषी हैं । कांग्रेस आन्दोलन के दिनों एक बार खुदाई खिदमतगारों ने एक जलूस निकाला । मिर्जा ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया बल्कि रास्ते में उनके एक एजेंट ने जलूस का स्वागत करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को जमालगोटा मिली चाय पिला दी । इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ ही देर बाद जलूस में नारे लगाने वालों को जुलाब लग गये और जलूस तित्तर-बित्तर हो गया ।

इस्कन्दर मिर्जा ने पहले तो गुलाम मुहम्मद से सीमा प्रान्त में कयूम का मन्त्रिमण्डल भग कराया और फिर इसी कयूम को केन्द्रीय सरकार से निकाल कर डा० खा साहिब से गठजोड़ करने की तैय्यारियां शुरू कर दी । डाक्टर खा साहिब को फास कर वह एक ओर पश्चिमी पाकिस्तान में मुस्लिम लीग को खतम करना चाहते थे और दूसरी ओर डा० साहिब को बदनाम करके अपनी तानाशाही के लिये मैदान तैय्यार करना चाहते थे । इसी लक्ष्य के लिये उन्होंने एक-एक करके पूर्वी बंगाल के नेताओं में फूट डाल कर सभी को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा ।

जनरल अयूब खा के हाथ इस समय मजबूत नहीं थे । उनके रिटायर होने के दिन नजदीक आ रहे थे । मेजर जनरल इस्कन्दर मिर्जा राष्ट्रपति की हैसियत से सेना के सुप्रीम कमाण्डर भी थे और वह किसी समय भी जनरल अयूब खा को चलता कर सकते थे । इसके अतिरिक्त पाकिस्तानी सेना में इस्कन्दर मिर्जा का अपना एक मजबूत गुट भी था ।

६

डाक्टर खां साहिब की हत्या

इस्कन्दर मिर्जा ने अपने आप को राष्ट्रपति के चुनाव में सफल बनाने के लिये मुस्लिम लीग का सहारा लिया था। पश्चिमी पाकिस्तान की विधान सभा में मुस्लिम लीग दल के नेता सरदार बहादुर खा जनरल अयूब खा के छोटे भाई थे। राष्ट्रपति बनने के बाद इस्कन्दर मिर्जा ने लीगी नेताओं को कहा कि वह डाक्टर खा साहिब को पश्चिमी पाकिस्तान का मुख्य मंत्री बनाये। लीग के नेताओं ने इन्कार किया तो इस्कन्दर मिर्जा ने ऐसी जोड़-तोड़ की कि लीग के कई सदस्य विद्रोह करके अलग हो गये और उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना करके डाक्टर साहिब को अपना नेता चुन लिया। इस पार्टी का मैनिफैस्टो प्रान्त के गवर्नर मिया मुश्ताक अहमद गुर्मांनी ने स्वयं तैयार किया था। मिया साहिब वही सज्जन है जिनका नाम पाकिस्तान के पहले प्रधान मंत्री श्री लियाकत अली की हत्या के षड्यंत्र के सम्बन्ध में लिया जा रहा था।

मजे की बात यह है कि पाकिस्तान की स्थापना में पहले रियासत बहावलपुर के प्रधान मंत्री की हैसियत से मिया साहिब ने बहावलपुर को भारत में मिलाने के लिये दौड़-धूप भी की थी परन्तु जब सरदार पटेल ने इन्कार कर दिया तो उन्होंने बहावलपुर को स्वतंत्र देश बनाने का प्रयत्न भी किया था।

डाक्टर खा साहिब को पश्चिमी पाकिस्तान का मुख्य मंत्री बना कर

इस्कन्दर मिर्जा ने पठानिस्तान आन्दोलन को कुचल देने की योजना बनाई। डाक्टर साहिब भोलेपन के कारण इस बात में आ गये। वह यह समझ रहे थे कि वह एक तो मुस्लिम लीग को कुचल देने में सफल हो जायेंगे और दूसरे उनके मुख्य मंत्री होने के कारण पाकिस्तान में पठानों को न्याय मिल सकेगा। डाक्टर साहिब जब दिल्ली में आये तो मैंने उन से भेंट की। मैंने उन्हें कहा कि आप ने इस्कन्दर मिर्जा से मिल कर गलती की है। एक न एक दिन आप इसके लिये पछतायेंगे। उन्होंने मुस्करा कर कहा - “इस्कन्दर मिर्जा को हालात ने बदल दिया है। अब उसे अंग्रेज की चाले चलने की आवश्यकता नहीं। वह मुस्लिम लीग को खतम कर देगा और इससे पाकिस्तान और भारत में मित्रता के लिये मैदान तैयार करने के लिये सहायता मिलेगी।”

डाक्टर साहिब भोले-भाले व्यक्ति थे। वह इस्कन्दर मिर्जा के बिछाये जाल में फँस गये। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अब पठानों का अलग प्रान्त बनाने की माग करने की कोई आवश्यकता नहीं रही क्यो कि पठानों को अपने पाव पर खड़ा होने का अवसर मिल गया है।

डाक्टर खा साहिब की नीति को उनके अपने भाई खा अब्दुल गफ्फार खा ने भी पसन्द नहीं किया। उन्होंने एक बयान में कहा कि वह पठानों का अलग प्रान्त बनाने और पश्तो बोलने वाले सभी इलाकों को मिला देने की माग का कभी त्याग नहीं करेंगे। इस्कन्दर मिर्जा को बादशाह खा पाकिस्तान की स्थापना से पहले भी गद्दार कहा करते थे और अब भी उनके सम्बन्ध में उनकी यही धारणा थी। इस्कन्दर मिर्जा ने बादशाह खा की गतिविधियों पर आपत्ति की और डाक्टर खा साहिब ने इस्कन्दर मिर्जा के इशारे पर अपने भाई की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। उनके बाद पठान नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। इस से पठानों में असंतोष और क्रोध की आग भड़क उठी।

डाक्टर खा साहिब के मुख्य मंत्री बन जाने से पंजाब में मुस्लिम लीग बिगड़ गई थी। उसने डाक्टर खान साहिब के मंत्रिमंडल को भग करने के लिये नेशनल अवामी पार्टी से गठ-जोड़ कर के मंत्रिमंडल पर अविश्वास का प्रस्ताव पेश करने का फैसला कर लिया। डाक्टर साहिब की सरकारी पार्टी के कई सदस्य मुस्लिम लीग से मिल गये। अविश्वास का प्रस्ताव पास हो गया। इस्कन्दर मिर्जा मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल बनाने की स्वीकृति देने के लिये तैयार नहीं थे। उन्होंने मंत्रिमंडल भग करके गवर्नर मुश्ताक अहमद गुर्मांनी को प्रान्त की सरकार का कर्त्ता-धर्त्ता बना दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि दो मास बाद फिर मिर्जा ने लीग के कई सदस्य खरीद लिये और डाक्टर खा साहिब की पार्टी को फिर मंत्रिमंडल बनाने की आज्ञा दे दी गई परन्तु इस बार डाक्टर साहिब नहीं बल्कि सीमा प्रान्त के भूतपूर्व मुख्य मंत्री और इस्पैक्टर जनरल पुलिस सरदार अब्दुल रशीद को पार्टी का नेता और प्रान्त का मुख्यमंत्री बना दिया गया। मजे की बात यह कि सरकारी पार्टी ने नेशनल अवामी पार्टी से गठ-जोड़ कर लिया और एक यूनिट को भग करने और फिर से पुराने प्रान्त बनाने की माग कर दी। हालांकि इसी दल ने इस से पहले पश्चिम के सभी प्रान्तों को ख़तम कर के एक यूनिट बनाने के लिये आन्दोलन किया था।

इस्कन्दर मिर्जा सभी नेताओं को बदनाम करके अपनी तानाशाही स्थापित करना चाहते थे। मुस्लिम लीग के नेता बदनाम हो चुके थे। डाक्टर खा साहिब पर उनके विरोधी अवसरवादी होने का आरोप लगा रहे थे। सरदार रशीद ने अपने विरोधियों की पकड़-धकड़ शुरू कर दी। इस से वह भी बदनाम हो गये। इस्कन्दर मिर्जा ने उन्हें त्याग-पत्र देने के लिये मजबूर किया और उनके स्थान पर नवाब मुजफ्फर-अली किजलबाश को मुख्य मंत्री नियुक्त कर दिया। नवाब साहिब विभाजन से पहले पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के एक नेता थे और शैय्या

मुसलमानों में उन्हें इज्जत से देखा जाता था ।

इस्कन्दर मिर्जा के विरोधी उनके विरुद्ध आन्दोलन कर रहे थे । जगह-जगह उनके विरुद्ध सार्वजनिक सभायें हो रही थी । मुस्लिम लीग, नेशनल अवामी पार्टी और खाकसार उन्हें तरह-तरह की धमकियाँ दे रहे थे ।

एबटाबाद में एक सरकारी जलसे में इस्कन्दर मिर्जा को स्वागत पत्र प्रस्तुत किया गया उसमें उनकी प्रशंसा के पुल बाधते हुए कहा गया था कि राष्ट्रपति को पाकिस्तान का बादशाह घोषित किया जाना चाहिये । जब विरोधी दलों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई और प्रजातन्त्र की स्थापना के लिये सार्वजनिक चुनाव कराने की माँग की तो डाक्टर खा साहिब ने एक बयान में धमकी दी कि यदि विरोधी दलों ने अपना रवैया न बदला तो सभी दलों को तोड़ कर देश का शासन करने के लिये एक “इन्कलाबी कौंसल” स्थापित कर दी जायेगी । श्री हुसैन शहीद सोहरावर्दी के समर्थकों ने इसके उत्तर में धमकी दी कि यदि ऐसा कोई कदम उठाया गया तो प्रजातन्त्र के समर्थक हिंसात्मक तरीकों से इस्कन्दर मिर्जा की सरकार का तख्ता उलट देंगे ।

अन्तिम दिनों में इस्कन्दर मिर्जा और डाक्टर खा साहिब में झगडा हो गया था । डाक्टर खा साहिब को मिर्जा के इरादों पर सन्देह होने लग गया था । डाक्टर साहिब एक नये दल की स्थापना के लिये अपने साथियों से विचार-विमर्श कर रहे थे । झगडे का एक और कारण यह भी था कि इस्कन्दर मिर्जा ने गुप्त रूप से मुस्लिम लीग के नेताओं से बात-चीत शुरू कर दी थी । डाक्टर साहिब लीगियों को मुह लगाने के लिये भी तैयार नहीं थे । मतभेद यहाँ तक बढ़ा कि इस्कन्दर मिर्जा ने अपनी कोठी में डाक्टर साहिब के प्रवेश पर भी एक तरह से प्रतिबन्ध लगा दिया । डाक्टर साहिब बिगड गये और उन्होंने धमकी दी कि वह इस्कन्दर मिर्जा का मुकाबला करेंगे ।

मई १९५७ में डाक्टर खा साहिब को नौकरी से निकाले हुए एक पटवारी अताउल्ला ने छुरा मार कर मृत्यु के घाट उतार दिया। पुलिस में उसने बयान दिया कि खाकसार नेता अलामा मशरिकी ने उसे डाक्टर साहिब की हत्या के लिये कहा था। हत्यारे पर मुकदमा चला और अदालत के आदेश पर उसे फासी दे दी गई। डाक्टर खा साहिब के निकट-सम्बन्धियों का कहना है कि डाक्टर साहिब को वास्तव में इस्कन्दर मिर्जा ने कतल कराया था। अलामा मशरिकी का नाम इसलिये लिया गया था कि उन्हें गिरफ्तार कर के खाकसारों के सगठन को कुचल दिया जाये। हत्यारे को गुप्त रूप से विश्वास दिलाया गया था कि यदि वह खाकसार नेता का नाम ले दे तो अदालत से फासी की सजा का आदेश मिलने पर भी उसे छड़ा लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में नुकते की बात यह है कि अलामा मशरिकी पर कोई मुकदमा नहीं चलाया गया बल्कि कुछ देर बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। इस हालात में कौन कह सकता है कि पाकिस्तान का राष्ट्रपति जिसने अग्रेजों के दिनों में कई व्यक्तियों की हत्या कराई थी डाक्टर खा साहिब का असली हत्यारा नहीं था ?

इस्कन्दर मिर्जा के अन्तिम हथकण्डे

इस्कन्दर मिर्जा अपने आपको सभी नेताओं से चालाक समझते थे ।

डाक्टर खा साहिब का खून कराने के बाद भी उन्हें अपनी तानाशाही खतरे में दिखाई दे रही थी । पाकिस्तान के दोनों भागों में अभी उनके कई विरोधी जीवित थे ।

इस्कन्दर मिर्जा ने अपने हाथ मजबूत करने के लिए एक ओर पूर्वी बंगाल के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री हक को अपने साथ मिला कर उन्हें केन्द्रीय मन्त्रिमंडल में नियुक्त कर दिया तो दूसरी ओर नेशनल आवामी पार्टी के नेता श्री हुसैन शहीद को सोहरावर्दी का समर्थन प्राप्त करके उन्हें प्रधान मंत्री नियुक्त कर दिया । इस सम्बन्ध में स्मरण रहे कि कुछ वर्ष पहले श्री हक को मुख्य मंत्री के पद से हटा दिया गया था और ढाका रेडियो पर भाषण देते हुए पूर्वी बंगाल के गवर्नर की हैसियत से इस्कन्दर मिर्जा ने यह आरोप लगाया था कि श्री हक पाकिस्तान की एकता के शत्रु हैं और अपने देश से गद्दारी कर रहे हैं ।

श्री सोहरावर्दी को भी उन्होंने पाकिस्तान का शत्रु करार देते हुए धमकी दी थी कि ऐसे लोगों को देश से धोखा करने पर गोली मार देनी चाहिये परन्तु अपनी तानाशाही की रक्षा के लिये इस्कन्दर मिर्जा ने दोनों से समझौता कर लिया था ।

मजे की एक और बात यह थी कि श्री सोहरावर्दी ने रक्षा

विभाग भी स्वयं सभाल लिया था और जनरल अयूब ने उसके अधीन काम करना शुरू कर दिया था हालांकि अयूब खा नये प्रधान मंत्री को अपना शत्रु समझते थे। सोहरावर्दी की नेशनल अवामी पार्टी अमरीका से पाकिस्तान की सैनिक सधि का विरोध कर रही थी। वह चुनाव में हिन्दुओं और मुसलमानों के अलग-अलग हलके बनाने का भी विरोध कर रहे थे परन्तु प्रधान मंत्री बनने के लिए उन्होंने इस्कन्दर मिर्जा की नीतियों को अपना लिया। इस पर मौलाना भाषानी का ग्रुप उनसे अलग हो गया। श्री सोहरावर्दी ने इसकी परवाह न की। जब १९५६ में मिस्र पर इजराइल, ब्रिटेन और फ्रान्स ने आक्रमण किया तो प्रधान मंत्री ने इसका समर्थन किया। इससे विरोधी नेताओं को उनके विरुद्ध प्रचार करने का अवसर मिल गया।

श्री सोहरावर्दी ने एक बयान में कहा कि उनकी सरकार चीन से पाकिस्तान की मित्रता के लिये कोशिश करेगी। चीन के नेताओं से बात-चीत के लिये वह पेंकिंग गये। एक और बयान में उन्होंने कहा कि दूसरे देशों से सैनिक सहायता लेने से उनकी सरकार का मतलब यह है कि अपने आप को मजबूत बना कर काश्मीर के लिये भारत पर दबाव डाला जाये। उनके समर्थकों का कहना है कि श्री सोहरावर्दी वास्तव में धीरे-धीरे पाकिस्तान को सैनिक गुट से निकाल लेना चाहते थे।

श्री सोहरावर्दी और इस्कन्दर मिर्जा में शीघ्र ही झगडा हो गया। इस्कन्दर मिर्जा को मालूम हुआ कि प्रधान मंत्री सार्वजनिक चुनाव कराने पर तुले हुए हैं और वह राष्ट्रपति के पद के चुनाव में उन्हें पराजित करने के लिये मुस्लिम लीग से गुप्त रूप से सौदेबाजी कर रहे हैं। इस पर मिर्जा ने प्रधान मंत्री को हटा देने का फैसला किया। रिपब्लिकन पार्टी ने प्रधान मंत्री का विरोध करने की घोषणा कर दी। राष्ट्रपति ने प्रधान मंत्री को त्याग पत्र दे देने के लिये कहा। प्रधान मंत्री ने कहा कि उन्हें ससद में बहुसंख्या का समर्थन प्राप्त है। इसलिये ससद का अधिवेशन

बुलाया जाये परन्तु इस्कन्दर मिर्जा सोहरावर्दी को हटा देने का फैसला कर चुके थे। उन्होंने धमकी दी कि यदि प्रधान मंत्री ने त्याग पत्र न दिया तो उन्हें डिसमिस कर दिया जायेगा। सोहरावर्दी को झुकना पड़ा। त्यागपत्र दे कर वह अलग हो गये। राष्ट्रपति के समर्थको ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये और माग की कि एक जाच-आयोग नियुक्त किया जाये।

श्री सोहरावर्दी ने ११ अक्टूबर १९५७ को त्याग-पत्र दिया था। राष्ट्रपति ने इसी दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रधान श्री चुन्द्रीगर को प्रधान मंत्री के पद के लिये नियुक्त किया परन्तु यह मन्त्रिमण्डल भी अधिक दिन नहीं चल सका। नये प्रधान मंत्री को भी इसी प्रकार त्याग-पत्र देना पड़ा और दिसम्बर १९५७ में राष्ट्रपति ने सर फीरोज खान को प्रधान मंत्री बना दिया।

अंग्रेजों से नये प्रधान मंत्री के पुराने सम्बन्ध सभी को भली-भांति मालूम थे। सर फीरोज खान पंजाब में विभाजन से कई वर्ष पहले शिक्षा-विभाग के मंत्री होते थे। इसके बाद उन्हें वाइसराय की कौंसिल में नियुक्त किया गया। कैंबिन्ट मिशन के आगमन पर जब अंग्रेज सरकार भारतीय नेताओं से समझौते की बातचीत कर रही थी तो सर फीरोज खान नून ने वाइसराय और ब्रिटेन के प्रधान मंत्री को एक लम्बे पत्र में लिखा था कि मुसलमान युद्ध में अंग्रेजों की सहायता कर रहे हैं इसलिये यदि कांग्रेस को देश की सत्ता सौंप दी गई तो मुसलमान नाराज हो जायेंगे।

सर फीरोज खान नून युद्ध समाप्त होने पर मुस्लिम लीग में सम्मिलित हो गये थे। उनकी पत्नी एक अंग्रेज महिला थी। उन्हें पाकिस्तान की स्थापना के बाद दो बार गवर्नर बनने का अवसर मिला था। जहाँ तक जनता का सम्बन्ध है उन्हें सभी लोग टोड़ी समझते थे।

इस्कन्दर मिर्जा ने अपने हाथ मजबूत करने के लिये सिख के भूत-

पूर्व मुख्य मंत्री श्री अयूब खुर्रो को रक्षा-विभाग का मंत्री बनाया। अयूब एक बहुत बड़े जमींदार थे। देश के विभाजन से पहले उन्होंने सिंध के देश-भक्त मुख्य मंत्री श्री मौला बक्स की हत्या करायी थी। सरकार की गुप्त रिपोर्टों के अनुसार किसी भी विरोधी की हत्या करा देना उनके बाये हाथ का खेल था। एक बार मि० जिन्नाह ने और दूसरी बार लियाकत अली ने उनका मन्त्रि-मण्डल भग किया था। इस पर भी इस्कन्दर मिर्जा ने उन्हें रक्षा-विभाग का मंत्री नियुक्त कर दिया तो इस का कारण यह था कि वह अपने हाथ मजबूत करने के लिये इस प्रकार के व्यक्तियों को सरकार में लाना चाहते थे।

इस्कन्दर मिर्जा ने मन्त्रि-मण्डल में जनरल अयूब को जूनियर स्थान देकर काबू कर लिया। जनरल अयूब खा ने यह अपमान इसलिये सहन कर लिया कि इस्कन्दर मिर्जा ने उन्हें नौकरी में दो वर्ष की वृद्धि कर के खरीद लिया था। शायद जनरल अयूब खा स्वयं तानाशाह बनने के लिये उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे।

देश की स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी। कल्लात के नवाब ने पाकिस्तान से अलग होने की घोषणा कर दी। नवाब साहिब को इस्कन्दर मिर्जा ने मन्त्रि-मण्डल से अलग कर दिया था। इससे बिगड़ कर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से सम्बन्ध स्थापित करते समय मुझे वचन दिया गया था कि मेरी रियासत को अलग रहने दिया जायेगा परन्तु पाकिस्तान सरकार ने एकाएक कल्लात का “एक यूनिट” में विलय करके उसका अस्तित्व खतम करके संधि का उल्लंघन किया है*।

यह विद्रोह अप्रैल १९५८ में हुआ। विद्रोहियों ने कई पाकिस्तानी सिपाहियों की हत्या कर दी। अक्टूबर में सूचना मिली कि “स्वतंत्र कल्लात” के सब्ज भण्डे नवाब के महल और दूसरे स्थानों पर लहरा रहे हैं। सरकारी बयान के अनुसार राजकुमार करीम खा और राजकुमार इब्राहिम खाने पाकिस्तान के विरुद्ध अफगानिस्तान से सैनिक-सहायता

की प्रार्थना की थी। एक पोस्टर में जिन्नाह और लियाकत अली के लिये “काफ़र” के शब्द का प्रयोग किया गया। नवाब ने इस्कन्दर मिर्जा से मिलने से इन्कार कर दिया। इस पर इस्कन्दर मिर्जा ने सेना को हमले का आदेश दिया। सेना ने कल्लात पर पुनः अधिकार कर लिया और नवाब को गिरफ्तार कर लिया। नवाब के पुराने समर्थक बिलोची गांधी खा अब्दुल स्मद खा और सैकड़ों दूसरे व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

कई वर्षों बाद इस्कन्दर मिर्जा की कड़ी आलोचना करते हुए जनरल अयूब खा ने अपनी पुस्तक *Friends Not Master* में लिखा कि यह विद्रोह वास्तव में इस्कन्दर मिर्जा का अपना नाटक था। शायद वह यह कह कर कि देश की एकता खतरे में है अपनी तानाशाही स्थापित करने के लिये मैदान तैयार कर रहे थे।

इस्कन्दर मिर्जा पूर्वी बंगाल में भी आये दिन मंत्रिमण्डल स्थापना करके उन्हे भग कर रहे थे। अपने हाथ मजबूत करने के लिये वह विभिन्न दलों को आपस में लड़ा रहे थे। भ्रगडे इतने बढ़े कि प्रान्तीय विधान सभा में विरोधी सदस्यों ने हमला करके उपाध्यक्ष की हत्या कर दी। इस पर वहाँ गवर्नर राज स्थापित कर दिया गया।

इस्कन्दर मिर्जा के विरोधी खामोश नहीं थे। खा अब्दुल कयूम पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रधान बन गये थे। सरकारी प्रतिबन्ध की धज्जिया उड़ा कर उनके हजारों सशस्त्र कार्यकर्ताओं ने कराची में जलूस निकाला। इसके बाद एक सार्वजनिक सभा में उन्होंने धमकी दी कि यदि चुनाव न कराये गये तो पाकिस्तान में लहू की नदियाँ बह जायेंगी। मुस्लिम लीग ने यह भी भाग की कि पाकिस्तान सैनिक गुट्टों से अलग हो जायें।

कहा जाता है कि कयूम खा सेना के कुछ अधिकारियों से ताल-मेल कर के सरकार का तख्ता उलट देने का षड्यन्त्र रचाने की तैयारियाँ

भी कर रहे थे ।

श्री सोहरावर्दी भी जोड़-तोड़ कर रहे थे । उन्होने नये प्रधान मंत्री का विरोध नहीं किया बल्कि उन्हीं से साठ-गाठ शुरू कर दी । एक सूचना के अनुसार दोनो मे समझौता हो गया था कि आगामी चुनाव मे सर फीरोज खा को राष्ट्रपति बनाया जाये ।

श्री सोहरावर्दी दूसरे पजाबी नेता मिया मुमताज दौलताना से भी सौदेबाजी का प्रयास कर रहे थे । उनकी कोशिश यह थी कि तानाशाही को खतम करने और जनतंत्र की स्थापना के लिये पाकिस्तान के दोनो भाग मिल कर काम करे । इस्कन्दर मिर्जा को उनमे फूट डाल कर लाभ उठाने न दिया जाये ।

इस्कन्दर मिर्जा को इन सभी गतिविधियो की सूचना मिल रही थी । उन्होने मन्त्रिमण्डल मे परिवर्तन का फैसला किया । इसके साथ ही वह विधान को मुअत्तल करने के लिये तैयारिया कर रहे थे क्योंकि उन्हे विश्वास हो चुका था कि यदि विधान-अनुसार चुनाव कराये गये तो उन्हे उनके विरोधी राष्ट्रपति के पद से हटा देगे । ६ अक्टूबर को उन्होने दो बार मन्त्रिमण्डल मे परिवर्तन किया परन्तु यह सब केवल एक नाटक था क्योंकि उसी समय इस्कन्दर मिर्जा मन्त्रिमण्डल और ससद को भग करने और सैनिक शासन स्थापित करने के लिये भी तैयारिया कर रहे थे, उसी रात जब मन्त्रिमण्डल के सदस्य राजभवन मे शराब उड़ा रहे थे । राष्ट्रपति ने घोषणा कि "देश की एकता की रक्षाकरने के लिये" उन्होने केन्द्रीय ससद को भग कर दिया है, विधान को मुअत्तल कर दिया है और अपने मन्त्रिमण्डल को भग करके सेनापति जनरल अयूब खा को अपने अधीन चीफ मार्शल-ला एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया है ।

अन्तिम प्रधान मंत्री सर फीरोज खा नून ने कई वर्ष बाद अपनी एक पुस्तक मे लिखा कि इस घोषणा से कई दिन पहले राष्ट्रपति ने उनसे देश की स्थिति पर एक-दो बार बात-चीत की थी और पूछा था कि

अयूब खां की सैनिक तानाशाही

अयूब खा को देश का “मार्शल ला एडमिनिस्ट्रेटर” नियुक्त कर के इस्कन्दर मिर्जा ने अपने पाव पर स्वयं ही कुल्हाड़ा मारा था। केवल बीस दिन बाद ही मिर्जा को सब कुछ छोड़-छाड़ कर पाकिस्तान से भाग कर ब्रिटेन में शरण लेनी पड़ी।

अयूब खा को राजनीति के क्षेत्र में लाने वाले इस्कन्दर मिर्जा ही थे। कई अफसरों का अधिकार छीन कर उन्होंने अयूब खा की मुलाजमत की अवधि बढ़ाई थी। राजनीति के क्षेत्र में कोई किसी का मित्र नहीं होता। लियाकत अली को उनके साथियों ने धोखा दिया। गुलाम मुहम्मद ने नाजिमुद्दीन को और गुलाम मुहम्मद को इस्कन्दर मिर्जा ने धोखा दिया था। अयूब खा को गद्दी पर बिठा कर इस्कन्दर मिर्जा उसके विरुद्ध कुछ सैनिक अधिकारियों को भड़का रहे थे। उन्होंने वायु-सेना के एक सीनियर अधिकारी अब्दुल रब्ब को बुलाया और जनरल याहिया खा, जनरल शेर बहादुर और जनरल हमीद खा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। यह अफसर कुछ हिचकिचाया और उसने टाल-मटोल की कोशिश की और अयूब खा को इसकी सूचना दे दी। इस पर सीनियर सैनिक अधिकारियों से आपस में बातचीत की और फैसला किया कि इस्कन्दर मिर्जा को हटा दिया जाये। उस रात जनरल बरकी, जनरल आहजम खा और जनरल खालिद शेख इस्कन्दर मिर्जा से मिले।

उनके हाथों में पिस्तौल थे। एक ने अपना पिस्तौल इस्कन्दर मिर्जा की छाती की ओर ताना और धमकी दी कि वह तुरन्त ही त्यागपत्र दे दे, नहीं तो उन्हें गोली से उड़ा दिया जायेगा। इस्कन्दर मिर्जा काप उठे। उनके मुख पर हवाइया उड़ रही थी। अपनी मौत का खतरा देख कर उन्होंने त्यागपत्र देना स्वीकार कर लिया। उसी समय त्यागपत्र लिखा गया और उन्होंने हस्ताक्षर कर दिये। दूसरे क्षण अफसर उन्हें और उनकी बेगम को एक कार पर हवाई अड्डे पर ले गये। एक विमान उन्हें कोयटा में ले गया। प्रातः काल उन्हें एक और विमान पर बिठा कर लन्दन पहुँचा दिया गया।

बहुत कम लोगो को मालूम है कि जनरल अयूब खा कई वर्षों से सरकार की गद्दी पर अधिकार करने के लिये कोशिश कर रहे थे। लियाकत अली की मृत्यु के बाद उन्होंने अमरीका से सम्पर्क स्थापित कर लिया था। पाकिस्तान को अपने लिये सुरक्षित करने के लिये अमरीका की सरकार ऐसे सैनिक अफसरों के हाथ मजबूत करना चाहती थी जो पाकिस्तान में प्रगतिशील दलों को कुचल दे। इस्कन्दर मिर्जा से भी अमरीका के अधिकारियों ने ताल-मेल कर रखा था। यहाँ तक कि मिर्जा के बेटे ने कराची स्थित अमरीकी राजदूत श्री होरेसे हिल्डरेथ की बेटी से विवाह कर के अमरीका का नागरिक बनना स्वीकार कर लिया था, परन्तु मिर्जा की अपनी गद्दी डोलने लगी और इस बात का खतरा पैदा हुआ कि चुनाव होने पर विरोधी दल शासन सत्ता पर अधिकार करके पाकिस्तान को अमरीका के सैनिक गुट्ट से अलग कर लेंगे। ईराक में अमरीका के मित्रों की सरकार का तख्ता उलट जाने के बाद पाकिस्तान में भी इसी प्रकार का खतरा पैदा हो चुका था। इस स्थिति में अमरीका ने जनरल अयूब खा के हाथ मजबूत करने का फैसला किया।

सितम्बर १८५६ के पहले सप्ताह अमरीका के गुप्तचर विभाग

“सी० आई० ए०” (सेण्ट्रल इण्टेलिजेन्स एजेंसी) के अध्यक्ष श्री एलन डलेज इण्डोनेशिया जाते हुए गुप्त रूप से कराची पहुँचे । उन्होंने अयूब खा से भेंट की । २३ सितम्बर को न्यूयार्क के साप्ताहिक पत्र “न्यूज वीक” ने लिखा कि “हिन्द महासागर में अमरीका के जगो बड़े के कुछ जहाज भेजे जायेंगे । यदि खतरा हुआ तो अमरीका अपना बड़ा बड़ा भी भेज देगा ।”

एलन डलेज के इण्डोनेशिया से लौट आने के बाद वहाँ अमरीका के मित्रों ने विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया । एलन डलेज इसी पड़्यत्र के लिये वहाँ गये थे ।

अयूब खा से अमरीकी अधिकारियों की मुलाकातो का सिलसिला जारी रहा ।

जनरल अयूब जानते थे कि अमरीका की रवीकृति के बिना पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही स्थापित करना मुश्किल है । इसके लिये वह एलन डलेज की मार्फत दौड़-धूप कर रहे थे । उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि

“८ मई १९५८ को मैं एलन डलेज से मिला और इस बात के लिये उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने हमारी समस्याओं के बारे में अपने भाई को जो कि अमरीका के विदेश मंत्री है दिलचस्पी लेने के लिये तैयार किया ।”

इन शब्दों से स्पष्ट है कि जनरल अयूब ने इस्कन्दर मिर्जा को अघेरे में रख कर अपने तौर पर अमरीका के गुप्तचर विभाग से जिसने कुछ ही वर्षों में ईरान, ग्वाटे माला और इण्डोनेशिया में विद्रोह कराया था पाकिस्तान में भी सरकार का तख्ता उलट देने के लिये स्वीकृति ली थी । श्री डलेज साम्यवाद का डर दिखा कर एशिया के देशों को काबू करने में लगे हुए थे । उन्होंने भारत की निरपेक्षता की नीति को “नैतिक पतन” का नाम देकर इसकी निन्दा की थी । उन्होंने यह विचारधारा

पेश की थी कि एशिया के लोगो को अमरीका के हितो के लिये आपस मे लडाया जाये और जो देश इसके लिये तैयार हो उन्हे भरपूर सैनिक सहायता दी जाये। जनरल अयूब खा स्वार्थी बन कर यह पार्ट अदा करने के लिय तैयार हो गये थे।

जनरल अयूब खा की डायरी के अध्ययन से यह मालूम होता है कि सैनिको और नेताओ का एक गिरोह उन्हे गिरफ्तार करना चाहता था। उन्होने लिखा है कि

२१ मई को मैं जेहलम गया। यहा जनरल आजम खा मुझे मिले। उन्होने बताया कि एबटाबाद से अफवाह निकली है कि एक जनरल और एक ब्रिगेडियर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरी पत्नी ने भी मुझे बताया कि उसने यह अफवाह सुनी है कि कई सीनियर अफसरो पर भारत के दलाल होने का आरोप लगाया जा रहा है। २१ मई को मैंने जनरल मूसा से पूछा। उन्होने बताया कि एबटाबाद मे कुछ नेताओ ने यह अफवाह फैलाई है। चुनाव निकट आ रहे है। नेता लोग विजय प्राप्त करने के लिये भाति-भाति के हथकण्डो का प्रयोग करेगे। इसके बाद उनके पास इसके अतिरिक्त कोई काम नही होगा कि पाकिस्तान के टुकडे-टुकडे कर दे। इस हालत मे सेना से और मुझसे उनका मुकाबला होगा। इसलिये मुझे वह अव्वल नम्बर का शत्रु समझते है।

पाकिस्तान का प्रोपेगैंडा करने वाले अग्नेज लेखक श्री रशब्रुक विलियम्ज ने अपनी पुस्तक The State of Pakistan के पृष्ठ १८२ पर लिखा है कि “इस बात के चिन्ह थे कि सेना के युवक अफसर सरकार का तख्ता उलट देगे।”

इन अफसरो का सम्बन्ध उसी गुटे से था जिन्होने १९५१ मे लियाकत अली खा की सरकार का तख्ता उलट देने की कोशिश की थी। यह लोग चाहते थे कि पाकिस्तान विदेशी मामलो मे स्वतंत्र नीति अपनाये और

सैनिक ब्लाको से अलग हो जाये । यह लोग यह भी चाहते थे कि बड़े-बड़े जमींदारों की जमीनें छोटे किसानों में बांट दी जाये । पाकिस्तान के दोनों भागों में साधारण जनता उनके साथ थी और लगभग सभी दल इन्हीं नीतियों को अपनाने के लिये मांगे कर रहे थे । यदि यह लोग सफल हो जाते तो जनरल अयूब खा और उनके मित्रों के लिये कोई गुजायश नहीं थी । बड़े-बड़े जमींदारों और पूँजीपतियों को अपना भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा था और अमरीका और ब्रिटेन भी परेशान हो रहे थे ।

श्री रशब्रुक विलियम्स ने जो जनरल अयूब खा के ढडोरची हैं, अपनी पुस्तक में लिखा है कि

“कुछ देर से सेना के नेता देश की स्थिति से परेशान हो रहे थे । अपने भरती अफसरों द्वारा उन्हें इस बात का पता लग रहा था कि किमान बड़े-बड़े जालिम जमींदारों के विरुद्ध जबरदस्त बगावत करेंगे । सरकारी मशीनरी का तानाबाना टूटने वाला था । सेना के अफसरों में मतभेद था । कुछ छोटे अफसरों ने यह योजना तैयार की थी कि जिस प्रकार मिस्र में कर्नल नासिर और उनके साथियों ने अचानक धावा बोल कर सरकार पर अधिकार कर लिया था इसी प्रकार पाकिस्तान में भी होगा । जनरल अयूब खा को इसकी सूचना मिली । इसलिये वह सीधे कराची पहुँचे और इस्कन्दर मिर्जा से मिले”

स्पष्ट है कि जनरल अयूब अपनी जान बचाने के लिये भी सरकार पर अधिकार करना चाहते थे ।

अयूब खा ने शासन की बागडोर सम्भालते ही सभी राजनैतिक दलों को भग कर दिया । देश के दोनों भागों में सैकड़ों नेताओं, और कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार कर लिया । इनमें केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के भूतपूर्व सदस्य अयूब खुर्रों, हमीदुलहक चौधुरी, अब्दुल मसूब और अब्दुल खालिक भी शामिल थे । पूर्वी बंगाल में अवामी लीग के नेता शेख

मुजीबुररहमान और उनके दर्जनो साथियों को गिरफ्तार करके नजर-बन्द कर लिया गया। नेशनल अवामी पार्टी के प्रमुख नेताओ मौलाना भाषानी, बादशाह खान, जी० एम० सैयद और खा अब्दुलसैय्यद से भी यही व्यवहार हुआ।

श्री सोहरावर्दी, अब्दुल कयूम, मिया मुमतअज दौलताना आदि सभी दलो के नेताओ पर मुकदमे चलाये गये। उन्हें कहा गया कि यदि वे राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना छोड़ दे तो मुकदमे वापिस ले लिये जायेंगे। उन्हें कहा गया कि वे विशेष अदालतों में अपने वकील पेश नहीं कर सकते। अदालत के फैसले के विरुद्ध अपील भी नहीं की जा सकेगी। सोहरावर्दी ने लिख दिया कि वह राजनीति के क्षेत्र से अलग हो गये हैं। अब्दुल कयूम को क्षमा नहीं किया गया। उन्हें तीन वर्ष कैद की सजा का आदेश दिया गया।

अयूब खा ने १६ अप्रैल १९५९ को एक अध्यादेश जारी करके नेशनल अवामी पार्टी के पंजाब के नेता मिया इफतिखारुद्दीन के समाचार पत्रों “पाकिस्तान टाइम्स,” “दैनिक इमरोज” और साप्ताहिक “लेलो निहार” को अपने अधिकार में ले लिया। जब मिया साहिब ने उच्चतम न्यायालय में अपील की तो अयूब खा ने एक और अध्यादेश जारी किया कि उनकी किसी भी कार्यवाही के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती।

मिया साहिब पर यह आरोप लगाया जा रहा था कि वह चीन और रूस के एजेन्ट हैं।

कई और पत्रकारों को जिनमें मेरे पुराने मित्र आगा शोर काश्मीरी सम्पादक साप्ताहिक “चट्टान” और चौधरी मुहम्मद शफी सम्पादक “इक्दाम” भी शामिल हैं कई बार गिरफ्तार किया गया। दैनिक “बागे हरम” पिशावर के सम्पादक को भी गिरफ्तार किया गया। दैनिक “हिलाले पाकिस्तान” को बन्द कर दिया गया। ढाका के दैनिक “इत्तफाक” को दो बार बन्द किया गया और उसका छापाखाना ज़ब्त कर लिया गया। बाद में

एक “नेशनल ट्रस्ट” स्थापित करके लगभग सभी बड़े-बड़े समाचार पत्रों को खरीद लिया गया। इन समाचार पत्रों में अयूब खा का प्रोपेगैंडा होने लगा। लगभग सभी पत्रों को गुप्त रूप से आदेश दिया गया कि वह सरकारी अधिकारियों के लिखे हुए सम्पादकीय ही प्रकाशित किया करें। यह आदेश भी दिया गया कि सरकार के प्रत्येक वक्तव्य को पूर्ण रूप से प्रकाशित किया जाये।

अयूब खा ने अपनी धाक जमाने के लिये नामी स्मगलरो को गिरफ्तार करके उनकी जायदादे जब्त कर ली। कई भ्रष्टाचारी अफसरों को नौकरी से अलग करके कैद कर दिया गया। जब कराची के नामी स्मगलर कासिम भुट्टो के विरुद्ध केस चला तो मालूम हुआ कि भूतपूर्व गवर्नर जनरल श्री गुलाम मुहम्मद और इस्कन्दर मिर्जा भुट्टो से बाकायदा हिस्सा लिया करते थे। परन्तु यह सब दिखावे की कार्यवाही थी क्योंकि कुछ देर बाद अयूब के अपने परिवार वालों के सदस्यों ने स्मगलिंग और भ्रष्टाचार से हाथ रगना शुरू कर दिया। अयूब की एक बेटी स्वात से अफगानिस्तान के रास्ते स्मगलिंग करती थी। उनके बेटे गोहर अयूब ने अपने बहनोई से मिलकर देखते-देखते करोड़ों के मूल्य की जायदाद बना ली। १९७० में पंजाब के भूतपूर्व डायरेक्टर सूचना विभाग श्री नूर अहमद ने स्मगलिंग के एक केस की दस्तावेजात प्रकाशित करते हुए आरोप लगाया कि जनरल अयूब का सम्बन्ध नामी स्मगलरो के एक गिरोह से था। जनरल अयूब खा को श्री नूर अहमद के विरुद्ध मुकदमा दायर करने का साहस नहीं हुआ।

अयूब खा ने देश की सभी मस्जिदों के अमामों और मौलवियों को सरकारी नौकर बना लिया। इस प्रकार मस्जिदों में इस्लाम के नाम पर सैनिक तानाशाही का समर्थन और प्रजातन्त्र-वाद का विरोध किया जाने लगा। इस प्रोपेगैंडे का एक उदाहरण यह है कि २२ जून १९६० को एक सरकारी मौलवी सैय्यद आसफुल्ला शाह ने भाषण देते हुए कहा कि

“कुरान शरीफ में लिखा है कि राष्ट्रपति शासन इस्लाम के सिद्धान्तों के अनुकूल है। प्रजातन्त्रवाद काफ़रो का सिद्धान्त है। मुसलमानों का कर्तव्य है कि वह जनरल अयूब खान को इस्लाम का खलीफा कहा करे।”

जनरल अयूब खा जनता को ससद के लिये अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देना नहीं चाहते थे। अपने सलाहकारों के कहने पर उन्होंने एक विधान तैयार कराया। उसके अनुसार प्रान्तीय विधान सभा और ससद के चुनाव कराये गये। इस विधान के अनुसार पहले प्राइमरी बेसिक कमेटीया स्थापित की गईं। इनसे थाना, जिला, और डिबिजनल कमेटीया स्थापित की गईं। प्रत्येक कमेटी के आधे सदस्य सरकार ने स्वयं नियुक्त किये। समस्त देश में इन कमेटीयों को ८० हजार मतदाता चुनने का अधिकार दिया गया। और इन ८० हजार को विधान सभाओं और ससद (नेशनल असेम्बली) के सदस्य चुनने का अधिकार दिया गया। कबायली इलाके में केवल पैंशन पाने वाले टोडी सरदारों को मतदान का अधिकार दिया गया। राष्ट्रपति का चुनाव करने का अधिकार भी इन्हें ही दिया गया।

विधान में तै किया गया कि ससद राष्ट्रपति को हटा नहीं सकती। राष्ट्रपति अपने मंत्री सदस्यों में से नियुक्त करेगा परन्तु मंत्री बनते ही वह ससद से त्यागपत्र दे देगे। मंत्रियों को हटाने का अधिकार भी केवल राष्ट्रपति को दिया गया। राष्ट्रपति के भाषण पर ससद को विचार-विमर्श के अधिकार से वंचित कर दिया गया। यह भी आदेश दिया गया कि राष्ट्रपति के फैसलों को ससद रद्द नहीं कर सकती। ससद में बजट में कटौती भी नहीं की जा सकती। यदि किसी मंत्री और विभाग के सैक्रेट्री में मतभेद हो तो अन्तिम फैसला राष्ट्रपति ही करेगा।

समाचार पत्रों को आदेश दिया गया कि वह विधान सभा और ससद की कार्यवाही की वही रिपोर्ट प्रकाशित कर सकेंगे जो सरकार

स्वयं तैयार करेगी। यह फैसला भी किया गया कि १० वर्ष तक रक्षा-विभाग का मंत्री मेना का कोई सीनियर अधिकारी ही हो सकेगा।

इतना करने पर भी विरोधी दलों के लगभग सभी नेताओं पर यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया कि वह न तो किसी विधानसभा के, न किसी राजनीतिक सस्था के सदस्य अथवा पदाधिकारी बन सकते हैं। पहले तो सभी राजनीतिक दलों को भग कर दिया गया था परन्तु अब तानाशाह की आवश्यकता पूरी करने के लिये आदेश दिया गया कि सरकार से लायसेंस लेकर सस्था स्थापित की जा सकती है परन्तु उसके प्रत्येक अधिवेशन में यहाँ तक कि कार्यकारिणी समिति की बैठक में भी खुफिया पुलिस के कर्मचारियों की रिपोर्टिंग के लिये बैठने की इजाजत देना पड़ेगी।

अयूब खा के तानाशाह बनने से पहले अब्दुलकयूम पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रधान थे। अयूब खा ने चौधुरी खलीकुज्जमान की अध्यक्षता में अपने समर्थकों को एकत्रित करके उनसे यह घोषणा करा ली कि जनरल अयूब खा मुस्लिम लीग के प्रधान हैं। यद्यपि सभी विरोधी नेताओं पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था कि वह किसी भी राजनीतिक सस्था के सदस्य नहीं बन सकते परन्तु जो ऐसा नेता अयूब खान की तानाशाही का समर्थन करता उसे सरकारी मुस्लिम लीग में सम्मिलित कर लिया जाता।

पुराने लीगियों ने सरकारी लीग के मुकाबले में अपनी लीग बना ली। इस का नाम कौंसल मुस्लिम लीग रखा गया।

अयूब खा को इस बात का भय था कि जिन जनरलों ने मिर्जा का तख्ता उलटने के लिये उनका साथ दिया था वही किसी दिन उनका पत्ता भी काट देंगे। इसलिये उन्हें सेना से त्यागपत्र देने के लिये विवश करके सरकार में भरती कर लिया गया। जनरल शेख को मंत्रिमण्डल से हटा कर जापान में राजदूत नियुक्त कर के भेज दिया गया। जनरल

आहजम को शरणाथियों के पुनर्स्थापन विभाग से हटा कर पूर्वी बंगाल में गवर्नर नियुक्त कर के भेज दिया गया। आहजम खान शीघ्र ही बंगालियों में आदर का स्थान प्राप्त कर गये। जनरल अयूब खा जब ढाका गये तो जनता ने उनके विरुद्ध नारे लगाये। पुलिस ने बंगाली विद्यार्थियों पर गोलिया चलाई परन्तु विरोधी आन्दोलन की गति तीव्र होती गई। विद्यार्थियों ने अयूब खा के चित्र फाड़ डाले। सरकारी जायदादों को आग लगा दी। पुलिस और सेना विरोधियों को दबा न सकी। जनरल अयूब खा को किसी जलसे में भाषण देने का साहस न हुआ। जनरल अयूब इस घटना से इतने बिगड़े कि उन्होंने गवर्नर आहजम खा को “त्यागपत्र” देने के लिये विवश कर दिया।

जुलाई १९५८ में ईराक में सेना ने अमरीका और ब्रिटेन के मित्रों की सरकार का तख्ता उलट दिया था। ईराक की नई सरकार ने बगदाद पैंक्ट से अलग होने की घोषणा कर के रूस से मित्रता की संधि कर ली। अफगानिस्तान की सरकार ने भी रूस से संधि कर ली।

१ मई १९६० को अमरीका के एक जासूसी विमान को रूस में गिरा लिया गया। उसके चालक ने बयान दिया कि वह पिशावर के निकट एक हवाई अड्डे से अपने विमान को उड़ा कर जासूसी के लिये आया था। इस पर रूस ने धमकी दी कि यदि ऐसी कोई और हरकत हुई तो रूस इस हवाई अड्डे को नष्ट कर देगा। अफगानिस्तान की सरकार ने भी इस विमान की उड़ान के विरुद्ध पाकिस्तान सरकार को विरोध-पत्र भेजा। पाकिस्तान सरकार ने इसके उत्तर में कहा कि पाकिस्तान में अमरीका का कोई अड्डा नहीं। स्पष्ट है कि यह सफेद भूट था। अमरीका के अपने समाचार पत्र लिख रहे थे कि पिशावर के निकट अमरीका ने एक जासूसी अड्डा बना रखा है और इस अड्डे से उड़ानों के लिये अमरीका के विमानों को पाकिस्तानी अधिकारियों से आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती।

अयूब खा के इस झूठ के विरुद्ध विरोधी दलों के नेताओं ने बयान दिये। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सेनाओं में झड़पे हुई। अफगानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों पर पाकिस्तान के विमानों ने बम-बर्षा की। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन हुए। काबुल में क्रोध में आये हुए एक विशाल जनसमूह ने पाकिस्तानी दूतावास पर हमला कर के पाकिस्तानी भंडे को फाड़ कर आग लगा दी। इससे दोनों देशों में तनाव बढ़ गया। उनके व्यापार सम्बन्ध टूट गये।

पाकिस्तानी अधिकृत काश्मीर में भी सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहे थे। अयूब खा के पिटू सरदार खुरशीद को तथाकथित आजाद काश्मीर सरकार का प्रधान बनाने के लिये चुनाव का जो नाटक खेला गया उसके विरुद्ध जगह-जगह प्रदर्शन होने लगे। लाहौर, रावलपिण्डी कराची और ढाका आदि शहरों में भी अयूब शाही के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहे थे।

विरोधियों को कमजोर करने के लिये अयूब खा ने पुरानी चाल चली। उनके विदेश मंत्री मजूर कादिर ने घोषणा की कि सरकार राष्ट्रीय सभा की सुरक्षा समिति में काश्मीर का प्रश्न उठायेगी। भारत को युद्ध की धमकिया देने के लिये प्रोपेगैंडा आन्दोलन शुरू कर दिया गया।

१९६२ में भारत पर चीन ने आक्रमण किया था। पाकिस्तान ने इस अवसर से लाभ उठा कर चीन से संधि कर ली। इस युद्ध में पाकिस्तान भारत पर यह आरोप लगाता रहा कि उसी ने चीन पर आक्रमण किया है। चीन ने आक्रमण नहीं किया। अमरीका और ब्रिटेन ने पाकिस्तान को प्रसन्न करने के लिये भारत सरकार पर काश्मीर के मामले में दबाव डालना शुरू किया परन्तु उन्हें और पाकिस्तान को सफलता नहीं हुई। अमरीका ने काश्मीर का बटवारा करने के लिये एक योजना तैयार की। २६ अक्टूबर १९६२ को यह योजना नई दिल्ली में अमरीका के सूचना

कार्यालय ने प्रकाशित की। भारत सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया।

१९६२ में ही अयूब खा ने श्री भुट्टो को अपना विदेश मंत्री नियुक्त किया था। श्री भुट्टो जूनागढ़ के भूतपूर्व प्रधान मंत्री के बेटे हैं। उनकी माँ एक हिन्दू नर्तकी थी। जब भुट्टो विदेश मंत्री नियुक्त हुए उस समय भी वह पाकिस्तानी नागरिक नहीं थे। दिल्ली में उच्चतम न्यायालय में अपनी जायदाद के लिये उन्होंने बयान दिया था कि वह अब भी भारत के नागरिक हैं। पाकिस्तान का विदेश मंत्री बन कर भारत के विरुद्ध उनका प्रचार अवसरवाद का प्रमाण ही था। श्री भुट्टो ने पाकिस्तान के लिये चीन से सैनिक सहायता लेने के लिये अयूब खा को अपनी सरकार की नीति बदलने के लिये विवश कर दिया। अयूब खा यह समझ रहे थे कि वह चीन से मिल जाने की धमकी देकर अमरीका को भारत पर इस बात के लिये दबाव डालने में सफल हो जायेंगे कि काश्मीर को पाकिस्तान के हवाले किया जाये परन्तु उन्हें शीघ्र ही मालूम हो गया कि भारत सरकार झुकने वाली नहीं।

अयूब सरकार की नींव कमजोर हो रही थी। जनता में असन्तोष बढ़ने लगा। आर्थिक स्थिति भी बिगड़ रही थी और विरोधी दलों के हाँसले बढ़ रहे थे। दिसम्बर १९६१ में श्री सोहरावर्दी विदेशों के दौरे पर गये। उन्होंने अयूब सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। जनवरी १९६२ में वह कराची लौटे। उनके विरुद्ध सरकार के समर्थक समाचार पत्रों ने प्रोपेगैंडा शुरू किया कि वह अमरीका से मिल कर अयूब खा की सरकार का तख्ता उलट देना चाहते हैं। इसी मास उन्हें अचानक कराची में उनके निवास स्थान से गिरफ्तार कर लिया गया। जमाइन इस्लामी के नेता मौलाना मौदूदी को पाकिस्तान सुरक्षा कानून के अधीन गिरफ्तार कर लिया गया। इसी कानून के अधीन “ढाका टाइम्स” और दैनिक “इत्तफाक” को बन्द कर दिया परन्तु कराची और

ढाका की अदालतों ने सरकार की इस कार्यवाही को रद्द कर दिया। जमाइत इस्लामी को भग कर देने के लिये सरकार ने जो आदेश दिया था उसे भी अदालत ने रद्द कर दिया। एक और अदालत ने फैसला दिया कि सरकार का यह अध्यादेश कि सी० आई० डी० के कर्मचारी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की प्राइवेट बैठकों में भी बैठ सकते हैं जनता के विरुद्ध सरकारी अधिकारों का नाजायज इस्तेमाल है।

अयूब खा की इन धाधलियों का मुकाबला करने के लिये विरोधी दलों ने राष्ट्रपति के चुनाव में अयूब खा के मुकाबले में मिस फात्मा जिन्नाह को खड़ा कर दिया। सरकारी मौलवियों ने इस पर फतवे दिये कि इस्लाम किसी स्त्री को देश की शासक बनने की आज्ञा नहीं देता। इस पर विरोधी दलों के मौलवियों ने फतवा दिया कि मिस जिन्नाह अयूब खा से बेहतर मुसलमान हैं। अयूब खा ऐसे तानाशाह को हटाने के लिये मिस जिन्नाह का समर्थन करना पाप नहीं।

अयूब खा स्थान-स्थान पर अपने भाषणों में यह कहते रहे कि मिस जिन्नाह को राष्ट्रपति के पद के लिये चुनना मरदों की बेइज्जती होगी। सेनापति के मुकाबले में मिस जिन्नाह की सफलता एक मजाक होगा और समस्त सत्तार इस पर हसी उड़ायेगा। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि मिस जिन्नाह का समर्थन करने वाले अधिकतर व्यक्ति पाकिस्तान की अखण्डता के शत्रु हैं। मतदाताओं को यह कह कर भी धमकाया गया कि यदि मिस जिन्नाह राष्ट्रपति बन गईं तो सेना विद्रोह कर देगी।

मिस जिन्नाह को कबायली इलाकों में जाने नहीं दिया गया। उनके समर्थकों पर हमले किये गये। परिणाम स्वरूप जनरल अयूब इस चुनाव के नाटक में सफल तो हो गये परन्तु उन्हें मालूम हो गया कि पूर्वी बंगाल में उनका विरोध बढ़ गया है। कराची में भी उनका बहुत विरोध हुआ।

अयूब खा ने अब अपने विरोधियों के गढ़ तोड़ने का फैसला किया । उनके बेटे गोहर अयूब ने जनवरी १९६५ के पहले सप्ताह में सीमा प्रान्त से सैकड़ों किराये के गुण्डे मगवाये । इन्होंने कराची में उत्तर प्रदेश और दिल्ली से आकर आबाद हुए मुसलमानों पर आक्रमण कर दिया । उनके मकान और दुकानें लूट कर जला दी गईं । उनकी बेटियों और स्त्रियों को भगा लिया गया ।

जनवरी के तीसरे सप्ताह मुझे कराची से एक पत्र मिला, जिसे मैंने अपने समाचार पत्र “सवेरा” में १८ जनवरी को प्रकाशित किया था । इसमें लिखा था कि :

“जनवरी १९६४ में पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दुओं के लहू की नदिया बहाई गई थी और अब जनवरी १९६५ में कराची में रहने वाले शरणार्थी मुसलमानों को गुण्डाशाही का निशाना बनाया गया है । ८ जनवरी भयानक फसादों, लूट-मार और अपहरण का पाचवा दिन था । २ जनवरी और ८ जनवरी के बीच एक दर्जन शरणार्थी बस्तियों को तबाह किया गया । लगभग आठ सौ मकान जला दिये गये । ६४ स्त्रियों को भगा लिया गया । १९ व्यक्तियों को जिनमें स्त्रिया भी थी जिन्दा जला दिया गया । सयुक्त दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है । पुलिस तमाशा देख रही है । वह भाग्यहीन शरणार्थियों की रक्षा नहीं कर रही बल्कि उलटा उन्हें ही गोलियों का निशाना बनाती है । मिस जिन्नाह ने यह देख कर दुखी होकर पुलिस से कहा—“इन लोगों को क्यों गोली मारते हो । मुझ पर गोली चलाओ ।”

इस पत्र में यह भी लिखा था कि विरोधी दलों को प्राइमरी यूनियो के चुनाव में ही मालूम हो गया था कि सरकारी एजेंट गडबड करेंगे । हजारों गुण्डे और सीमा प्रान्त से हजारों पठान गाड़ियों और बसों पर छाये गये थे । यह सब बोगस मतदाता थे । इससे जनता को बहुत क्रोध

आया और दुख हुआ कि अयूब खा अपनी तानाशाही कायम रखने के लिये ओछे हथकण्डो का प्रयोग कर रहे हैं। फसाद से एक दिन पहले अयूब खा ने हैदराबाद में अत्यन्त भडकीला भाषण दिया। अयूब खा के बेटे गोहर अयूब ने अपने समर्थकों की एक गुप्त बैठक में यह फैसला किया कि अयूब खा हारे अथवा जीते, विरोधी दल का यह मजबूत गढ़—कराची—तबाह कर दिया जाये। इस बैठक में एक सरकारी मौलवी ने फतवा दिया कि शरणार्थी काफिर हैं। उस रात हजारों सशस्त्र पठानों ने एक जलूस निकाला और शरणार्थियों के भोपड़ों पर हमला कर दिया। उनकी बेटीयों और स्त्रियों को बलपूर्वक उठा कर ट्रकों पर बिठा लिया गया और कितने ही व्यक्तियों को जिन्दा जला दिया गया। अधिकारियों ने शरणार्थियों की बस्तियों में धारा १४४ लागू कर दी परन्तु यह प्रतिबन्ध वास्तव में शरणार्थियों के लिये था। गुण्डों को हमले करने और लूट-मार करने की खुली छुट्टी मिली हुई थी।

पत्र लिखने वाले ने लिखा कि कराची में लोग पूछते हैं, कहा है हमारी सेना ? कहा है हमारे अफसर ? क्या लाखों मुसलमानों ने इसी पाकिस्तान की स्थापना के लिये सघर्ष किया था ?

बिलोचिस्तान में विरोधियों को कुचल देने के लिये सेना और बम-वर्षक विमानों का प्रयोग किया गया। “विद्रोहियों” को नगा कर के पेड़ों से उलटा लटका कर गोली मार दी गई। जिसने अयूब का समर्थन करने से इनकार किया उसे गिरफ्तार कर लिया। जब उसने सरकार का समर्थन करने का विश्वास दिलाया उसे रिहा कर के सरकारी पार्टी में सम्मिलित कर लिया गया। इस सम्बन्ध में एक प्रमुख कबायली सरदार खा बगटी का केस दिलचस्प है। पहले तो उसे विद्रोह और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जब उसने वफादारी का विश्वास दिलाया तो रिहा करके केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित कर लिया गया। परन्तु कुछ देर बाद उसने आखे दिखाई तो डिसमिस कर

के उसे पुराने आरोपो में ही गिरफ्तार कर लिया गया। भूतपूर्व रक्षा-मन्त्री अयूब खुरो को अयूबशाही की स्थापना होते ही गिरफ्तार कर के चोरबाजारी के आरोप में नजरबंद कर दिया गया था। परन्तु जब उसने सरकार का समर्थन करने का विश्वास दिलाया तो उसे सरकारी मुस्लिम लीग में सम्मिलित कर लिया गया।

पूर्वी बंगाल में शेख मुजीबुर्रहमान को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। बादशाह खा को भी पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी सेहत बिगड़ गई तो उन्हें रिहा कर के चिकित्सा के लिये ब्रिटेन जाने की इजाजत दे दी गई। बादशाह खा पाकिस्तान से बाहर गये तो लौटे नहीं। उन्होंने अफगानिस्तान में डेरे डाल लिये।

इन सभी हथकण्डों से भी जनता को दबाया नहीं जा सका। अस्तोप की आग भड़क रही थी। जनरल आज़म खा ने जिन्होंने इस्कन्दर मिरजा का शासन खत्म करने के लिये अयूब खा का साथ दिया था और जिन्हे बंगाल के राज्यपाल के पद से पृथक् कर दिया गया था, लाहौर में डेरे डाल लिये। उन्होंने मिस्र जिन्नाह से मिल कर अयूबशाही के विरुद्ध प्रोपेगैंडा शुरू कर दिया। कराची, रावलपिण्डी और ढाका में विद्यार्थी अयूबशाही को ललकारने के लिये सामने आने लग गये। लाहौर में अयूबशाही के विरुद्ध एक विशाल जलूस निकला। देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही थी। कारखानों में हड़तालें होने लगीं।

इस स्थिति से परेशान होकर सरकार के सकेत पर समाचार पत्रों ने भारत के विरुद्ध प्रचार शुरू कर दिया। माग की जाने लगी कि काश्मीर पर अधिकार करने के लिये भारत से युद्ध किया जाये।

विदेश मन्त्री की हैसियत से श्री भुट्टो चीन गये। उन्होंने चीन से मित्रता की सधि की। गिलगित (काश्मीर) का २५०० वर्ग मील इलाका चीन के हवाले करके चीन को गिलगित में सड़क के निर्माण की इजाजत दी गई। इस सड़क को चीन से मिलाने का फैसला किया

गया। चीन से विमानों की उड़ानों की एक सधि भी की गई। पाकिस्तानी जनता को यह कह कर भड़काने का सिलसिला शुरू किया गया कि काश्मीर पर अधिकार करने के लिये चीन पाकिस्तान की सहायता करेगा।

पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर की तथाकथित सरकार के प्रधान ने भारत को युद्ध की धमकिया देना शुरू कर दिया। खुले तौर पर कहा जाने लगा कि चीन से गस्त्र लेकर काश्मीर पर हमला किया जायेगा। १९६४ में चीनी नेताओं ने पाकिस्तान का दौरा किया था। मार्च १९६५ में जब अयूब खा स्वयं चीन गये, बात-चीत के बाद एक वक्तव्य में अयूब खा ने ससार की समस्याओं पर चीन के दृष्टिकोण का समर्थन किया। पाकिस्तान में उनके लौट आने पर पाकिस्तान सरकार ने भारत के विरुद्ध प्रोपेगैंडा आन्दोलन तेज कर दिया। कहा गया कि भारत और अमरीका मिल कर पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं।

मेजर जनरल अकबर खा ने जो रिहा हो चुके थे कहा कि वह काश्मीर पर हमला करने के लिये गोरिलो को प्रशिक्षण दे रहे हैं। वास्तव में अयूब सरकार स्वयं भी काश्मीर पर हमला करने के लिये इसी प्रकार की तैयारियां कर रही थी। अमरीका और ब्रिटेन के बाद अब उसे चीन ने भी युद्ध सामग्री मिलने लग गई थी। पहले तो अमरीका की सैण्ट्रल इण्टेलिजेंस एजेंसी के विशेषज्ञों की सहायता से रावल-पिण्डी के निकट और कोयटे में ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये जिन में भारत में साम्प्रदायिक गडबड, तोड़-फोड़, जासूसी और भारतीय नेताओं को हत्या करने के लिये अपने आदमियों को प्रशिक्षण देने का आयोजन किया गया और इसके बाद काश्मीर में सशस्त्र घुसपैठिये भेजने के लिये गोरिलो को बड़ों पैमाने पर ट्रेनिंग देने का प्रबन्ध किया गया। ऐसे लोगों को हिन्दुओं, सिखों, साधुओं, ग्रन्थियों और पुजारियों के वेष बदल

कर काम करने की ट्रेनिंग दी गई। इन्हें हिन्दी और सस्कृत पढ़ाई गई। शस्त्रों का प्रयोग करने की ट्रेनिंग भी दी गई। छोटे-छोटें व्यापारियों, चाय बेचने वालों, साधारण हाँकरो, कपड़ा बेचने वालों, सपेरो और बाजीगरों की हैसियत में हवाई अड्डों, सरकारी कार्यकर्ताओं और पुलों, रेलवे स्टेशनों और छावनियों के निकट रह कर जासूसी करने की ट्रेनिंग दी गई। बाद में चीनियों से भी इसी प्रकार के जासूसों और गोरिलों के प्रशिक्षण के लिये सहायता ली गई। पाकिस्तान के शासक यह समझ रहे थे कि इस प्रकार वह भारत में उपद्रव कराने और काश्मीर पर अधिकार करने में सफल हो जायेंगे।

भारतीय नेताओं की हत्या के लिये पाकिस्तानी षड्यंत्र

१९५० में पाकिस्तान ने प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू और रक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेमन की हत्या करने का षड्यंत्र किया। इसके लिये पंजाब विश्वविद्यालय के एक नवयुवक रणवीर सिंह सहगल को तैयार किया। यह व्यक्ति लाहौर गया। वहाँ उस समय मुरिलम लीग के प्रधान श्री अब्दुल कयूम और गुप्तचर विभाग के डायरेक्टर श्री एन० एम० रिजवी से उनकी भेंट कराई गयी। उसे शस्त्रों के प्रयोग की ट्रेनिंग दी गई और कई हजार रुपये, बन्दूक और पिस्तौल देकर भारत में भेजा गया। यह शस्त्र हिन्दूमल कोट रेलवे स्टेशन के निकट जमीन में दबाकर रखे गये। सहगल ने गद्दारों का एक दल भरती किया और उन्हें कहा कि प्रधान मंत्री और दूसरे नेताओं की हत्या करके सरकार का तख्ता उलट दिया जायेगा। सहगल इसके लिये तैयारियाँ कर रहा था। यह तै किया गया कि श्री नेहरू कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) में आराम करने के लिये जाये तो रास्ते में पठान कोट के निकट एक पुल उड़ा दिया जाये। परन्तु सहगल की यह योजना विफल हो गई। उसे और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अम्बाला में उनके विरुद्ध केस चला और उसे तथा उसके साथियों को कैद की सजा दी गई।

फरवरी १९५८ में दो पठानों को दिल्ली में भेजा गया। ये लोग

प्रधान मंत्री की हत्या करने के लिये आये थे। इन्हें चादनी चौक के एक होटल में गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक का नाम समीन जान था।

सितम्बर १९६२ में रक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन की हत्या करने का षड्यंत्र किया गया। काश्मीर पुलिस ने दो पाकिस्तानियों को गिरफ्तार करके इस षड्यंत्र को विफल कर दिया। ये दोनों पाकिस्तानी पुलिस के सीनियर अधिकारी थे और ८ सितम्बर को काश्मीर में घुस आये थे। उन्होंने पुखवाडा के जंगल में घुस कर सोनामार्ग में प्रवेश किया। श्री कृष्ण मेनन ने श्रीनगर लेह रोड के उद्घाटन के लिये इस मार्ग से गुजरना था। गुजरते के वेष में यह पाकिस्तानी सोनामार्ग गये। उन्होंने पुल के नीचे बम रखे। परन्तु रक्षा-मंत्री के गुजरने से पहले ही बम फट गये। पुल नष्ट हो गया परन्तु श्री मेनन बच गये। सीमा सुरक्षा सेना और पुलिस के जवान उस जगह पहुँचे और जंगल में इन पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया।

जून १९६२ में उस समय के काश्मीर के प्रधान मंत्री बक्शी गुलाम मुहम्मद की हत्या के लिये पाकिस्तानियों ने दो-तीन बार प्रयत्न किये। पहले कैसे में पाग ग्राम में एक पुल के नीचे एक बम रखा गया। परन्तु बक्शी साहिब के इस पुल पर से गुजरने से दो दिन पहले यह बम फट गया। १६ जून को जम्मू में बक्शी साहिब के निवास स्थान पर बम रख कर उनकी हत्या की कोशिश की गई। पुलवामा के निकट बक्शी साहिब के गुजरने के मार्ग पर आधा दर्जन बम रखे गये। परन्तु तीनों बार बक्शी साहिब की हत्या करने की कोशिश विफल रही।

काश्मीर पर पाकिस्तान के दूसरे आक्रमण से पहले दर्जनों पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किये गये। श्री नेहरू ने २४ अगस्त १९६२ में राज्य सभा में बताया कि भारत की सैनिक पुलिस ने काश्मीर में कई दर्जन पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान सरकार ने अधिकृत क्षेत्र में ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर

रखे हैं जिन में काश्मीर में तोड़-फोड़ करने की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि १९५९ और १९६० के बीच काश्मीर में पाकिस्तानी एजेंटों से शस्त्र पकड़े जाने के १८८ केस हुए। पाकिस्तानियों ने जो बम फेंके उन से १५ व्यक्तियों की हत्या हुई।

१९६५ में पाकिस्तानी आक्रमण से पहले मार्च में ६५ व्यक्तियों को पकड़ा गया। उनके पास से पाकिस्तानी बम मिले। एक मन्दिर में हिन्दू साधु के वेष में एक पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक रेडियो ट्रांसमीटर मिला। उसके बयान पर उसके ६० साथियों को विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया गया। जम्मू के निकट एक पाकिस्तानी को सपेरे के वेष में गिरफ्तार किया गया। उसके पास से जो कागजात मिले उनसे मालूम होता था कि वह भारतीय सेना की गतिविधियाँ मालूम करने के लिये जासूसी कर रहा था। जून में टीथवाल (काश्मीर) के इलाके में दो पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किये गये। उनके पास बम और पिस्तौल निकले। जम्मू काश्मीर, बंगाल और असम में इन्ही दिनों कई और पाकिस्तानी जासूस पकड़े गये। श्रीनगर में दस ऐसे पाकिस्तानी पकड़े गये जो स्त्रियों के वेष में बुरके पहन कर घूम रहे थे।

हज़रत मुहम्मद के बाल की चोरी पाकिस्तानी षड्यंत्र और शेख अब्दुल्ला

शेख अब्दुल्ला को अगस्त १९५३ में ऐसे समय गिरफ्तार किया गया था जब वह अपनी राजनीतिक धारणा बदल कर भारत सरकार को आखे दिखा रहे थे। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया परन्तु जब यह मालूम हुआ कि वह पाकिस्तान से मिल कर काश्मीर को भारत से अलग करने के लिये षड्यंत्र कर रहे हैं तो उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी पत्नी का १ पत्र पकड़ा गया था जिससे मालूम होता था कि काश्मीर में गड़बड़ कराने के लिये पाकिस्तान से रुपया लिया जा रहा है। मुकदमा चलता रहा। ऐसी हालत पैदा हो गई कि काश्मीर के लोग भी शेख को भूलने लग गये। १९६३ में मैं जब जम्मू गया तो शेख के के विरुद्ध केस के समय अदालत में केवल ३ व्यक्ति मौजूद थे। शेख की अपनी पत्नी भी केस से कोई दिलचस्पी नहीं ले रही थी। उनका एक बेटा श्रीनगर में सरकारी नौकर बन गया था और दूसरा लन्दन में भारतीय दूतावास में काम कर रहा था। शेख अब्दुल्ला निराश हो चुके थे परन्तु भारत में कुछ लोग उनकी वकालत कर रहे थे। ये लोग दबाव डाल रहे थे कि शेख को रिहा कर दिया जाये। उनकी ओर से यह भी प्रचार किया जाता था कि शेख अब्दुल्ला बदल गये हैं।

काश्मीर के प्रधान मंत्री बख्शी गुलाम मुहम्मद कामराज प्लान के अनुसार त्याग पत्र देकर अलग हो चुके थे। उनकी जगह श्री समशुद्दीन

प्रधान मंत्री बने थे ।

मै दिसम्बर के तीसरे सप्ताह एक सम्मेलन के सम्बन्ध में जन्मू गया था । बख्शी साहिब की माता की मृत्यु हुई थी । वह अन्तिम संस्कार से दस-बारह दिन बाद श्रीनगर से जन्मू आये थे । उनसे भेंट हुई तो उन्होंने कहा कि मै दिल्ली आकर कांग्रेस का काम करना चाहता हूँ इसके लिये बात-चीत करूंगा । २७ सितम्बर को वह दिल्ली पहुँचे । रात को उनका फोन आने पर फैसला हुआ कि दूसरे दिन उनसे भेंट होगी । परन्तु दूसरे दिन प्रातः काल मालूम हुआ कि श्रीनगर में उपद्रव हो गये हैं और समाचार मिलते ही वह विमान पर श्रीनगर चले गये हैं ।

श्रीनगर शहर से लगभग ८ मील की दूरी पर हजरत बल की दरगाह में सुरक्षित रूप से रखा हुआ हजरत मुहम्मद का बाल चोरी हो गया था । यह घटना आधी रात के बाद हुई । श्रीनगर और दूसरे इलाकों में जबरदस्त हिमपात होने पर भी सूर्योदय से पहले लाखों व्यक्ति दूर-दूर से एकत्रित हो गये । सरकारी जायदादों पर हमले होने लगे । जगह-जगह आग लगने लगी । प्रोपेगैंडा किया जा रहा था कि हजरत मुहम्मद का पवित्र बाल बख्शी साहिब ने अपनी मरती हुई माता की इच्छा पर उसे दिखाने के लिये चुरा लिया था । हालांकि यह आरोप झूठा था । बख्शी साहिब की माता को मरे हुए दस-बारह दिन हो चुके थे जबकि चोरी २७ दिसम्बर की रात को हुई थी ।

रेडियो पाकिस्तान बख्शी साहिब को ही दोषी ठहरा रहा था । उसके प्रसारणों में कहा जा रहा था कि भारत के अधीन काश्मीर में इस्लाम खतरे में है । जनरल अयूब खाँ, श्री भुट्टो और दूसरे पाकिस्तानी नेता अपने भाषणों में मुसलमानों को यह कहकर भड़का रहे थे कि काश्मीर को “आजाद” करा के ही इस्लाम और काश्मीरी मुसलमानों की रक्षा की जा सकती है ।

लाहौर में एक विशाल समारोह में केन्द्रीय सरकार के माल मंत्री

पीरजादा खा ने कहा हजरत बल दरगाह की पवित्रता भग कर ससार भर के मुसलमानों को आघात पहुंचाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सरकार ने स्वयं यह हरकत की है ताकि काश्मीर के मुसलमान भटके तो सेना का प्रयोग करके उनका सफाया किया जाये।

एक और नेता शेख हिस्सामुद्दीन ने धमकी दी कि काश्मीर में इस्लाम की रक्षा के लिये पाकिस्तान के मुसलमानों को तलवार उठानी पड़ेगी। २ जनवरी १९६४ को अयूब खा ने एक भाषण में कहा कि पाकिस्तान के लोग और उनकी सरकार काश्मीर में इस्लाम पर इस हमले को देख कर खामोश नहीं रह सकती।

कई पाकिस्तानियों ने यहां तक कहा कि चोरी की इन घटना में श्री नेहरू का हाथ है और उनकी सेना काश्मीरी मुसलमानों के लहू से होली खेलना चाहती है।

पूर्वी बंगाल में इसी स्टंट की ओट लेकर बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक फसाद कराये गये। बंगाली हिन्दुओं को लूट-मार का निशाना बना कर उन्हें भारत की ओर धकेलना शुरू कर दिया गया।

वास्तव में हजरत मुहम्मद के पवित्र बाल की चोरी का यह षड्यंत्र शेख अब्दुल्ला के साथी पीर मकबूल गेलानी ने पाकिस्तान की सहायता से कराया था। गेलानी काश्मीर षड्यंत्र केस में शेख के साथ ही गिरफ्तार किया गया था। परन्तु जमानत पर रिहा होकर पाकिस्तान भाग गया था। यहां से वह युद्ध विराम लाइन पार कर गुप्त रूप से श्रीनगर आया था। उसने हजरत बल दरगाह के एक मौलवी से मिल कर योजना तैयार की थी। चोरी के लिये दिन और समय तक नियत किया गया था। यह योजना भी तैयार की गई थी कि प्रातः काल सूर्योदय से पहले ही लाखों लोग श्रीनगर पहुंच कर लूटमार शुरू कर दें। पुलिस गोली चलाये तो मुकाबला किया जाये ताकि युद्ध विराम रेखा से सेना हटा कर शहर में लाई जाये और पाकिस्तान इस स्थिति से फायदा उठाकर काश्मीर पर

हमला कर दे ।

शेख अब्दुल्ला के समर्थकों को चोरी के सम्बन्ध में सब कुछ पता था । इसीलिये तो उन्होंने माग की कि शेख साहब को रिहा कर दिया जाये और बख्शी साहिब को कैद कर लिया जाय । उनका कहना था कि शेख साहिब पवित्र बाल को बरामद करने में सफल हो जायेंगे ।

स्थिति बड़ी गम्भीर हो चुकी थी । गोली चलाना और सेना का प्रयोग करना पाकिस्तान के हाथों में खेलना था और बख्शी साहिब को गिरफ्तार करना एक निर्दोष देश भक्त से अन्याय करना था । श्री नेहरू ने श्री लालबहादुर शास्त्री को पूरे अधिकार देकर श्रीनगर भेजा । उन्होंने सभी दलों के नेताओं से बातचीत की । शेख के समर्थक देश की रिहाई और बख्शी साहिब की गिरफ्तारी की माग के साथ ही काश्मीर के प्रधानमंत्री श्री समशुद्दीन की सरकार को भग करने की माग भी कर रहे थे ।

पाकिस्तानी एजेंटों ने श्री समशुद्दीन की हत्या के लिये उनकी कार पर हमला किया । कार जला दी गई परन्तु समशुद्दीन अपने आप का बचाने में सफल हो गये ।

पुलिस ने पवित्र बाल बरामद कराने के लिये कोशिश की और तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया । इनमें से एक दरगाह हजरतबल का मौलवी अब्दुलरहीम बाण्डे थे । दो दूसरे व्यक्ति रशीद तराल और गुलाम कादिर बट थे । इनकी गिरफ्तारी पर पवित्र बाल मिल गया और सरकार को मालूम हो गया कि यह शरारत शेख के समर्थकों और पाकिस्तान ने की थी ।

अपने षड्यंत्र का भण्डा फूटते देख कर पाकिस्तानियों और शेख के समर्थकों ने कहना शुरू कर दिया कि बाल असली नहीं बल्कि मुसलमानों को धोखा देने के लिये कोई और बाल रख दिया गया है । इस प्रोपेगैंडे से स्थिति और भी खराब हो जाने की आशंका थी ।

रेडियो पाकिस्तान से मुसलमानों को भड़काने के लिये कहा जा रहा था कि वह “असली बाल” बरामद करने के लिये आन्दोलन जारी रखें, यह भी कहा जाता था कि जब तक काश्मीर की सरकार का तख्ता उलट नहीं दिया जाता तब तक पवित्र बाल का पता नहीं लग सकता ।

इस अवसर पर श्री लालबहादुर शास्त्री ने दूरदर्शी नेता की हैसियत से काम किया । उन्होंने शेख अब्दुल्ला के साथियों से बातचीत की । उनकी बातों से यही मालूम होता था कि यदि शेख साहिब को को रिहा करके उनसे बातचीत की जाये तो सकट टल सकता है । श्री शास्त्री को यह भी बताया गया कि शेख अब्दुल्ला काश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करना नहीं चाहते बल्कि वह मन से भारत के समर्थक हैं ।

शास्त्री जी ने खतरा मोल लेने का फैसला किया । उन्होंने शेख को रिहा करने के लिये वचन दिया । इस उपद्रव में जो लोग गिरफ्तार किये गये थे उन्हें रिहा कर दिया गया । इसका परिणाम यह हुआ कि जब शेख साहिब के साथी मौलवी मुहम्मद सईद मसूदी और दूसरे मौलवियों के सामने पवित्र बाल रखा गया तो उन्होंने फतवा दे दिया कि असली बाल बरामद हो गया है ।

पाकिस्तान रेडियो और पाकिस्तानी नेताओं की ओर से इसके बाद भी प्रोपेगैंडा किया जाता रहा कि यह बाल असली नहीं परन्तु काश्मीर के मुसलमान अपने धार्मिक नेताओं के फतवे से सन्तुष्ट हो गये । पाकिस्तानी तानाशाह का षड्यंत्र श्री लालबहादुर शास्त्री की दूरदर्शिता से विफल हो गया ।

कुछ सप्ताह बाद ही श्री सादिक को काश्मीर का मुख्य मंत्री बना दिया गया । शेख अब्दुल्ला और उनके साथियों को छोड़ दिया गया । श्री नेहरू ने एक और खतरा मोल लेकर शेख को पाकिस्तानी शासकों से काश्मीर की समस्या पर बातचीत करने के लिये पाकिस्तान जाने की

अनुमति दे दी ।

शेख अब्दुल्ला यह कह रहे थे कि पाकिस्तान से समझौता हो सकता है। वास्तव में श्री नेहरू जानते थे कि समझौता नहीं हो सकता परन्तु वह चाहते थे कि शेख साहिब बातचीत करें। श्री नेहरू का ख्याल यह था कि शेख अब्दुल्ला निराश होकर लौटेंगे तो उनकी विचारधारा बदल जायेगी। परन्तु शेख की कोई भी योजना जनरल अयूब खा ने स्वीकार नहीं की। शेख साहिब ने अब काश्मीर के दोनों भागों को मिला कर “स्वतंत्र काश्मीर” की अमरीकी योजना पर सोचना शुरू कर दिया। इसके लिये उन्होंने पाक अधिकृत काश्मीर के नेताओं से गुप्त रूप से बात-चीत की। परन्तु श्री नेहरू की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण उन्हें लौट आना पड़ा। उनके दिल्ली लौटते ही अयूब सरकार ने पाक अधिकृत काश्मीर सरकार के प्रधान सरदार खुरशीद को डिस-मिस कर दिया और शेख से गुप्त बातचीत करने वाले काश्मीरी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया।

श्री लालबहादुर शास्त्री भारत के प्रधान मंत्री बन चुके थे। अब शेख साहिब हज्रत का बहाना करके भारत से बाहर चले गये। अपने साथ वह अपने बेटे को भी ले गये। उन्होंने अलजेरिया में पाकिस्तानी नेताओं से और उनकी सहायता से चीन के प्रधान मंत्री से बातचीत की। ऐसा मालूम होता है कि दोनों से उनका गठजोड़ हो गया था। इसके अनुसार ही शेख ने काश्मीर में गोरिला युद्ध की धमकिया देना शुरू कर दिया। शायद उन्हें यह भी मालूम हो चुका था कि पाकिस्तान काश्मीर पर हमला करने के लिये तैयारियां कर रहा है।

रणकच्छ और काश्मीर पर हमला

१९६५ में पाकिस्तानी सेना ने पहले तो रणकच्छ पर और इसके बाद काश्मीर पर आक्रमण किया।

रणकच्छ की सीमा पर यह हमला एक गहरी चाल थी। पाकिस्तान ने सीमा का भगडा बना कर जब भडपे शुरू की तो भारत सरकार को इस बात की आशंका नहीं थी कि पाकिस्तान हमला करेगा इसलिये सीमा पर सशस्त्र पुलिस ही रखी गई थी। पाकिस्तान ने इससे फायदा उठा कर सेना भेज दी जिसने टैंकों की सहायता से हमला कर दिया। भारत सरकार ने तुरन्त विमानों द्वारा अपनी सेनायें भेज दी। जब पाकिस्तानी सेना को परेशानी का सामना करना पड़ा तो पाकिस्तान सरकार की प्रार्थना पर ब्रिटिश सरकार ने युद्ध विराम की योजना पेश कर दी। ब्रिटिश सरकार के प्रधान मंत्री ने यह सुझाव दिया कि रणकच्छ की सीमा का भगडा अन्तर्राष्ट्रीय अदालत में पेश किया जाये और अदालत जो फैसला दे उसे दोनों देश स्वीकार कर लें। प्रधान मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया।

अभी राष्ट्रीय अदालत में मामला पेश ही हुआ था कि पाकिस्तान के शासकों ने काश्मीर की सीमा पर अपनी सेनाओं को भेजना शुरू कर दिया। पंजाब और राजस्थान की सीमाओं पर भी पाकिस्तानी सेनायें एकत्रित होने लगीं। भारत को इस बात की आशंका नहीं थी कि पाकि-

स्तान हमला करेगा। इस सम्बन्ध में अब इस बात का रहस्योद्घाटन किया जा सकता है कि गुप्तचर विभाग को ऐसी सूचना मिली थी कि पाकिस्तान काश्मीर पर हमला करेगा परन्तु यह समझा गया कि वह एक भूठी सूचना है और पाकिस्तान के गुप्तचर विभाग ने भारत सरकार को भ्रम में डालने के लिये चाल खेली है। परन्तु वास्तव में यह सूचना ठीक थी और पाकिस्तान कई महीनों से बड़े हमले के लिये तैयारियाँ कर रहा था।

पाकिस्तानी हमले की योजना यह थी कि पहले चरण में काश्मीर में हजारों सशस्त्र घुसपैठिये भेज दिये जायें। ये लोग श्रीनगर और इसके आस-पास के इलाकों में मस्जिदों, होटलों और अन्य स्थानों पर फकीरों, व्यापारियों और सैलानियों के वेप में ठहरे और जब ६ अगस्त को शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी की वर्षगांठ मनाने के लिये जलूस निकले तो ये लोग उसमें सम्मिलित होकर मुख्य मंत्री और दूसरे मंत्रियों की कोठियों पर हमले कर उनकी हत्या कर दें और रेडियो स्टेशन और सचिवालय आदि की इमारतों पर अधिकार कर लें। यह भी तय किया था कि रेडियो स्टेशन पर अधिकार करके वहाँ से “रेडु-लीशनरी काउंसिल” की स्थापना की घोषणा कर दी जाये और पाकिस्तान से सहायता की अपील की जाये और पाकिस्तानी यह कह कर कि काश्मीर में विद्रोही जनता ने अपनी स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर के पाकिस्तान से सहायता की अपील की है, पाकिस्तानी सेना काश्मीर में प्रवेश कर जाये।

ऐसा मालूम होता है कि पाकिस्तान के पश्चिम के मित्र-राष्ट्र किसी न किसी रूप में पाकिस्तानी शासकों से मिले हुए थे। पाकिस्तान में अमरीका का सैनिक मिशन मौजूद था। यह हो नहीं सकता कि पाकिस्तान की इन तैयारियों का उसे कोई पता न हो। ब्रिटेन अंधेरे में हो इस पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। सम्भवतः दोनों यह

समझ रहे थे कि पाकिस्तान अपने हजारों सशस्त्र घुसपैठियों की सहायता से काश्मीर की वादी पर अधिकार कर लेगा और भारत इसके उत्तर में पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा बल्कि काश्मीर में मुकाबला करने की कोशिश करेगा। इस हालत में यू० एन० ओ० की सुरक्षा समिति युद्ध-विराम का आदेश दे देगी और बीच-बचाव का नाम लेकर ऐसी स्थिति पैदा कर दी जायेगी कि पाकिस्तान अपना लक्ष्य सिद्ध करने में सफल हो जायेगा। पाकिस्तानी हमले से पहले शेख अब्दुला के समर्थकों ने श्रीनगर में तथाकथित शान्तिमय “सत्याग्रह” आन्दोलन शुरू कर दिया था। उन दिनों मैं श्रीनगर गया था। शेख साहिब के साथी मौलवी मसूदी ने मुझे अपने प्रधान कार्यालय में निमन्त्रित किया। मौलवी साहिब ने बड़े भोले अन्दाज में कहा कि “मैं और मेरे साथी गांधी जी के सिद्धान्तों पर विश्वास रखते हैं। कुछ युवक हिंसात्मक तरीकों से काम कर रहे हैं। उन्हें इस मार्ग से हटाने के लिये अहिंसा के सिद्धान्तों के अनुसार आन्दोलन किया जा रहा है।”

मौलवी साहिब ने इसी भोले अन्दाज में कहा कि सरकार और शेख साहिब में समझौता हो सकता है।

मजे की बात यह है कि पाकिस्तान में काश्मीर का विलय करने की माग करने वाली संस्था “काश्मीर पोलिटिकल कान्फ्रेंस” के अध्यक्ष श्री गुलाम मुहीउद्दीन करार ने भी मुझे यही कहा कि वह गांधी जी के सिद्धान्तों पर विश्वास करते हैं। मेरे मुस्करा देने पर उन्होंने कहा कि—
“क्या कोई पाकिस्तानी गांधी जी का श्रद्धालु नहीं हो सकता?”

करार साहिब का कहना था कि वह राजनीति में धर्म-निर्पेक्षता के सिद्धान्त पर भी विश्वास करते हैं और कि जब काश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जायेगा तो वह पाकिस्तान को धर्म-निर्पेक्ष स्टेट बनाने के लिये आन्दोलन करेंगे।

मौलवी साहिब और करार साहिब की चालाकी को मैं भली-भांति

जानता था। दोनों को निःसन्देह मालूम था कि पाकिस्तान हमला करने वाला है और मुझे विश्वास है कि दोनों को यह भी मालूम था कि पाकिस्तान के सशस्त्र घुसपैठिये काश्मीर में घुस रहे हैं।

४ अगस्त १९६५ को दो मुसलमान गोजरो ने कई सशस्त्र पाकिस्तानियों को देखा। उन्हें उनकी गतिविधियों पर सदेह है। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इस सूचना ने भारत सरकार को सतर्क कर दिया। सेना हरकत में आ गई और मालूम हुआ कि हजारों सशस्त्र पाकिस्तानी कश्मीर में घुस कर श्रीनगर और उसके हवाई अड्डे और रेडियो स्टेशन पर अधिकार करना चाहते हैं। ऐसे पाकिस्तानियों का एक गिरोह श्रीनगर की एक बस्ती बटमालू में घुस आया था। दूसरा हवाई अड्डे के निकट वडगाव में घुस गया था और तीसरा निशात बाग के निकट पहुंच गया था। सेना ने इन तीनों ठिकानों पर हमला कर के घुसपैठियों का सफाया कर दिया था। परन्तु दूसरे हजारों पाकिस्तानी सीमावर्ती देहात पर हमले कर रहे थे। इनके विरुद्ध सेना ने कार्यवाही शुरू कर दी।

पाकिस्तान को शायद मालूम नहीं था कि श्रीनगर में उसके घुसपैठियों का सफाया हो चुका है। घुसपैठियों की एक टोली जो बड़े-बड़े पोस्टर लेकर आई थी उसका भी सफाया कर दिया गया था। इन पोस्टरों में “काश्मीर की जनता की इकलाबी कौंसल” की स्थापना की घोषणा की गई थी। यह सभी पोस्टर छीन लिये गये परन्तु लाहौर और रावलपिण्डी के समाचार पत्रों ने अपने शासकों की योजनानुसार इन पोस्टरों के फोटो प्रकाशित करते हुए दावा किया कि श्रीनगर की दीवारों पर यह पोस्टर लगे हुए हैं। एक समाचार पत्र ने लिखा कि काश्मीर में माओ त्से तुंग के तरीकों के अनुसार युद्ध हो रहा है। इस पत्र (दैनिक मशरिक रावलपिण्डी) ने लिखा है कि हमें विश्वास है कि बटमालू की बस्ती में “देश भक्त श्री करा” और उनके समर्थक स्वतंत्रता सेना-

नियो की पूरी-पूरी सहायता करेंगे। इस पत्र को यह मालूम नहीं था की बटमालू में पाकिस्तानी घुसपैठियों का सफाया हो चुका है और करा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है।

भारतीय सेना ने श्रीनगर से ६ मील की दूरी पर उड़ी से हमला करके पाकिस्तानी सेना को भगाते हुए पुछ को मिलने वाली सड़क पर अधिकार कर लिया। यह भारतीय सेना की शानदार विजय थी।

पाकिस्तानी सेना ने छम्ब और जोरिया पर हमला किया। इस हमले का प्रयोजन यह था कि जम्मू से श्रीनगर को मिलने वाली सड़क काट दी जाये। इस जगह पाकिस्तानी सेना को अड्डे और छावनिया बहुत निकट थी। इसलिये पाकिस्तानी सेना को आगे बढ़ने का अवसर मिल गया। इसके मुकाबले में भारतीय सेना ने पंजाब और राजस्थान में एक साथ पांच स्थानों पर हमला कर दिया। राजस्थान की सीमा पार करने वाली सेना ने सिंध में गदरा के शहर और रेलवे स्टेशन पर अधिकार कर लिया। अमृतसर से बढ़ने वाली सेना ने बाहगा की सीमा पार कर तमाम रास्ते में पाकिस्तानी सेना को खदेड़ते हुए इच्छोगिल नहर के इस पार डोगराई पर अधिकार करके नहर पार कर ली और लाहौर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। लाहौर के हवाई अड्डे और शालामार बाग पर भारतीय तोपों के गोले गिरने लगे। एक और सेना ने खेमकरन से कस्सूर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। डेरा बाबा नानक के क्षेत्र पर भी हमला किया गया। इस कार्यवाही का परिणाम यह हुआ कि छम्ब-जोरियो क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना का दबाव खतम हो गया।

वास्तव में पाकिस्तान के शासक यह समझ रहे थे कि भारत पंजाब और राजस्थान से हमला नहीं करेगा और एक ओर पाकिस्तानी सेना जम्मू-श्रीनगर रोड काट देगी और दूसरी ओर घुसपैठिये श्रीनगर के हवाई अड्डे और शहर पर अधिकार कर लेंगे और ऐसा होते ही उसके मित्र-देश युद्ध विराम के लिये भारत पर दबाव डालना शुरू कर देंगे

परन्तु न तो पाकिस्तान को पंजाब और सिंध पर जवाबी हमले की आशका थी न ही पाकिस्तान के मित्र-देश यह समझते थे कि पाकिस्तान सेना इतनी फिसड्डी निकलेगी।

खेमकरन के मोर्चे पर पाकिस्तान के एक पूरे टैंक-डिवीजन ने जवाबी हमला किया। भारतीय सेना ने पीछे हट कर एकाएक तीन ओर से हमला करके पाकिस्तान की यह टैंक सेना तबाह कर दी। इस लड़ाई में पाकिस्तानी सिपाहियों ने अपनी जानें बचाने के लिए ५० से अधिक पैटन टैंक भारतीय सेना के हवाले करके शस्त्र डाल दिये।

पाकिस्तानी सेना का एक मेजर जनरल और कई दूसरे सीनियर अफसर मारे गये।

भारतीय सेना ने हुडयारा पर अधिकार करके बरकी के शहर पर भी अधिकार कर लिया और नहर पर अपने मोर्चे बना लिये। बरकी पाकिस्तानी सेना के जनरल बख्तियार राना का शहर था। यह जगह भी लाहौर को जाने वाले मार्ग पर है, यहाँ से लाहौर छावनी साफ दिखाई देती है।

जम्मू की सीमा पार कर भारतीय सेना ने स्यालकोट के मोर्चे पर हमला कर दिया। भारतीय सेना तजी से आगे बढ़ कर स्यालकोट छावनी पर गोले बरसाने लग गई। इस मोर्चे पर टैंक सेनाओं में घमासान का युद्ध हुआ। पाकिस्तान के तीन सौ से अधिक टैंक नष्ट हो गये।

पाकिस्तान की वायु सेना ने लाहौर के मोर्चे पर हमला होते ही पंजाब पर सैकड़ों सिपाही पैराशूटों से गिरा दिये परन्तु इन्हें हमला करने का अवसर ही नहीं मिला। पंजाब के वीर किसानों ने इनका सफाया कर दिया। भारत की वायु सेना ने लाहौर, सरगोधा, गुजरात लालामूसा, रावलपिण्डी और पिशावर तक बम वर्षा की।

लाहौर से जवाबी हमले का आदेश देते हुए अयूब खा ने दावा

किया था कि पाकिस्तानी सेना अमृतसर पर अधिकार करके दिल्ली तक पहुँच कर दम लेगी परन्तु उसकी सेना खेमकरन और इच्छोगिल नहर से भी आगे न बढ़ सकी। श्री भुट्टो का कहना है कि उस समय अपनी हार देख कर जनरल अयूब खाँ भयभीत होकर थर-थर काप रहे थे। उस समय एयर मार्शल असगर खान अयूब को लेकर चीन गये। चीन से सहायता के लिये भीख मागी गई। चीन ने भारत को धमकिया देना शुरू कर दिया परन्तु पाकिस्तानी सेना के हौसले टूट चुके थे। अमरीका और रूस का सहारा लेकर अयूब खाने युद्ध विराम की सधि पर हस्ताक्षर कर दिये। इस तरह से अयूब की सैनिक तानाशाही को बुरी तरह से पराजित होना पड़ा।

अयूब खान ने काश्मीर पर हमले का रास्ता क्यों अपनाया था ? विद्यार्थी नेता श्री तारिक अली ने लिखा है कि अयूब शाही अपने देश में बदनाम हो रही थी। जनता में असंतोष बढ़ रहा था। पाकिस्तान के दोनों प्रान्तों में अयूब शाही से छुटकारा पाने के लिये आन्दोलन हो रहा था। देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही थी। इसलिये अयूब खान ने अपने आप को वीर सिद्ध करने के लिये और जनता का ध्यान असली समस्याओं से हटाने के लिये भारत से टक्कर लेने का फैसला किया था परन्तु उसे इस बात की आशंका नहीं थी कि उसे मुह की खानी पड़ेगी और यही हार अन्त में उसकी तानाशाही के विनाश का कारण बनेगी।

पाकिस्तान में विद्रोह : अयूबशाही का अन्त

१९६५ का युद्ध अयूब खा को बहुत महंगा पड़ा। युद्ध का अन्त होने पर जब ताश्कद में दोनों देशों में समझौता हुआ तो अयूब खा और भुट्टो दोनों बड़ी मुश्किल में थे। भुट्टो ने अपनी चमड़ी बचाने के लिये समझौते का विरोध करना शुरू कर दिया और पाकिस्तानी सेना की हार के लिये अयूब खा को दोषी ठहरा दिया। इसके फलस्वरूप भुट्टो को मन्त्रिमण्डल से अलग होना पड़ा। इससे भुट्टो को अयूब खा और भारत के विरुद्ध प्रोपेगैंडा करने का अवसर मिल गया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि सैनिक तानाशाही को खतम करके और जनता को शासन के अधिकार देकर ही पाकिस्तान सफल हो सकता है। इस से तानाशाही से दुखित जनता की निगाहों में भुट्टो को हीरो बनने का अवसर मिल गया।

पाकिस्तानी सेना में भी असतोष फैल रहा था। कई सीनियर अफसर इस हार में सटपटा रहे थे। उन्हें जनता को मुह दिखाने की हिम्मत भी नहीं होती थी। उन्होंने भी दबे शब्दों में अयूब खा को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। अयूब खा ने सैनिक विद्रोह के भय के कारण एक दर्जन से अधिक जनरलों और दूसरे सीनियर अफसरों को सेना से अलग कर दिया।

यदि अयूब खा दूरदर्शी होते तो तानाशाही खतम करके जनता को

प्रजातंत्र के अधिकार दे देते परन्तु युद्ध के मोर्चे पर हार कर बदनाम होने पर भी उन्होंने अकलमन्दी से काम लेने की आवश्यकता का अनुभव न किया। उन्होंने फिर अपने विरोधियों को गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू कर दिया। एक दर्जन से अधिक जनरलों को सेना से अलग कर देने का परिणाम यह हुआ कि इन लोगों ने अब खुल कर अयूब का विरोध शुरू कर दिया। जनरल आजम खा, एयर मार्शल असगर खा और दूसरे अफसर जो पहले ही अलग किये गये थे इन से मिल गये। इनका सम्बन्ध बड़े-बड़े जमींदार परिवारों से था। इनके सम्बन्धी मित्र और साथी सेना और सरकार में भी थे। यह लोग भी अयूब खा के विरोधी हो गये। १९ नवम्बर १९६६ को लन्दन के समाचार-पत्र "टैलीग्राफ" ने कराची स्थित अपने सवाददाता द्वारा मिले इस समाचार को प्रकाशित करके सनसनी फैला दी कि

अयूब खा की सरकार का तख्ता उलट देने के एक सनसनी पूर्ण षड्यंत्र का पता लगा है। इस सूचना के अनुसार एक प्रसिद्ध नवाब (यह सकेत नवाब कालाबाग की ओर था जिन्हें पश्चिमी पाकिस्तान के राज्यपाल के पद से पृथक किया गया था) ने जनरल अयूब खा का शासन खतम करने के लिये जनरलों की एक गुप्त कौंसिल बनाई है।

इसी पत्र ने लिखा कि पाकिस्तान में सैनिक पराजय से मायूसी फैली हुई है और चीन से पाकिस्तान के गठजोड़ का विरोध किया जा रहा है। टैलीग्राफ ने लिखा कि जिन जनरलों को भारत से युद्ध में पाकिस्तान की हार के लिये दोषी ठहरा कर सेना से पृथक कर दिया गया है वास्तव में उनका दोष यह है कि वह चीन से पाकिस्तान के गठजोड़ का विरोध कर रहे थे। उनका कहना है कि यह नीति पाकिस्तान को विनाश की ओर ले जायेगी। नवम्बर १९६६ के अन्त में कई विदेशी समाचार पत्रों ने अयूब खा के बेटे गोहर अयूब और उसके

बहनोंई मेजर जनरल हबीबुलरहमान की काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा प्रकाशित किया। दोनों ने सेना से त्यागपत्र देकर “गांधारा इंडस्ट्रीज” के नाम से एक कम्पनी स्थापित की थी। सरकार ने उसे लाखों रुपये दिये। इससे दोनों ने दर्जनों पाकिस्तानी और विदेशी कम्पनियाँ और कारखाने खरीद लिये। देखते ही देखते उन्होंने करोड़ों की जायदाद बना ली और अब समाचार मिल रहे थे कि गोहर अयूब अपने पिता की तानाशाही के खतम हो जाने की आशका से अपनी पूँजी इटली और स्विटजरलैण्ड में गुप्त रूप से भेज रहा है। यह आरोप भी लगाया जा रहा था कि अयूब खा के दो दामादों नजीब और याकूब ने बड़े-बड़े जमींदारों पर नाजायज दबाव डाल कर उनकी हजारों एकड़ भूमि कौड़ियों के मोल प्राप्त करली थी।

१९६२ का एक स्कैण्डल फिर जनता के सामने गया। अयूब खा के एक सम्बन्धी कर्नल मुहम्मद यूसफ ने पंजाब के एक भूतपूर्व मंत्री और प्रमुख व्यापारी सैयद अली निवाज गरदेजी की जर्मन पत्नी क्रिस्टियाना को किसी तरह काबू कर लिया था। गरदेजी ने केस किया। इसकी कार्यवाही के दौरान मालूम हुआ कि इस स्त्री को भगाकर लाहौर में पंजाब के सैनिक राज्यपाल जनरल बख्तियार राना आफ बरकी की कोठी पर रखा गया था। जब अदालत में यह बात आई तो समाचार पत्रों के सम्पादकों को धमकी दी गई कि यदि उन्होंने यह समाचार प्रकाशित किया तो उन्हें पाकिस्तान सुरक्षा कानून के अधीन गिरफ्तार कर लिया जायेगा। उस समय तो यह मामला दब गया परन्तु अब १९६५ के युद्ध में पाकिस्तान की हार के बाद जनता के सामने आ गया। जनरल बरकी के सम्बन्ध में यह अफवाह फैल रही थी कि वह अयूब खा का तख्ता उलट देने के लिये षड्यंत्र कर रहे हैं। अयूब खा ने खामोशी से उन्हें रिटायर कर दिया।

१९६७ में अयूब खा के विरोधियों की राजनीतिक गतिविधियाँ

रहा था ।

अयूब खा देश की समस्याओं का समाधान करने की बजाय अब भी पुराने हथकण्डों का प्रयोग कर के अपने हाथ मजबूत करना चाहते थे । वह अपनी तानाशाही को इस्लाम के सिद्धान्तों के अनुकूल बता कर विद्यार्थियों को इस्लाम के शत्रु ठहरा रहे थे । ढाका में वकीलों की एक बैठक में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि

“मैं किसी हालत में भी ससदीय प्रशासन स्थापित करने के लिये तैयार नहीं क्योंकि यह शासन प्रणाली इस्लाम के सिद्धान्तों के विरुद्ध है ।”

उन्होंने पूर्वी बंगाल को घरेलू मामलों में अधिक अधिकार देने की मांग भी ठुकरा दी और कहा कि पूर्वी बंगाल को पहले ही बहुत स्वतंत्रता मिली हुई है ।

‘ इस बैठक में अयूब खा के एक पिटू ने एक पैम्फलेट बाटा । इसमें तानाशाह की प्रशंसा करते हुए लिखा था कि “अल्लाह ने पाकिस्तान का निर्माण किया है और अयूब खा ने इसकी रक्षा की है ।”

अयूब खा के पिटूओं ने भुट्टो की कड़ी आलोचना करते हुए उन पर आरोप लगाया कि वह भारत के एजेंट हैं और पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं । मंत्रियों ने धमकिया दी कि उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों में मुकदमा चलाया जायेगा ।

भुट्टो जगह-जगह भाषणों में कह रहे थे कि अयूब खा ने ताशकन्द में एक गुप्त समझौता करके भारत से काश्मीर के प्रश्न पर सौदेबाजी करली है । वह यह दावा कर रहे थे कि उन्हें इस सौदेबाजी का पूरा ब्यौरा मालूम है और वह इसके सम्बन्ध में गुप्त दस्तावेजात प्रकाशित करके अयूब खा का भाण्डा फोड़ देंगे । इससे भी आगे बढ़ कर भुट्टो ने कहना शुरू किया कि पाकिस्तान को समस्त काश्मीर पर ही नहीं बल्कि असम और बंगाल के कई भागों पर भी अधिकार करना चाहिए ।

उनका कहना था कि अयूब खा कायर है। उसकी तानाशाही का अन्त करके एक मजबूत पाकिस्तान सफलता से भारत में टक्कर ले सकता है। इसके उत्तर में अयूब खा के समर्थक भुट्टो की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे।

१९६८ में समस्त देश में विद्रोह के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। बिलोचिस्तान में जहाँ पजाबियों को बसाया जा रहा था और बिलोचियों को दबाने के लिये पजाबी पुलिस का प्रयोग किया जा रहा था अक्टूबर और नवम्बर में पजाबी पुलिस और बिलोची विद्रोहियों में कई झड़पे हुईं। काबुल के समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार दो झड़पों में कम से कम ७० पजाबी सिपाही मारे गये। अयूब सरकार ने ५ हजार से अधिक सैनिक विद्रोहियों पर हमले के लिये भेज दिये। विमानों से विद्रोहियों के क्षेत्रों पर बमवर्षा भी कि गई। बिलोचियों को शिकायत थी कि बगालियों की भाँति उनसे भी दूसरी श्रेणी के नागरिकों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। प्रान्त में लगभग सभी व्यापार पजाबियों के हाथों से चला गया था, यही हाल नौकरियों का था। बिलोचियों को दबा देने के लिये पजाबी नागरिकों में शस्त्र बाँटे जा रहे थे। बिलोचिस्तान की नेशनल आवामी पार्टी की ओर से मांग की जा रही थी कि बिलोचियों को आत्म-निर्णय का अधिकार दिया जाये।

सीमा प्रान्त में खा वली खा की नेशनल आवामी पार्टी ने मांग की कि पश्तो बोलने वाले सभी क्षेत्रों को मिला कर पठानिस्तान का प्रान्त बनाया जाये और इसे आन्तरिक स्वतंत्रता दे दी जाये।

सिंध में “जय सिंध” का आन्दोलन चल रहा था। सिंधी देश भक्तों का कहना था कि पाकिस्तान बनने से उनकी भाषा और सस्कृति खतरे में पड़ गई है। उर्दू के लिये सिंधी भाषा को खतम किया जा रहा है और सिंध के व्यापार पर पजाब, दिल्ली और उत्तरप्रदेश से आये हुए लोग अधिकार जमाते जा रहे हैं। सिंधी नेताओं ने अलग प्रान्त बनाने के लिये

आन्दोलन की तैयारिया शुरू कर दी थी। बिलोचिस्तान, सीमा प्रान्त और पूर्वी बंगाल के देशभक्त उनकी माग का समर्थन कर रहे थे।

पंजाब में मिया मुमताज दौलताना की कौसल मुस्लिम लीग, नवाबजादा नसुरल्ला की नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी और स्वर्गीय मिया इफतेस्वारद्दीन के समर्थक मिलकर अयूब शाही के विरुद्ध आन्दोलन की तैयारिया कर रहे थे। भूतपूर्व एयर मार्शल असगर खा, जनरल आजम खा, जनरल जेलानी और अन्य कई भूतपूर्व सैनिक अधिकारी अयूब खा को ललकार रहे थे।

पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर्रहमान की अवामी लीग ने पूर्वी बंगाल के लिये सम्पूर्ण आन्तरिक स्वतंत्रता की माग करते हुये छ बुनियादी मागों के लिये सघर्ष करने की तैयारिया शुरू कर दी। उनका कहना था कि पूर्वी बंगाल रक्षा और विदेशी विभाग के अतिरिक्त दूसरे सभी मामलों के अधिकार अपने पास रखेगा। बंगालियों को शिकायत थी कि यद्यपि उनकी कोशिशों से १९४७ में पाकिस्तान की स्थापना हुई थी परन्तु उनके प्रान्त को पश्चिम का उपनिवेश बना लिया गया है। बंगाली भाषा और सभ्यता का विनाश किया जा रहा है। सरकारी नौकरियों और व्यापार में बंगालियों को उनकी जनसंख्या के अनुसार भाग नहीं दिया जाता। पूर्वी बंगाल के माल की एक्सपोर्ट से विदेशी मुद्रा की मिलने वाली आमदनी पश्चिम में खर्च कर दी जाती है। पश्चिम के व्यापारियों ने बंगाल में व्यापार पर अधिकार कर लिया है और जब भी बंगाली अपने अधिकारों के लिये माग करते हैं उन्हें कुचल दिया जाता है।

मौलाना भाषानी जो किसी समय सोहरावर्दी के साथी थे अब अलग होकर नेशनल अवामी पार्टी के अध्यक्ष थे। उन्होंने चीन का दौरा करके दोनों देशों में मित्रता कराई थी। इसलिये वह अयूब खा के समर्थक बन गये परन्तु अब वह भी विरोधियों से मिल रहे थे। उनका कहना था कि तानाशाही का अन्त हुए बिना पाकिस्तान की जनता को न्याय नहीं

मिलेगा।

समस्त देश में अयूब शाही के विरुद्ध प्रदर्शन हुए। इनमें जनता के अधिकारों के लिये मांगे की गई। यह मांग भी की गई कि समाचारपत्रों पर से सेंसर का प्रतिबन्ध हटा दिया जाये और सभी राजनीतिक कैदियों और नजरबन्दों को रिहा कर दिया जाये। इसका उत्तर यह दिया गया कि अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर्रहमान को सरकार का तख्ता उलट देने के झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले कुछ ही दिनों में चार स्थानों पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था परन्तु वह हर बार जमानत पर रिहा हो जाते। इस पर उन्हें पड़्यत्र के केस में पकड़ लिया गया। यह आरोप लगाया गया कि वह भारत की सहायता से सैनिक विद्रोह के लिये तैयारियाँ कर रहे हैं। सीमाप्रान्त की नेशनल अवामी पार्टी के अध्यक्ष खा वली खा को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

६ नवम्बर १९६८ को एक छोटी-सी घटना ने अयूब खा की तानाशाही के विनाश की बुनियाद रख दी। उस दिन खैबर के दर्रे में कस्टमज के अधिकारियों ने ७० विद्यार्थियों को स्मगलिंग के आरोप में पकड़ लिया। यह विद्यार्थी लण्डी कोतल की फ्री मार्केट से कुछ माल लाये थे। अधिकारियों ने उन्हें बुरी तरह से पीटा। रावलपिण्डी में आने पर उन्हें मालूम हुआ कि श्री भुट्टो आये हुये हैं। वह उनसे मिलना चाहते थे। रावलपिण्डी में पहले ही एक कालेज में हड़ताल हो रही थी। उन्होंने एक विशाल प्रदर्शन किया। अयूब के विरुद्ध नारे लगाये और सरकारी गाड़ियों को रोककर उनसे सरकारी भण्डे उतारकर आड़ दिये और अधिकारियों को अयूब के विरुद्ध नारे लगाने के लिये बाध्य किया। जब जिलाधीश ने रोका तो विद्यार्थियों ने उसके कपड़े फाँकर उसे नंगा किया, उस पर थूका और उसे नगनावस्था में मार्च करने और “अयूब शाही मुर्दाबाद” के नारे लगाने के लिये मजबूर किया। इसके बाद विद्यार्थियों ने उस होटल की ओर मार्च किया जहाँ श्री

भुट्टो ठहरे हुए थे। पुलिस ने उन्हें रोका, लाठी चाज किया और कई एक के सिर फोड़ दिये। एक विद्यार्थी अब्दुल हमीद वहीं मर गया। क्रोध में आकर विद्यार्थियों ने पुलिस पर पत्थरो और ईंटो की वर्षा की और लौटते हुए जगह-जगह सरकारी गाड़ियो और जायदादो पर हमला किया और उन्हें आग लगा दी। सरकार ने जलसो और जलूसो पर प्रतिवध लगा दिया परन्तु दूसरे दिन १५ हजार से अधिक विद्यार्थियो ने जलूस निकाल कर सरकारी आदेश की धज्जिया उडा मार्ग में जिस दुकान पर अयूब खा का फोटो दिखाई दिया उस पर हमला कर फोटो को जला दिया। एक घण्टे के अन्दर-अन्दर यह हालत हो गई कि रावलपिण्डी की किसी दुकान पर अयूब खा का फोटो नहीं रहा। विद्यार्थियो ने सरकारी अधिकारियो की गाड़ियो को रोका। कार्यालयो पर हमला किया और अधिकारियो को पकड कर बाजार में घसीट-घसीट कर उन्हें अयूब खा के विरुद्ध नारे लगाने के लिये मजबूर किया। जलूस में साधारण जनता भी सम्मिलित हो गई। उसने फैक्ट्रियो, बैंको और पूजीपतियो की कोठियो को लूट लिया। देखते-देखते सारा शहर काबू से बाहर हो गया। सरकारी मशीनरी टूट गई। सरकार ने दमन चक्र तो चलाया परन्तु हफ्ते भर के अन्दर-अन्दर यह आन्दोलन समस्त देश में फैल गया। यद्यपि पुलिस ने कई विद्यार्थी नेताओ को पकड लिया परन्तु विद्रोह जारी रहा। लाहौर, कराची, पिशावर, हैदराबाद, ढाका, शिलांग, चटगाव और दूसरे शहरो में विद्यार्थियो और पुलिस में झड़पे हुईं। सरकार ने सभी कालेज और विश्वविद्यालय बन्द कर दिये परन्तु आन्दोलन तेज होता गया। फैक्ट्रियो में काम करने वाले और बेकार युवक भी आन्दोलन में सम्मिलित होने लगे।

१० नवम्बर को अयूब खा पिशावर में एक सरकारी जलसे में भाषण देने के लिये पहुंचे। पिशावर खा बली खा की नेशनल अवामी पार्टी का गढ़ था। सरकारी जलसे से पहले पार्टी ने एक शानदार जलूस

निकाला। पठानों के इतिहास में पहली बार हजारों पठान स्त्रियाँ जलूस में सम्मिलित हुईं। शायद अयूब खा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। केन्द्रीय खाद्य मंत्री नवाब अब्दुलगफूर खान आफ होती जो चीनी की सबसे बड़ी मिल के मालिक थे, अयूब खा के साथ थे। उन दिनों देश में चीनी की चोर-बाजारी बढ़ रही थी। जनता बहुत दुखी थी। नवाब साहिब जैसे ही अयूब खा का स्वागत करने के लिये उठे, लोगों ने शोर मचा दिया और नारे लगाये कि इस चीनी-चोर को गिरफ्तार किया जाये। अयूब खा जनता को शान्त कराने के लिये उठे तो एक पठान युवक हाशम खा ने उन पर गोली चला दी। परिणाम यह हुआ कि भगदड़ मच गई। लोग भागने लगे। अयूब खा अपनी जान बचाने के लिये एक सोफे के नीचे छुप गये। हमला करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया परन्तु अयूब खा काफी देर तक छुपे रहे। बाद में वह भाषण दिये बिना सैनिकों की रक्षा में भाग गये। हाशम ने पुलिस को बताया कि मुझे इस बात का दुख है कि मैं इस जालिम को जिसने दस वर्षों से जनता को गुलाम बना रखा है मौत के घाट उतार नहीं सका।

अयूब खा ने इस घटना से भी कुछ नहीं सीखा। उसके आदेश से भुट्टो और बहुत से विद्यार्थी नेताओं को शासन-मर्यादा भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया।

नवम्बर के तीसरे सप्ताह में लन्दन के दैनिक "टैलीग्राफ" ने लिखा कि पाकिस्तानी सेना में भी अयूब खा का विरोध फैल रहा है। अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि अयूब खा अपनी शासन सत्ता की रक्षा के लिये सेना से भी सहायता की आशा नहीं कर सकते।

ऐसे समय जब समस्त देश में विद्रोह फैल रहा था, सूचना विभाग के मंत्री श्री शहाबुद्दीन ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान के लोगों को किसी भी स्वतंत्र देश से बढ़ कर प्रजातंत्र के अधिकार मिले हुए हैं।

दूसरी ओर पश्चिमी पाकिस्तान के राज्यपाल जनरल मूसा ने रेडियो पर भाषण देते हुए कहा कि कानून तोड़ने वाले नेताओं को सरकार कुचल देगी।

१९ नवम्बर को लाहौर में एक जलूस पर हमला करके पुलिस ने कुछ युवकों को पकड़ कर नगा कर दिया और मार पीट की। दूसरे दिन हजारों स्त्रियाँ मैदान में निकल आईं। पेशावर में सरकारी मुस्लिम लीग और अमरीकन सूचना कार्यालय की इमारतों को जला दिया गया। रावलपिण्डी में समस्त आबादी सामने आ गई। छ घण्टों तक पुलिस और जनता में लड़ाई होती रही।

पूर्वी बंगाल की जनता यह विद्रोह देख कर खामोश नहीं रह सकती थी। विद्यार्थियों में विद्रोह की आग भड़क रही थी। उन्हें भय-भीत करने के लिये अयूब खा के पिटुओं ने विद्यार्थियों को धमकाना शुरू कर दिया। विद्यार्थियों ने ऐसे एक युवक सईदरहमान को गोली का निशाना बना दिया। इस युवक ने गवर्नर मुनहम खा के इशारे पर सरकारी विद्यार्थी सघ बनाया था। इससे टोडियों के हौसले टूट गये।

६ दिसम्बर को मौलाना भाषानी ने हजारों विद्यार्थियों और किसानों के जलसे में भाषण देते हुए कहा कि बंगाल के लोग सम्पूर्ण आन्तरिक स्वतंत्रता प्राप्त किये बिना चैन नहीं लेगे और यह लक्ष्य भारी आन्दोलन शुरू किये बिना सिद्ध नहीं हो सकता। उन्होंने दूसरे दिन के लिए आम हड़ताल की घोषणा की। सरकार ने धारा १४४ लागू कर दी थी परन्तु हजारों विद्यार्थियों ने कानून भंग कर के जलूस निकाला। पुलिस और सेना ने कई बार गोली चलाई। एक बीस वर्षीय कर्मचारी अब्दुलमजीद मारा गया और बीस से अधिक घायल हो गये। उसी

□ मुनहम खा को अक्टूबर १९७१ में गोरिलों ने गोली का निशाना बना दिया था।

शाम एक विशाल जलसे मे भाषण देते हुए मौलाना ने घोषणा की कि कल फिर हड़ताल होगी और मैं स्वयं राज्य भवन के सामने प्रदर्शन करूंगा। १६ दिसम्बर को फिर हड़ताल थी। अयूब खा दुर्भाग्यवश इस दिन अपने समर्थकों को थपकी देने के लिये ढाका पहुंचे। लाखों बंगालियों ने उनसे विरुद्ध नारे लगाये। सेना ने उन पर गोली चलाई। पूर्वी बंगाल में एक हजार से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी बड़े-बड़े नगरों में पुलिस और जनता में टकराव हुआ। अयूब खा मायूसी से लौट गये। उसी दिन एयर मार्शल असगर खा का ढाका में भव्य स्वागत किया गया। कर्मचारियों के जलसे में भाषण देते हुए उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि जनता के विरुद्ध सैनिक-शक्ति का प्रयोग करने से समस्त देश में आग लग जायेगी। उन्होंने सेना से कहा कि वह राजनीति में द्रिलचस्पी न ले।

मौलाना भाषानी से भेंट करने के बाद एयर मार्शल असगर खा ने कहा कि पूर्वी बंगाल के लोग देशभक्त हैं। उन्होंने अपील की कि राष्ट्रपति के चुनाव में सभी विरोधी दल मिलकर अयूब खा का मुकाबला करें।

इस दौरान रावलपिण्डी में अयूब खा के एक पिछू शेर बहादुर ने रावलपिण्डी के ही एक पत्रकार पर गोली चला कर उसे घायल कर दिया था। इस पर रोष प्रकट करने के लिये सभी पत्रकारों ने हड़ताल कर दी। पत्रकारों ने अपनी मांगें स्वीकार कराने के लिये भी आन्दोलन शुरू कर दिया। उनकी सब से बड़ी मांग यह थी कि वह सरकारी अध्यादेश कैंसल कर दिया जाये जिसके अनुसार किसी आपत्तिजनक लेख पर किसी भी सम्पादक, रिपोर्टर और कम्पाजिटर को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाये बिना नजरबंद किया जा सकता है।

जनवरी १९६६ में श्री भुट्टो की पीपल्स पार्टी के अतिरिक्त सभी दूसरे विरोधी दलों ने एक संयुक्त मोर्चा स्थापित कर लिया। मोर्चे ने

कम-से-कम मागो का जो चार्टर तैयार किया उसमे कहा गया कि पाकिस्तान मे ससदीय फ़ैडरल शासन व्यवस्था लागू की जाये । प्रत्येक बालिग को मतदान का अधिकार दिया जाये और शेख मुजीबुर्रहमान भुट्टो, अब्दुल समद और वली खा सहित सभी राजनीतिक कैदियों को तुरन्त मुक्त कर दिया जाये ।

अयूब खा ने अब भी कुछ नहीं सीखा था । ३० दिसम्बर १९६८ को सरकारी मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं की बैठक मे भाषण देते हुए उन्होने कहा

“मेरे विरोधी जनता, पाकिस्तान और इस्लाम के शत्रु है । मैं उनके जलूसो से भयभीत होने वाला नहीं । यह लोग मेरी सरकार का तख्ता उलट देने मे सफल नहीं होंगे । मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हू कि वर्तमान शासन प्रणाली को तोड़ने से समस्त देश मे गृहयुद्ध शुरू हो जायेगा और जगह-जगह लहू की नदिया बहने लग जायेगी ।”

ढाका के विद्यार्थियों ने एक सघर्ष समिति बनाई और दूसरे विरोधी दलों के आन्दोलन मे भाग लेने की घोषणा की । समिति ने २१ मागो का चार्टर तैयार किया । इसमे कहा गया कि केन्द्र मे ऐसी सरकार स्थापित की जाये जिसके पास केवल सुरक्षा और करसी के अधिकार हो । बाकी सभी अधिकार प्रान्तीय सरकारो को दे दिये जाये । बिलोचिस्तान, सिंध और सीमा प्रान्त की एक सब-फ़ैडरेशन बना करके केन्द्र से उसका सम्बन्ध स्थापित किया जाये और पाकिस्तान पश्चिम के सभी सैनिक गुट्टो से अलग हो जाये ।

जनवरी मे ढाका मे कई बार गोली चली परन्तु आन्दोलन की गति तीव्र होती गई । जनता का साहस बढ़ता ही गया । विरोधी दलों ने घोषणा की कि ११ फरवरी से मागो स्वीकार कराने के लिये सघर्ष शुरू कर दिया जाये ।

३० जनवरी को मेजर जनरल जेलानी ने सघर्ष में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी ।

अयूब खा अब भी समझ रहे थे कि जनता को दबाया जा सकता है । उनके एक एजेन्ट मिर्जा शमसी ने गोहर अयूब के कहने पर कराची में एक जनसमूह पर गोली चला दी । जनसमूह ने क्रोध में आकर अयूब के समर्थकों की पाच सौ से अधिक दुकानें और १०० से अधिक मकान जला दिये । सेना और पुलिस को बुलाया गया । ७०० से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया । अयूब के विरोधियों ने इसके जवाब में अयूब के दो समर्थकों को जिन्दा जला दिया ।

अयूब ने अब हवा का रुख बदलने के लिये एक और चाल चली । उसने भारत को काश्मीर के प्रश्न पर धमकिया देना शुरू कर दिया और कहा कि यदि भारत सरकार सीधे हाथों समस्या का समाधान नहीं करेगी तो पाकिस्तान दूसरे तरीकों का प्रयोग करेगा । इसके साथ ही अयूब सरकार ने किराये के कुछ सशस्त्र मित्रों गद्दारों से भारत की सीमा-वर्ती चौकियों पर हमला करा दिया परन्तु आक्रमणकारियों को मुहंकी खानी पड़ी । अयूब खा जनता का ध्यान अपने आन्दोलन से हटाने में सफल न हुए । लाहौर, कराची, रावलपिण्डी और लायलपुर में आन्दोलन चलाने वालों ने सरकारी जायदादों पर हमले करना जारी रखा । लाहौर में पुलिस के एक आई० जी० को जनसमूह ने पकड़ कर नगा कर दिया और प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करने के लिये मजबूर कर दिया ।

स्थिति काबू से बाहर होते देख कर अयूब खा ने रेडियो पर भाषण देते हुए घोषणा की कि वह जनता के हित के लिये राजनीतिक नेताओं से बातचीत करने के लिये तैयार है । परन्तु वह केवल “जिम्मेदार विरोधी दलों” से बातचीत करेंगे और कोई ऐसा सुझाव स्वीकार नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान की एकता को क्षति पहुँचे ।

विरोधी दलों ने यह पेशकश अस्वीकार कर दी और अपना आन्दोलन

जारी रखने की घोषणा कर दी ।

अयूब खा सरकारी मुस्लिम लीग की कार्यकारिणी समिति के अधिवेशन में भाग लेने के लिए ढाका पहुँचे । सारे शहर ने हडताल की और राज भवन के सामने प्रदर्शन किया । ढाका से ६० मील दक्षिण पूर्व में थागिल में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी कार्यालयों पर हमला करके आग लगा दी ।

अयूब खा ने लाहौर में डेमोक्रेटिक एक्शन कमेटी के नेताओं से बात-चीत शुरू की । उन्होंने कहा कि वली खा और भुट्टो को रिहा करने के लिए तैयार हूँ परन्तु शेख मुजीबुर्रहमान को रिहा नहीं किया जा सकता । अधिक से अधिक यही किया जा सकता है कि उन्हें बातचीत में भाग लेने का अवसर देने के लिए पैंरोल पर कुछ दिन के लिए रिहा कर दिया जायेगा । पश्चिम और पूर्व में फूट डालने के लिये यह एक गहरी चाल थी । इसलिए विरोधी दलों ने उनकी पेशकश ठुकरा दी ।

इस सम्बन्ध में यह महत्वपूर्ण बात है कि जिस समय अयूब खा विरोधी दलों के नेताओं से यह बात-चीत कर रहे थे, वह और उनके साथ जनरल अपने कुछ पिटू नेता मित्रों से गुप्त रूप में साजबाज कर रहे थे । जमायत इस्लाम के नेता इस साजबाज में भाग ले रहे थे । सैनिक अधिकारी सैनिक शासन लागू करने और अयूब खा की शासन सत्ता को बचाने के लिए तैयारियाँ कर रहे थे । सैनिक शासन लागू करने की तारीख तै हो चुकी थी और सैनिक अध्यादेश छप कर मिल गये थे परन्तु एकाएक पूर्वी बंगाल की खतरनाक स्थिति के कारण सेना ने अपना फैसला स्थगित कर दिया । अयूब खा के भूतपूर्व कानून मंत्री श्री मुहम्मद मुनीर ने “पाकिस्तान टाइम्स” में एक लेख में धमकी दी कि पाकिस्तान में गृहयुद्ध का खतरा है और यदि हालत में परिवर्तन न हुआ तो गृह-युद्ध के खतरे पर काबू पाने के लिए सेना को हस्तक्षेप करना पड़ेगा । उन्होंने लिखा कि “नेशनल असेम्बली” को एक वर्ष और काम करने दिया

जाये और उसे ही नया विधान तैयार करने के लिये कहा जाये। उस समय तक अयूब खा ही राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त रहे।

अयूब शाही के विरुद्ध आन्दोलन और भी तेज होता गया। ढाका में १२००० स्त्रियों ने एक भव्य प्रदर्शन किया। अयूब का प्रोपेगैंडा करने वाले दो समाचार पत्रों “मॉनिंग न्यूज” और “पाकिस्तान” के कार्यालय जला दिये गये। रावलपिण्डी और लाहौर में भी इसी प्रकार “दैनिक कोहिस्तान” के कार्यालय जला दिये। इस समाचार पत्र के मालिक नवाब होती थे। बदलती हुई स्थिति से भयभीत होकर सभी दूसरे पत्रों ने अयूब खा के विरोध में प्रोपेगैंडा शुरू कर दिया।

१५ फरवरी को एक बगाली सैनिक जहुरलहक, जिसे शेख मुजीब के साथ गिरफ्तार किया गया था, गोलियों से आये हुए घावों के कारण मर गया। ढाका में यह अफवाह फैल गई कि अधिकारियों ने उसकी हत्या की है। सारे शहर में हड़ताल हो गई। हजारों विद्यार्थियों ने पुलिस चौकियों पर हमला कर दिया। मौलाना भापानी ने १६ फरवरी को एक शोक सभा का आयोजन किया। उन्होंने बड़ा प्रभावशाली भाषण दिया और अन्त में कहा बगला जागो! अगन लागो! अर्थात् “बगालियों जागो और आग लगा दो।”

कुछ ही क्षणों में क्रोध से बिफरे हुए लोगो ने सरकारी जायदादों और अयूब खा के समर्थकों के भकानों को जलाना शुरू कर दिया। सरकारी मुस्लिम लीग की लाखों रुपये से निर्माण की हुई इमारत जलकर राख हो गई। प्रान्तीय मंत्री नवाब हसन अस्करी और केन्द्रीय सूचना और प्रसार मंत्री श्री शहाबुद्दीन की कोठियों को भी जला दिया गया। सेना को स्थिति पर काबू पाने के लिये बुलाया गया। दूसरे ही दिन असाधारण स्थिति का कानून हटा लिया गया और भुट्टो, वली खा और अब्दुल समद खा और दूसरे राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया। १८ फरवरी को राजशाही विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर को

एक प्रदर्शन में एक सिपाही ने गोली मार दी। इससे स्थिति फिर बिगड़ गई। हजारों विद्यार्थियों, कर्मचारियों, मिल मजदूरों और अन्य लोगों ने रोष प्रकट करने के लिये जलूस निकाला। उन्होंने सेना के विरुद्ध नारे लगाये। लोगों में इतना जोश था कि कई जगह सेना शस्त्र छोड़ कर भाग गई। यह एक खुला विद्रोह था। रेल के कर्मचारियों ने सेना की गतिविधियों में रुकावट डालने के लिये रेल की पटरियाँ उखाड़ दी। उनमें से कई एक को सेना ने गोलियों का निशाना बना दिया। लगता था जैसे समस्त ढाका रणभूमि बन गया हो। इनसानी लहू जगह-जगह बह रहा था और सेना खुलकर कतले-आम कर रही थी। निहत्थे कर्मचारी और भुग्गी-भोपड़ियों में रहने वाले बिना किसी नेता के मुकाबला कर रहे थे। कुछ पत्रकारों ने बड़ी मुश्किल से छुप-छिपाकर दौरा किया। उन्होंने देखा कि सेना के सिपाही किसानों और मजदूरों के शव सड़कों और गलियों से उठा-उठाकर फौजी गाड़ियों में डालकर ले जा रहे थे और लहू को धो-धोकर सड़कों और गलियों को रात के अंधेरे में साफ किया जा रहा था ताकि इस नरसंहार का कोई चिन्ह रहने न पाये। एक सूचना के अनुसार उस रात एक हजार से अधिक व्यक्तियों को सेना ने गोलियों से भून दिया था।

यदि कोई सगठित इकलाबी संस्था होती तो उसके लिये शासन सत्ता पर अधिकार करके स्वतंत्रता-संग्राम शुरू कर देने का यह उचित समय था। परन्तु मौलाना भाषानी सहित सभी नेताओं ने कभी इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार नहीं किया था। यद्यपि वह अपने आपको इकलाबी नेता कहते थे और जनता को कहा करते थे कि वह जालिमों के विरुद्ध विद्रोह कर दें परन्तु उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि आज के ससार में जहाँ शासकों को ससदीय प्रजातंत्र शासन प्रणाली पर विश्वास नहीं, शस्त्रों का प्रयोग किये बिना स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। पूर्वी बंगाल में सैनिक शासन की मशीनरी टूट चुकी

थी। जनता विद्रोह के लिये उठ खड़ी हुई थी और सेना के लिये प्रान्त पर कन्ट्रोल करना मुश्किल हो रहा था परन्तु नेताओं को पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करने और जनता को सशस्त्र युद्ध के लिये संगठित करने के लिये साहस नहीं था।

कहा जाता है कि स्थिति बिगड़ती देख कर ढाका छावनी के कमाण्डर ने इस्लामाबाद में प्रधान सेनापति को अपनी रिपोर्ट भेजी। अयूब खा ने स्थल, वायु और जल सेना के कमाण्डरों को बुलाया और यह इच्छा प्रकट की कि समस्त देश में सैनिक शासन स्थापित किया जाये। परन्तु कहा जाता है कि जनरल याहिया खा ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि

“मुझे ढाका में अपने सूत्रों से रिपोर्ट मिली है कि यदि मार्शल ला लागू किया गया तो ढाका पर तो कन्ट्रोल किया जा सकता है परन्तु बाकी के देश के सम्बन्ध में कोई आश्वासन नहीं दिलाया जा सकता। मेरे अफसरों ने मुझे बताया है कि वह देश की रक्षा के लिये मार्शल ला लागू करने के विरुद्ध नहीं परन्तु यह मार्शल ला आपके (अयूब खा के) बिना ही होगा।”

कहा जाता है कि याहिया खा ने अयूब खा को परामर्श दिया कि वह डेमोक्रेटिक एक्शन कमिटी की मांगे स्वीकार करके राजनीति से अपने आपको अलग कर ले।

यह सभी बातें कहा तक सत्य हैं? इनके सम्बन्ध में पूरे विश्वास से कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता यह बात स्पष्ट थी कि स्थिति गम्भीर हो चुकी थी। ऐसे समय जब पश्चिमी पाकिस्तान में भी विद्रोह हो रहा था, सेना के लिये पूर्वी बंगाल पर शक्ति के प्रयोग से काबू पाना मुश्किल था। ऐसा मालूम होता था कि अयूब खा के सैनिक अफसर विशेषतया याहिया खा आदि इस अवसर से स्वयं फायदा उठाना चाहते थे। अयूब खा इतने बदनाम हो चुके थे कि सेना उनका साथ देकर अपने

आप को जनता की विरोधी बनना नहीं चाहती थी। उधर अयूब खा भी समझ चुके थे कि भुके बिना काम नहीं चल सकता। वह विरोधी दलो में फूट डालने की एक और कोशिश करने के लिये तैयारियां करने लगे। वह यह समझ रहे थे कि कुछ भुक कर दोनों प्रान्तों में अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाई जा सकती है और शायद वह यह भी सोच रहे थे कि धीरे-धीरे स्थिति पर काबू पाकर सेना में भी अपने गुट को मजबूत किया जा सकता है।

रेडियो पर एक सदेश प्रसारित करते हुए अयूब खा ने कहा कि मैं कुछ परिवर्तन करके पूर्वी बंगाल को देश के शासन में अधिक भाग देने के लिये तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि पूर्वी बंगाल के लोगो को शिकायत है कि उन्हें पश्चिमी पाकिस्तान के लोगो की तरह सरकार में पूरा भाग नहीं मिल रहा। मैं बदलती हुई स्थितियों और नई आवश्यकताओं के अनुसार विधान में परिवर्तन के लिये भी तैयार हूँ। पूर्वी बंगाल में किसी ने भी इस बयान का स्वागत नहीं किया। दूसरी ओर उनके अपने दल के ३७ सदस्यों ने एक वक्तव्य में पूर्वी बंगाल के राज्यपाल अब्दुल मुनहम खा को नर-संहार के लिये दोषी ठहराया।

पूर्वी बंगाल से हिंसात्मक प्रदर्शनों के समाचार अब भी आ रहे थे। खुलना में पुलिस से एक झड़प में १० व्यक्ति मारे गये। पूर्वी बंगाल के विद्यार्थियों की संघर्ष समिति ने प्रान्तीय और केन्द्रीय विधान सभाओं और बेसिक कमेटियों के सदस्यों को आदेश दिया कि वह सदस्यता से त्यागपत्र दे दें। क्रोध में आये हुए एक जनसमूह ने मरामारा की बेसिक कमेटी के अध्यक्ष को उसके निवास-स्थान के सामने मार डाला। खुलना में ३० हजार व्यक्तियों ने हमला कर केन्द्रीय मंत्री सब्बूर खान की कोठी को जला दिया। पुलिस ने गोली चलाकर तीन व्यक्तियों की हत्या कर दी। जनसमूह ने एक पुलिस कर्मचारी को इतना पीटा कि उसकी हत्या हो गई। ढाका में अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के कार्यालय

और जापानी एयरलाइस के कार्यालय को तोड़फोड़ दिया गया। ढाका और दूसरे नगरों में सिविल सरकार का ढाँचा टूट गया। इस स्थिति से भयभीत होकर अयूब खा ने ११ फरवरी को घोषणा की कि मैं इस वर्ष के अन्त में होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा नहीं होगा। उन्होंने कहा

“मेरा फैसला अटूट है। पाकिस्तान इस समय अत्यन्त नाजुक स्थिति में गुजर रहा है। पागलपन की-सी हालत में हो रही है। मैं इस बात को सहन नहीं कर सकता कि पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में पड़ जाये। कुछ लोग वर्तमान शासन प्रणाली में असन्तुष्ट हैं। वह सीधे तौर पर बालिगों को मतदान का अधिकार देने की बुनियाद पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कराना चाहते हैं। मैं यह भी महसूस करता हूँ कि पढ़े-लिखे लोगों को शिकायत है कि उन्हें शासन में पूरा भाग नहीं मिल रहा। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि विधान सभाओं को काफी अधिकार प्राप्त नहीं। जनता की शिकायतें दूर करने के लिये मैंने विरोधी दलों के प्रतिनिधियों और स्वतंत्र नेताओं का सम्मेलन बुलाया है। इस गम्भीर स्थिति में हमारा कर्तव्य है कि राजनीतिक संकट का हल ढूँढें। मैं सभी रुकावटों को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे राजनीतिक दल और नेता बातचीत में भाग ले सकें।”

दूसरे दिन अयूब खा ने शेख मुजीबुर्रहमान और उनके साथियों को रिहा करके उनके विरुद्ध षड्यंत्र का केस वापस ले लिया। बाद में बिलोच नेताओं और जी० एम० सैय्यद को भी रिहा कर दिया गया।

क्या यह परिवर्तन लाने के लिये सेना के नेताओं ने दबाव डाला था? एक सैनिक प्रवक्ता ने अमरीका के दैनिक समाचार पत्र “वॉशिंगटन पोस्ट” के सवादादाता को बताया कि सेना के तीनों उच्च जरनलों ने अयूब खा को कहा था कि वह यह कार्यवाही करे नहीं तो सेना उनका

तख्ता उलट देगी।

कहना मुश्किल है कि श्री भुट्टो और मौलाना भाषानी ने इस पर भी सम्मेलन का बायकाट करने की घोषणा क्यों की और जमायत ईस्लामी हिमात्मक गतिविधियों में क्यों लगी हुई थी? दोनों ने एक ओर तो अयूब खा के तुरन्त त्यागपत्र की माग की और दूसरी ओर भुट्टो ने भारत के विरुद्ध उत्तेजनाजनक प्रोपेगंडा शुरू कर दिया। ११ फरवरी को भुट्टो ने एक वक्तव्य में कहा कि मैं भारत के “आक्रमणों” का मुकाबला करने के लिये जनता की सेना का संगठन करूंगा। श्री भुट्टो इस प्रकार बातें कर रहे थे मानो वह अयूब खा की जगह राष्ट्रपति बनने वाले हैं। उन्होंने कहा कि “मेरी सरकार काश्मीर को स्वतंत्र करायेगी और काश्मीर के लिये ‘मेरी जिहाद’ में पूर्वी बंगाल का समर्थन प्राप्त करने के लिये ‘मेरी सरकार’ फरक्का बाध का प्रश्न उठायेगी।” मौलाना भाषानी ने कहा कि “हम असम को स्वतंत्र कराके उसे पाकिस्तान का अंग बनायेगे।”

ऐसा मालूम होता है कि भुट्टो और भाषानी समझौते की बातचीत को विफल बनाने के लिये यह स्टैट-बाजी कर रहे थे। अथवा उन्हें विश्वास हो रहा था कि अयूब शाही का पतन होने वाला है और वह माओ त्से-तुंग की लाइन पर पाकिस्तान की सरकार स्थापित करने में सफल हो जायेगे। शायद सैनिक नेता चाहते थे कि स्थिति और भी बिगड़े जिससे फायदा उठाकर वह जनता को मूर्ख बनाकर अपना शासन कायम कर ले। इस सम्बन्ध से एक महत्वपूर्ण घटना यह है कि रेडियो पाकिस्तान विद्रोह के समाचार अधिक से अधिक प्रसारित कर रहा था।

पूर्वी बंगाल में विद्यार्थियों की सघर्ष समिति ने अल्टीमेटम दिया कि यदि बंगाली सदस्यों ने ३ मार्च तक नेशनल असेम्बली, प्रान्तीय विधान सभा और जिला और नगर समितियों से त्यागपत्र न दिया तो उन्हें इसका परिणाम भुगतने के लिये तैयार रहना चाहिये। इस धमकी

के साथ ही मन्त्रिमण्डल के सदस्यों, जिला अधिकारियों और दूसरे सरकारी अफसरों पर हमले होने लगे। एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने लिखा कि इस अल्टीमेटम से अयूब के समर्थकों को जान के लाले पड़ गये हैं। १६ सप्ताह के विद्रोह में नये परिवर्तन का पहले यह उदाहरण मिला कि कुश्तिया में बेसिक डेमोक्रेसी कौंसिल के अध्यक्ष को एक जन-समूह ने पकड़ कर पीट-पीटकर जान से मार दिया। पांच मंत्रियों की कोठिया जला दी गईं। इसका परिणाम यह हुआ है कि त्यागपत्रों का सिलसिला शुरू हो गया।

इसी समाचार पत्र ने लिखा कि “पुलिस की चौकियों और छोटे-छोटे रेलवे स्टेशनों पर हमले हो रहे हैं, बदनाम अधिकारियों की हत्या की जा रही है। अयूब खा और पश्चिमी पाकिस्तान के विरोधी नेताओं के लिये खतरनाक स्थिति बंगाली विद्यार्थियों की इस मांग से पैदा हो गई है कि पूर्वी बंगाली को पूर्ण रूप से स्वतन्त्रता दे दी जाये।”

१६ फरवरी को अत्यंत गम्भीर स्थिति में गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ। शेख मुजीबुर्रहमान, एयर मार्शल असगर खान, खान बली खा और डेमोक्रेटिक एक्शन कमेटी के अन्य सदस्य सम्मेलन में सम्मिलित हुए परन्तु भुट्टो और भाषानी ने बातचीत में भाग लेने से इन्कार कर दिया। दोनों ने मांग की कि अयूब खा तुरन्त त्यागपत्र दे दे। भाषानी ने कहा कि यदि विद्यार्थियों की सघर्ष समिति की सभी मांगें स्वीकार न की गईं तो समस्त देश में सत्याग्रह आन्दोलन शुरू कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि पूर्वी बंगाल को आन्तरिक स्वतन्त्रता दी जाये, सभी कारखानों को सरकारी मिलकियत में ले लिया जाये और पश्चिम के सभी सैनिक गुट्टो से पाकिस्तान को अलग कर लिया जाये।

अयूब खा को शायद अब विश्वास हो गया था कि उनकी तानाशाही कायम नहीं रह सकती। सेना के नेता चाहे कुछ भी स्वीकार कर लें परन्तु वह न तो पूर्वी बंगाल को किसी भी रूप में स्वतन्त्रता देने के हक

मे थे न ही वह यह सहन कर सकते थे कि पाकिस्तान में किसी भी रूप में समाजवाद लागू हो जाये। अपने तौर पर वह प्रसन्न थे कि भुट्टो और भाषानी स्थिति को खराब करके शेख मुजीब और दूसरे नर्मदलो के नेताओं के हाथ कमजोर कर रहे हैं।

अयूब खा के समर्थकों और जमायत इस्लामी के नेताओं ने भुट्टो और भाषानी के समर्थकों पर हमले शुरू कर दिये। मौलाना मौदूदी और मौलाना एतशामुल हक ने जगह-जगह उत्तेजनात्मक भाषण देते हुए कहा कि इस्लाम के शत्रु विदेशों से रुपया लेकर पाकिस्तान में इस्लाम का सफाया करना चाहते हैं। जनता इनकी गतिविधियों को सहन नहीं करेगी बल्कि हर कीमत पर पाकिस्तान की रक्षा करेगी। ४ मार्च को जमायत इस्लामी के समर्थकों ने लायलपुर में भुट्टो के समर्थकों के जलूस पर हमला किया। रावलपिण्डी में अयूब खा के समर्थकों ने एक जलूस निकाल कर समाजवाद के विरोध में नारे लगाये। एक सशस्त्र टोडी ने सरकारी लीग के नेता राजा अल्लादाद खा के नेतृत्व में अयूब के विरोधियों पर हमला किया। नवाब शाह में भुट्टो और मौदूदी के समर्थकों में जम कर लड़ाई हुई। बहावलपुर में ६ मार्च को भुट्टो के आगमन पर जमायत इस्लामी के कार्यकर्ताओं ने भुट्टो के दल के कार्यालय और साम्यवादियों के एक बुकस्टाल को आग लगा दी।

लाहौर में दोनों दलों के समर्थकों में कई झड़पें हुईं। ९ मार्च को लाहौर में भाषानी के जलसे पर जमायत इस्लामी के युवकों ने पत्थर फेंके। इसका बदला लेने के लिये भाषानी के समर्थकों ने जमायत इस्लामी के कार्यालय पर हमला करके उसे आग लगा दी। जमायत इस्लामी के अध्यक्ष मौलाना मौदूदी ने एक बयान में आरोप लगाया कि भाषानी के समर्थकों ने कुरान शरीफ को जला कर इस्लाम का अपमान किया है। समाचार पत्रों ने कुरान के जले हुए पन्नों के फोटो प्रकाशित

किये। मौलाना मौदूदी ने घोषणा की कि समस्त देश में भाषानी की इस हरकत की निन्दा के लिये सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया जायेगा। भाषानी ने इसके उत्तर में आरोप लगाया कि जमायत इस्लामी के नेता सरकार से रुपया लेकर पाकिस्तान में इण्डोनेशिया की तरह खून-खराबा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं हिंसात्मक कार्यवाइयों से भयभीत होने वाला नहीं। मैं गृहयुद्ध के लिये तैयार हूँ और हिंसा का मुकाबला हिंसा से करने के सिद्धान्त में विश्वास रखता हूँ।

दूसरे दिन जमायत इस्लामी के कार्यकर्ताओं ने मुलतान में भुट्टो की पार्टी के कार्यालय पर हमला कर दिया और नेशनल अवामी पार्टी के मंत्री की दुकान को आग लगा दी। १० मार्च को मैमन सिंह (पूर्वी बंगाल) के जिला अफसर ने बताया कि जमालपुर में एक जनसमूह ने २१ व्यक्तियों को जिन्दा जला दिया है। लाहौर के समाचार पत्र “दैनिक निवाये वक्त” ने लिखा कि १२ मार्च को भाषानी के समर्थकों ने राजशाही में ४०८ मकानों को जला दिया है। इसी पत्र ने १६ मार्च को लिखा कि प्रभातीपुर में १००० से अधिक मकानों को जला दिया गया है और दो सौ से अधिक व्यक्ति भाषानी और मौदूदी के समर्थकों की भड़पो में घायल हो गये हैं।

१८ मार्च को ढाका में पूर्वी पाकिस्तान के राज्यपाल मुनहम खा की कोठी पर हमला हुआ। एक हिन्दू कर्मचारी ने उसकी रक्षा की। १६ मार्च को जब राज्यपाल विमान पर कराची पहुँचा तो वह सिर और पाव से नगा था।

११ मार्च को एयर मार्शल असगर खाने एक बयान में आरोप लगाया कि सरकार के दलाल गोलमेज सम्मेलन को विफल बनाने के लिये जगह-जगह फसाद करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शासक दल के किराये के गुण्डे उपद्रव मचाने पर तुले हुए हैं। बड़े-बड़े पूजीपतियों से लाखों रुपया प्राप्त करके फसाद कराने के लिये प्रयोग में लाया जा रहा

है। देहात से गुण्डे भरती करके शहरो मे फसाद कराने के लिये लाये जा रहे हे।

इस दौरान मे कराची, लायलपुर, लाहौर आदि शहरो मे कार-खानो मे हडताले होने लगी। हडतालियो ने कई स्थानो पर कपडा-मिलो को लूट लिया। कराची मे डाक और तारघर मे हडताल हो गई। जमालपुर मे वामपथियो ने चार व्यक्तियो को टुकडे-टुकडे कर दिया। लाहौर के समाचार पत्रो ने लिखा कि वामपथी पूर्वी पाकिस्तान मे “जनता की अदालते” स्थापित करके स्मगलिंग के आरोप मे लोगो को फासी पर लटका रहे है। कई सरकारी अधिकारियो को पत्थर मार-मार कर मौत के घाट उतार दिया गया।

८ मार्च को एक अमरीकी समाचार एजेसी ने लिखा कि पूर्वी बंगाल मे गृहयुद्ध की-सी स्थिति पैदा हो रही है। विद्यार्थियो की सघर्ष समिति सरकारी कर्मचारियो पर दबाव डाल रही है कि वह त्याग-पत्र देकर सघर्ष मे सम्मिलित हो जाये।

१० मार्च को गोलमेज सम्मेलन आरम्भ होने से पहले सभी विरोधी दलो मे इस बात पर समझौता हो गया था कि पश्चिमी पाकि-स्तान का एक यूनिट भग करके पाच प्रान्त बना दिये जाये। बी० बी० सी० ने एक प्रसारण मे कहा कि यह शेख मुजीबुर्रहमान की अवामी लीग की शानदार विजय है। परन्तु भाषानी और भुट्टो ने पुन घोषणा की कि वह सम्मेलन मे भाग नही लेगे। दोनो ने माग की कि अयूब खा तुरन्त त्यागपत्र दे दे परन्तु खा वली खा, जी० एम० सैय्यद और सयुक्त एक्शन कमेटी के सयोजक नवाबजादा नसरुल्ला खा ने कहा कि आगामी चुनाव तक के लिये जो अन्तरिम सरकार बनाई जाये अयूब खा उसके राष्ट्रपति बने रहे।

पाकिस्तान के दोनो भागो मे अब भी उपद्रव हो रहे थे। लाहौर मे विद्यार्थियो ने अमरीका के सूचना कार्यालय को आग लगा दी।

कराची में जमायत इस्लामी के समर्थकों ने सरकारी समाचार एजेंसी के कार्यालय को आग लगा दी। पूर्वी बंगाल में एक व्यक्ति को एक पेड़ से बांध कर ज़िन्दा जला दिया गया।

गोलमेज सम्मेलन में अयूब खान ने विरोधी दलों की यह मांग स्वीकार कर ली कि सभी बालिगों को मतदान का अधिकार दिया जाये और सदन का सीधा चुनाव हो। परन्तु उन्होंने न तो चुनाव के लिये कोई तारीख निश्चित की, ना ही प्रान्तों के अधिकारों का उल्लेख किया। उन्होंने इन समस्याओं पर केवल यही कहा कि इस समय स्थिति गम्भीर है इसलिये जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते हमें खामोशी से प्रतीक्षा करनी चाहिये नहीं तो पाकिस्तान कमजोर हो जायेगा। इस भाषण से कोई भी सन्तुष्ट नहीं हुआ। जो लोग समझ रहे थे कि जनता की, विशेषतया पूर्वी बंगाल की मांगें सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर ली जायेंगी उन्हें मायूसी हुई। शेख मुजीबुर्रहमान ने घोषणा की कि उनकी अवामी लीग डेमोक्रेटिक एक्शन कमेटी से अलग होकर जनता की मांगें स्वीकार कराने के लिये आन्दोलन जारी रखेगी। पूर्वी बंगाल से आये हुए उनके साथियों श्री नूरुलअमीन और भूतपूर्व जज श्री मुरशिद हुसेन ने कहा कि अयूब खान ने एक हाथ से जो कुछ दिया है वह दूसरे हाथ से छीन लिया है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में प्रान्तों की आन्तरिक स्वतन्त्रता की समस्या का समाधान होता चाहिये था। नेशनल अवामी दल के अध्यक्ष खान बली खान ने दो बुनियादी मांगें स्वीकार किये जाने का स्वागत किया परन्तु ; कहा कि प्रान्तीय स्वतन्त्रता और पश्चिमी पाकिस्तान के एक यूनिट को भग करने की मांग को खटाई में डाल देने से घृणा बढ़ेगी और स्थिति और भी खराब होगी।

जमायत इस्लामी के नेता मौलाना मौदूदी और विरोधी मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मिया मुमताज दौलताना ने अयूब खान की प्रशंसा की।

१५ मार्च को रेडियो आस्ट्रेलिया ने ढाका के एक सरकारी अधि-

कारी के बयान का हवाला देते हुए बताया कि पूर्वी बगाल में बड़े पैमाने पर गडबड हो रही है। विभिन्न इलाकों में २० हजार मकान जलाये जा चुके हैं और २६७ व्यक्तियों को जिनमें अयूब खा के समर्थक भी सम्मिलित हैं मौत के घाट उतार दिया गया है। मदारीपुर में एक उत्तेजित जनसमूह ने आठ व्यक्तियों को पत्थर मार-मार कर मार दिया और इसके बाद उनके शव जलते हुए मकानों में फेंक दिये। दो और व्यक्तियों की गर्दन काट दी गई। जमालपुर में २२२ और मानिकगज में २२५ मकान जला दिये गये। ढाका से आने वाले लोगों का कहना है कि एक विद्यार्थी नेता श्री अहमद एक प्रकार से राज्यपाल बना हुआ है।

पश्चिमी पाकिस्तान में जमायत इस्लामी के कार्यकर्ता वामपथियों को कुचल देने के लिये हमले कर रहे थे। पिशावर में उन्होंने भापानी और भुट्टो के समर्थकों और उनके मकानों पर हमले किये। एक सार्वजनिक सभा में पिस्तौलों से गोलियां चलाई गईं। कराची में जमायत इस्लामी के तीन हजार समर्थकों ने भुट्टो और भापानी को इस्लाम के शत्रु ठहराते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाये। मौलाना मौदूदी ने एक सार्वजनिक सभा में भाषण देते हुए धमकी दी कि “जो जुवान समाजवाद का समर्थन करेगा उसे काट दिया जायेगा।” उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दिया कि वह वामपथियों को किसी भी मुहल्ले में रहने न दें।

इस बात में कोई सन्देह नहीं कि जमायत इस्लामी ने अयूब खा और दूसरे सैनिक अधिकारियों से गठजोड़ कर रखा था। बटे-बड़े पूजीपति भी उसकी सहायता कर रहे थे क्योंकि पूजीपतियों को इस बात का भय था कि यदि वामपथी सरकार पर अधिकार करने में सफल हो गये तो उनके कारखानों पर सरकार अधिकार कर लेगी। इसलिये वह इस्लाम का नाम लेकर उनका विरोध कर रहे थे। कई भूतपूर्व सैनिक अधिकारी जमायत इस्लामी में सम्मिलित हो

गये थे ।

श्री भुट्टो यह समझ रहे थे कि पुराने वामपथियो, युवको, विद्यार्थियो और किसानो का समर्थन प्राप्त करके ही अपने हाथ मजबूत किये जा सकते हे । इसलिये वह समाजवाद के समर्थक होने का दावा कर रहे थे, हालांकि भुट्टो ने अपने दल मे बडे-बडे जमीदारो को मिला रखा था । मौलाना भाषानी एक ओर जमायत इस्लाम का विरोध कर रहे थे तो दूसरी ओर शेख मुजीबुर्रहमान के हाथ भी कमजोर करना चाहते थे । उग्रवाद का मार्ग अपना कर वह हिंसात्मक कार्यों के लिये जनता को उत्तेजित कर रहे थे । उनका कहना था कि बातचीत से कोई लाभ नही होगा । लडकर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है । मजे की बात यह है कि सैनिक तानाशाही उनके विरुद्ध कोई कार्यवाई नही करना चाहती थी । बल्कि उसकी इच्छा थी कि स्थिति और भी बिगडे, जिससे पाकिस्तान की रक्षा के नाम पर सेना को हस्तक्षेप करने का अवसर मिल जाये ।

आवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर्रहमान ढाका मे पहुचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया । एक विशाल सार्वजनिक सभा मे भाषण देते हुए उन्होने मौलाना भाषानी की कडी आलोचना की और कहा कि मौलाना ८६ वर्ष के हो चुके है । उन्हें अब राजनीतिक जीवन से रियाटर हो जाना चाहिए । शेख साहिब ने कहा कि

“नेशनल असेम्बली मे मेरे दल के सदस्य ससदीय शासन प्रणाली और सभी बालिगो को मतदान का अधिकार दिये जाने के अयूब खा के सुझाव का समर्थन करेगे । वह अपने दल की ६ भागो के अनुसार विधान मे सशोधन का बिल भी पेश करेगे । यदि डेमोक्रेटिक एक्शन कमेटी ने गोलमेज सम्मेलन मे मेरे दल की मागो का समर्थन किया होता तो अयूब खा को भुकना पडता । हम अपनी मागो के लिये शान्तिमय आन्दोलन जारी रखेगे ।”

१६ मार्च को लाहौर के समाचार पत्र “दैनिक निवाह वक्त” ने यह समाचार प्रकाशित किया कि रावलपिण्डी से ४० किलोमीटर की दूरी पर साहीवाल के रेलवे स्टेशन पर जमायत इस्लामी के कार्यकर्ताओं ने मौलाना भाषानी की हत्या की कोशिश की है। भाषानी के समर्थकों ने “मौलाना मौदूदी की हत्या करो” के नारे लगाये। भाषानी ने एक जलसे में कहा कि ब्रिटेन और अमरीका पाकिस्तानी जनता के शत्रु और शासकों के मित्र है। पाकिस्तान के असली मित्र चीन, इण्डोनेशिया, ईरान, तुर्की और जोर्डन है, जिन्होंने १९६५ में भारत के विरुद्ध पाकिस्तान की सहायता की थी। विदेशी एजेंटों ने पूर्वी पाकिस्तान में हमारे ७०० कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी है परन्तु यदि गुलामी के बंधन तोड़ देने के लिये हमें २० लाख व्यक्तियों की कुर्बानी देनी पड़े तो भी हम पीछे हटने वाले नहीं।

कारखानों में काम करने वाले अपनी मांगों के लिये आन्दोलन कर रहे थे। उनकी यूनियनों ने घोषणा की कि १९ मार्च से पश्चिमी पाकिस्तान की सभी मिलों में हड़ताल की जायगी। पूर्वी बंगाल में विद्यार्थी संघर्ष समिति ने इसी तरह अपनी मांगें स्वीकार कराने के लिये हड़ताल करने की घोषणा की।

अयूब खा ने मार्च के तीसरे सप्ताह जनरल मूसा को हटा कर सिंध के प्रमुख मिल मालिक सेठ यूसुफ हाख को पश्चिमी पाकिस्तान का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। इसी तरह एक और पुराने टोडी एम० एन० हुदा को पूर्वी बंगाल का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया।

अयूब खा यह जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे कि वह असैनिक सरकार स्थापित करने के लिये मैदान तैयार कर रहे हैं, परन्तु इसी दिन भारतीय समाचार एजेंसी पी० टी० आई० ने सूचना दी कि पूर्वी पाकिस्तान से बंगाल में घडाघड सेनायें जनता को कुचलने के लिये भेजी जा रही हैं।

रेडियो पाकिस्तान ने २८ मार्च को एक प्रसारण में कहा कि पूर्वी बंगाल में गड़बड़ से आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है।

मौलाना भाषानी ने ढाका में एक जलसे में कहा कि

“अमरीका पाकिस्तान में जनता के आन्दोलन को विफल करने के लिये अपने किराये के टट्टुओं पर ७ करोड़ रुपया प्रति मास खर्च कर रहा है। मेरे पास इस आरोप के लिये ठोस प्रमाण है।”

अमरीकी दूतावास ने इस आरोप का खंडन किया। २४ मार्च को अमरीकी सरकार ने पूर्वी बंगाल में रहने वाले अमरीकी नागरिकों को आदेश दिया कि वह खतरे की हालत में वहां से निकल जायें।

बी० बी० सी० ने एक प्रसारण में कहा कि पूर्वी बंगाल में इस्लाम और साम्यवाद में टक्कर हो रही है। अयूब खा के समर्थकों पर हमले किये जा रहे हैं।

लाहौर के अर्ध-सरकारी समाचार पत्र “पाकिस्तान टाइम्स” ने आरोप लगाया कि “भारतीय नागरिक पूर्वी बंगाल में घुसपैठ कर रहे हैं और बंगालियों को हमले करने के लिये भारत बन्दूक दे रहा है।” अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर्रहमान ने इस आरोप को शरारतपूर्ण और झूठा ठहराते हुए कहा कि

“हम गत २१ वर्षों से यह खेल देख रहे हैं। जब भी पूर्वी बंगाल की जनता अपने अधिकारों के लिये कोई आन्दोलन शुरू करती है शासक दल और उसके पिद्दू हमें भारतीय एजेंट करार देकर बदनाम करना शुरू कर देते हैं। इन लोगों को हमारी हर बात और हमारी हर मांग में भारत के षड्यंत्र की बदबू मिलती है।”

१५ मार्च को जब दोनों प्रान्तों के असैनिक राज्यपाल विपक्षी दलों के नेताओं को बातचीत के लिये निमन्त्रण पत्र भेज रहे थे, एकाएक रेडियो पाकिस्तान ने घोषणा की कि फील्ड मार्शल जनरल अयूब खा

ने देश की शासन सत्ता सेनापति जनरल याहिया खा के हवाले कर दी है और सेनापति ने समस्त देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया है।

चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर नियुक्त होते ही जनरल याहिया खा ने ससद और प्रांतीय विधान परिषदों को भग करने की घोषणा कर दी और दोनों राज्यपालों को डिसमिस करके लेफ्टीनेण्ट अतीकुर्रहमान को पश्चिमी पाकिस्तान का और मेजर जनरल मुफज्जुल्लाह को पूर्वी बंगाल का सैनिक गवर्नर नियुक्त कर दिया। इस प्रकार १८५८ का नाटक पुनः स्टेज किया गया। १९५८ में जब केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में परिवर्तन कर नए मंत्री नियुक्त किए जा रहे थे, इस्कन्दर मिर्जा और अयूब खा गुप्त रूप से सैनिक शासन स्थापित करने के लिए तैयारियां कर रहे थे। दोनों नहीं चाहते थे कि जनता को अपनी सरकार नियुक्त करने का अवसर मिले। इस बार भी जब पाकिस्तान के दोनों भागों में असैनिक राज्यपाल नियुक्त किए जा रहे थे और जनता को यह संकेत दिया जा रहा था कि ससदीय सरकार स्थापित कर दी जाएगी, पाकिस्तानी सेना के नेता सैनिक शासन स्थापित करने की तैयारियां कर रहे थे। इस प्रकार एक बार फिर शासकों ने जनता को धोखा दिया।

इतिहास ने अपने आपको दोहराया। १९५८ में सेनापति को शासन की जिम्मेदारी देने के बाद इस्कन्दर मिर्जा को तीन सप्ताह के अंदर स्वयं भी भागना पड़ा था। इस बार सेनापति ने राष्ट्रपति को एक दिन भी अपने पद पर रहने नहीं दिया। अपने पद का चार्ज लेते ही याहिया खा ने अयूब खा को छुट्टी दे दी और राष्ट्रपति का पद भी सभाल लिया।

३१ मार्च १९६९ और १८५८ के नाटक में केवल इतना ही अन्तर था कि जहाँ इस्कन्दर मिर्जा को अलग किए जाने पर जनता सामूहिक रूप से प्रसन्न थी वहाँ इस बार जनरल याहिया खा के सैनिक शासक

बन जाने पर जनता परेशान थी। अपने अधिकार प्राप्त करने के लिये जनता का आन्दोलन विफल हो गया था और ऐसा मालूम होता था पाकिस्तान के लोगो को कभी सुख और शान्ति का स्वास लेने का अवसर नहीं मिलेगा। जनरल याहिया खा जानते थे कि १९५८ के मुकाबले में इस बार अधिक बेचैनी पाई जाती है इसलिये जनता पर तुरन्त ही प्रहार करना खतरे से खाली नहीं होगा। इसलिये उन्होंने अपने पद का चार्ज लेते ही जो भाषण दिया उसमें उन्होंने वचन दिया कि वह सैनिक शासन को स्थाई रूप नहीं देगे बल्कि शान्ति स्थापित होते ही चुनाव करा के ससदीय सरकार की स्थापना करेगे। उन्होंने राजनीतिक दल को भग करने की घोषणा नहीं की अलबत्ता धमकी दी कि सैनिक शासन की आलोचना करने वालो को सख्त सजा दी जायेगी। उन्होंने समाचार पत्रो पर कड़ी पाबन्दिया लगा दी और जलसो और जलूसो की मनाही कर दी।

सैनिक शासन लागू करने के लिये बढती हुई अराजकता की ओट ली गई थी परन्तु इस स्थिति के लिये कौन दोषी था ? १० वर्षों से अयूब खा की तानाशाही जनता पर जुल्म कर रही थी। जनता से वह अधिकार भी छीन लिये गये थे जो अंग्रेजो के शासन काल में जनता को प्राप्त थे। इस्लाम के नाम पर एक गिरोह अपनी गद्दियों के लिये जनता की भावनाओ को कुचल रहा था। जिस पाकिस्तान की स्थापना के लिये लोगो ने मुसीबतों का सामना किया था उस पर केवल पश्चिमी पाकिस्तान के गिनती के कुछ बड़े-बड़े जमीदारो और पूजीपतियो ने अधिकार कर लिया था और वह अपने हितो के लिये समस्त जनता को गुलाम बनाये हुए थे। जनता इनसे दुखी हो अपने अधिकारो के लिये आन्दोलन कर रही थी। जो लोग हिंसात्मक कार्यवाइयो में लगे हुए थे, वे शासक वर्ग से ही किसी न किसी रूप में सम्बन्धित थे। जमायत इस्लामी को सेना के एक गुट का समर्थन प्राप्त था। भुट्टो को एक और

सैनिक गुट्ट प्रोत्साहन दे रहा था और मौलाना भाषानी चीन से शासक-वर्ग को सहायता दिलाने के कारण मजबूत हो रहे थे ।

मार्च १९६९ में ढाका के समाचार पत्र “पाकिस्तान आबजरवर” ने पूर्वी बंगाल में एक कृषि फार्म को तबाह किये जाने का ब्योरा देते हुए लिखा था कि स्थानीय बेसिक डेमोक्रेसी के अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं को हमले के लिये भडकाया । यह व्यक्ति अयूब खा का पक्का समर्थक था ।

फातिमा जिन्नाह और सोहरावर्दी के हत्यारे कौन ?

इससे पहले बताया जा चुका है कि श्री जिन्नाह की मृत्यु से पहले लियाकत अली किस प्रकार से षड्यंत्र रचा रहे थे। पाकिस्तान का जन्मदाता दम तोड़ रहा था और उसका प्रधान मंत्री शराब के जाम उड़ा रहा था। लियाकत अली की हत्या में उनके अपने साथियों का हाथ था। गवर्नर जनरल गुलाम मुहम्मद ने प्रधान मंत्री सर नाजिमुद्दीन को गद्दी से उतार फेंका। स्वयं गुलाम मुहम्मद को इस्कन्दर मिर्जा ने गद्दी से उतारा। गुलाम मुहम्मद ने बसीयत की थी कि उनके शव को भारत में देवल शरीफ में दफनाया जाये परन्तु ऐसा नहीं किया गया। इस्कन्दर मिर्जा ने पाकिस्तान के सभी राजनीतिक नेताओं को बदनाम किया। अपने निकटतम साथियों को भी धोखा दिया। उन्होंने अयूब खा को अपनाया था परन्तु अयूब खा ने समय आने पर इस्कन्दर मिर्जा को गद्दी से उतार दिया। जिन जनरलों ने अयूब खा का साथ दिया था, उन्हें अयूब खा ने एक-एक करके राजनीतिक क्षेत्र में खतम कर दिया। जनरल याहिया खा सेना में सबसे सीनियर अफसर नहीं थे। जनरल बरकी उनसे सीनियर थे परन्तु अयूब खा ने जनरल बरकी की बजाय जनरल याहिया खा को सेनापति बना दिया। इसी याहिया खाने अवसर मिलने पर अयूब खा का पत्ता काट दिया। अयूब खा ने भुट्टो को यह समझ कर मंत्रिमण्डल में नियुक्त किया था कि उसका पाकिस्तान के

राजनीतिक क्षेत्र में कोई स्थान नहीं, इसलिये भुट्टो से किसी प्रकार का खनरा नहीं हो सकता। परन्तु भुट्टो स्वयं राष्ट्रपति बनने के लिये साज-बाज कर रहे थे और यदि यह कहा जाये कि अयूब खा का तख्ता उलट देने में भुट्टो का बड़ा हाथ था तो यह कोई गलत बात नहीं होगी।

गत २४ वर्षों से कितने ही और व्यक्ति शासकों के षड्यन्त्रों का शिकार हुए हैं। इनमें मिस फातिमा जिन्नाह और श्री सोहरावर्दी को भी शामिल किया जा सकता है। मिस जिन्नाह निसन्देह राष्ट्रपति के चुनाव में अयूब खा के मुकाबले में हार गई थी परन्तु यदि चुनाव में गोल-माल न होता और यह चुनाव स्वतंत्र तरीके से होता तो अयूब खा जीत नहीं सकते थे। इस चुनाव के बाद मिस जिन्नाह खामोशी से बैठ नहीं गई थी। वह विरोधी दलों को तानाशाही के विरुद्ध संगठित करने में लगी हुई थी। जब भी अवसर मिलता वह तानाशाही के विरुद्ध भाषण और वक्तव्य देती। पाकिस्तानी मुसलमान उन्हें आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। समाचार पत्रों में उन्हें “मादरे मिल्लित” (जाति की माता) के शब्दों से सम्बोधित किया जाता था। अपने भाई की तरह वह अपने इरादों की पक्की और साहसी थी। अपने भाषणों में वह कहा करती थी कि श्री जिन्नाह के दिमाग में जिस पाकिस्तान का नक्शा था वह आज का पाकिस्तान नहीं। जिन्नाह पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर तानाशाही स्थापित करने और जनता का खून निचोड़ने वाले पूँजीपतियों को देश पर ठोस देने के विरोधी थे। लियाकत अली से लेकर अयूब खा तक पाकिस्तान के शासक मिस जिन्नाह की गतिविधियों से भयभीत रहते थे परन्तु मिस जिन्नाह किसी से डरती नहीं थी।

एक दिन एकाएक समाचार मिला कि मिस जिन्नाह हृदय की गति बन्द हो जाने से चल बसी हैं। उनके शव को दफना दिया गया। इसे एक साधारण मृत्यु ही समझा गया परन्तु १९६९ में जब अयूब शाही का अन्त हुआ और अयूब खा के स्कैण्डल जनता के सामने स्पष्ट रूप में

आने लगे तो यह माग भी की गई कि मिस जिन्नाह की मृत्यु के सम्बन्ध में जांच कराई जाय । मिस जिन्नाह के अपने नौकर ने कहा कि उनके शरीर पर ऐसे चिन्ह थे जिनसे सन्देह होता था कि मिस जिन्नाह की मृत्यु हृदय की गति बन्द होने से नहीं हुई । उनका गला किसी ने दबा दिया था । रात को सोते समय वह जो चादर ओढ कर सोई थी मृत्यु के समय वह गायब थी । नौकर का कहना है कि मिस जिन्नाह को कभी दिल की बीमारी नहीं हुई । उनके डाक्टरों ने भी इस बात की पुष्टि की । नौकर के इस बयान की पुष्टि भी हुई कि मुस्लिम लीग के कई अधिकारियों ने उस समय भी जांच की माग की थी परन्तु अधिकारियों ने यह मामला दबा दिया । यह भी मालूम हुआ कि मिस जिन्नाह को हत्या की धमकियां मिल रही थी । सी० आई० डी० उन्हें परेशान करती थी और वह राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ी हुई तो किराये के मौलवियों से प्रोपेगैंडा कराया गया कि मिस जिन्नाह इस्लाम के सिद्धान्तों का उल्लंघन कर रही है । कई समाचार-पत्रों ने लिखा कि मिस जिन्नाह की मृत्यु में अयूब शाही का हाथ है ।

यद्यपि इस मामले को दबा दिया गया है परन्तु एक दिन ऐसा आयेगा जब वास्तविकता का पता लग जायेगा । खून हमेशा के लिए गुप्त नहीं रह सकता ।

अवामी लीग के नेता श्री हुसैन शहीद सोहरावर्दी की मृत्यु कैसे हुई ? श्री सोहरावर्दी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पाकिस्तान की स्थापना पर अचानक बंगाल के विभाजन का विरोध किया था । वह बंगाल को अखण्ड रखना चाहते थे । क्योंकि उन्हें इस बात की आशंका थी कि बंगालियों को पाकिस्तान में न्याय नहीं मिलेगा । वह श्री जिन्नाह की मृत्यु के बाद ही पाकिस्तान गये । मिस जिन्नाह के आशीर्वाद से उन्होंने विरोधी दल की स्थापना की । पहले इसका नाम जिन्नाह मुस्लिम लीग रखा गया । बाद में इसका नाम अवामी लीग रख दिया गया । लियाकत

अली ने विरोधी दल की कड़ी आलोचना की। वह जानते थे कि सोहरावर्दी जनता में आदर और सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं और वह किसी भी प्रकार की तानाशाही चलने नहीं देंगे। इसलिये लियाकत अली ने उन्हें गद्दार ठहरा कर उनकी आलोचना शुरू कर दी परन्तु मोहरावर्दी की पोजीशन मजबूत होती गई। उन्होंने रावलपिण्डी षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किये हुए अधिकारियों की वकालत की थी। इसके कारण इस्कन्दर मिर्जा और अयूब खा उन्हें अपना शत्रु समझते थे। इस्कन्दर मिर्जा ने एक बार एक वक्तव्य में उन्हें गोली मार देने की धमकी भी दी थी। परन्तु परिस्थितियों से विवश होकर इस्कन्दर मिर्जा ने उन्हें प्रधान मंत्री बनाया। १९४८ में ढाका में जब बंगाली पुलिस ने विद्रोह किया तो जनरल अयूब खा ने सोहरावर्दी को गोली मार देने की धमकी दी थी, परन्तु इसी अयूब खा को सोहरावर्दी के मंत्रिमण्डल में उनके अधीन काम करना पड़ा। सोहरावर्दी ने विधान तैयार होने के समय हिन्दुओं और मुसलमानों को अलग करने के सुझाव का विरोध किया था। उनके डट जाने पर भी यह सुझाव स्वीकृत नहीं हुआ था। बाद में इस्कन्दर मिर्जा ने सोहरावर्दी को त्याग-पत्र देने के लिये बाध्य कर दिया क्योंकि सोहरावर्दी ससद का चुनाव कराने की तैयारियां कर रहे थे और वह यह भी फैसला कर चुके थे कि इस्कन्दर मिर्जा अथवा अयूब खा को तानाशाह बनने नहीं देंगे।

अयूब खा ने तानाशाह बनते ही सोहरावर्दी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमा चलाया। वास्तव में इस मुकदमे का मतलब सोहरावर्दी को ब्लैकमेल करना था। सोहरावर्दी ने स्थिति को देख कर कह दिया कि वह राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगे। इस पर मुकदमा वापिस ले लिया गया, परन्तु सोहरावर्दी फिर राजनीतिक मैदान में आ गये। समस्त बंगाल उनके साथ था। पंजाब, सीमा प्रान्त और सिंध में भी उनके समर्थक थे। पाकिस्तान से बाहर भी उनके मित्र थे। १९६२ में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रिहा होते ही उन्होंने फिर राजनीतिक

गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। उन्होंने समस्त बंगाल का भ्रमण करके तानाशाही के विरुद्ध भाषण दिये। अयूब खा ने सटपटा कर १८ सितम्बर १९६२ को एक बयान में कहा कि

“जब भी देश की सुरक्षा को खतरे का सामना होता है सोहरावर्दी देश-द्रोहियों का नेतृत्व करने के लिये आगे आ जाते हैं। यदि देश के विभाजन के बाद लाखों शरणार्थी यहाँ न आ जाते तो सरकार इस व्यक्ति को पाकिस्तान की नागरिकता के अधिकार देने का खतरा कभी मोल न लेती।”

सोहरावर्दी ने इसके उत्तर में कहा कि पाकिस्तान तानाशाह की जायदाद नहीं। मैं किसी धमकी से भयभीत होने वाला नहीं। पाकिस्तानी जनता अपने अधिकार लेकर ही रहेगी।

सोहरावर्दी इसके बाद पश्चिमी पाकिस्तान गये। जगह-जगह हजारों व्यक्तियों ने उनका स्वागत किया। गुजरावाला में वह एक विशाल सभा में भाषण दे रहे थे कि अयूब के एक एजेंट ने बम फेंक दिया। स्पष्ट रूप से सोहरावर्दी की हत्या के लिये यह एक प्रयास था। अयूब-शाही के एजेंट जगह-जगह उनके जलसे में गडबड डालने की कोशिश करते रहे। कराची में एक जलसे में उनके एक साथी अब्दुलमजीद को चाकू मार दिया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। परन्तु सोहरावर्दी अयूब-शाही के विरोध में आन्दोलन चलाते रहे। उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान में विरोधी दलों को नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट के रूप में संगठित कर लिया। पाकिस्तान के दोनों भागों में सोहरावर्दी की बढ़ती हुई ताकत से तानाशाही का सिंहासन डोलने लग गया था। सरकारी पत्र “पाकिस्तान टाइम्स” ने लिखा कि सोहरावर्दी ने मुस्लिम लीग को तबाह कर दिया है।

सोहरावर्दी जनवरी १९६३ के पहले सप्ताह में सभी विपक्षी दलों का एक सम्मेलन बुलाने की तैयारियाँ कर रहे थे। अयूब खा विपक्षी दलों को कुचल देने का इरादा कर चुके थे। उसके गुण गाने वाले

कराची के समाचार पत्र 'दैनिक नई रोशनी' ने यह आरोप लगाया कि सोहरावर्दी अपने अमरीकन मित्रों की सहायता से सरकार का तख्ता उलट देने के लिये षड्यंत्र कर रहे हैं। तीन दिन बाद पुलिस ने अचानक श्री सोहरावर्दी को कराची में उनकी बेटी के निवासस्थान से गिरफ्तार करके नजरबन्द कर दिया। उस समय सोहरावर्दी अपनी वर्षगांठ मनाते के लिये अपने मित्रों को पत्र लिख रहे थे। जेल में वह बीमार हो गये तो जनता के बावेली मचाने पर उन्हें केन्द्रीय हस्पताल में दाखिल कर दिया गया। बाद में उन्हें इस शर्त पर छोड़ दिया गया कि वह लैबनान की राजधानी बैरुत चले जायेंगे। बाद में एक दिन समाचार मिला कि हृदय की गति बन्द होने से उनकी मृत्यु हो गई है। उनके समर्थकों को सन्देह तो हुआ, परन्तु तानाशाही का जमाना था। कौन बोलता ? १९७१ में शेख मुजीबुर्रहमान ने आरोप लगाया कि यह मृत्यु नहीं बल्कि हत्या थी और इसमें अयूब खा का हाथ था।

* अगस्त १९७१ में लन्दन से प्रकाशित होने वाले पाकिस्तानी साप्ताहिक पत्र 'वतन' ने सोहरावर्दी की बेटी बेगम अब्तर का एक वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसमें माग की गई थी कि उनके पिता की रहस्यमयी मृत्यु के कारणों की जांच कराई जाये। बेगम अब्तर ने कहा कि

“यह गलत है कि मेरे पिता की मृत्यु हृदय की गति बन्द होने से हुई थी। मेरे पिता बैरुत के एक होटल में ठहरे हुए थे। उन्हें अपना जीवन खतरे में दिखाई देना था। उन्होंने मुझे कहा था कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं और एक सप्ताह से ऐसा हो रहा है। उन्होंने लाहौर के नेता नवाबजादा नसरुल्ला खा से भी यह बात कही थी। मेरे पिता की मृत्यु से पहले अयूब खा के मन्त्रिमण्डल के एक सीनियर सदस्य ने एक मित्र द्वारा यह सन्देश भेजा था कि यदि वह यह विश्वास दिलाये कि वह राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगे और अयूब खा के सम्बन्ध में अपनी विचारधारा

बदल ले तो पाकिस्तान में लौट आने से उन्हें रोका नहीं जायेगा। जब मुझे पता लगा कि एक व्यक्ति मेरे पिता की हत्या के लिये बैरत को चल पड़ा है तो मैंने अपने पिता को लन्दन जाने के लिये नवाबजादा नसरुल्ला को उनके पास भेजा। नवाबजादा ने मेरे पिता को हत्या के पड़यंत्र से भली-भांति सूचित कर दिया था। यद्यपि मेरे पिता का डाक्टर होटल के निकट ही ठहरा हुआ था परन्तु मेरे पिता की मृत्यु की सूचना उसे नहीं दी गई। मेरे पिता के शव का पोस्टमार्टम भी नहीं करने दिया गया। पाकिस्तानी दूतावास ने होटल के डाक्टर से मृत्यु का सर्टीफिकेट प्राप्त कर लिया और विमान पर उनका शव पांच घण्टे के अन्दर-अन्दर कराची भेज दिया गया।”

बेगम अख्तर के इस बयान पर जनरल याहिया खा की सरकार ने कोई कार्यवाई नहीं की।

पश्चिमी पाकिस्तान के वामपथी कार्यकर्ता और मेरे अपने समाचार पत्र के सवाददाता हसन नासिर को अक्टूबर १९५८ में गिरफ्तार करके लाहौर के शाही किले में बन्द कर दिया था। उन पर अमानुषिक अत्याचार किये गये। उनकी मृत्यु हो गई, उनका शव गुप्त रूप से जला कर राख रावी में बहा दी गई। जब जनता ने बाबेला मचाया और माग की कि इस दुर्घटना की जांच कराई जाये तो सरकार ने कहा कि हसन ने आत्महत्या कर ली थी। हसन की माँ भारत से लाहौर गई। उसे जो शव दिखाया गया उसे देखते ही उसने चिल्लाकर कहा कि यह मेरे बेटे का शव नहीं। किसी और का शव किसी कब्र से निकाल कर मेरे सामने रख दिया गया है। नासिर के मित्रों को सम्बोधित करते हुए माँ ने कहा—“मेरे बेटे ने देश के लिये अपना जीवन दिया है और मुझे विश्वास है कि पाकिस्तान के लोग किसी न किसी दिन इसका बदला लेकर रहेंगे।”

याहिया खा की तानाशाही बंगला देश मे विद्रोह

याहिया खा ने शासन-सत्ता सभालने के समय जनता को धोखा देने के लिये घोषणा की थी कि वह इस पद पर स्थाई रूप से रहना नहीं चाहते। उन्होंने वचन दिया था कि समस्त देश में चुनाव करायेगे और जनता के प्रतिनिधियों को देश का विधान तैयार करने की स्वतन्त्रता दी जायेगी।

जनरल याहिया खा ने राजनीतिक दलों को भग करने की घोषणा नहीं की। उन्होंने तुरन्त ही किसी प्रमुख नेता को गिरफ्तार भी नहीं किया। वह जानते थे कि इससे स्थिति और भी बिगड़ जायेगी, इसलिये वह धीरे-धीरे पुराने हथकण्डों का प्रयोग करने के लिये मैदान तैयार कर रहे थे। इसके लिये उन्होंने जलसों, जलूसों और हड़तालों की मनाही कर दी। उन्होंने एक अध्यादेश जारी कर के सैनिक-शासन की कार्यवाही की आलोचना करना जुर्म करार दिया। समाचार पत्रों पर भी इसी प्रकार के कड़े प्रतिबंध लगा दिये गये। एक अध्यादेश द्वारा बाहर से कोई भी समाचार पत्र मगवाने और पाकिस्तान से कोई भी समाचार पत्र बाहर भेजने की मनाही कर दी गई। इस कार्यवाही का उद्देश्य यह था कि पाकिस्तान के लोगों को यह मालूम न हो सके कि दूसरे देशों के समाचार पत्र पाकिस्तान की स्थिति पर क्या लिख रहे हैं और बाहर के लोगों को यह मालूम न हो सके कि पाकिस्तान में क्या

रहे और जिन्होंने लगभग सभी बड़े-बड़े समाचार पत्रों को खरीद लेने वाले नेशनल प्रेस ट्रस्ट पर कंट्रोल कर रखा था आय कर के कागजात में जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। मिया सईद सहगल पश्चिमी पाकिस्तान के चोटी के पूजीपतियों में गिने जाते थे। लायलपुर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी कपड़ा मिल—कोहेनूर मिलज—से उन्हें लाखों रुपये मासिक की आमदनी होती थी। समुद्री जहाजों की एक नई कम्पनी पर भी उनका कंट्रोल था। इस कम्पनी के जहाज कराची और शर्घाई के बीच चलते थे। अयूब खा के दूसरे बेटे कैप्टन अख्तर अयूब को एक बड़े जमींदार राजा अमजद खा की इस शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया गया कि उसे डरा-धमका कर उसकी १०० एकड़ जमीन अपने नाम करा ली थी।

अयूब खा के कई खुशामदी अफसरों को नौकरी से हटा दिया गया अथवा दूर-दूर के स्थानों पर भेज दिया गया। इस आशंका से कि कई सीनियर सैनिक अफसर याहिया खा के विरुद्ध षड्यंत्र कर सकते हैं उन्हें हटाकर दूसरे देशों में भेज दिया गया। याहिया खा को सेना में अपने निकटतम जनरलों से भी डर था। इसलिये एयर मार्शल नूर खा आदि अफसरों को पहले तो मंत्रिमण्डल में नियुक्त किया गया और इसके बाद ऐसे हालात पैदा किये गये कि वह त्यागपत्र देकर अलग हो गये। बंगाली अफसरों में से जल सेना के एडमिरल एह्सन सब से शक्तिशाली थे। उन्हें पूर्वी बंगाल का राज्यपाल बनाकर इस्लामाबाद से दूर भेज दिया गया।

अगस्त १९६९ में अपना मंत्रिमण्डल सगठित करने के लिये याहिया खा ने जनता के किसी भी नेता को नियुक्त नहीं किया। पूर्वी बंगाल से उन्होंने डाक्टर ए० एम० मल्लिक और एम० के० हफीजुद्दीन को नियुक्त किया। डाक्टर मल्लिक किसी समय चीन में पाकिस्तान के राजदूत थे। १९६२ में उन्हें इसलिये हटा दिया गया था कि उन्होंने

एक रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि चीन किसी समय पाकिस्तान को छोखा देकर उसी प्रकार आक्रमण कर देगा जिस प्रकार उसने भारत पर किया था। बंगाल में कहा जाता था कि डाक्टर मलिक अमरीका के एजेंट है। हफीजुद्दीन कुछ वर्ष पहले पूर्वी बंगाल में पुलिस के आई० जी० थे। इस हैसियत से उन्होंने देशभक्तों और प्रगतिशील वर्ग पर बड़ा जुल्म किया था। जनता उन्हें घृणा की दृष्टि से देखती थी।

सीमा प्रांत से जिस व्यक्ति को घरेलू मामलों और कश्मीर विभाग का मंत्री नियुक्त किया गया वह पुलिस के भूतपूर्व आई० जी० सरकार अब्दुल रशीद थे। इस्कन्दर मिर्जा ने उन्हें एक बार सीमा प्रान्त का और दूसरी बार पश्चिमी पाकिस्तान का मुख्य मंत्री नियुक्त किया था। नवाब मुजफ्फर अली खा किजलबाश एक और मंत्री थे। देश के विभाजन से पहले वह अंग्रेज सरकार के एजेंट थे। इस्कन्दर मिर्जा ने उन्हें पश्चिमी पाकिस्तान का मुख्य-मंत्री नियुक्त किया था। उनकी खूबी यही थी कि वह एक बहुत बड़े जमींदार थे। मेजर जनरल शेख अली खा को सूचना एव प्रसार विभाग का मंत्री नियुक्त किया गया। यह साहिब नवाब पटौदी के मामू हैं। देश के विभाजन से पहले याहिया खा के विरुद्ध एक लड़की पर बलात्कार के अभियोग में कार्यवाही होने वाली थी तो उस समय शेर अली ने अंग्रेज अधिकारियों को सिफारिश करके याहिया खा को बचा लिया था। शायद इसका बदला देने के लिये ही मेजर जनरल अली खा को मन्त्रिमण्डल में नियुक्त कर दिया गया था।

सिंध के करोड़पति मिल मालिक महमूद हार को याहिया खा ने सिंधियों का प्रतिनिधि बनाकर मन्त्रिमण्डल में नियुक्त किया। सेठ साहिब की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि उनकी गिनती पश्चिमी पाकिस्तान के उन २० परिवारों में होती थी जो पाकिस्तान के ८० प्रतिशत कारखानों और व्यापार पर कन्ट्रोल करते हैं। पाकिस्तान का ६० प्रति-

गत विदेशी 'कारोबार इन्ही सेठ साहिब की मिल्कियत मे था । तथा-
कथित असैनिक मन्त्रिमण्डल मे सुरक्षा, विदेशी मामलो और खजाना
आदि के विभाग याहिया खा ने अपने पास रखे । दो टोडी बगालियो के
अतिरिक्त अन्य सभी मन्त्री पश्चिमी पाकिस्तान से सम्बन्ध रखते थे ।
इस प्रकार से जहा पूर्वी बगाल से फिर घोर अन्याय हुआ वहा प्रगति-
शील वर्गों के लिये यह एक नया चैलेज था क्योंकि बड़े-बड़े पूजीपतियो
और जमींदारो को मन्त्रिमण्डल मे नियुक्त करने से यह बात स्पष्ट हो
गई थी कि याहिया खा जनता के हितो की रक्षा करने के लिये तैयार
नही थे ।

विदेशी मामलो मे अयूब खा चीन की ओर झुक गये थे । याहिया
खा ने पूजीपतियो और मिल मालिको को अपनी सरकार मे नियुक्त
करके अमरीका को इस बात का संकेत दिया कि उनका झुकाव चीन
की ओर नही बल्कि अमरीका की ओर है । उन्होंने स्वयं अमरीका जा
कर अमरीकी नेताओ को यही बात कही और यह इसी का परिणाम
था कि अमरीका ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने का जो सिल-
सिला १९६५ मे बन्द कर दिया था वह दोबारा शुरू करने के लिये
मैदान तैयार करना शुरू कर दिया । याहिया खा ने अमरीका को यह
बताया कि वामपन्थी पाकिस्तान सरकार को अपनी रक्षा के लिये
चीन से सैनिक सहायता लेने के लिये मजबूर कर रहे है परन्तु पाकि-
स्तान इस्लामी देश होने के कारण चीन की सहायता पर निर्भर करना
नही चाहता । याहिया खा ने अमरीका को यह भी विश्वास दिलाया कि
पश्चिमी एशिया मे पाकिस्तान मिस्र का साथ नही देगा बल्कि जोर्डन
और सउदी अरब की सहायता करके अमरीका के हितो की रक्षा मे
सहयोग देगा ।

याहिया खा ने रूस पर भी डोरे डाले । रूस को यह विश्वास दिलाने
की कोशिश की गई कि पाकिस्तान रूस के विरुद्ध चीन का साथ नही

देगा। याहिया खा का वास्तव मे अभिप्राय यह था कि भारत और रूस और भारत और अमरीका मे मतभेद पैदा हो और चीन के साथ ही इन देशो से भी अधिक से अधिक सैनिक सहायता लेकर पाकिस्तान की सैनिक शक्ति को ऐसा मजबूत किया जाय कि उचित अवसर मिलने पर भारत पर आक्रमण करके १९६५ की हार का बदला लिया जाये।

अमरीका और रूस से मित्रता की बातें करने का एक और अभिप्राय यह था कि ये दोनों देश पूर्वी बंगाल की जनता से किसी प्रकार की सहानुभूति न करें। यह बात किसी से गुप्त नहीं कि जब से पाकिस्तान ने चीन से गठजोड़ किया था अमरीका का ध्यान पूर्वी बंगाल पर लगा हुआ था। पाकिस्तान के समाचार पत्र यह आरोप लगाया करते थे कि अमरीका पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान से अलग करने के लिये साज-बाज कर रहा है। याहिया सरकार ने अमरीका मे यह प्रापेगैंडा शुरू किया कि पाकिस्तान का भगडा केवल भारत से है। अमरीका पाकिस्तान को सहायता दे तो पाकिस्तान मे चीन के समर्थक कमजोर हो जायेगे।

याहिया सरकार अमरीका के साथ ही रूस से भी कुछ युद्ध सामग्री लेने मे सफल हो गई। रूस से उसे “टी—५४” और “टी—५५” के कुछ टैंक मिल गये और आर्थिक सहायता का वचन भी मिल गया। पाकिस्तानी समाचार पत्रो ने इसे सैनिक सरकार का बहुत बड़ा कारनामा ठहराया और प्रापेगैंडा किया कि रूस को भारत से दूर रखने के लिये पाकिस्तान के किसी भी दूसरे शासक को जो सफलता नहीं हुई वह याहिया खा को हो रही है। जब भारत सरकार ने पाकिस्तान को रूसी सैनिक सहायता मिलने पर विरोध पत्र भेजा तो याहिया खा को प्रसन्नता हुई। वास्तव मे रूस पाकिस्तान मे चीन का प्रभाव खत्म करने के लिये यह कदम उठा रहा था। भारत के सम्बन्ध मे रूस की नीति मे कोई परिवर्तन नहीं हुआ था।

अगस्त १९७० में याहिया खा ने अमरीका के प्रधान श्री निक्सन और विदेश मंत्री श्री रॉजर्स से भेंट की। इसके परिणाम स्वरूप अमरीका ने पाकिस्तान को युद्ध सामग्री देने का फैसला कर लिया। जहाँ अमरीका की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान को चीन के प्रभाव से दूर करने के लिये यह सहायता देना अमरीका के हित में है वहाँ रूस की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान को सहायता देकर रूस पाकिस्तान में अपना प्रभाव मजबूत करना चाहता है जिससे पाकिस्तान युद्ध का मार्ग न अपनाये। याहिया खा सरकार ने इस पर यह प्रापेगैंडा किया कि ससार भर में अब भारत का कोई मित्र नहीं रहा। यह भी कहा गया कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने के लिये तैयारियाँ कर रहा है इसलिये पाकिस्तान अपनी रक्षा के लिये दूसरे देशों से सैनिक सामग्री खरीदने के लिये मजबूर हो रहा है। पश्चिमी पाकिस्तान के समाचार पत्रों ने लिखना शुरू किया कि पाकिस्तानी सेना काश्मीर को “स्वतंत्र” कराने के लिये अमरीका और रूस से प्राप्त किये हुए शस्त्रों का प्रयोग करेगी। पश्चिमी पाकिस्तान और पाकिस्तानी अधिकृत काश्मीर के कई नेताओं ने काश्मीर पर आक्रमण करने के नारे लगाना शुरू कर दिया। अधिकृत काश्मीर में “अल बर्क” नाम की छापामारों की एक गुरिला संस्था स्थापित की गई। काश्मीर में जासूसी और तोड़-फोड़ की गति-विधियों के लिये इस सेना में भरती होने वालों को ट्रेनिंग देने के लिये कैम्प खोले गये और दिल्ली में समाचार पढ़ते कि कुछ चीनी विशेषज्ञ पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में छापामारों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। यह भी मालूम हुआ कि विलोचिस्तान में अमरीका के विशेषज्ञ भी एक बहुत बड़े कैम्प में पाकिस्तानी छापामारों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। बाद के हालात ने सिद्ध कर दिया कि याहिया खा की जासूसी एजेंसी समस्त भारत में जासूसी और तोड़फोड़ के लिये अपने एजेंट तैयार कर रही थी।

याहिया खा ने वचन दिया था कि वह एक वर्ष के अन्दर चुनाव

करायेगे। ज्यू ही विपक्षी दलों की ओर से शीघ्र ही चुनाव कराने की माग की जाती थी याहिया सरकार ऐसी गतिविधियां तेज कर देती थी जिनमें यह मालूम हो कि भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करने वाला है और याहिया सरकार ने काश्मीर पर अधिकार करने का पक्का फैसला कर चुकी है। अगस्त १९६९ के पहले सप्ताह में याहिया खा ने जनरल अब्दुलहमीद खा के नेतृत्व में एक सैनिक डैलीगेशन चीन भेजा। याहिया खा ने चीन के प्रधान मंत्री को व्यक्तिगत रूप से भी एक सन्देश भेजा जिसमें चीन को उसकी सहायता पर धन्यवाद देते हुए आशा प्रकट की गई थी कि “आने वाले दिनों में दोनों देशों में यह सहयोग और भी बढ़ेगा।” चीन के प्रधान मंत्री ने पाकिस्तानी नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि “चीन काश्मीर को स्वतंत्र कराने के पाकिस्तानी संघर्ष में पूरा-पूरा सहयोग देगा।” चीन के समाचार पत्रों ने प्रोपेगैंडा किया कि “हमारे देशवासी काश्मीर की जनता को स्वतंत्रता प्राप्त करने के आन्दोलन में और पाकिस्तानी जनता को “भारतीय साम्राज्य” के “हथकण्डों” का मुकाबला करने के लिये पूरी-पूरी सहायता देंगे।”

चीन से सहायता का वचन प्राप्त करने के बाद याहिया खा स्वयं नवम्बर १९७० के पहले सप्ताह में चीन गये। उनके साथ ही लेफ्टिनेन्ट जनरल एम० एम० पीरजादा, मेजर जनरल मल्लिक अब्दुल अली और मेजर जनरल मुहम्मद खुरशीद हैदर भी चीन गये। इन सैनिक अधिकारियों का याहिया खा के साथ चीन जाना यह बात स्पष्ट करता था कि याहिया खा सामूहिक रूप से सैनिक नीति पर चीनियों से विचार-विमर्श करना चाहते थे।

चीन की राजधानी में याहिया खा और उनके सहकारियों का भव्य स्वागत किया गया। सरकारी समाचार पत्र “पीपल्स डेली” ने एक सम्पादकीय में लिखा कि “चीन पाकिस्तान को विश्वास दिलाता है कि राष्ट्रपति याहिया खा के इस दौरे के परिणाम सन्तोषजनक होंगे और

चीन पाकिस्तान को उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिये और काश्मीर के लोगो को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त करने के लिये सहायता देता रहेगा।” १५ नवम्बर १८७० को लाहौर के सरकारी समाचार पत्र “पाकिस्तान टाइम्स” ने अपने सम्पादकीय में लिखा कि चीन पाकिस्तान पर किसी भी आक्रमण और पाकिस्तान में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप की अवस्था में पाकिस्तान को पूरी-पूरी सहायता देगा। चीन ने पाकिस्तान को २ अरब डालर का ऋण देने की पेशकश की है। इस पर कोई सूद भी नहीं लिया जायेगा। याहिया खा ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि चीन की पेशकश इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि चीन की जनता को पाकिस्तान की जनता से अथाह प्रेम है।

प्रश्न उठता है कि याहिया खा यह दौड़-धूप क्यों कर रहे थे ? भारत ने तो उन्हें युद्ध की कोई धमकी नहीं दी थी। धमकिया तो पाकिस्तान की ओर से ही दी जा रही थी। वास्तव में याहिया खा देश की शासन-सत्ता जनता और उसके प्रतिनिधियों को सौंप देना नहीं चाहते थे। उन्हें मालूम हो चुका था कि उनके समर्थक चुनाव में किसी भी प्रान्त में जीत नहीं सकते थे। याहिया खा ने पश्चिमी पाकिस्तान का एक यूनिट भंग कर पहले की तरह वहां पांच प्रान्तों के पुनर्संगठन की घोषणा कर दी थी परन्तु अब पंजाब की विरोधी मुस्लिम लीग सीमा प्रान्त की नेशनल अवामी पार्टी, और सिंध और बिलोचिस्तान के देशभक्तों ने पूर्वी बंगाल की आवामी लीग से समझौता कर लिया था और याहिया खा को दिखाई दे रहा था कि चुनाव में सैनिक शासन के विरोधी जीत जायेंगे और पूर्वी बंगाल ही नहीं सभी प्रान्त आन्तरिक रूप से स्वतंत्र हो जायेंगे। सेना को जो अधिकतर पश्चिमी पाकिस्तान के सिपाहियों की है एक प्रकार से बंगालियों के अधीन रहना पड़ेगा। इसलिये वह चाहते थे कि ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाये कि चुनाव ही न हो। इसके लिये वह भारत पर आक्रमण करके स्थिति

को असाधारण बना देने के लिये चाले चल रहे थे। इसके लिये वह काश्मीर में जासूस भेज रहे थे। इन लोगो ने जगह-जगह आग लगाना शुरू किया। शेख अब्दुल्ला के समर्थको से इनका गठजोड़ हो गया था। शेख अब्दुल्ला और उनके साथी मिर्जा अफजल बेग ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी राजदूत से मुलाकाते करना शुरू कर दिया। उनके समर्थक काश्मीर में अफवाहें फैला रहे थे कि भारतीय सेना के अधिकारी आग लगा रहे हैं। ऐसा करके भारतीय सेना के प्रति घृणा फैलाई जा रही थी। मिर्जा ने माग की कि सेना को देहात से हटा लिया जाये। पाकिस्तान के शासक यह समझ रहे थे कि युद्ध होने पर शेख के समर्थक उनका साथ देंगे। काश्मीर में घुसे हुए पाकिस्तानी छापामार भी हमले करेंगे। पाकिस्तानी एजेंट काश्मीर में “अल-फातेहा” नाम की छापामार सस्था संगठित कर रहे थे। इन लोगो को शस्त्र और बम दिये जा रहे थे। पूर्वी बंगाल में गद्दार नागा और मीजो कबायलियों को भी इसी प्रकार भारत से युद्ध के लिये प्रशिक्षण दिया जा रहा था।

पाकिस्तान में चुनाव अक्टूबर १९७० में होने थे। अगस्त में पूर्वी बंगाल में भयंकर समुद्री तूफान आया। इससे एक लाख से अधिक व्यक्ति मारे गये। गांव के गांव बाढ़ में डूब गये। सरकारी अधिकारियों ने तूफान के लिये समय पर चेतावनी नहीं दी थी और तूफान आने पर भी सरकार ने पीड़ितों की सहायता के लिये तुरन्त प्रबन्ध नहीं किया था। इस पर पूर्वी बंगाल में तानाशाही के विरुद्ध क्रोध की आग भड़क उठी। बंगाली नेताओं ने कहा कि शासको ने लापरवाही का प्रमाण देकर बंगालियों से दासों का-सा बर्ताव किया है। इसका हल यही है कि बंगाली जनता अपने अधिकारों के लिये संघर्ष करे। इस समय भारत सरकार ने बंगाली पीड़ितों की सहायता के लिये एक करोड़ रुपया दिया। भारत सरकार पीड़ितों की सहायता के लिये गाड़ियां, जहाज और कार्यकर्ता भी भेजना चाहती थी परन्तु याहिया

खा ने यह पेशकर ठुकरा दी। रेडियो पाकिस्तान भारत को पाकिस्तान का शत्रु ठहराता रहा। इससे बंगाली जनता पर गामको के भिन्न प्रभाव पड़ा। याहिया खा ने तूफान की ओट लेकर चुनाव स्थगित कर दिये। इस पर भी बंगाली जनता ने क्रोध प्रकट किया। अन्त में घोषणा की गई कि दिसम्बर के पहले सप्ताह में चुनाव होंगे। इसके साथ ही याहिया खा ने एक बयान में कहा कि चुनाव के बाद नेशनल असेम्बली का अधिवेशन शुरू होगा। इस अधिवेशन को देश के भविष्य के सविधान की तैयारी का अधिकार होगा परन्तु विधान के लिये यह शर्त आवश्यक है कि पाकिस्तान की एकता को कोई खतरा पैदा न हो। केन्द्रीय सरकार मजबूत हो और जो भी विधान तैयार हो प्रत्येक प्रान्त के सदस्यों की बहुसंख्या उसका समर्थन करे। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा सविधान तीन मास के अन्दर-अन्दर तैयार करना होगा। यदि ऐसा न हुआ तो नेशनल असेम्बली को भग करके पुन चुनाव कराये जायेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि असेम्बली जो भी सविधान तैयार करे वह उसी हालत में लागू होगा जब उसे मेरी स्वीकृति प्राप्त हो जायेगी।

यह घोषणा करने के बाद उन्होंने गुप्त रूप से अपने समर्थकों को तैयार करना शुरू किया उन्होंने घोषणा की कि सविधान इस्लाम की नींव पर बनाया जाये। इसका मतलब यह था कि समाजवाद तथा प्रगतिशील मुधारों के लिये सविधान में किसी प्रकार की गुजायश नहीं रखी जा सकती। ऐसे प्रयत्नों को इस्लाम के विरुद्ध बताकर विफल कर दिया जायेगा और प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार नहीं दिये जायेंगे। इसका मतलब यह धमकी भी देना था कि जनता के प्रतिनिधियों को किसी हालत में भी अपनी इच्छा अनुसार अपने देश के लिये शासन प्रणाली का ढांचा तैयार करने की स्वतंत्रता नहीं दी जायेगी। याहिया खा जो चाहेंगे वही होगा।

याहिया खा ने इस्लाम के नाम पर प्रगतिशील दलों का विरोध

करने वाले राजनीतिक दलों को उभारना शुरू कर दिया। इस बात के प्रमाण हैं कि उन्होंने गुप्तरूप से जमायत इस्लामी, कियूम मुस्लिम लीग, डेमोक्रेटिक पार्टी और जमायत इस्लाम से साठ-गाठ कर ली थी। यह राजनीतिक दल इस्लाम का नाम लेकर अपने विरोधियों की कड़ी आलोचना कर रहे थे और यह प्रोपेगैंडा भी कर रहे थे कि समाजवाद और प्रातो को अधिकार देने की माग करने वाले इस्लाम के शत्रु हैं। भारत और हिन्दुओं के एजेंट हैं। उनका यह कहना भी था कि काश्मीर पर हर हालत में अधिकार करने के लिये भारत से युद्ध किया जाना चाहिये। इन दलों के नेता शेख मुजीबुर्रहमान और खान वली खा को भारत और हिन्दुओं के दलाल कहकर बदनाम कर रहे थे। यह आरोप लगाया जा रहा था कि भारत इन राजनीतिक दलों की आर्थिक सहायता कर रहा है ताकि पाकिस्तान के टुकड़े-टुकड़े हो जायें। स्वयं याहिया खा ने चीन से लौट आने पर पिशावर में एक पत्रकार सम्मेलन में वक्तव्य देते हुए वली खा की नेशनल अवामी पार्टी पर यह आरोप लगाया। ढाका में जब याहिया खा से एक पत्रकार सम्मेलन में कहा गया कि मौलाना भापानी और शेख मुजीबुर्रहमान प्रातो की आन्तरिक स्वतंत्रता की माग कर रहे हैं और जनता उन्हें अपना नेता समझती है तो याहिया खा ने कहा कि चुनाव में मालूम हो जायेगा कि जनता के असली नेता कौन हैं। मैं उन्हें जनता के प्रतिनिधि नहीं समझता। जाहिर है कि प्रगतिशील दल चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अपने विरोधियों के हाथ कमजोर करने के लिये याहिया खा भारत के विरुद्ध प्रोपेगैंडा कर रहे थे। जहाँ प्रगतिशील दल इस बात पर जोर देते थे कि पाकिस्तान को भारत में अपने सम्बन्धों में सुधार करना चाहिये, वहाँ याहिया खा यह गोर मचा रहे थे कि भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करने की तैयारियाँ कर रहा है। याहिया खा के समर्थक शोर मचा कर यह ब्राह्मण कर रहे थे कि भारत से मित्रता की बातें करना पाकिस्तान और

इस्लाम से शत्रुता करना है।

मि० भुट्टो की पीपल्स पार्टी याहिया खा के विरुद्ध प्रोपेगैंडा कर रही थी और “इस्लामी समाजवाद” लाने की बातें भी कर रही थी परन्तु यह दल भारत के विरुद्ध जहर उगल रहा था। याहिया खा के समर्थकों से भी दो कदम आगे बढ़कर मि० भुट्टो कह रहे थे कि यदि उनकी पार्टी शासन-सत्ता प्राप्त करने में सफल हो गई तो वह काश्मीर पर अधिकार करने के लिये अवश्य ही भारत से युद्ध करेगी।

याहिया खा युद्ध की तैयारियां कर रहे थे। पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के तथाकथित प्रधान सरदार अब्दुल कयूम ने एक भाषण में कहा कि १९७१ में काश्मीर के लिये अवश्य युद्ध किया जायेगा। जमायत इस्लामी के अध्यक्ष मौलाना मौदूदी ने कहा कि काश्मीर पर हमला करने का समय निकट आ गया है। कराची के समाचार पत्र “जिन्दगी” ने लिखा कि काश्मीर के मुसलमान स्वतंत्र होने के लिये पाकिस्तान की ओर देख रहे हैं। “दैनिक जग” कराची ने लिखा कि काश्मीर की जनता पाकिस्तान से सम्मिलित होने के लिये उत्सुक है और हमें विश्वास है कि युद्ध का बिगुल बजते ही काश्मीरी मैदान में निकल आयेगे।

याहिया खा ने कहा कि काश्मीर की स्वतंत्रता के लिये चीन पाकिस्तान का साथ देगा। शेख अब्दुल्ला और मिर्जा अफजल बेग ने चीन और पाकिस्तान के शासकों की प्रशंसा करते हुए बयान दिये।

दिसम्बर के पहले और दूसरे सप्ताह में जब पाकिस्तान में चुनाव होने वाले थे पाकिस्तान रेडियो ने अचानक आरोप लगा दिया कि भारतीय सेना ने पूर्वी बंगाल के एक गांव पर हमला करके सैकड़ों मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया है। वास्तव में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। इस भूठे आरोप का उद्देश्य यह था कि पूर्वी बंगाल के लोग अवामी लीग का जो भारत से मित्रता के सम्बन्ध स्थापित करने की मांग कर रही थी, चुनाव में समर्थन न करे। चुनाव से कुछ दिन पहले सभी

वामपंथी दल बंगाल में शेख मुजीबुर्रहमान के समर्थन में मुकाबले से हट गये थे। एक दिन पहले मौलाना भाषानी ने एक सार्वजनिक सभा में घोषणा की थी कि उनका दल पाकिस्तान से अलग होने और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये आन्दोलन करेगा। इनके इस फैसले का एक परिणाम यह हुआ कि याहिया खा के विरोधियों में फूट की कोई आशंका नहीं रही।

चुनाव के परिणामों ने याहिया खा, उनके साथियों और भुट्टो को परेशान कर दिया। शेख साहिब की अवामी लीग ने नेशनल असेम्बली में ३०० सीटों में से १६० पर जीत कर बहुमत प्राप्त कर लिया। इसके साथ ही वली ग्रुप की नेशनल अवामी पार्टी ने ६ और जमायते इस्लाम हजारवी ग्रुप ने सात-सात सीटों पर अधिकार कर लिया। दौलताना ग्रुप की मुस्लिम लीग ने भी सात सीटें प्राप्त कर लीं। जमायत इस्लामी केवल चार सीटें प्राप्त कर सकी, जबकि भुट्टो के दल ने ८१ सीटें जीतीं। पूर्वी बंगाल विधान सभा में अवामी लीग ने आठ के अतिरिक्त बाकी सभी सीटों पर अधिकार कर लिया। सीमा प्रान्त और बिलोचिस्तान में वली खान की नेशनल अवामी पार्टी का बोल-बाला रहा। इस बात से स्पष्ट था कि केन्द्र और पूर्वी बंगाल में अवामी लीग बहुमत होने के कारण अपने मंत्रिमण्डल बना सकती थी और नेशनल असेम्बली में बहुमत होने के कारण वह अपनी इच्छानुसार विधान तैयार कर सकती थी। परन्तु न तो सैनिक शासक यह चाहते थे न ही भुट्टो को यह बात पसन्द थी इसलिये जनता को पराजित करने के लिये नई चालें चली जाने लगीं। सबसे पहली चाल यह थी कि भारत से युद्ध किया जाये। १८ जनवरी १९७१ को काश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान के जासूसों और एजेंटों का एक संगठित गिरोह जिसके २२ सदस्य थे पकड़ लिया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के एक उच्च अधिकारी सरदार इकबाल राठौर से इन लोगों का सीधा सम्बन्ध था। राठौर को

भारत से निकल जाने का आदेश दिया गया। यह मालूम होने पर कि शेख अब्दुल्ला के “रायशुमारी मुहाज” का भी पाकिस्तान से सम्बन्ध है, इस सस्या को अवैध घोषित कर दिया गया और शेख और मिर्जा अफजल बेग के काश्मीर में प्रवेश की मनाही कर दी गई।

इससे पहले पुलिस ने पंजाब में पाकिस्तानी जासूसों का एक गिरोह पकड़ा था, जिसके नेता हिन्दुओं के वेष में रह कर जासूसी कर रहे थे। काश्मीर और जम्मू में कई और पाकिस्तानी जासूस भी पकड़े गये। पाकिस्तान की इन हरकतों से यह सिद्ध हो गया कि पाकिस्तान काश्मीर पर हमला करने के लिये तैयारियाँ कर रहा था। यह भी मालूम हुआ कि पाकिस्तानी एजेंटों ने काश्मीर के मुख्य मंत्री और दूसरे मंत्रियों की हत्या का षड्यंत्र रचाया था।

जनवरी के अन्तिम सप्ताह में दो पाकिस्तानी एजेंटों मुहम्मद अशरफ और हाशिम कुरेशी ने भारत के एक विमान का अपहरण किया और उसे लाहौर ले जाकर बाख़्द से उड़ा दिया। इनमें से एक कुछ सप्ताह पहले पाकिस्तान से श्रीनगर आया था और भारतीय अधिकारियों को उसने सूचना दी थी कि पाकिस्तान भारत के विमानों का अपहरण करने के लिये तैयारियाँ कर रहा है। यह व्यक्ति भारतीय सरकार की एक एजेंसी में भरती हो गया और इसे ही श्रीनगर और जम्मू के बीच भारतीय विमानों की देख-भाल का काम सौंपा गया। वास्तव में यह व्यक्ति पाकिस्तान षड्यंत्र के अनुसार काम कर रहा था। बाद में मालूम हुआ कि उसकी चाल यह थी कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के सुपुत्र को किसी विमान पर भगा लिया जाये। यह षड्यंत्र विफल रहा तो फैसला किया गया कि काश्मीर के मुख्य मंत्री श्री जी० एम० सादिक श्रीनगर से जिस विमान पर बैठे उसका अपहरण कर लिया जाये और इसके बाद समस्त सत्तार में प्रोपेगैंडा किया जाये कि काश्मीर में स्वतन्त्रता संग्राम हो रहा है। जिस विमान का अपहरण किया गया, उसमें

मुख्य-मंत्री ने यात्रा करनी थी परन्तु किसी कारण उन्होंने अपना विचार बदल दिया । दूसरी ओर सरकार पाकिस्तानी गुप्तचरो को गिरफ्तार कर रही थी, इसलिये इन पाकिस्तानी एजेंटो ने स्टन्टबाजी के लिये इसी भारतीय विमान का अपहरण कर लिया । जब यह विमान लाहौर के अड्डे पर उतरा तो एक ओर मि० भुट्टो और दूसरी ओर लाहौर के जिलाधीश पाकिस्तानी एजेंटो के स्वागत के लिये गये । दोनो एजेंटो ने धमकी दी कि यदि काश्मीर में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को मुक्त न किया गया और शेख अब्दुल्ला और उनके साथियों पर से प्रति-बन्ध न हटाया गया तो इस विमान को नष्ट कर दिया जायेगा । पाकिस्तान सरकार के एक प्रवक्ता ने इन मांगो का समर्थन किया और पश्चिमी पाकिस्तान के सभी समाचार पत्रो ने लिखा कि काश्मीर को “स्वतन्त्र” कराने के लिये संघर्ष शुरू हो गया है और अभी इससे भी बड़ी कई घटनाये होगी ।

जाहिर है कि इस हरकत का मतलब पाकिस्तानी जनता की असली समस्याओ से ध्यान हटाकर भारत से युद्ध के लिये तैयारिया करना था । परन्तु भारत सरकार ने साहस से काम लेकर भारत पर पाकिस्तानी विमानो की उड़ानो की मनाही कर दी और सीमाओ की रक्षा के लिये उचित प्रबन्ध कर लिया । यद्यपि पश्चिमी पाकिस्तान के नेता भारत को युद्ध की धमकिया दे रहे थे परन्तु पूर्वी बंगाल के नेताओ ने स्पष्ट शब्दो में इस घटना की निन्दा की । उन्होंने आरोप लगाया कि यह हरकत बंगाली जनता के आन्दोलन को विफल करने के लिये की गई है । उनके समाचार पत्रो ने लिखा कि यह कोई नई बात नहीं । जब भी जनता अपने अधिकारो के लिये संघर्ष करती है उन्हें विफल करने के लिये भारत से झगडा मोल ले लिया जाता है । याहिया खा के समर्थको ने इस पर पश्चिमी पाकिस्तान में बंगाली नेताओ के विरुद्ध प्रदर्शन कराये ।

भुट्टो ने अवामी लीग के नेताओं को सरकार की बागडोर देने का विरोध शुरू कर दिया। याहिया खा के समर्थकों ने कहना शुरू कर दिया की अवामी लीग के नेता पाकिस्तान को खतम कर देना चाहते हैं। याहिया खा ने कहना शुरू किया कि पहले सभी दलों के नेता आपस में बातचीत करके भविष्य के सविधान के सम्बन्ध में बातचीत करें, तब ही नेशनल असेम्बली का अधिवेशन बुलाया जायेगा। अवामी नेता जानते थे कि यह एक खतरनाक चाल है और याहिया खा का उद्देश्य नेशनल असेम्बली के सदस्यों में फूट डाल कर अपना उल्लू सीधा करना है। वह मांग कर रहे थे कि प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के अनुसार बहुमत रखने वाले दल को मन्त्रिमण्डल निर्माण करने का आमन्त्रण दिया जाये और सविधान तैयार करने का काम असेम्बली को सौंपा जाये। जनता के दबाव पर याहिया खा ने घोषणा की कि ३ मार्च को ढाका में असेम्बली का अधिवेशन शुरू हो जायेगा। भुट्टो ने इसका बहिष्कार करने की घोषणा कर दी और धमकी दी कि पश्चिमी पाकिस्तान से जो भी सदस्य जायेगा उसकी टांगें तोड़ दी जायेगी। उन्होंने यह भी धमकी दी कि मैं समस्त पाकिस्तान में आन्दोलन की आग लगा दूंगा। इस पर याहिया खा ने अधिवेशन स्थगित कर दिया और पुनः इस बात पर जोर देना शुरू किया कि अधिवेशन से पहले सभी दलों के नेता आपस में समझौता कर लें। इन्हीं दिनों दिल्ली में सूचना मिली कि पाकिस्तानी सेना को बुला लिया गया है और तेजी से नई भरती भी की जा रही है। पश्चिमी पाकिस्तान से सेनाओं को पूर्वी बंगाल में भेजा जाने लगा। इन गतिविधियों का यही उद्देश्य था कि बंगाली जनता को कुचल देने की तैयारियाँ की जायें। याहिया खा ने पूर्वी बंगाल के बंगाली राज्यपाल एडमिरल एसन को इस्लामाबाद में बुलाया और उनके ढाका में पहुंचते ही उन्हें डिसमिस करके लेफ्टिनेन्ट जनरल शहाबुद्दीन को उनकी जगह नियुक्त करने की घोषणा कर दी। रेडियो पर भाषण देते हुए याहिया खा ने कहा कि भारत

ने स्थिति बिगाड़ दी है, इसीलिये मैंने असेम्बली का अधिवेशन स्थगित कर दिया है। बंगाली समझ गये कि उन्हें गुलामी की जजीरो में जकड़े रखने के लिये भारत का नाम घसीटा जा रहा है। ढाका, चटगाव, सिल्हट और दूसरे शहरों में जनता याहिया खा के विरुद्ध उठ खड़ी हुई। पुलिस और सेना से उसका टकराव होने लगा।

याहिया सरकार ने अब यह प्रोपेगैंडा करना शुरू किया कि भारत पूर्वी बंगाल पर आक्रमण करने के लिये तैयारियाँ कर रहा है और पूर्वी बंगाल में पाकिस्तानी सेना को भेजने में रुकावट डालने के लिये भारत ने अपने ही एजेंटों द्वारा अपने विमान का अपहरण कराके और लाहौर में उसे नष्ट कराके इस दुर्घटना की ओट ली और पाकिस्तानी विमानों की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया। यह एक और भूठ था क्योंकि भारतीय विमान का अपहरण करने वालों को इससे पहले पाकिस्तान ने ही “स्वतंत्रता संग्राम के वीर सैनिक” करार दिया था। याहिया खा को शायद इस बात की आशंका नहीं हुई थी कि उनका यह षड्यंत्र उनके अपने लिये खतरनाक सिद्ध होगा। बंगाली जनता को उसके आन्दोलन से हटाया नहीं जा सका। और इस स्थिति में पाकिस्तान के लिये भारत सरकार से युद्ध करना भी असम्भव था। इस पर समुद्र के रास्ते याहिया खा ने पूर्वी बंगाल में सेनायें भेजना शुरू कर दिया। यह बात स्पष्ट हो रही थी कि याहिया खा बंगाली जनता पर प्रहार करने के लिये तैयारियाँ कर रहे थे।

शेख मुजीबुर्रहमान ने तानाशाही की इस घाघली के विरुद्ध हड़ताल करने का आदेश दे दिया और याहिया सरकार से पूर्ण नामलवर्तन का आन्दोलन शुरू कर दिया। यह आन्दोलन इतना सफल हुआ कि पूर्वी बंगाल के सरकारी कर्मचारियों ने पाकिस्तानी अधिकारियों का कोई भी आदेश मानने से इन्कार कर दिया। यहाँ तक कि याहिया खा के नियुक्त किये हुए सैनिक गवर्नर को हाई कोर्ट के जजों ने पद सम्भालने की सौगंध दिलाने से साफ इन्कार कर दिया। सरकारी कार्यालयों, पुलिस थानों,

बन्दरगाहों और बैंकों में शोख साहिब के सिवा किसी का आदेश नहीं माना जाता था। याहिया खा पश्चिमी पाकिस्तान से जो सेना भेज रहे थे, बंगाली उसे राशन नहीं देते थे। रेलवे कर्मचारी उनके लिये गाड़िया नहीं चलाते थे, बन्दरगाहों पर कर्मचारी सैनिक सामान जहाजों से नहीं उतारते थे। सेना जगह-जगह गोलियों का प्रयोग कर रही थी परन्तु जनता जान पर खेल कर मुकाबला कर रही थी।

ऐसी स्थिति में याहिया खा स्वयं ढाका में आये। भुट्टो, अब्दुल कयूम, और दूसरे नेता भी आये। याहिया खा ने बातचीत का नाटक रचाया परन्तु वास्तव में वह बंगाली जनता को सैनिक शक्ति से कुचल देने की तैयारियाँ कर रहे थे। शोख मुजीबुर्रहमान ने घोषणा की कि उन्होंने पूर्वी बंगाल का सिविल शासन अपने हाथ में ले लिया है। समस्त प्रान्त में इसका स्वागत किया गया। यहाँ तक कि उनके विरोधी मि० नूरउल अमीन ने भी जो नेशनल असेम्बली में शोख साहिब के एकमात्र विरोधी बंगाली सदस्य थे शोख साहिब की माँगों के समर्थन में घोषणा कर दी। प्रान्तीय सरकार पर वास्तव में शोख साहिब का अधिकार हो गया था। सभी सरकारी कर्मचारी उनके आदेशों के अनुसार काम कर रहे थे। याहिया खा जानते थे कि इस समय टक्कर लेना कठिन है। इसलिये वह पश्चिमी पाकिस्तान से अधिक से अधिक सेना लाकर प्रहार करना चाहते थे। उन्हें बंगाली पुलिस और बंगाली सेना पर भी कोई विश्वास नहीं रहा था। उन्हें मालूम हो चुका था कि सभी बंगाली अवामी लीग और शोख साहिब के समर्थक हैं। स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई थी कि बंगाली कर्मचारियों ने याहिया खा के लिये भोजन तैयार करने से इन्कार कर दिया था। रेडियो पाकिस्तान के ढाका स्टेशन ने अपना नाम बदल कर “बंगला देश बेतार केन्द्र” रख लिया था और खुलकर शोख साहिब के आन्दोलन का समर्थन शुरू कर दिया।

शोख साहिब को पुलिस और बंगाली सैनिक अधिकारियों ने कहा

था कि याहिया खा को गिरफ्तार कर लिया जाय परन्तु शेख साहिब इस मीमा तक जाना नहीं चाहते थे। वह याहिया खा से समझौता करना चाहते थे परन्तु याहिया खा ने धोखा दिया। २५ मार्च की रात को अचानक बातचीत खत्म करके कराची लौट गये और पाकिस्तानी सेना ने अकस्मात ढाका पर हमला कर दिया। आधी रात के बाद शेख साहिब को गिरफ्तार करके पाकिस्तानी सेना ने विश्वविद्यालय, पुलिस और बंगाली सेना के प्रधान कार्यालयों पर मशीनगनों और टैंकों का प्रयोग करके हमला कर दिया। विश्वविद्यालय में सैकड़ों विद्यार्थियों को मौत के घाट उतार दिया गया। शहर में जगह-जगह आग लगा दी गई। जो बंगाली सामने दिखाई दिया उसे गोली का निशाना बना दिया गया। मन्दिर, मस्जिदें जलाई जा रही थीं। ऐसा मालूम होता था कि ढाका रणभूमि बन गया है। ढाका विश्वविद्यालय के कई देशभक्त प्रोफेसर अपने कमरों में जिन्दा जला दिये गये। विश्वविद्यालय के होस्टल में रहने वाली लड़कियों पर हमला किया गया। सैकड़ों को मौत के घाट उतार दिया गया। कई ने अपनी इज्जत बचाने के लिये छलांग लगा कर आत्महत्या कर ली। पाकिस्तानी सैनिक जुल्म में चगेज खान और हिटलर को भी मात कर रहे थे। उन्होंने बंगाली लड़कियों और स्त्रियों पर बलात्कार किया। उनकी छातियाँ काट डाली और उनके नग्न शव बाजारों और गलियों में फेंक दिये ताकि दूसरे लोग यह सब कुछ देख कर भयभीत हों।

ढाका में बंगाली पुलिस और सेना पर उस समय हमला हुआ था जब यह सैनिक सो रहे थे। फिर भी उन्होंने डटकर मुकाबला किया। सैकड़ों मारे गये। जो बचे वह भाग कर सुरक्षित स्थानों पर पहुँच गये और उन्होंने युद्ध जारी रखा।

ऐसी अवस्था में बंगाली नेताओं ने घोषणा की कि अब पाकिस्तान के साथ रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्होंने अपने देश—

बंगला देश—को स्वतंत्र घोषित करते हुए पाकिस्तानी सेना से बाका-यदा युद्ध शुरू कर दिया। याहिया खा ने कराची पहुँचते ही रेडियो से बोलते-हुए आरोप लगाया कि शेख मुजीबुर्रहमान समेत अवामी लीग भारत की एजेंट है। इसलिये लीग को भग कर दिया गया है। शेख मुजीबुर्रहमान के विरुद्ध पाकिस्तान से गद्दारी के आरोप में मुकदमा चलाया जायेगा। नेशनल असेम्बली के जो सदस्य लीग से सम्बन्धित रहेंगे, उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जायेगी। याहिया खा ने घोषणा की कि उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया है कि विद्रोहियों को सख्ती से कुचल दिया जाये। उन्होंने समस्त पाकिस्तान में मार्शल ला लागू कर दिया। समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया गया। जलसों और जलूसों की मनाई कर दी गई। सैनिक सरकार की किसी भी कार्यवाही की आलोचना करना जुर्म करार दिया गया और देश के दोनों प्रान्तों में घडाघड गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया।

ढाका में जो कुछ हुआ वही पूर्वी बंगाल के दूसरे शहरों और देहात में हुआ। पाकिस्तानी सेना बहुत बड़े पैमाने पर नरसंहार कर रही थी। बस्तियों की बस्तियाँ लूटी और जलाई जा रही थी। अवामी लीग के समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ ही विद्यार्थियों, प्रोफेसरों, डामौ केषा कटरो, तट उतारना शुरू कर बकीलो और युवक वर्ग को दिया गया। पूर्वी बंगाल से सभी विदेशी पत्रकारों को बाहर निकाल दिया गया ताकि इस नरसंहार का व्योरा ससार को न मिल सके। परन्तु किसी न किसी तरह यह समाचार बाहर जाने लगे।

पूर्वी बंगाल की जनता युद्ध के लिये तैयार नहीं थी। कोई ऐसा सगठन भी नहीं था जो आक्रमणकारियों का मुकाबला करने के लिये जनता को तैयार कर सके। फिर भी आक्रमणकारी सेना के आतंक ने जनता को लडने के लिये मजबूर कर दिया। पूर्वी बंगाल के सभी भागों में विद्रोह की सी स्थिति पैदा हो गई। लोग लाठियों, भालों और

कुल्हाडियो से मुकाबला करने लगे। पाकिस्तानी सेना के पास बंदूके, मशीनगने, तोपे, टैंक और बमवर्षक विमान थे। इसके मुकाबले में जनता शस्त्रहीन होने पर भी मुकाबला कर रही थी। कई स्थानों पर लाठिया लिये हुए हजारों व्यक्तियों ने चारों ओर से पाकिस्तानी सिपाहियों को घेर कर पीट-पीट कर मार डाला। कई स्थानों पर पुलिस की चौकियों पर हमला करके क्रोध से बिफरे हुए लोगों ने शस्त्र छीन लिये और लड़ाई शुरू कर दी। जनता का कोई संगठन न होने पर भी लोग स्वयं ही अपने नेता बन गये। बंगाली सरकारी कर्मचारी, अफसर और पुलिस के लोग विद्रोहियों में सम्मिलित होने लगे। यह सभी याहिया खा की सेना के आतंक से दुखी होकर मरने-मारने के लिये घरों से बाहर निकल आये थे। पाकिस्तानी सेना को रोकने के लिये सड़को और रेल की लाइनों को उखाड़ा जाने लगा। पुल और बिजली-घर नष्ट किये जाने लगे। पाकिस्तानी सेनाओं के जुल्म को देख कर ससार भर में क्रोध और घृणा की लहर फैलने लगी। राजनीतिक नेता और पत्रकार फतवे देने लगे कि याहिया खा की सेना पूर्वी बंगाल में जो नरसंहार कर रही है, उसने चंगेज खा, हलाकू और हिटलर के जुल्म को भी मात कर दिया है।

याहिया खा ने जहाँ इस नरसंहार की आज्ञा दी थी वहाँ उसने यह फैसला भी किया कि अधिक से अधिक बंगालियों को भारत में धकेल दिया जाये ताकि एक तो पूर्वी बंगाल की आबादी पश्चिमी पाकिस्तान की आबादी के मुकाबले में कम हो जाये और दूसरे लाखों बंगालियों के भारत में चले जाने से भारत में साम्प्रदायिक फसाद शुरू हो जाये। पाकिस्तानी शासक अपनी राजनीतिक कठिनाइयों पर काबू पाने के लिये वर्षों से इन ही हथकण्डों का प्रयोग कर रहे थे। वे चाहते थे कि भारत में साम्प्रदायिक फसाद हो ताकि ससार का ध्यान पूर्वी बंगाल में होने वाले नरसंहार से हटाकर यह प्रोपेगैंडा किया जाये कि भारत में मुसलमानों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। परन्तु याहिया खा इस

चाल में सफल नहीं हुए।

भारत के सभी राजनीतिक दलों ने याहिया खा की हरकतों की निन्दा की। पूर्वी बंगाल की जनता के प्रति सहानुभूति प्रकट की और निश्चय कर लिया कि भारत में किसी भी हालत में साम्प्रदायिक दंगे नहीं होने दिये जायेंगे।

याहिया खा ने भारत के मुसलमानों को भड़काने के लिये प्रोपेगैंडा शुरू किया कि शेख मुजीबुर्रहमान के समर्थकों ने पूर्वी बंगाल में भारत से गये हुए मुसलमानों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया था, इसलिये उनकी रक्षा के लिये पाकिस्तानी सेना को कार्यवाही करनी पड़ी है। इस भूटे आरोप का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

यद्यपि २५ मार्च को शेख मुजीबुर्रहमान की गिरफ्तारी और ढाका में याहिया खा की सेना के आक्रमण करने के बाद ही अवामी लीग के नेताओं ने स्वतंत्रता-संग्राम आरम्भ करने की घोषणा कर दी थी परन्तु अवामी लीग के अधिकारी किसी एक जगह एकत्रित नहीं हो सके थे। पाकिस्तानी सेना चुन-चुन कर उनकी हत्या कर रही थी। किसी को एक दूसरे के सम्बन्ध में कुछ मालूम नहीं था। बंगाली सैनिक इस स्थिति से दुखी थे। चटगाव में बंगाली सेना पाकिस्तानी आक्रमणकारियों का मुकाबला कर रही थी। ईस्ट बंगाली सेना के कमाण्डर जनरल जिया-उद्दीन थे चटगाव के रेडियो स्टेशन पर अधिकार कर लिया और वहाँ उन्होंने घोषणा की कि शेख मुजीबुर्रहमान की अध्यक्षता में स्वतंत्र बंगला देश सरकार की स्थापना कर दी गई है और इस सरकार ने पाकिस्तान से युद्ध करने की घोषणा कर दी है। जनरल जिया-उद्दीन की इस घोषणा से दूसरे स्थानों पर भी बंगाली सैनिकों को डट जाने का साहस हुआ। पाकिस्तानियों ने जगह-जगह बंगाली सिपाहियों से शस्त्र छीन लेने की कोशिश की। कई एक स्थानों पर उनकी चौकियों और ठिकानों पर हमले भी किये परन्तु बहुत से बंगाली सैनिक सुरक्षित स्थानों पर पहुँच जाने

मे सफल हो गये। हजारों सिपाही अपने साथ छोटे-छोटे शस्त्र भी ले आये। जनरल जिया-उद्दीन कई दिन तक मुकाबला करते रहे। अन्त मे वह अपने सैकड़ों सिपाहियों को सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्र मे लाने मे सफल हो गये और वहा उन्होंने अपनी सेना के पुर्नगठन का काम शुरू कर दिया।

२० अप्रैल को अवामी लीग के कई उच्च नेता नेशनल असेम्बली के सदस्य और सैनिक अधिकारी भारत की सीमा के निकट एक स्थान पर एकत्रित हुए। यहा विधिपूर्वक स्वतंत्र सरकार की स्थापना की गई। शेख साहिब को राष्ट्रपति घोषित किया गया परन्तु चूँकि वह पाकिस्तानी सेना की कैद मे थे इसलिये कार्य चलाने के लिये उनकी अनुपस्थिति मे श्री कमुरज्जमान को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। श्री ताजुद्दीन को प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया और कर्नल उसमानी को स्वतंत्र सेना का प्रधान सेनापति और सरकार का रक्षामंत्री नियुक्त किया गया। मन्त्रिमण्डल के सदस्यों ने अपने पदों का चार्ज लेते हुए युद्ध जारी रखने का प्रण लिया। स्वतंत्र देश का सुनहरी लाल झण्डा लहराया गया। स्वर्गीय रवीन्द्र नाथ ठाकुर के गीत “आमार सोनार बागला” को राष्ट्रीय गान का दर्जा देकर गाया गया और स्वतंत्र सेना ने राष्ट्रीय ध्वज को बैण्ड-बाजे से सलामी दी। इस समय कई विदेशी पत्रकार भी उपस्थित थे।

भारतीय ससद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव स्वीकृत करके बगला देश की जनता के सघर्ष से सहानुभूति प्रकट की। भारत के सभी राजनीतिक दलों ने बगला देश स्वतंत्रता आन्दोलन का समर्थन किया। ससार के विभिन्न देशों से पत्रकार, राजनीतिक नेता, ससद सदस्य और मंत्री भारत और बगला देश मे आने लगे। उन्होंने अपनी आँखों से पीड़ितों और स्वतंत्रता सन्ग्रामियों को देखा और प्रभावित हुए।

भारत सरकार ने बगला देश से लाखों की सख्या मे आने वाले शरणार्थियों की स्थिति पर ससार का ध्यान दिलाया तो याहिया खा

ने शोर मचाया कि भारत सरकार अपने भूखे-नगे लोगो को कैम्पो मे रखकर उनके नाम पर दूसरे देशो से सहायता लेने के लिये यह आरोप लगा रही हे कि यह दुखी शरणार्थी है, परन्तु ससार ने इस भूठ को सत्य नही माना। इसके बाद जब शरणार्थियो की सख्या एक करोड के लगभग हो गई तो याहिया खा ने कहा कि केवल बीस लाख व्यक्ति पूर्वी बंगाल मे विद्रोहियो से भयभीत होकर भाग गये थे परन्तु अब वह तेजी से लौट रहे है और उनकी सरकार उन्हे पुन आबाद कर रही है, परन्तु अब यह भी भूठ था। याहिया की सरकार ने दिखावे के लिये जो कैम्प खोले थे उनमे विदेशी पत्रकारो को लौट कर आने वाला कोई शरणार्थी दिखाई नही दिया। एक विदेशी पत्रकार ने लिखा कि इन कैम्पो मे पशु तो दिखाई देते है परन्तु कोई व्यक्ति दिखाई नही देता। इस पर याहिया सरकार ने शोर मचाना शुरू किया कि शरणार्थी तो लौट आना चाहते है परन्तु भारतीय सरकार अपने राजनीतिक हितो के लिये उन्हे लौट आने नही देती।

बंगला देश सरकार स्थापित हो जाने के परिणाम स्वरूप ससार भर मे पूर्वी बंगाल के लोगो मे जिन्दगी की लहर दौड गई। सबसे पहले नई दिल्ली मे याहिया सरकार के दूतावास के दो सीनियर बंगाली अधिकारियो ने विद्रोह का झण्डा उठाया और बंगला सरकार से वफादारी की घोषणा कर दी। इसके बाद कलकत्ता मे पाकिस्तानी दूतावास के बंगाली अध्यक्ष और उसके समस्त बंगाली स्टाफ ने विद्रोह किया। उन्होने दूतावास की इमारत पर बंगला देश का झण्डा लहरा कर कार्यालय का नाम “बंगला देश दूतावास” रख दिया। यह आन्दोलन दूसरे देशो मे भी फैला। ब्रिटेन मे पाकिस्तानी दूतावास अके सभी बंगाली फसरों और कार्यकर्ताओ ने त्यागपत्र देकर पाकिस्तानी शासको के अत्याचारो की निन्दा की। ढाका हाई कोर्ट के एक सीनियर न्यायाधीश भाग कर लन्दन पहुच गये थे। उनके नेतृत्व

मे इन बगाली अधिकारियो ने लदन मे बगला देश का दूतावास स्थापित कर दिया। ब्रिटेन मे बगला देश के एक लाख से अधिक नागरिक रहते है। उन्होने याहिया शाही के विरुद्ध प्रदर्शन किया और बगला देश मे सरकार की आर्थिक सहायता के लिये रुपया एकत्रित करना शुरू कर दिया।

अमरीका, फ्रांस, जापान, फिलीपाइन, कनाडा, हालैण्ड, हागकाग आदि देशो मे भी बगाली स्टाफ ने पाकिस्तानी दूतावासो से त्यागपत्र देने के साथ ही दूतावास का कोष भी बगला देश सरकार के हवाले कर दिया। धीरे-धीरे नई दिल्ली मे पाकिस्तानी कार्यालय के अन्य सभी बगाली कर्मचारियो ने भी यही मार्ग अपनाया। पाकिस्तानी अधिकारी कुछ बगाली कर्मचारियो को एक बस मे सवार करके लाहौर ले जाना चाहते थे परन्तु उन्होने सीमा के इस पार छलाग लगा कर अपने आप को मुक्त करा लिया और बगला देश सरकार के लिये काम करने की घोषणा कर दी।

इन बगालियो के साथ ही पश्चिमी पाकिस्तान से कितने ही दूसरे बगाली सैनिक अधिकारी भाग कर भारत मे आ गये।

इन बगालियो के विद्रोह से दो महत्वपूर्ण परिणाम निकले। पहला यह कि ससार को मालूम हो गया कि कोई बगाली याहिया खा की सरकार से सहयोग करने के लिये तैयार नहीं। दूसरे इन बगाली डिप्लोमेटो के अलग हो जाने से भारत मे याहिया शाही के कई पड्यत्रो का भेद ले गया। उदाहरण स्वरूप यह मालूम हुआ कि

याहिया सरकार भारत मे जासूसी और तोड-फोड के लिये चिर-काल से अपने एजेटो के गिरोह सगठित कर रही थी। जासूसी के लिये कई पाकिस्तानी हिन्दुओ और सिखो के वेष मे घुमे हुए थे और साधुओ, व्यापारियो, हाकरो और भिखारियो आदि का वेष धारण कर के जासूसी कर रहे थे।

सबसे पहले कलकत्ता में छापे मार कर पुलिस ने संसद के एक भूतपूर्व सदस्य और प्रादेशिक सरकार के एक भूतपूर्व मंत्री को गिरफ्तार किया। इसके बाद कुछ पत्रकार गिरफ्तार किये गये। ये लोग रुपये के लालच में पाकिस्तान सरकार के लिये देशद्रोही गतिविधियों में लगे हुए थे। इसके ठोस प्रमाण केन्द्रीय सरकार को पाकिस्तानी दस्तावेजात के रूप में मिल गये थे।

आगरा और दिल्ली में पाकिस्तानी वायु सेना के दो अधिकारी पकड़े गये। दोनों हिन्दुओं के वेष में रह रहे थे। इनमें से एक ने हवाई अड्डे के निकट लाण्डरी की दुकान खोल रखी थी। यह व्यक्ति प्रायः धोने के लिये हवाई अड्डे के कर्मचारियों से कपड़े लाया करता था। अपने मकान के एक कमरे में उसने एक मन्दिर बना रखा था। उसमें रखी हुई शिव भगवान की मूर्ति के अन्दर उसने एक वायरलेस ट्रांसमीटर रखा हुआ था। इसका प्रयोग करके वह पाकिस्तान सरकार को अपनी रिपोर्टें भेजा करता था। दूसरे जासूस ने पंजाब के एक प्रसिद्ध हवाई अड्डे के निकट चाय का स्टाल खोला हुआ था।

पंजाब के एक सीमावर्ती नगर में एक पाकिस्तानी गुप्तचर एक साधु महात्मा के वेष में गिरफ्तार किया गया। उसने वहाँ एक मन्दिर बनवाया था और वह वहाँ पुराणों की कथा किया करता था और रोगियों को मुफ्त औषधियाँ दिया करता था। मन्दिर के एक तहखाने में उसने रेडियो ट्रांसमीटर लगा रखा था। जिला होशियारपुर में कपड़ा बेचने वाले हॉकरो के वेष में पाकिस्तानी जासूस पकड़े गये। काश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी कई पाकिस्तानी जासूस पकड़े गये।

पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में भी याहिया सरकार ने शरणाश्रितियों के वेष में अपने गुप्तचर और तोड़-फोड़ करने वाले एजेंट भेजने शुरू कर दिये। आरम्भ में कई एक पाकिस्तानी पकड़े गये जो कुओं में विष मिलाने के लिए आये थे।

कई एक के पास से छोटे-छोटे रेडियो ट्रांसमीटर मिले। कुछ पाकिस्तानी जासूस स्त्रियों के वेष में गिरफ्तार कर लिये गये। बाद में जो पाकिस्तानी एजेण्ट आये उन्होंने पुलो, रेल की लाइनों और दूसरे सरकारी ठिकानों को नष्ट करने की योजनाये बनाई हुई थी। ये लोग कुछ एक दुर्घटनाओं में सफल भी हुए परन्तु धीरे-धीरे इन पर काबू पा लिया गया। कई पाकिस्तानियों ने भारत में घुसते ही अपने आप को सरकारी अधिकारियों के हवाले कर दिया और बताया कि बंगला देश में पाकिस्तानी अधिकारियों ने जासूसी और तोड़-फोड़ की ट्रेनिंग देने के लिये कैम्प खोले हुए हैं।

यह देखकर कि बंगला देश सरकार को भारत में अपने सूचना केन्द्र स्थापित करने की अनुमति मिल गई है और स्वतंत्रता संग्रामियों को भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रों में शरण मिल जाती है याहिया खा ने भारत पर आक्रमण करने की धमकिया देना शुरू कर दिया। पश्चिमी पाकिस्तान के समाचार पत्रों में दावा किया जाने लगा कि युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान अकेला नहीं होगा। इसके उत्तर में भारत के विदेश मन्त्री ने कहा कि भारत भी अकेला नहीं। इसके कुछ दिन बाद ही भारत और सोवियत यूनियन में मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर हो गये और पाकिस्तानी शासकों को मालूम हो गया कि भारत अब अकेला नहीं। भारत के रक्षा मन्त्री श्री जगजीवनराम ने चेतावनी दी कि यदि पाकिस्तानी शासकों ने भारत पर युद्ध ठोसा तो यह युद्ध पाकिस्तान की धरती पर लड़ा जायेगा।

लगभग छ मास तक बंगला देश में स्वतन्त्र सरकार के सैनिक केवल गोरिल्ला हमले करते रहे। इन सैनिकों में अधिकतर कालेजों के विद्यार्थी और किसान और मजदूर युवक सम्मिलित थे। इस दौरान पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में बाकायदा सेना भी हमले करती रही परन्तु स्वतन्त्रता-संग्राम के सेनानियों की गतिविधिया अधिकतर पाकिस्तानी

सिपाहियों को परेशान करने तक सीमित रही। यह गोरिल्ले रेल की लाइनो, सैनिक रेल गाड़ियो, पुलो और बिजली-धरो को नष्ट करने और पाकिस्तानी सेना की छोटी-छोटी टुकड़ियो पर हमले करने तक सीमित रहे। नदियो और समुद्र की बन्दरगाहो मे जहाजो को डुबोने के लिये भी छापे मारे जाते। याहिया खा के किराये के टोले से सबध रखने वालो को मौत के घाट उतारा जाता। इस दौरान बाकायदा सेना जिसे मुक्ति-वाहिनी का नाम दिया गया आधुनिक शस्त्रो के प्रयोग और युद्धनीतियो का प्रशिक्षण प्राप्त करती रही। देखते-देखते लगभग एक लाख बगाली युवको ने गोरिल्ला ढग से और औपचारिक युद्ध की ट्रेनिंग प्राप्त कर ली। इस सेना ने बाकायदा हमले शुरू करके पाकिस्तानी सेना को ग्रामीण क्षेत्रो और शहरो से खदेडना शुरू कर दिया। याहिया खा की सरकार ने बगला देश मे पश्चिमी पाकिस्तान से सशस्त्र पुलिस भेजी। सचिवालय मे भी पश्चिमी पाकिस्तान से धडाधड कर्मचारी लाकर नियुक्त किये जाने लगे। बगाली बेकार लोगो पर दबाव डालकर अथवा लालच देकर उन्हे “रजाकार” सेना मे भरती किया जाने लगा। जिन लोगो का पेशा गुण्डागर्दी था उन्हे भी भरती किया जाने लगा परन्तु इनकी सहायता से भी मुक्तिवाहिनी को कुचलने मे किसी प्रकार की सफलता नहीं मिली। हजारो ऐसे युवक जिन्हे डरा-धमका कर भरती कर लिया गया था भाग कर भारत मे आ गये। किराये के सैकडो गुण्डो को मुक्तिवाहिनी ने मौत के घाट उतार दिया। बगला देश की जनता यहिया सरकार के मुकाबले मे मुक्तिवाहिनी से सहयोग कर रही है।

मुक्तिवाहनी ने सीमावर्ती बहुत से इलाको को स्वतत्र करा लिया और दूसरे ठिकानो को स्वतत्र कराने के लिये हमले शुरू कर दिये। मुक्ति वाहिनी के युवक ढाका, चटगाव और बारीसाल तक के दूर-दूर के इलाको मे लडने लगे। ढाका मे मार्च १९७१ के अन्त मे पाकिस्तानी

सेना ने बड़े पैमाने पर नरसंहार किया था परन्तु कुछ दिन बाद ही मुक्ति वाहिनी के गोरिलो ने ढाका नगर के अन्दर और बाहर फिर अपनी गतिविधिया शुरू कर दी। ढाका में आये दिन बम फटने लगे। सरकारी ठिकानों पर हमले होने लगे और कारखानों को आग लगाये जाने का सिलसिला शुरू हो गया। तीन बार नगर के बिजली-घरों को तोड़फोड़ दिया गया। ढाका में पाकिस्तान के भूतपूर्व राज्यपाल मुन्-हम खा को एक युवक ने गोली से उड़ा दिया। यह वही सज्जन है जिन्होंने अयूबशाही के दिनों राज्यपाल की हैसियत से ढाका में खून-खराबा कराया था और अन्त में अपनी जान बचाने के लिये नगे सिर और नगे पाव राजभवन से भाग कर एक विमान पर सवार हो रावलपिण्डी भाग गये थे। सैनिक अधिकारियों को उनका शव कब्रिस्तान तक ले जाने का साहस न हुआ बल्कि उसे मुन्हम खा की कोठी के अन्दर ही दबा दिया गया।

याहिया खा सरकार की स्थापित की हुई तथ्याकथित शान्ति-समितियों के कई अधिकारी इसी प्रकार गोलियों से उड़ा दिये गये। कुछ ही दिनों में एक दर्जन से अधिक पाकिस्तानी और विदेशी जहाज चटगाव, खुलना और चालना की बन्दरगाहों में डुबो दिये गये। पाकिस्तानी नवसेना की सैकड़ों नावों पर मुक्ति सेना ने अधिकार कर लिया।

याहिया शाही के आतंक और बंगला देश के स्वतंत्रता संग्राम से समस्त ससार प्रभावित हुआ। सोवियत यूनियन की सरकार ने आरम्भ में ही कह दिया था कि बंगला देश के झगड़े का एकमात्र हल यह है कि पाकिस्तानी शासक जनता को उसके अधिकार देना स्वीकार कर ले। सोवियत यूनियन के प्रधान ने याहिया खा को लिखा कि शेख मुजीबुर्रहमान को रिहा करके उनसे समझौते की बातचीत की जाये। दूसरे कई देशों ने भी यही सुझाव दिया। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान,

कैनेडा, आस्ट्रेलिया आदि देशों ने पाकिस्तान को सैनिक और आर्थिक सहायता देना बंद कर दिया। इसमें सन्देह नहीं की अमरीका ने अप्रैल में ही पाकिस्तान को सैनिक सहायता देना बंद करने की घोषणा कर दी थी परन्तु इसके बाद भी पाकिस्तान को युद्ध सामग्री मिलती रही। इस पर अमरीका के सभी राजनीतिक दलों और पत्रकारों ने सरकार की कड़ी आलोचना की। ससद के दोनों हाउसों ने पाकिस्तान को सभी प्रकार की सहायता न देने की मांग की। इस पर सरकार को झुकना पड़ा परन्तु बाद की घटनाओं से यह सिद्ध हो गया कि अमरीका के राष्ट्रपति श्री निकसन किसी की भी परवाह न करते हुए याहिया सरकार की सहायता कर रहे थे। बंगला देश के स्वतंत्रता संग्राम को विफल करने के लिये वह राष्ट्र सभ के प्रेक्षकों का प्रयोग करना चाहते थे। शायद उसके इशारे पर ही याहिया खा बंगला देश से गद्दारी करने वाले डाक्टर मलिक को पूर्वी बंगाल का राज्यपाल नियुक्त कर दिया और दिसम्बर १९७० के चुनावों में हारे हुए व्यक्तियों को बिना मुकाबला चुनाव के नाटक में जनता के प्रतिनिधि घोषित करके डाक्टर मलिक की कठपुतली सरकार में मंत्री बना दिया। इस नाटक को और आगे ले जाकर याहिया खा ने एक और गद्दार श्री नूरुल अमीन को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और श्री भुट्टो को उप-प्रधानमंत्री नियुक्त करने के इरादे की घोषणा कर दी। डा० मलिक और नूरुल अमीन आदि गद्दारों से गठजोड़ करके याहिया खा यह दावा करना चाहते थे कि उन्होंने पूर्वी बंगाल के “प्रतिनिधियों” से समझौता कर लिया है। अपने किराये के विशेषज्ञों से उन्होंने एक सविधान तैयार कराया जिसमें यह निश्चित किया गया था कि भविष्य में पाकिस्तान का राष्ट्रपति प्रधान सेनापति हुआ करेगा। इस सविधान को कानूनी रूप देने के लिये उन्होंने जमायत इस्लामी आदि विपक्षी दलों का एक संयुक्त दल बना लिया था। ऐसा मालूम होता है कि इस सविधान को श्री निकसन का आशीर्वाद प्राप्त

था। यदि यह षड्यंत्र सफल हो जाता तो श्री निक्सन दावा करते कि बंगला देश की राजनीतिक समस्या का समाधान हो गया है।

इसी दौरान पूर्वी बंगाल की कठपुतली सरकार ने जमायत इस्लाम को “अलबदर” और “अलरामस” नाम की तथाकथित स्वयंसेवक सैन्य संगठित करने की आज्ञा दी। इन तथाकथित स्वयं सेनकों को शस्त्र दिये गये और इन लोगों ने प्रगतिशील बंगाली प्रोफेसरों, डाक्टरों, वकीलों और कार्यकर्तों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। एक अनुमान के अनुसार दिसम्बर के पहले दो सप्ताहों में ढाका, नारायण गंज, जैसोर, खुलना और दीनाजपुर में एक हजार से अधिक ऐसे व्यक्तियों को इस्लाम के शत्रु घोषित करके गोली मार दी गई।

बंगला देश में स्वतंत्रता संग्राम की गति तीव्र हो रही थी। पाकिस्तान का दमन चक्र विफल हो रहा था। याहिया खा अब भारत को भी आक्रमण की धमकियाँ देने लगे। बाद की घटनाओं से सिद्ध हो जाता है कि अमरीका और चीन की सरकारें याहिया खा को इस बात के लिये भड़का रही थी कि वह भारत से युद्ध छेड़ दे जिससे सुरक्षा परिषद को दखल देने के लिये प्रयोग में लाया जा सके।

भारत पर आक्रमण याहियाशाही का अन्त

इसमें सदेह नहीं कि १९६५ के आक्रमण में हार जाने के तुरन्त बाद पाकिस्तान के तानाशाहों ने भारत पर एक और आक्रमण की तैयारियां शुरू कर दी थीं। ताशकन्द समझौते की अवहेलना करते हुए भारत से व्यापार के सम्बन्ध स्थापित नहीं किये गये। पश्चिमी बंगाल से पूर्वी बंगाल में दरियाओं के रास्ते जो व्यापार होता था उसे पुनः चालू करने से इन्कार कर दिया गया। भारतीय जहाजों से जब्त किया हुआ माल लौटा देने की जगह नीलाम कर दिया गया। भारत से समाचार पत्रों और पुस्तकों के निर्यात पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया और अमरीका, चीन और दूसरे देशों से धड़ा-धड़ विमान, टैंक और दूसरे शस्त्र खरीदना शुरू कर दिया गया। दिसम्बर १९७० में पाक अधिकृत काश्मीर के तथाकथित राष्ट्रपति सरदार अब्दुल क्यूम ने साफ-साफ कह दिया था कि १९७१ में काश्मीर पर अधिकार करने के लिये भारत पर आक्रमण किया जायेगा यदि बंगला देश में स्थिति न बिगड़ती तो मार्च तक १९७१ में याहिया खा भारत पर आक्रमण कर देता।

अगस्त १९७१ में याहिया खा ने भारत को युद्ध की धमकियां देना शुरू कर दिया। पाकिस्तान को अमरीका से युद्ध सामग्री मिल रही थी। याहिया शाही के समर्थन में चीनी शासकों ने भी बयान देना शुरू कर दिया। 'पाकिस्तान के समाचार पत्रों ने दावा कि युद्ध की हालत में

ईरान, जोरहन और तुर्की पाकिस्तान की सहायता करेंगे। याहिया खा ने स्वयं दावा किया युद्ध में पाकिस्तान अकेला नहीं होगा। इस पर भारत के विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ने चेतावनी दी कि याहिया खा यह न समझे कि भारत अकेला रहेगा। सुरक्षा मंत्री श्री जगदीश राम ने याहिया खान को चेतावनी दी कि वह भारत पर आक्रमण करने की बजाय बंगला देश के नेताओं से समझौता करे अन्यथा भारत पर हमला हुआ तो भारतीय सेना पाकिस्तान की धरती पर दो-दो हाथ करेगी। याहिया खान ने इसकी परवाह न करते हुए भारत की सीमाओं पर सेना को एकत्रित करना शुरू कर दिया। भारत अकेला नहीं इसका प्रमाण भारत और रूस में मित्रता की संधि से मिल गया। रूस की सरकार ने भारत सरकार की तरह याहिया खा को परामर्श दिया कि वह युद्ध के मार्ग पर चलने की बजाय बंगला देश के नेताओं से समझौता कर ले परन्तु याहिया खा अमरीका और चीन के दृष्टारों पर नाच रहे थे। २३ नवम्बर को तक्षशिला में चीन के एक प्रतिनिधि दल की उपस्थिति में याहिया खान ने एक भाषण में धमकी दी कि दस दिन के बाद वह पश्चिमी पाकिस्तान के युद्ध के मोर्चे पर होंगे। इससे कुछ ही दिन पहले याहिया खान ने अपने सीनियर जनरलों का एक दल श्री भुट्टो के नेतृत्व में चीन भेजा। वहाँ से लौट आने पर श्री भुट्टो ने कहना शुरू कर दिया कि युद्ध की स्थिति में चीन पाकिस्तान की पूरी-पूरी सहायता करेगा।

आक्रमण की तैयारियाँ करते हुए एक ओर याहिया खान की सेनाओं ने बंगला देश की सीमाओं से भारतीय क्षेत्रों पर गोलाबारी शुरू कर दी तो दूसरी ओर माग की कि भारत अपनी सेना सीमाओं से हटा ले। प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इसके उत्तर में कहा कि पाकिस्तान बंगला देश में अपनी सेना हटा ले तो हम भी अपनी सेनाएँ हटा लेंगे।

आक्रमण की तैयारियाँ करते हुए पाकिस्तानी विमानों ने काश्मीर और पंजाब की वायुसीमा का उल्लंघन किया। काश्मीर की युद्ध विराम रेखा पर पाकिस्तानी सेनाओं ने कई छापे मारे। नवम्बर के अन्तिम सप्ताह में चार पाकिस्तानी विमान बंगाल की वायुसीमा में आ घुसे। भारतीय वायु सेना के विमानों ने इनमें से तीन को गिरा लिया। दो पाकिस्तानी विमान चालको को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय सेना ने अपनी सीमा की ओर बढ़ती हुई पाकिस्तानी सेना को रोकने के लिये जवाबी कार्यवाई की। मन्त्रालय से भी इसी तरह भारतीय सेना को पाकिस्तानी हमले को रोकने के लिये कार्यवाई करनी पड़ी।

३ दिसम्बर १९७१ को सध्या समय से अकस्मात् पाकिस्तान की वायु सेना ने अमृतसर, श्रीनगर, पठानकोट और आगरा आदि भारत के हवाई अड्डों पर बम वर्षा शुरू की। पाक सेनाओं ने भी पश्चिमी पंजाब की सीमाओं पर हमले शुरू कर दिये। प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी उस समय कलकत्ता में थी। उन्होंने दिल्ली आकर रेडियो पर घोषणा की कि भारत किसी भी हमले का मुकाबला करेगा। ४ दिसम्बर को याहिया खा ने भारत पर आक्रमण की घोषणा कर दी। इसके उत्तर में भारतीय वायु सेना ने पश्चिमी पाकिस्तान में दूर-दूर तक सैनिक अड्डों पर बम वर्षा की और भारतीय सेना ने बंगला देश में प्रवेश करके मुक्तिवाहिनी से सम्पर्क करके आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दो दिन में ही भारतीय सेना ने यहाँ कई महत्वपूर्ण स्थानों पर अधिकार कर सभी पाकिस्तानी अड्डों को नष्ट कर दिया और पश्चिमी पाकिस्तान से बंगला देश का सभी प्रकार का सम्पर्क काट दिया। बंगला देश में पाकिस्तान की वायु और जल सेना को नष्ट कर दिया गया। पाकिस्तानी सेना ने कई स्थानों पर शस्त्र फैंक कर अपने आप को भारतीय सेना के आगे समर्पण करना शुरू कर दिया।

पश्चिमी पाकिस्तान में भारतीय सेना सिंध में घुस गई और उसने

एक ही दिन में कई स्थानों पर अधिकार कर लिया। भारतीय वायु सेना और जल सेना ने कराची के समुद्री अड्डे पर हमला करके पाकिस्तान के तीन विध्वंसक जगी जहाज डुबो दिये। यह हमला सफल रहा। कराची का हवाई और समुद्री अड्डा तबाह हो गया। तेल के भण्डारों में आग लग गई। बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान की प्रसिद्ध पनडुब्बी “गाजी” डुबो दी गई। अमरीका से मुफ्त मिली हुई यह पनडुब्बी शायद विशाखा-पटनम के भारतीय समुद्री अड्डे पर हमले के लिये भेजी गई थी।

भारतीय सेना की तीव्र प्रगति से परेशान होकर अमरीका ने राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव में भारत को आक्रमणकारी घोषित करने के लिये एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया। चीन ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया परन्तु जहा ब्रिटेन और फ्रांस ने धमकियों का साथ नहीं दिया वहाँ रूस के प्रतिनिधि ने अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करके इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया। अमरीका और चीन ने जो पाकिस्तान की पीठ ठोकने पर कटिबद्ध थे राष्ट्रसंघ की जनरल असेम्बली में यही प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया। यह प्रस्ताव भारत रूस और कई दूसरे देशों के विरोध पर भी स्वीकृत हो गया परन्तु इस प्रस्ताव द्वारा भारत को कोई आदेश नहीं दिया जा सकता था। भारत सरकार ने घोषणा की कि हमला पाकिस्तान ने किया है इसलिये मुकाबला किया जायेगा। इस दौरान भारतीय सेनाओं ने राजस्थान पर पाकिस्तान के सभी हमलों को विफल कर लगभग ३ हजार वर्ग मील क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। पंजाब में खेमकरण, और डेरा बाबा नानक के मोर्चों पर कई पाकिस्तानी देहात पर अधिकार कर लिया। साम्बा से बढ़ने वाली भारतीय सेना ने बड़कर स्यालकोट के पाकिस्तानी क्षेत्र में लगभग चार सौ वर्गमील क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। काश्मीर में टीथबाल पुच्छ से आगे बढ़कर भारतीय सेना ने कई पाकिस्तानी चौकियों पर अधिकार कर लिया। लद्दाख में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को ४०

चौकियो से भगा दिया ।

बगला देश मे पाकिस्तानी सेना किमी स्थान पर जम कर मुकाबला नही कर सकी । दो दिनो मे पाकिस्तानी वायुसेना को तबाह कर दिया था । ७ दिसम्बर को भारत सरकार ने और इसके बाद भूटान सरकार ने बगला देश सरकार को मान्यता दे दी और भारत और बगला देश ने मिलकर मुकाबला करने की घोषणा कर दी । इसी दिन भारतीय सेना ने जैसोर सिल्हट और कोमिला को मुक्त करा लिया । समाचार आने लगे कि पाकिस्तान सेना बगला देश से भाग जाने के लिये ढाका, चटगाव और वारीसाल की ओर जा रही है । भारतीय नव सेना ने समुद्र के सभी रास्ते बन्द कर दिये । ढाका और चटगाव को घेरने के लिये भारतीय सेना चारो ओर से बढ़ने लगी । पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना की प्रगति रोकने के लिये मार्ग मे आने वाले सभी पुल गिरा दिये परन्तु भारतीय सेना ढाका के चारो ओर पैराशूटो द्वारा उतरने लगी । १४ दिसम्बर के बगला देश के कठपुतली राज्यपाल डा० मलिक उसके मंत्रियो और सभी सीनियर सिविल अधिकारियो ने त्याग पत्र दे दिये । राज्यपाल के सैनिक सलाहकार मेजर जनरल फरमान अली ने राष्ट्र सभ के प्रतिनिधियो द्वारा सभ के प्रधान मंत्री से प्रार्थना की कि पाकिस्तान की सेना को बगला देश से निकाल देने के लिये सहायता दी जाये परन्तु याहिया खा ने इस प्रार्थना को स्वय ही रद्द कर दिया और दावा किया कि युद्ध जारी रहेगा । बाद की घटनाओ से मालूम हुआ कि अमरीका और चीन के झंझकाने पर याहिया खान ने ऐसा किया था । इन देशो के इशारे पर सुरक्षा परिषद मे एक और प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया परन्तु रूस ने इसे भी रद्द कर दिया ।

भारतीय सेना ढाका के दरवाजो पर पहुच चुकी थी । भारत के सेनापति श्री मानिक शाह ने बगला देश मे पाकिस्तान के सेनापति जनरल नियाजी को अल्टीमेटम दिया कि वह अपनी सेना को आत्मसमर्पण के

लिये आदेश दे दे अन्यथा भारतीय सेना ढाका पर निश्चयात्मक आक्रमण कर देगी। इसी समय समाचार आया कि अमरीका के राष्ट्रपति श्री निक्सन के आदेश से अमरीका का सातवा समुद्री बेड़ा बंगाल की खाड़ी में घुस रहा है। शायद इन गतिविधियों का मतलब भारत को भयभीत करना था परन्तु प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक भव्य समारोह में चेतावनी दी कि भारत किसी दबाव से झुकने वाला नहीं। सेनापति मानिकशाह ने पाकिस्तान के सेनापति को फिर चेतावनी दी और इसके बाद अपनी सेना को हमले का आदेश दे दिया। इस पर बचाव की कोई सूरत न देख कर जनरल नियाजी ने अपनी सेनाओं को आत्मसमर्पण करने का आदेश देना स्वीकार कर लिया। १६ दिसम्बर को भारतीय सेना की पूर्वी कमाण्ड के कमाण्डर जनरल जगजीत सिंह अरोरा हैली-कोप्टर पर कलकत्ता से ढाका पहुँचे और इतिहासक परेड ग्राउन्ड पर जहाँ २४ मार्च को शेख मुजीबुर्रहमान ने बंगला देश का झण्डा लहराया था जनरल नियाजी ने बंगला देश में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण की दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिये। भारतीय सेना ढाका नगर में प्रवेश कर गयी और स्वतन्त्र बंगला देश के नारों से शहर का वातावरण गूँज उठा।

देश के इतिहास में भारत की यह महान विजय थी। बंगला देश को स्वतन्त्र कराने के लिये भारतवासियों ने जो प्रण किया था हमारी सेना के जवानों ने पूरा कर दिखाया।

पश्चिमी पाकिस्तान की जनता को याहिया सरकार अधरे में रखती रही। अन्तिम घड़ियों तक उन्हें यही बताया जाता रहा कि पाकिस्तानी सेना सभी मोर्चों पर जीत रही है। पाकिस्तानी जनता को थह भी नहीं बताया गया कि बंगला देश में पाकिस्तानी सेना आत्मसमर्पण कर चुकी है। भारत सरकार ने बंगला देश के स्वतन्त्र होते ही घोषणा कर दी कि १८ दिसम्बर को ८ बजे रात पश्चिमी मोर्चे पर

लडाई बन्द कर दी जायेगी। पाकिस्तानी सेना इस मोर्चे पर भी हार रही थी। यदि लडाई बन्द न होती तो पश्चिमी पाकिस्तान भी खतम हो जाता। परन्तु भारत सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं था। इसलिए उसने युद्ध समाप्त करने का फैसला किया। याहिया खान को झुकना पड़ा और इस प्रकार जो युद्ध पाकिस्तान आक्रमण से ३ दिसम्बर को आरम्भ हुआ था वह पूरे १४ दिन बाद समाप्त हो गया। याहिया खान का घमण्ड टूट गया। बंगला देश स्वतन्त्र हो गया दो दिन बाद याहिया खान श्री भुट्टो को सरकार की बागडोर देकर स्वयं अलग हो गये। इस तरह १९५८ में पाकिस्तान में जो सैनिक तानाशाही स्थापित हुई थी वह भारत और बंगला देश से टक्कर लेने के परिणामस्वरूप खत्म हो गई। २२ दिसम्बर को जब पश्चिमी पाकिस्तान में याहिया खान के विरुद्ध मुकद्दमा चलाने की माग करते हुए जनता प्रदर्शन कर रही थी, ढाका में स्वतन्त्र बंगला वासी सरकार ने अपना कार्य सभाल लिया था।

किया। मुसलमानों में प्रचार किया गया कि उनकी आर्थिक दुर्दशा के लिये हिन्दू जिम्मेदार हैं। हिन्दुओं को कहा गया कि मुसलमान उनके शत्रु हैं। जहाँ यह नीति हिन्दुओं में राष्ट्रीयता की भावनाओं को रोक न सकी और हिन्दुओं के सभी वर्गों के नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़-चढ़-कर भाग लिया वहाँ देशभक्त मुसलमान नेताओं को बदनाम और परेशान करने के लिये किराये के मौलवियों से उनके विरुद्ध प्रचार कराया गया। ज्यू-ज्यू स्वतंत्रता का मघर्ष तेज होता गया, अंग्रेज शासक मुसलमानों को हिन्दुओं के विरुद्ध अधिक-से-अधिक भड़काने के प्रयास करते। अंग्रेज सरकार समझ गई थी कि भारत को हमेशा के लिये दासता की जजीरो में जकड़े रखा नहीं जा सकता इसलिये उसने अन्त में यही फैसला किया कि हिन्दू मुसलमान के नाम पर देश को विभाजित कर दिया जाये और दोनों देशों में आरम्भ में ही ऐसे झगड़े कराये जाये कि भारत और पाकिस्तान के नेता जनता की आर्थिक और सामाजिक उन्नति की ओर ध्यान न दे सके बल्कि आपस में झगड़ते रहे और इससे ब्रिटेन स्वयं फायदा उठाये।

देश के विभाजन का एक और भी कारण था। भारत शक्तिशाली बनकर राजनीतिक और व्यापारिक क्षेत्र में यूरोप का मुकाबला कर सकता है। इसलिये भारत की दोनों सीमाओं पर पाकिस्तान की तलवारें लटका दी गईं। अमरीका ब्रिटेन का सहयोगी बन गया था। दोनों पश्चिमी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिये पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर इस्तेमाल करना चाहते थे। भारत से तो उन्हें मैनिंक अड़्डे नहीं मिल सकते थे परन्तु पाकिस्तान को भारत, चीन और रूस से भयभीत करके उससे अड़्डे प्राप्त किये जा सकते थे। साधारण स्थिति में इन अड़्डों को जामूसी के लिये और युद्ध की हालत में लड़ाई के लिये इस्तेमाल किया जा सकता था। इसलिये देश का विभाजन करने से पहले ही मुस्लिम-

लीग के नेताओं से इसके लिये सौदेबाजी करली गई थी। देश के विभाजन में एक शासन सत्ता उन नेताओं के हाथों में आई जिन्होंने स्वतन्त्रा संग्राम में भाग लिया था। स्वतन्त्रता का अर्थ विदेशी शासकों को देश से निकालना ही अमिट देश की सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था का सुधारना और साधारण जनता का जीवन स्तर ऊँचा कर के ही सामयिक रूप से देश को स्वतन्त्र किया जा सकता है। इसलिये ब्रिटिश सत्ता समाप्त होते ही भारत के नेताओं ने इन समस्याओं का समाधान करने पर ध्यान दिया। स्वतन्त्रता को सुदृढ़ करने के लिये जो संविधान तैयार किया गया उसमें सभी देशवासियों को समान अधिकार दिये गये। भारत में अनेक भाषाएँ हैं। इन सबकी रक्षा और उन्नति के लिये भाषा के आचार पर प्रदेशों का पुनर्निर्माण किया गया। भारत पर विदेशी शक्तियों का प्रभुत्व स्थापित न हो जाये इसलिये आवश्यक वस्तुओं की तैयारी अपने देश से करने के लिये कारखाने स्थापित किये जाने लगे। पाकिस्तान के शासकों ने स्वतन्त्रता के लिये किसी आन्दोलन में भाग नहीं लिया था। ब्रिटेन ने मुसलमानों में हिन्दुओं के प्रति घृणा की भावना पैदा करके देश के विभाजन के लिये मुस्लिम लीग का इस्तेमाल किया था। यह लोग अधिकतर बड़े-बड़े जमींदार और अंग्रेज सरकार से उपाधियाँ पाने वाले बड़े-बड़े अधिकारी थे। अपने हितों की रक्षा के लिये अंग्रेज सरकार इसी वर्ग के लोगों को सेना, पुलिस और अन्य सरकारी कार्यालयों में भरती किया करती थी। गरीब मुसलमान वर्गों का समर्थन प्राप्त करने के लिये इन्होंने कट्टरपंथी मौलवियों का प्रयोग करके यह प्रचार किया कि हिन्दू ही उनकी निर्धनता के जिम्मेदार हैं। मुसलमान पूजापतियों ने इस स्थिति से लाभ उठाने का प्रयास किया। यह लोग “इस्लाम” के नारों में सम्मिलित हुए तो इसलिये कि ये समझते थे कि पाकिस्तान की स्थापना होने पर हिन्दुओं और सिखों को भगाकर व्यापार और उद्योग-

धन्यो पर उनका अपना अधिकार हो जायेगा। पाकिस्तान बनने पर जब किसानो, मजदूरो, अन्य गरीब वर्गों और भापाई वर्गों की समस्याये सामने आने लगी तो नेताओ को अपनी नाव डोलती हुई दिखाई देने लगी। ये लोग जनता को शासन सत्ता मे भाग देने के लिये तैयार नहीं थे इसलिये उन्होने शोर मचाना शुरू किया कि भारत पाकिस्तान को खतम कर देना चाहता है। उनकी इस कमजोरी से अमरीका आदि पश्चिमी देशो ने लाभ उठाया। पाकिस्तानी शासको को बडे पैमाने पर युद्ध सामग्री दी गई। पाकिस्तान के सैनिक अड्डे ले लिये गये। पाकिस्तान को भरपूर आर्थिक सहायता भी दी गई परन्तु पश्चिमी देशो ने कोशिश की कि पाकिस्तान उनके माल की मण्डी बने। आर्थिक रूप से अपने पाव पर खडा न हो सके। पाकिस्तानी शासको ने विदेशी शक्तियो को खत दिया कि वह अपने देश मे प्रगतिशील वर्गों को सिर उठाने नहीं देगे। शासको का अपना हित भी यही था कि सत्ता मे जनता हिस्सेदार न बने इसका परिणाम यह हुआ कि पूर्वी बंगाल, सीमा प्रान्त, सिंध और बिलोचिस्तान मे जब भी किसी राजनीतिक दल ने जनता के अधिकारो के लिए माग की उसे पाकिस्तान का शत्रु ठहराकर कुचल देने की कोशिश की गई। जनता के प्रतिनिधियो को गिरफ्तार किया जाने लगा। आर्थिक समस्याओ से जनता का ध्यान हटाने के लिये भारत पर आक्रमण करने की बाते की जाने लगी। गत २५ वर्षों मे पाकिस्तान ने पश्चिमी देशो से दो हजार करोड रुपये की युद्ध सामग्री प्राप्त की। यदि इतना धन आर्थिक प्रगति के लिये खर्च किया जाता तो देश को लाभ होता परन्तु सहायता देने वाली शक्तिया भी जानती थी कि पाकिस्तान मे आर्थिक प्रगति हुई तो उनका माल पाकिस्तान मे नहीं बिकेगा।

पाकिस्तानी शासको और पश्चिमी देशो के हित एक जैसे हो गये थे। इसलिये दोनो ने षडयंत्र करके पाकिस्तान मे सैनिक तानाशाही की

स्थापना की। इस तानाशाही ने पाकिस्तानी जनता को उसके अधिकारों से वंचित कर दिया और भारत के विरुद्ध घृणा का प्रचार जारी रखा।

१९६५ में इसी वातावरण में अयूब खान ने भारत पर आक्रमण किया था परन्तु उनकी हार हुई और इसके परिणाम स्वरूप तानाशाही के विरुद्ध विद्रोह हुआ। १९६९ में अयूब खान का तुरन्त तख्ता उलट कर याहिया खान तानाशाह बने। उन्होंने भी अपनी जनता को कुचलने की कोशिश की और भारत पर हमला कर दिया। इस बार पाकिस्तानी सेना की बुरी तरह हार हुई और बंगला देश स्वतन्त्र हो गया। श्री भुट्टो राष्ट्रपति बन गये और याहिया खान को अपने सभी सीनियर सैनिक साथियों समेत गद्दी से हटा दिया गया।

इसमें सन्देह नहीं कि बंगला देश को पुनः पाकिस्तान में मिलाना असम्भव है। बंगला देश पूर्ण रूप से स्वतन्त्र देश बन चुका है। इसकी स्वतन्त्रता ने पाकिस्तानी नेताओं की दो कौकों की ट्यूटी को खतम कर दिया है। यह सिद्ध हो गया कि धर्म के आधार पर किसी देश को जीवित नहीं रखा जा सकता। धर्म का नाम लेने वालों ने अपने ही धर्मावलम्बियों पर अत्याचार किये। प्रश्न पैदा होता है कि क्या बचा हुआ पाकिस्तान जीवित रह जायेगा? कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान के नये राष्ट्रपति श्री भुट्टो भूमि सुधार, आर्थिक सुधार और पिछड़े वर्गों की समस्याओं का समाधान करके देश की एकता को सुरक्षित रखना चाहते हैं। परन्तु एक तो जनता को मूर्ख बनाने के लिये वह भी भारत के प्रति घृणा का प्रचार कर रहे हैं दूसरे अभी तक इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि वह जनता को शासन सत्ता में भाग देना चाहते हैं। वह अपने आपको “इस्लामी समाजवाद” का समर्थक कहते हैं परन्तु समाजवाद का यह सर्कीर्ण दृष्टिकोण हिटलर के नेशनल समाजवाद अर्थात् निजीवाद से विभिन्न नहीं। नाजी शासकों ने आर्थिक

प्रगति पर तो बल दिया परन्तु जनता को उसके अधिकार नहीं दिये और देश की शक्तियों को अपने पडोसियों पर हमलो के लिये इस्तेमाल किया था। श्री भुट्टो एक इसी प्रकार के तानाशाह बन रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति के साथ ही सैनिक शासन का पद भी सम्भाला हुआ है। बगला देश की वास्तविकता को स्वीकार न करके वह युद्ध की धमकियां दे रहे हैं। सम्भव है वह यह सब कुछ केवल अपने हाथ मजबूत करने के लिये कर रहे हों परन्तु तनाव का वातावरण पैदा किया जाये तो उस पर काबू पाना कठिन हो जाता है और इसके कारण कई बार न चाहने पर भी युद्ध हो जाता है।

श्री भुट्टो स्वयं माग करते रहे कि नया संविधान तैयार करने के लिये नेशनल असेम्बली की बैठक बुलाई जाये परन्तु अब वह स्वयं यही कदम उठाने के लिये तैयार नहीं। उन्होंने अपने दल के नेताओं को प्रदेशों के राज्यपाल नियुक्त किया। भाषा और संस्कृति के आधार पर प्रदेशों के निर्माण के लिये उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। अपने राजनीतिक दल को मजबूत बनाने के लिये वह सरकारी मशीनरी को प्रयोग में ला रहे हैं। ये सभी बातें पाकिस्तानी जनता के हित में नहीं हो सकती। जनता में विरोध की भावना पैदा होगी। इस भावना को कुचलने के लिये पुलिस को प्रयोग में लाया जायेगा और इससे पुनः विद्रोह हो सकता है।

पश्चिमी पाकिस्तान में सीमा प्रान्त और बिलोचिस्तान में अपने अधिकारों के लिये जनता वर्षों से संघर्ष कर रही है। अफगानिस्तान और ईरान में इनके प्रति सहानुभूति पाई जाती है। दिसम्बर १९७० के चुनाव में इन दोनों प्रान्तों में श्री भुट्टो का राजनीतिक दल हार गया था। इस वास्तविकता को महसूस कर स्वीकार न करना एक बड़ी भारी गलती होगी। नेशनल अवामी पार्टी ने जो इन दोनों प्रदेशों में सफल हुई थी बगला देश के नेताओं की मांगों का समर्थन करते हुये अपने

लिये भी यही मार्ग प्रस्तुत की थी। यदि ये मार्ग स्वीकार न की गई तो आन्दोलन की आग भडक सकती है और यही आन्दोलन किसी समय विद्रोह में बदल सकता है। श्री भुट्टो को यह भी समझ लेना चाहिये कि जब भारत से पाकिस्तानी जगी कैंदी इन प्रदेशों में लौटेंगे तो उनकी मायूसी भी उनके लिये परेशानी का कारण बनेगी।

पाकिस्तान की आय के साधन अब आधे भी नहीं रहे। बंगला देश की मण्डी छिन जाने के कारण पश्चिमी पाकिस्तान के कई कारखाने बन्द हो जायेंगे। इससे बेकारी बढ़ेगी। अब पाकिस्तान के पास सैनिक तैयारियों के लिये काफी साधन नहीं रहे। उसे अपना सैनिक बजट आधे से भी कम करना पड़ेगा। परन्तु यदि श्री भुट्टो ने युद्ध की तैयारियाँ की तो फिर विदेशी शक्तियाँ पाकिस्तान में दखल देकर उसे अपने हितों के लिये इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। पाकिस्तान को अमरीका की ओर से बताया जा रहा है कि उसी ने पश्चिमी पाकिस्तान को बनाया है। यह भी कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान और ईरान सीमा प्रान्त और बिलोचिस्तान पर अधिकार करना चाहते हैं। सम्भव है कि इस झूठे प्रचार से बचे-खुचे पाकिस्तान को किसी ऐसे सैनिक गुट में सम्मिलित करने की कोशिश की जाये जिसका मतलब भारत, अफगानिस्तान और ईरान को कमजोर करना हो। यदि श्री भुट्टो ने यह मार्ग अपनाया तो रहा सहा पाकिस्तान भी नष्ट हो जायेगा। पाकिस्तान का अस्तित्व इसी स्थिति में कायम रह सकता है कि उसके शासक सभी प्रदेशों को अधिक-से-अधिक स्वतन्त्रता दे। जनता को उसके अधिकार दे और भारत सहित सभी पड़ोसी देशों से मित्रता के सम्बन्ध स्थापित करे। भारत की भाँति धर्म निषेध और गुट निषेध नीति पाकिस्तान को बचा सकती है। पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो इस नीति को पाकिस्तान के हित में समझते हैं।

अक्तूबर १९७१ में पश्चिमी पाकिस्तान के प्रसिद्ध देशभक्त नेता

स्वर्गीय अताउल्ला शाह बुखारी के सुपुत्र मौलाना हयातउल्ला शाह ने एक पुस्तक में लिखा कि

“मेरे पिता कहा करते थे कि मुस्लिम लीग और मि० जिन्नाह मुसलमानों को तबाही की ओर ले जा रहे हैं। मेरे पिता को इस्लाम का शत्रु कहकर मुस्लिम लीग गालियाँ दिया करते थे। आज जो कुछ हो रहा है इससे सिद्ध हो रहा है कि मेरे पिता ठीक थे। यदि वर्तमान रूप में पाकिस्तान का निर्माण न होता तो अखंड भारत में मुसलमानों की दशा बहुत अच्छी होती।”

इस सच्चाई पर मौलाना हयातउल्ला को गिरफ्तार करके उन्हें दो वर्ष कैद की सजा का आदेश दिया गया। परन्तु यही बात और भी कई पाकिस्तानी कह रहे हैं। उर्दू के प्रसिद्ध कवि जोश मलीहाबादी देश के विभाजन के बाद कई वर्ष भारत में रहे। उनके परिवार ने उन्हें पाकिस्तान चले जाने के लिये विवश किया। हाल ही में उन्होंने “यादों की बारात” नाम से अपने सस्मरणों पर एक पुस्तक प्रकाशित की। इस में उन्होंने इस बात का रोना रोया कि पाकिस्तान में अन्याय से जनता दुखी है। अपने सम्बन्ध में उन्होंने लिखा कि वह उस दिन को रो रहे हैं जब उन्होंने भारत को छोड़कर पाकिस्तान में आबाद होने का फैसला किया था।

लाहौर में एक प्रसिद्ध पत्रकार अहमद सिद्दीकी ने हाल ही में “बंगला देश की सच्ची कहानी” के नाम से एक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक हाथों-हाथ बिक गई। इसमें लिखा है कि बंगला देश में यहिया खा ने नरसंहार किया। इसी के कारण विद्रोह हुआ। उन्होंने यह भी लिखा कि पश्चिमी पाकिस्तान में भी यही हो सकता है। श्री अहमद को गिरफ्तार करके कारागार में बन्द कर दिया गया।

पश्चिमी पाकिस्तान के एक और लेखक श्री हुस्सैन असकरी रिजवी ने अंग्रेजी में “सच्चाई” (The Truth) के नाम से अपनी

पुस्तक में लिखा कि

“हमारे शासक बगला देश की वास्तविक स्थिति के मामले में झूठ बोल रहे हैं। शेख मुजीबुर्हमान पाकिस्तान के विभाजन के लिए जिम्मेदार नहीं। इसके लिये सैनिक टोला दोषी है। यही हालत पश्चिमी पाकिस्तान में भी पैदा हो सकती है। सैनिक हमलों से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता।”

श्री हुसैन को भी गिरफ्तार करके कैद कर दिया गया।

लाहौर में पंजाबी के कवि श्री अहमद सलीम ने “मेरा प्यारा बगला देश” के शीर्षक से एक कविता में लिखा कि यहियाशाही बगाल में नरसंहार कर रही है। पश्चिमी पाकिस्तान की जनता भी उससे तग आई हुई है। श्री सलीम को गिरफ्तार करके दो वर्ष के लिये कैद कर दिया गया।

सिंध के संयुक्त दल के प्रधानमंत्री श्री गुलाम जीलानी मल्लिक ने एक वक्तव्य में शेख मुजीबुर्हमान से सहानुभूति प्रकट की थी और यहिया खा को चेतावनी दी थी कि यदि उन्होंने सिंधियों की मांगों स्वीकार नहीं की तो सिंध में स्थिति बिगड़ जायेगी।

कराची के प्रसिद्ध उर्दू कवि श्री हबीब जालब ने एक कविता में सैनिक तानाशाही की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि जनता के प्रतिनिधियों को शासनसत्ता सौंप देनी चाहिये। इस पर उन्हें गिरफ्तार करके मुकदमा चलाये बिना नजरबन्द कर दिया गया।

यह हालात बताते हैं कि पश्चिमी पाकिस्तान में भी जनता तानाशाही को पसंद नहीं करती। इन्हीं हालात से परेशान होकर अयूब खा ने अपने भाई की तानाशाही की कड़ी आलोचना करते हुए पश्चिमी पाकिस्तान की सदन में कहा था कि

“यदि मुझे मालूम होता कि पाकिस्तान में हमारी यह दुर्दशा होगी तो हम कभी पाकिस्तान की स्थापना की मांग का समर्थन न

करते ।”

श्री भुट्टो इस वास्तविकता को समझ लेंगे तो पाकिस्तान बच जायेगा अन्यथा पश्चिमी पाकिस्तान के टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे ।

भारत-पाक युद्ध पर एक और रोचक पुस्तक !

ससद्-सदस्य श्री शकरदयाल सिंह रचित

युद्ध के आस-पास

(प्रस्तावना : रक्षामंत्री श्री जगजीवनराम)

सीमाओं के भ्रमण के बाद लेखक के रोचक सस्मरण !

‘स्टार सीरीज’ में प्रकाशित

मूल्य केवल दो रुपये